मनरेगा मजदूर : सर्वे में चौंकाने वाले खुलासे

दिहाड़ी निकालने को बैंक के लगाने पड़ते हैं चक्कर

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. मनरेगा के तहत महज 202 रुपए की दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों को अपनी इस रकम को निकालने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है।

लिबटेक इंडिया की ओर से किए गए एक सर्वे के मुताबिक, 45 फीसदी मनरेगा मजदूर ऐसे हैं, जिन्हें अपनी दिहाड़ी की रकम निकालने के लिए बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इनमें से 40 फीसदी मजदूर ऐसे हैं, जिन्हें बायोमीट्रिक डिटेल्स मैच न करने

के चलते कई बार बैंक या फिर डाकघर से खाली हाथ वापस लौटना पड़ा है। ऐसा उनके साथ 5 ट्रांजेक्शंस में से कम से कम एक बार हुआ है। यही नहीं, इसके चक्कर में बेहद मामूली कमाई कर पाने वाले मजदूरों को अपनी जेब से पैसे भी गंवाने पड़ते हैं।

हालात बेहद चिंताजनक

सर्वे के मुताबिक, एक मजदूर का पोस्ट ऑफिस जाने का एक बार का खर्च करीब 6 रुपए तक आता है। इसके अलावा बैंक विजिट पर 31 रुपए और एटीएम तक जाने और कैश निकालने के लिए उन्हें 67 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लिबटेक इंडिया की ओर से आंध्र प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में 1,947 लोगों पर किए गए सर्वे में यह बात सामने आई है।

जीडीपी : पूर्वानुमानों पर सकारात्मक असर

इंफ्रा परियोजनाएं: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की सितंबर, 2020 की रिपोर्ट जारी

4.37 लाख करोड़ महंगे हुए 437 प्रोजेक्ट

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. बुनियादी ढांचा क्षेत्र की 437 परियोजनाओं की लागत में तय अनुमान से 4.37 लाख करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि हुई है। देरी और अन्य कारणों की वजह से इनकी लागत बढ़ी है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय 150 करोड़ रुपए या इससे अधिक लागत वाली बुनियादी ढांचा क्षेत्र की परियोजनाओं की निगरानी करता है। मंत्रालय की सितंबर, 2020 की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह की 1,663 परियोजनाओं में से 437 की लागत बढ़ी है, जबकि 531 देरी से चल रही हैं। रिपोर्ट में 924 परियोजनाओं के चालू होने के साल के बारे में जानकारी नहीं दी गई है।

1663 परियोजनाओं में से 437 की लागत बढ़ी

531 परियोजनाएं देरी से चल रही हैं अभी

45.60% खर्च हो चुका है अनुमानित लागत का

अनुमानित लागत का 45.60 फीसदी

1,663 परियोजनाओं के क्रियान्वयन की मूल लागत 21,09,236.41 करोड़ रुपए थी, जो बढ़कर 25,47,057.52 करोड़ हो जाने का अनुमान है। इनकी लागत 20.76 फीसदी यानी कि 4,37,821.11 करोड़ रुपए बढ़ी है। सितंबर, 2020 तक इन परियोजनाओं पर 11,61,524.97 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, जो कुल अनुमानित लागत का 45.60 फीसदी है।

देरी का औसत 43.89 महीने

मंत्रालय का कहना है कि यदि परियोजनाओं के पूरा होने की हालिया समय सीमा के हिसाब से देखें, तो देरी से चल रही परियोजनाओं की संख्या कम होकर 430 पर आ जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि देरी से चल रही 531 परियोजनाओं में 122 परियोजनाएं एक महीने से 12 महीने की, 128 परियोजनाएं 13 से 24 महीने की, 160 परियोजनाएं 25 से 60 महीने की तथा 121 परियोजनाएं 61 महीने या अधिक की देरी में चल रही हैं। इन 531 परियोजनाओं की देरी का औसत 43.89 महीने है।

देरी के लिए कई कारक जिम्मेदार

इन परियोजनाओं की देरी के कारणों में भूमि अधिग्रहण में विलंब, पर्यावरण व वन विभाग की मंजूरियां मिलने में देरी तथा बुनियादी संरचना की कमी प्रमुख हैं। इनके अलावा परियोजना का वित्त पोषण, विस्तृत अभियांत्रिकी को मूर्त रूप दिए जाने में विलंब, परियोजनाओं की संभावनाओं में बदलाव, निविदा प्रक्रिया में देरी, ठेके देने व उपकरण मंगाने में देरी, कानूनी व अन्य दिक्कतें, अप्रत्याशित भू-परिवर्तन आदि जैसे कारक भी देरी के लिए जिम्मेदार हैं।

आरसीईपी: चीन विरोध का लाभ मिलने की उम्मीद

अमरीका-ईयू से फ्री ट्रेड पर फिर से बातचीत शुरू कर सकता है भारत

नई दिल्ली @ पत्रिका. भारत यूरोपियन यूनियन (ईयू) और अमरीका से फिर संभावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू कर सकता है। आरसीईपी से बाहर रहने के बाद मोदी सरकार अन्य आर्थिक ब्लॉक्स से ट्रेड डील करने के लिए उत्सुक है। दुनिया में बन रहे चीन विरोधी सेंटिमेंट का भारत को लाभ मिलने की उम्मीद है। ईयू भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है।

अब बेहद जरूरी

विशेषज्ञों का कहना है कि यूरोपियन यूनियन-अमरीका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को लाभ मिलेगा और बातचीत जल्द शुरू होगी। भारत ने कभी भी दूसरे देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट का विरोध नहीं किया है। अब जब भारत आरसीईपी से बाहर हो गया है, तो यह काफी जरूरी है।

लुधियाना

वुलन इंडस्ट्री को लगा बड़ा झटका

नई दिल्ली @ पत्रिका. कोरोना वायरस महामारी से देश में मशहूर लुधियाना की वुलन होजरी इंडस्ट्री को करीब 5000 करोड़ रुपए के कारोबार का नुकसान हुआ है। हर साल 10 से 12 हजार करोड़ का कारोबार करने वाली लुधियाना इंडस्ट्री बुरी तरह प्रभावित हुई है। लॉकडाउन में इंडस्ट्री में काम ठप रहने से लुधियाना की वुलन होजरी इंडस्ट्री का उत्पादन इस साल 40 से 50 फीसदी कम हुआ।

सर्दी शुरू: बिकने लगे गर्म कपड़े

श्रीगंगानगर. सर्दी के दस्तक देने के बाद गर्म कपड़ों की बिक्री शुरू हुई है। शहर के गोल बाजार

लक्ष्मी विलास बैंक के विलय पर सवाल

चेन्नई @ पत्रिका. निजी क्षेत्र के कर्जदाता लक्ष्मी विलास बैंक और सिंगापुर स्थित डीबीएस होल्डिंग्स की भारतीय शाखा के विलय में बैंकिंग क्षेत्र के संगठनों को गड़बड़ लग रही है। बैंक के शेयरधारकों, आम नागरिकों और कई यूनियन का मानना है कि आरबीआइ ने जिस तरह से डीबीएस इंडिया को लक्ष्मी विलास बैंक मुफ्त में देने का फैसला किया है, उसमें कई झोल हो सकते हैं। एआइबीईए के महासचिव सीएच वेंकटचलम ने कहा कि आरबीआइ के नेतृत्व में एलवीबी के डीबीएस में विलय की जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें घोटाले की भी आशंका है।

न कोरोना संक्रमितों का इलाज किए जाने में अस्पताल प्रबंधन व चिकित्सकों को आश्वासन दिया कि जिला प्रशासन का सम्पूर्ण सहयोग उन्हें प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि

किया जाएगा। एडीएम तृतीय अंजुम ताहिर सम्मा, उप सीएमएचओ डॉ प्रीतम, डॉ आनंद गोयल, डॉ सुयश गोयल, निम्बाराम बेनीवाल व डॉ नरेश मेवाड़ा उपस्थित थे।

इमारत सीज मुक्त के लिए मांगी थी दो लाख की रिश्वत

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जोधपुर. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने निर्माणाधीन इमारत को सीज मुक्त करने की एवज में एक लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में नगर निगम के कनिष्ठ सहायक ने इमारत को सीज मुक्त कराने के लिए दो लाख रुपए रिश्वत मांगी। इमारत मालिक के आग्रह पर वो एक लाख रुपए लेने को सहमत हो गया। कनिष्ठ सहायक ने रिश्वत राशि लेने के लिए बतौर बिचौलिए उदयमंदिर निवासी मोहम्मद जाहिद को शाम छह बजे ताराचंद की 12वीं रोड स्थित कार डेकोरेशन की दुकान भेजा, जहां उसने मोहम्मद जाहिद को एक लाख रुपए दे दिए। साथ ही बिचौलिए की कनिष्ठ सहायक से बात भी करा दी। कनिष्ठ सहायक चन्द्रजीत ने रिश्वत राशि लेने के लिए बिचौलिए को सोजती गेट चौकी के सामने बुलाया। कुछ देर बाद मोहम्मद जाहिद सोजती गेट चौकी के पास पहुंचा, जहां पहले से तैयार खड़े नगर निगम के कनिष्ठ सहायक डीओ शाखा (अविज्ञा अतिक्रमण शाखा) चन्द्रजीत को एक लाख रुपए दे दिए। इतने में वहां खड़े एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेन्द्र चौधरी के नेतृत्व में निरीक्षक मनीष वैष्णव ने वहां दबिश दी और कनिष्ठ सहायक चन्द्रजीत (28) पुत्र जितेन्द्र हंस और उदयमंदिर निवासी बिचौलिए मोहम्मद जाहिद (40) पुत्र मोहम्मद रज्जाक को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से रिश्वत राशि बरामद कर ली गई।

निर्माणाधीन इमारत सीज कराने और फिर उसे सीज मुक्त करने की एवज में लेन-देन के मामले में कुछ कथित पत्रकारों की भूमिका भी एसीबी के सामने आई है। जिनकी जांच की जा रही है।

अनुकम्पा नौकरी पर लगा है कनिष्ठ सहायक

एएसपी नरेन्द्र चौधरी का कहना है कि आरोपी कनिष्ठ सहायक के पिता भी नगर निगम में थे। ड्यूटी के दौरान पिता की मृत्यु हो गई थी। तब चन्द्रजीत को करीब पांच-छह साल पहले अनुकम्पा नौकरी मिली थी।

पत्रिका सिटीजन

घर पर ही रहें और कोरोना को फैलने से बचाएं

12-09-2020

तीन बड़े नालों को जोजरी से मिलाने में कई दिक्कतें

अड़चनों की गिरफ्त में बदहाल हुआ ड्रेनेज सिस्टम

हाईकोर्ट में कबूल किया निगम-जेडीए ने

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

जोधपुर. शहर के बरसाती नालों की बदहाल स्थिति और उनके जोजरी नदी तक जुड़ाव में आ रही अड़चनों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में अब 5 अक्टूबर को सुनवाई होगी। शहर के मुख्य पांच नालों में तीनों की अब भी जोजरी नदी तक पहुंच नहीं है।

वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा तथा न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ में एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से अधिवक्ता राजेश पंवार और जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से अधिवक्ता मनोज भंडारी ने कहा कि कोर्ट के पूर्ववर्ती आदेशों की पालना में जोधपुर शहर में ड्रेनेज की मौजूदा स्थिति पर रिपोर्ट पेश कर दी गई है। याची के अधिवक्ता सीएस कोटवानी ने बारिश के दौरान जल भराव की स्थिति पर कोर्ट का ध्यान खींचा। स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार शहर में पांच मुख्य बरसाती नाले (ड्रेनेज चैनल) हैं, जिनमें पाबूपुरा नाला तथा यूनिवर्सिटी नाले का क्षेत्राधिकार निगम का है, जबकि माता का थान, आरटीओ तथा भैरव नाले का जिम्मा जोधपुर विकास प्राधिकरण का है। निगम की ओर से बताया गया कि शहर में प्रभावी ड्रेनेज सिस्टम के लिए अमृत योजना के तहत हाईकोर्ट परिसर, नागौरी गेट (मूथाजी का मंदिर), सर्किट हाउस व वेस्ट पटेल नगर, भदवासिया ओवर ब्रिज के पास, खेतानाडी एरिया, गौशाला मैदान तथा खेमे का कुआं, अशोक उद्यान, अणदाराम स्कूल चौराहा, सेक्टर 18 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड से फिल्ट हाउस तक बरसाती पानी की निकासी सुनिश्चित करने के लिए कार्यादेश जारी किए गए हैं। निगम का दावा है कि इन चैनल का निर्माण होने पर शहर में बारिश के दिनों में जल भराव की समस्या का काफी हद तक निदान संभव है। हालांकि, जेडीए और निगम की ओर से पेश रिपोर्ट में यह साफ तौर पर माना गया है कि तीन मुख्य नालों के जोजरी से जुड़ाव में अब भी कई अड़चनें हैं।

माता का थान नाला : जन सुनवाई ने रोकी राह

माता का थान नाले को जोजरी से जोड़ने के लिए भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया नए अधिनियम के तहत प्रारंभ की गई थी। जेडीए ने पिछले साल भूमि अवाप्ति का सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन करवाया। योजना पर 169.81 करोड़ रुपए का खर्च प्रस्तावित है। इसमें करीब 80 फीट चौड़ी रोड के सहारे 20 फीट का नाला बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई करीब 7.9 किमी होगी। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर अब कानूनी प्रावधानों के अनुसार जन सुनवाई की जानी है। जेडीए ने इस संबंध में जिला कलक्टर को इस साल 13 मार्च को पहला पत्र लिखा था। उसके बाद 9 जुलाई और 4 सितंबर को स्मरण पत्र भेजे गए। कोविड-19 प्रकोप के चलते जन सुनवाई नहीं हो पाई है।

यूनिवर्सिटी नाला : पेड़ों के कारण अटका काम

यूनिवर्सिटी से जोजरी नदी तक बरसाती पानी की निकासी के लिए करीब 6.93 किमी ड्रेनेज चैनल का निर्माण किया जाना है। इसके लिए 33.20 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। चैनल के दो भाग पूरे हो चुके हैं, लेकिन बीच का एक बड़ा भाग 362 पेड़ों की मौजूदगी के कारण अटक गया है। नगर निगम ने पेड़ कटवाने की अनुमति के लिए जिला कलक्टर को पत्र भेजा, जिन्होंने 2 जुलाई को पेड़ काटते हुए लकड़ी को नीलाम करने के आदेश दिए। यह जिम्मा वन विभाग को दिया गया। इसके लिए निगम ने वन अमले को पत्र भी लिखा, लेकिन उप वन संरक्षक ने जैव विविधता को खतरे का अंदेशा जताते हुए मार्गदर्शन के नाम पर गेंद दुबारा जिला कलक्टर के पाले में डाल दी।

भैरव नाला : जोजरी से जुड़ाव की मूल योजना ड्रॉप

भैरव नाले में सूरसागर, गेंवा, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, शोभावतों की ढ़ाणी तथा न्यू विकसित कॉलोनियों से बरसाती पानी की आवक होती है, लेकिन इस नाले का पानी डर्बी टेक्टसाइल इकाई के पास जाकर फैल जाता है। इसे सालावास के पास जोजरी नदी से जोड़ने के लिए कृषि भूमि की अवाप्ति का प्रस्ताव तैयार किया गया और भूमि अवाप्ति के लिए अधिसूचना भी प्रस्तावित की गई, लेकिन इस बीच नेशनल हाइवे ॲथोरिटी के अधिकारियों ने एक बैठक में रिंग रोड से नाले का जुड़ाव सुनिश्चित करने की योजना पर सहमति नहीं दी। जेडीए ने बाद में मूल योजना ही ड्रॉप कर दी। अब एलाइनमेंट बदलने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करवाई जा रही है। इसके लिए एडवांस इंजीनियरिंग कंसल्टेंट कंपनी को कार्यादेश दिया गया है, जिसे 5 दिसंबर तक रिपोर्ट देने को कहा गया है। उसके बाद ही इस नाले का भविष्य तय होगा।

ऋण माफी योजना में घपले पर मांगा जवाब

जोधपुर@पत्रिका. राजस्थान हाईकोर्ट ने किसानों के नाम से फर्जी ऋण उठाकर माफी योजना का लाभ लेने के मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर डुंगावत ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के हित में राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019 लागू की थी। याची सहित कई किसानों की जानकारी में आया कि उनके नाम से उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने इन अनियमितता की शिकायतें की, लेकिन शुरुआत में कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में जांच प्रतिवेदन में यह माना गया कि

बाजार की रफ्तार से टूटेगा कोरोना का चक्रव्यूह

केयर रेटिंग्स रिपोर्ट: वित्त वर्ष 2020 में 3.5 फीसदी रहा जॉब ग्रोथ रेट

सिर्फ 50.02 लाख लोगों को मिली नौकरी

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. केयर रेटिंग्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अर्थव्यवस्था में लंबे समय से बने तनाव के कारण वित्त वर्ष 2020 में जॉब ग्रोथ रेट घटकर 3.5 फीसदी पर आ गया है, जबकि वित्त वर्ष 2019 में यह 3.8 फीसदी था। हालांकि कुल नौकरियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 2019 की 48.32 लाख के मुकाबले 2020 में कुल 50.02 लाख नौकरी मिली हैं।

वित्त वर्ष 2020 में 1.70 लाख नई नौकरियां पैदा हुई हैं। 2019 में यह आंकड़ा 1.76 लाख था। 2020 में 321 कंपनियों ने अपने हेडकाउंट में 1.13 लाख की कमी की। वहीं 2019 में 272 कंपनियों ने अपने हेडकाउंट में 1.18 लाख की कमी की थी।

1.70 1.70 लाख नई नौकरियां पैदा हुईं पिछले वित्त वर्ष में

23% के साथ आईटी सेक्टर टॉप पर रहा नौकरी देने में

9 कंपनियों में 1 लाख हेडकाउंट

पिछले साल देश में 9 कंपनियों में हेडकाउंट की संख्या 1 लाख से ज्यादा रही। इसमें चार कंपनियां आईटी सेक्टर, दो बैंकिंग, एक-एक ऑटो, एनबीएफसी और अन्य सेक्टर की शामिल रहीं। वहीं सात कंपनियों में हेडकाउंट की संख्या 50 हजार से 1 लाख के बीच रही। 17 कंपनियों में हेडकाउंट की संख्या 25 से 50 हजार के बीच रही। 33 कंपनियों में हेडकाउंट की संख्या 25 हजार से ज्यादा रही, जो कुल रोजगार का 57 फीसदी था।

नौकरी देने में आईटी सेक्टर रहा टॉप पर

पिछले साल सबसे ज्यादा नौकरी देने में चार सेक्टरों की भागीदारी 61 फीसदी रही। इसमें 23 फीसदी के साथ आईटी सेक्टर टॉप पर रहा। इसके बाद 2 फीसदी के साथ बैंकिंग सेक्टर दूसरे, 9 फीसदी के साथ ऑटो तीसरे और 7 फीसदी के साथ फाइनेंस सेक्टर चौथे नंबर पर रह कभी सबसे ज्यादा नौकरियां देने शामिल रहा टेक्सटाइल सेक्टर 2. फीसदी की हिस्सेदारी के साथ पांचवें स्थान पर रहा। अन्य सेक्ट में भी नौकरियों को लेकर कोई खास इजाफा नहीं हुआ।

अब शहद कारोबार में उतरेगी अमूल

नई दिल्ली. अमूल अब शहद कारोबार में भी उतरेगी। कंपनी स्वीट रिवॉल्यूशन के तहत यह पहल करेगी। कंपनी ने इस पर काम शुरू कर दिया है और जल्द ही वह शहद की टेस्टिंग के लिए लैब में भेजेगी।

एबीसी के चेयरमैन बने देवेंद्र दर्डा

नई दिल्ली. लोकमत मीडिया समूह के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेंद्र वी दर्डा 'ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन' (एबीसी) का चेयरमैन चुना गया है। उन चुनाव वर्ष 2020-21 के लिए किया गया है।

मप्र : 43 साल बाद सामने आया का पत्र

15 हजार करोड़ से ज्यादा की हो सकती है शत्रु संपत्ति

भोपाल@ पत्रिका. संपत्ति को लेकर 43 साल पहले भोपाल नवाब हमीदुल्लाह खान की बेगम आफताब जहां के लिखे पत्र के सामने आने से शत्रु संपत्ति के मामले में खलबली मच गई है।

मप्र के भोपाल में सुल्तानिया रोड निवासी मधुदास बैरागी ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री से लेकर सांसद और कलक्टर तक से इसकी शिकायत की है। इसमें कहा है कि आफताब जहां के नाम से भोपाल, रायसेन और सीहोर में जहां भी संपत्तियां हैं, उन्हें शत्रु संपत्ति घोषित करते हुए केंद्र सरकार अपने अधीन ले। यदि ऐसा होता है तो करीब 15 हजार करोड़ मूल्य से अधिक की शत्रु संपत्ति घोषित हो सकती है।

तब दबा दिया था पत्र

यह पत्र तत्कालीन केंद्र सरकार के सचिव व ऑफिसर इंचार्ज कस्टोडियन एनीमी प्रॉपर्टी, केंद्रीय गृह मंत्रालय को 2 मई 1977 को कराची से लिखा गया था। तब इस पर अमल नहीं हो सका। इधर, काफी जमीनें बेच दी गईं। पत्र को भी दबा दिया गया। लेकिन जून-जुलाई में केंद्र की एक टीम पत्र की कॉपी लेकर भोपाल आई और आफताब जहां के नाम की संपत्तियों की जानकारी ली। घर बचाओ संघर्ष समिति के उप संयोजक जगदीश छावानी का कहना है, पत्र की वैधानिकता कितनी है, ये भी साफ नहीं है।

मौसम विभाग का अनुमान

चीन ने छेड़ा हाइब्रिड युद्ध | बिग डेटा से भारतीय हस्तियों की जासूसी

अब तक... 5 पीएम, 24 सीएम, 350 सांसद

दुनिया की महाशक्ति बनने का सपना देख रहे चीन ने अपने छोटे-बड़े सभी प्रतिद्वंदी देशों के खिलाफ हाइब्रिड युद्ध छेड़ दिया है। इसका खुलासा चीन के शेनजेन प्रांत में स्थित डेटा कंपनी की कारगुजारियों के सामने आने से हो गया है। यह कंपनी दुनिया के करीब 24 लाख लोगों से जुड़े डिजिटल डेटा को चोरी-छिपे जमा कर उनकी निगरानी कर रही है। उसने माना भी है कि यह काम वह चीनी सेना व सरकार के लिए कर रही है। बिग डेटा के जरिए चीनी जासूसी का किस्सा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सीडीएस जैसी राजनीतिक व सैन्य हस्तियों और उनके रिश्तेदारों तक ही सीमित नहीं। उसकी निगरानी में खेल जगत से लेकर सांस्कृति और धार्मिक हस्तियां भी है।

दरअसल चीन भविष्य में असल युद्ध के बजाय डिजिटल डेटा का इस्तेमाल कर ऐसे युद्ध की तैयारी में जुटा है, जिसमें वह सेना उतारे बिना शत्रु देश को बर्बाद कर सके। नीति तय करने वालों और उनके फैसलों को प्रभावित करने वालों की छोटी-बड़ी जानकारी जुटाकर चीन न केवल पहले से ही फैसलों का पता करना चाहता है बल्कि उन्हें अपने हिसाब से बदलवाना भी। चीनी जासूसी के अलावा कई और हथकंडे भी अपना रहा है, जिससे वह अपना वर्चस्व कायम कर सके। कोरोना का जनक होने के बावजूद उसका आर्थिक फायदे में होने को भी कई विशेषज्ञ चीनी साजिश का ही हिस्सा मान रहे हैं।

टारगेट पर ये...

- [0 मौजूदा व पूर्व मुख्यमंत्री, डिप्टी [ए]एम और उनके परिवार
- [.]50 मौजूदा व पूर्व सांसद, कई [सं]सदीय समिति सदस्य
- [.]60 लोग जो राजनेताओं के [क]रीबी रिश्तेदार
- [.]00 राजनेताओं पर सीधी नजर

1 जासूसी

[च]ार दशकों से [ज]ारी चीनी [ज]ासूसी का खेल

[प]त्रिका न्यूज नेटवर्क
[pa]trika.com

[न]ई दिल्ली. चीन बिग डेटा से यह [जा]सूसी चार दशकों से कर रहा है। [इ]नकी निगरानी में भारत के मौजूदा [रा]ष्ट्रपति-प्रधानमंत्री के अलावा कम [से] कम दो तत्कालीन राष्ट्रपति और [पां]च तत्कालीन प्रधानमंत्री भी रहे। [इन]में तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे [अ]ब्दुल कलाम व प्रणब मुखर्जी, [स]मेत तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव [गां]धी, पीवी नरसिंह राव, अटल [बि]हारी वाजपेई, एचडी देवगौड़ा, [म]नमोहन सिंह और उनके रिश्तेदार [श]ामिल है। इस कांड खुलासा करने [वा]ले अंग्रेजी इंडियन एक्सप्रेस के [अ]नुसार कई नामी परिवारों की भी [ची]न निगरानी कर रहा है, इनमें गांधी [प]रिवार (संजय गांधी समेत), पवार [प]रिवार (शरद व सुप्रिया), सिंधिया [प]रिवार (ज्योतिरादित्य व उनकी [प]त्नी), संगमा परिवार और बादल [प]रिवार शामिल हैं। ड्रैगन की नजर [हे]मा मालिनी, अनुपम खेर, परेश रावल और विनोद खन्ना पर भी रही है।

पढ़ें अब @ पेज 05

क्या-क्या हो सकता है इससे

[क्री]मिया जैसे बड़े इलाके पर कब्जा

विशेषज्ञों का अनुसार 2014-15 में क्रीमिया का रूस में विलय हाइब्रिड वारफेयर का नतीजा है, पूर्वी यूक्रेन में हुए इस अघोषित युद्ध में रूस नेतृत्व सुनिश्चित था कि कोई भी वैश्विक शक्ति हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस दौरान सैनिक दिखे जरूर मगर युद्ध लड़ा गया राजनीति, आर्थिक और तकनीक के मैदान में।

■ ***हांगकांग जैसे प्रदर्शनों पर काबू :*** चीन ने निगरानी तंत्र के जरिए हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचल दिया है। आंदोलन में शामिल छोटे से छोटे से नेता की पहचान कर प्रदर्शनकारियों को काबू किया है।

नंबर गेम

24 लाख लोगों की दुनिया में जासूसी कर रहा चीन, इनमें दस हजार भारतीय भी शामिल।

चिंता की बात यह

एलएसी पर सैन्य तनाव के बाद भारत ने 100 से ज्यादा चीन ऐप्स पर भले ही रोक लगा दी, मगर विशेषज्ञों का कहना है कि इनसे झेनहुआ जैसी कंपनियों के काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

हाइब्रिड वारफेयर है क्या?

1999 में चीनी सेना के कर्नल किआओ लियांग और कर्नल वांग ने 1999 में 'अप्रतिबंधित युद्ध' नाम से किताब इसकी रूपरेखा रखी। इसके अनुसार, हिंसा को सैन्यक्षेत्र से हटाकर राजनीतिक, आर्थिक और तकनीक के क्षेत्र में ले जाना हाइब्रिड वारफेयर है। इसके हथियार वह जो आम आदमी की जीवन से जुड़े हैं। लोग किसी सुबह उठेंगे और उन्हें पता चलेगा कि कुछ बेहद सौम्य और नाजुक से दिखने वाली चीजों में आक्रामक और घातक विशेषताएं हैं।

करती क्या है झेनहुआ कंपनी?

चीनी खुफिया, सैन्य व सुरक्षा एजेंसियों के साथ काम करने का दावा करने वाली झेनहुआ डेटा आईटी कंपनी ... सोसाइटी के लोगों व संस्थानों के डिजिटल फुटप्रिंट यानी हर तरह की डिजिटल जानकारी की निगरानी करती है। इन जानकारियों के सूचना लाइब्रेरी रखता है। इनमें समाचार स्त्रोतों, पेटेंट व बिडिंग से जुड़े दस्तावेजों से जानकारी जमा की जाती है।

2 साजिश का वायरस

वुहान लैब से ही निकल कर दुनिया में फैला है कोरोना वायरस

बीजिंग@पत्रिका. चीन की मशहूर वायरॉलाजिस्ट ने दावा किया है कि चीन ने कोरोना वायरस पैदा किया है। हांगकांग स्कूल चीन की वायरॉलजिस्ट डॉ. ली-मेंग यान ने दावा किया है कि पेइचिंग को कोरोना वायरस के बारे में तब ही पता चल गया था महामारी फैलना शुरू नहीं हुआ था। यह दावा करने के बाद से वह अपनी जान बचाकर भागने को मजबूर हैं।

उन्होंने दावा किया है कि वे इसका सबूत भी पेश करेंगी कि वायरस चीन की देन है। चीन ने सरकारी डेटाबेस से उनकी सारी जानकारी हटा दी है। डॉ. यान ने दावा किया है कि वुहान मार्केट में कोविड-19 शुरू होने की खबरें केवल छलावा हैं। उनका कहना है कि वे एक रिपोर्ट पब्लिश करने वाली हैं जिसमें वायरस के इंसानों के हाथों बनाए जाने के सबूत हैं। डॉ. यान ने जान बचाने के लिए अमरीका में शरण ली है। डॉ. यान ने कहा कि वायरस प्राकृतिक नहीं है।

मैं स्टडी वाली पहली वैज्ञानिक

मैं कोरोना वायरस को स्टडी करने वाले पहले वैज्ञानिकों में से एक हूं। 2019 के आखिर में सॉर्स जैसे केस के क्लस्टर देखने के लिए कहा था। मौत के बढ़ते आंकड़े के चलते यह मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि सब लोगों के सामने आए। **-डॉ. ली-मेंग यान, वायरॉलाजिस्ट**

सबूत दूंगी कैसे आया कोविड-19

जब डॉ. यान से से पूछा गया कि वायरस कहां से आया तो उन्होंने जोर देकर कहा कि यह वायरस वुहान की प्रयोगशाला से आया है। जीनोम सीक्वेंस इंसानी फिंगर प्रिंट जैसा है। इस आधार पर इसकी पहचान की जा सकती है। मैं सबूत देकर बताऊंगी कि कैसे यह चीन की लैब से आया है। डॉ. यान ने कहा कि उनकी जानकारी चीन के डेटाबेस से हटा दी गई है। उनके साथियों को कहा गया है कि वे डॉ यान के बारे में झूठी खबरें फैलाएं। यही कारण है कि मेरे बारे में बेबुनियादी खबरें आ रही हैं।

3 सीमा पर धमकी

कोरोना से जूझ रहे देशों की परेशानी बढ़ा रहा है चीन

नई दिल्ली. कोरोना महामारी फैलने के बाद चीन ने भारत सहित अपने कई पड़ोसी देशों के साथ मोर्चा खोल रखा है। इससे उसकी मंशा पर शक होता है। कुछ लोगों को यह भी शक है कि कोविड-19 वायरस उसके जैविक युद्ध का हिस्सा हो सकता है। भारत-चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) को एकतरफा बदलने की चीनी साजिश का खुलासा उस समय सामने आया जब 15 जून को लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई। उसके बाद से ही चीन गलवान घाटी पर अपना दावा ठोक कर तनाव बढ़ा रहा है। अब भी दोनों देशों की सेनाएं एलएसी पर आमने-सामने हैं। दक्षिण चीन सागर में फौज की तैनाती, ताइवान के हवाई सीमा का बार-बार उल्लंघन, भूटान सीमा पर विवाद बढ़ाकर चीन कोरोना से जूझ रहे देशों की परेशानी बढ़ा रहा है।

4 धोखेबाजी

सहायता के नाम पर घटिया मेडिकल सामान की आपूर्ति

नई दिल्ली. दुनिया में कोरोना फैलने के बाद उससे निपटने के लिए जरूरी स्वास्थ्य उपकरणों और सुरक्षा साधनों की आपूर्ति में चीन ने रुचि दिखाई पर ज्यादातर देशों को घटिया सामान की आपूर्ति की गई, उनमें भारत भी एक है। चीन से आए मास्क, वेंटिलेटर और पीपीई किट की खराब गुणवत्ता के कारण महामारी से जूझ रहे स्वास्थ्यकर्मियों को खासी परेशानी हुई। अभी इसका खुलासा भी हुआ है कि मध्यप्रदेश के खंडवा में एक विधायक ने चीन से मंगाई गई थर्मल स्क्रीनिंग गन बांटी थी जो अधिकतर खराब निकली।

नेशनल विंडो

पेट्रोल 15, डीजल 14 पैसे सस्ता

जयपुर @ पत्रिका. तेल कम्पनियों ने सोमवार को पेट्रोल व डीजल के दामों में एक बार फिर थोड़ी कमी की है। कम्पनियों ने पेट्रोल के दाम 15 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 14 पैसे प्रति लीटर घटाए हैं। दामों में कमी होने के बाद राजधानी जयपुर में पेट्रोल 89.03 रुपए प्रति लीटर और डीजल 81.89 रुपए प्रति लीटर बिका।

राजस्थान : पूर्व राज्यपाल

कल्याण सिंह भी कोरोना संक्रमित, भर्ती

लखनऊ @पत्रिका. राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।

88 वर्षीय कल्याण सिंह को पीजीआइ लखनऊ में भर्ती कराया गया है। उनका रसोइया तीन दिन पहले कोरोना पॉजिटिव गया था। उनके निजी सचिव ने बताया कि पहले उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया था, लेकिन शाम को डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें पीजीआइ में भर्ती किया गया है।

आदेश : काले हिरणों का शिकार

सलमान 28 को जोधपुर कोर्ट में रहें मौजूद

जोधपुर @ पत्रिका. अभिनेता सलमान खान के खिलाफ 21 वर्ष से चल रहे काले हिरणों के शिकार मामले में सोमवार को नया मोड़ आ गया। मामले में जोधपुर जिला न्यायालय के जज ने सलमान के अधिवक्ता को 28 सितंबर को आरोपी सलमान खान को कोर्ट में उपस्थित रहने तथा जमानत व मुचलके भरने का आदेश दिया। सलमान को 28 सितंबर को न्यायालय में उपस्थित होना होगा।

दिल्ली हाईकोर्ट : सरकार का जवाब

कानून में समलैंगिक शादी को मान्यता नहीं : केंद्र

नई दिल्ली@ पत्रिका. केंद्र सरकार ने सोमवार को हिंदू विवाह एक्ट 1956 के तहत समलैंगिक विवाहों को मान्यता और रजिस्ट्रेशन देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक याचिका का विरोध किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान की खंडपीठ के समक्ष दलील दी कि 'हमारा कानून, समाज समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं देता है।'

ग्राउंड रिपोर्ट | भारत की सैकड़ों साल पुरानी सांस्कृतिक जड़े काटने की साजिश

नेपाल में भारतीय सीमा से सटे गांवों में चीन ने बिछाया अपने स्टडी सेंटरों का जाल

आनंद मणि त्रिपाठी
patrika.com

बिछिया बहराइच. नेपाल को भारत से अलग थलग करने के लिए चीन साजिश पर साजिश रच रहा है। एक तरफ जहां उसने लिपुलेख की तरफ तीन दिन चहल कदमी करने के बाद अपनी सेना बढ़ा दी है।

वहीं सांस्कृतिक, धार्मिक और भारत जुड़ाव की जड़ों को कटाने के लिए भारत-नेपाल सीमा पर चीनी स्टडी सेंटर की संख्या भी बढ़ी है। पहले यह केंद्र करीब 19 हुआ करते थे लेकिन हाल के वर्षों में इनकी संख्या बढ़कर 50 हो गई है। खास बात यह है कि इसमें से ज्यादातर भारत के साथ लगती सरहदी इलाकों में हैं। इन केंद्रों से चीन अपनी भाषा मंदारिन की अनिवार्य शिक्षा नेपाली नागरिकों को दे रहा है बल्कि वह नेपाल के लोगों को चीन जोड़ने के लिए भी तमाम कोशिश कर रहा है। नए सिरे से चीन से नेपाल की सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनैतिक जुड़ाव का नया इतिहास गढ़ रहा है।

पढ़ें नेपाल @ पेज 05

चीनी शह पर नेपाल की पाबंदी से बेजार हुए भारतीय व्यापारी गांव-गांव में बेच रहे कपड़े।

शहर ही नहीं गांवों को भी बांटा

तराई इलाके में भारत के झुकाव को कम करने के लिए नेपाल सरकार लगातार ही मधेशी इलाकों मे पहाड़ी नागरिकों को बसा रहा है। सरहद के सभी गांवों का नगरीकरण कर दिया है। सभी गांवों को बकायदे किसी निगम या पालिका में डालकर वार्ड में बांटा है।

जानवर तक नहीं जाने देते

कतरनिया के जंगल को पार करते हुए जब आप बीओपी 82 पर पहुंचते हैं तो यहां आपको नेपाल और भारत के बीच चल रही रस्साकसी में तनाव भले ही न नजर आए, लेकिन दोनों के बीच चल रहे खिंचाव का अंदाजा आराम से हो जाता है। यहां नेपाल पुलिस के साथ आर्म्ड पुलिस फोर्स भी तैनात। यह इतने हैं कि आदमी तो छोड़िए जानवरों को भी सीमा पर नहीं आने दे रही है।

3 मिनट की बात में 2 मिनट चीन

भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी के एक वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि चीन का असर तो साफ झलकता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आप नेपाली आर्म्ड पुलिस जवानों के साथ बात करें तो तीन मिनट की बात में दो मिनट बात उनकी चीन की रहती है।

कलक्टर की जांच : सामने आई यूरिया की कालाबाजारी

65 किसानों के अंगूठे लगवा बेचे 6 हजार कट्टे

15.9.20

एक्सक्लूसिव

कृषि विभाग के अधिकारियों ने करवाया मामला दर्ज

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

बाड़मेर. सेड़वा क्षेत्र में खाद बीज भण्डार संचालक ने किसानों के अंगूठे लगवाकर 6 हजार यूरिया खाद के कट्टों की कालाबाजारी कर दी। शिकायत पर कलक्टर ने जांच करवाई तो सामने आया कि किसानों को यूरिया खाद मिली नहीं, जबकि पोस मशीन से किसानों के नाम यूरिया खाद उठा दी।

कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सेड़वा थाने में मीनाक्षी खाद बीज भण्डार संचालक सुरेशकुमार निवासी सेड़वा के खिलाफ कृषि उपनिदेशक ने मामला दर्ज कराया कि कलक्टर के निर्देश पर खाद भण्डार की ओर से किसानों को विक्रय किए गए यूरिया खाद का सत्यापन करवाया। इसमें सामने आया कि खाद भण्डार संचालक ने फर्जी तरीके से 65 किसानों के पोस मशीनों पर अंगूठे लगवाकर खाद बेच दी। पुलिस ने सुरेश कुमार के खिलाफ जांच शुरू कर दी है तथा कृषि विभाग ने फर्म का लाइसेंस निरस्त कर दिया।

कृषकों के बनाए झूठे बिल

सत्यापन में सामने आया कि बीज लेने के दौरान किसानों के अंगूठे लगवा दिए और बाद में यूरिया खाद के बिल पेश कर दिए। किसानों का आरोप है कि बीज लेने के दौरान अनभिज्ञ रखकर पोस मशीन पर यूरिया खाद के लिए अंगूठे करवा दिए।

खाद भण्डार संचालक का लाइसेंस निरस्त

खाद भण्डार संचालक सुरेश कुमार के खिलाफ यूरिया की कालाबाजारी करने का मामला दर्ज करवाया है। उसका लाइसेंस निरस्त किया जा रहा है।

डॉ. जेआर भाखर, उपनिदेशक, कृषि विभाग, बाड़मेर

कोरोना मीटर

प्रदेश में कुल स्क्रीनिंग	2672224
कुल पॉजिटिव	104138
कुल डिस्चार्ज	84638

पुलिस और गोतस्करों के बीच फायरिंग

खुद को आग लगा थाने में दौड़े किसान की मौत

पोकरण (जैसलमेर) @ पत्रिका. पेट्रोल डाल खुद को आग लगाकर पोकरण थाने में दौड़े 30 वर्षीय किसान की सोमवार सुबह अस्पताल में मौत हो गई। पोकरण व रामदेवरा थाने में मामले दर्ज किए गए हैं।

फलोदी थाना क्षेत्र के सिहड़ा हाल सोहनसिंह की ढाणी रामदेवरा निवासी उक्त किसान गिरधारीराम भील ने रविवार अपराह्न पोकरण थाने पहुंचकर खुद को आग लगा ली थी। आरोप है कि वह पड़ोसी रामदेवरा सरपंच समंदरसिंह तंवर व उसके परिजनों से परेशान था।

उसने पूर्व में राजस्व विभाग की टीम से कई बार खेत की सीमाओं का सीमाज्ञान कराया लेकिन पड़ोसी उसे परेशान कर रहे थे। मामले में पुलिस ने आरोपी सरपंच समंदरसिंह व माधुसिंह को गिरफ्तार किया है।

प्रदेश में 50 फीसदी से अधिक खाद्य तेल के पैकेज्ड ब्राण्ड में व्यापारी कर रहे हेरफेर

बाजार में तेल का खेल, पैकेज्ड बोतल में 100 से 300 एमएल तेल कम

एक्सक्लूसिव

एक लीटर में 100, दो लीटर में 150 और पांच लीटर में 300 मिली तक तेल कम

गजेन्द्र सिंह दहिया
rajasthanpatrika.com

जोधपुर. सुपर मार्केट और बाजार में किराणा स्टोर पर मिलने वाले पैकेज्ड खाद्य तेल में तेल की मात्रा पैकेजिंग में अंकित मात्रा से कम पाई गई है। एक लीटर खाद्य तेल में 90 से 100 मिलीमीटर, दो लीटर खाद्य तेल में 150 से 200 मिली और पांच लीटर के जरिकन में 300 मिलीमीटर (एमएल) तक तेल कम आ रहा है।

राजस्थान पत्रिका ने मंगलवार को मंडोर मण्डी और आसपास के किराणा स्टोर पर पैकेज्ड खाद्य तेल की जांच की तो बाजार में उपलब्ध 50 फीसदी से अधिक ब्राण्ड में खाद्य तेल कम मिला।

एक लीटर तेल का वजन 910 ग्राम होना चाहिए लेकिन इस बोतल का वजन 800 ग्राम के आसपास ही है।

बोतल के वजन सहित इस एक लीटर की बोतल का वजन 932 ग्राम लगभग सही आ रहा है।

इस बोतल को देखने भर से ही खाद्य तेल की मात्रा कम नजर आ रही है। वजन भी कम है।

एक लीटर खाद्य तेल में ज्यादा नुकसान

एक लीटर की बोतल में बिक रहे खाद्य तेल में ग्राहकों को सर्वाधिक नुकसान हो रहा है। एक लीटर का अर्थ 910 ग्राम होता है। बोतल का 15 से 20 ग्राम जोड़ने पर एक लीटर की बोतल का वजन 930 ग्राम के आसपास होना चाहिए, लेकिन पत्रिका की ओर से चार-पांच ब्राण्ड की बोतलों वजन किया गया उसमें से पचास फीसदी का वजन 800 से 850 ग्राम तक ही आया।

ग्रामीण अधिक ठगे जा रहे

ग्रामीण तबकों में सस्ते के नाम पर स्थानीय ब्राण्ड चलते हैं। गांवों में एक लीटर और दो लीटर की बोतल अधिक बिकती है। ऐसे में सर्वाधिक नुकसान ग्रामीणों को हो रहा है।

यिह गलत है, हम कार्यवाही करेंगे

प्रदेश में अगर तय मानकों से कम खाद्य तेल की मात्रा बेची जा रही है तो यह गलत है। हम शीघ्र इसकी जांच करके छापेमारी करवाएंगे।

चंदीराम जसवानी, डिप्टी कंट्रोलर, विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ जयपुर

किस ब्राण्ड में कम मिली खाद्य तेल की मात्रा

- भीलवाड़ा से पैक होकर आए ब्राण्ड में एक लीटर खाद्य तेल की बोतल का वजन 804 ग्राम ही था।
- आसोप से आए 400 मिली बोतल के ब्राण्ड में 50 एमएल तेल कम।
- ब्यावर से पैक 5 लीटर के जरिकन में 350 ग्राम तक तेल कम मिला। पैकेजर्स ने चालाकी यहां तक कर दी कि पांच लीटर के जरिकन में तेल की मात्रा 3 लीटर बताकर 1.5 लीटर मुफ्त में देने का अंकित किया हुआ है
- जोधपुर में बने तीन ब्राण्ड का वजन क्रमशः 917, 915 और 925 ग्राम मिला जो थोड़ा कम था।
- राष्ट्रीय ब्राण्ड के एक लीटर खाद्य तेल की बोतल का वजन 933 ग्राम आया।

देशभर के कंटे

अवैध खनन रोकने में नाकाम : 70 फीसदी कब्जा राजनेता व नौकरशाहों का

माफिया को 'छूट', जनता पर भार

21-9-20

अंतहीन खेल हाथ पर हाथ धरे बैठे जिम्मेदार

बनास नदी से हरियाणा-पाक बॉर्डर तक हो रहा अवैध खनन

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर . राज्य में बड़े पैमाने पर महत्त्वपूर्ण खनिजों का अवैध खनन हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों से तो खनन माफिया इतना हावी है कि पुलिस और खान विभागों की टीमों पर ही हमला बोल रहा है। इस पर रोक नहीं लग पाने की बड़ी वजह इस कारोबार पर करीब 70 फीसदी कब्जा राजनेता व नौकरशाहों का है।

ऐसे में राज्य सरकार ने जब भी हिम्मत दिखाकर अवैध खनन गतिविधियों पर रोकथाम का अभियान चलाया तो बीच में ही रोकना पड़ा। आज प्रदेश के दर्जनभर से ज्यादा जिले ऐसे हैं, जहां बड़े पैमाने पर कीमती खनिजों का अवैध खनन हो रहा है। हरियाणा बॉर्डर से सटे जिलों से अवैध खनन कर पत्थर हरियाणा जा रहा है। वहीं पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती कुछ जिलों में जिप्सम व अन्य खनिज का अवैध खन चल रहा है। इसकी जानकारी खान विभाग को भी है लेकिन इसे रोकने में लाचार ही नजर आते हैं। अवैध खनन माफिया ही नहीं, खान संचालन भी अपने लीज क्षेत्र से बाहर कर रहे हैं लेकिन यहां भी विभाग मौन है। प्रदेश की बनास नदी बजरी का सबसे बड़ा स्त्रोत है। जहां से राज्य के कुल बजरी खनन का 80 फीसदी खनन होता है।

पढ़ें **बनास** @ पेज 10

इन जिलों में हो रहा **अवैध खनन**

- **भरतपुर:** पिंक पत्थर, लाल पत्थर, चुनाई पत्थर
- **धौलपुर-करौली:** लाल पत्थर, बजरी
- **झुंझुनूं:** चुनाई पत्थर
- **टोंक:** बजरी, चुनाई पत्थर
- **भीलवाड़ा:** क्वार्ट्स, फेल्सपार, बजरी
- **अजमेर:** क्वार्ट्स, फेल्सपार
- **राजसमंद:** क्वार्ट्स, फेल्सपार, बजरी
- **बीकानेर:** जिप्सम
- **बांसवाड़ा:** मैगनीज
- **नागौर:** लाइमस्टोन, बजरी

सतर्कता शाखा कागजों में खान विभाग की सतर्कता शाखा इन दिनों कागजों में सिमटी हुई है। विभाग में अधिकारियों की कमी के चलते सतर्कता शाखा के अधिकांश पत्र अतिरिक्त भार के रूप में चल रहे हैं। इससे अधिकारी भी अवैध खनन की रोकथाम को छोड़कर अन्य विभागीय कामों में लगे हुए हैं। ऐसे में अवैध खनन पर रोक-टोक करने वाले अधिकारी ही फील्ड में नजर नहीं आ रहे हैं।

खजाना खाली ऐसे जुटाएंगे पैसा

पत्रिका डे-स्पेशल संडे मेगा स्टोरी

60 फीसदी तक बढ़ेंगी खनिज रॉयल्टी दरें

सुनील सिंह सिसोदिया,
अरविन्द सिंह शक्तावत
patrika.com

जयपुर . कोरोना की वजह से राजस्व की कमी से जूझ रही राज्य सरकार अपनी आय के स्त्रोत बढ़ाने में जुटी है। रजिस्ट्री और शराब की बिक्री पर तमाम प्रकार के टैक्स लगाने के बाद अब प्रदेश में निकलने वाले खजिनों की रॉयल्टी दरों में भारी वृद्धि की तैयारी कर ली गई है।

बताया जा रहा है कि रॉयल्टी की दरों में 20 से 60 फीसदी तक की दर वृद्धि के प्रस्ताव तैयार कर खान निदेशालय ने राज्य सरकार को भेज दिए हैं। बढ़ी हुई दरें 26 अक्टूबर से लागू करने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के शिड्यूल द्वितीय में रॉयल्टी दरों के पार्ट-ए में शामिल 14 प्रकार के खनिज की रॉयल्टी दरें में बढ़ोतरी को लेकर प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके मुताबिक प्रत्येक खनिज के सामान्य व तैयार माल के हिसाब से अलग-अलग दरें तय की गई हैं। ऐसे में प्रत्येक मिनरल की बाजार की मांग के हिसाब से अलग-अलग रॉयल्टी तय की गई है। सभी मिनरल की बढ़ोतरी 20 से 60 फीसदी के बीच की गई है।

पढ़ें **60 फीसदी** @ पेज 10

ये होंगे महंगे (प्रतिटन दर)

मिनरल	पुरानी	नई
बजरी	40	60
मार्बल	560	615
ग्रेनाइट	280	305
सैण्ड स्टोन	240	335
लाइम स्टोन	125	165
लाइम स्टोन एण्ड लाइम	175	210
लाइम कंकर	25	30
चिप्स मेकिंग मेटेरियल	90	110
मेसोनरी स्टोन	130	155
ब्रिक अर्थ, [illegible]	25	40
फेलाइट-शीस्ट	150	195
स्लेट स्टोन	155	190
ऑर्डिनरी क्ले	20	25
उद्योगों के उपयोगी	150	180

(फेस व कटिंग के हिसाब से अलग श्रेणी हैं जिनमें अलग दरें बढ़ाई गई हैं। वृद्धि सभी मिनरल में 20 से 60% के बीच है)

सूचना

कोविड-19: मध्यप्रदेश और हरियाणा में बढे मरीज

राज्यसभा में अभूतपूर्व हंगामा : विपक्ष-काला दिन, सरकार-किसानों को मिली आजादी

माइक तोड़े, किताब फाड़ी पर बिल पास

विपक्षी दल उपसभापति के खिलाफ लाएंगे अविश्वास प्रस्ताव

पत्रिका ब्यूरो
patrika.com

नई दिल्ली. संसद से सड़क तक विपक्ष के कड़े विरोध और हंगामे के बीच राज्यसभा ने भी रविवार को दो कृषि विधेयकों को पारित कर दिया। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सरलीकरण) विधेयक-2020 तथा कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020 को ध्वनिमत से पारित किया गया।

चर्चा के दौरान इन विधेयकों पर सदन में अभूतपूर्व हंगामा भी हुआ। कई सांसद नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए थे। वहीं तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन उपसभापति के आसन के सामने पहुंच गए और विधेयक की कॉपी छीनने का प्रयास भी किया। नाराज विपक्ष ने 12 दलों ने उपसभापति हरिवंश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इधर, हरियाणा, पंजाब सहित कई राज्यों में कुछ किसान संगठन विरोध में सड़क पर उतर आए और हाइवे जाम कर दिया। कई जगह छिटपुट हिंसा की भी सूचना है।

राज्यसभा में आसन पर 'हमला'

राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण के सामने हाउस की रूल बुक फाड़ते टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन।

एक बार फिर कहता हूं, एमएसपी जारी रहेगा

पहले भी कहा है फिर कह रहा हूं। न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली बरकरार रहेगी। सरकार किसानों से फसल खरीदती रहेगी। हम यहां किसानों की सेवा के लिए हैं। उनकी भावी पीढ़ी की बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। – **नरेंद्र मोदी,** पीएम

मूल्य तय करने के लिए किसान स्वतंत्र

संसद ने कृषि सुधार से संबंधित बिल पारित कर दिया है। अपनी फसल कहां और किस मूल्य पर बेचें, यह तय करने के लिए किसान अब स्वतंत्र हैं। दशकों से किसान इसकी मांग कर रहे थे। एमएसपी जारी रहेगा।
– **निर्मला सीतारमण,** वित्तमंत्री

यह बिल किसानों की मौत का फरमान

जो किसान धरती से सोना उगाता है, मोदी सरकार का घमंड उसे खून के आंसू रुलाता है। राज्यसभा में आज जिस तरह कृषि विधेयक के रूप में सरकार ने किसानों के खिलाफ मौत का फ़रमान निकाला, उससे लोकतंत्र शर्मिंदा है।– **राहुल गांधी,** कांग्रेस

किसानों की आय दोगुनी करने का वादा निभाया नहीं। संसद में हर नियम तोड़ा गया है। राज्यसभा टीवी की फीड काट दी गई ताकि देश देख न सके। आज लोकतंत्र की हत्या हो गई है। **-डेरेक ओ'ब्रायन,** टीएमसी

साक्षात्कार

नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री

'अन्नदाताओं का हित ही केंद्र में, एमएसपी प्रणाली नहीं होगी प्रभावित'

क्या यह एमएसपी को खत्म करने की कोशिश है?
किसानों के सर्वांगीण हित में पारित दो महत्वपूर्ण विधेयकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रणाली किसी भी सूरत में खत्म नहीं होगी। इक्का-दुक्का विपक्षी साथी हैं, जो अपने राजनीतिक हित साधना चाहते हैं और इसीलिए भ्रम फैला रहे हैं। खरीफ फसलों पर एमएसपी घोषित हो चुकी है एवं फसल आने पर सरकारी खरीद चालू हो जाएगी। रबी फसलों की एमएसपी भी हफ्तेभर में घोषित कर दी जाएगी।

मूल्य निर्धारण के लिए कोई कार्यप्रणाली नहीं है। कानूनी लड़ाई की स्थिति में किसान कंपनियों का मुकाबला कैसे करेगा?
सरकार ने स्वामीनाथन समिति की दो सौ एक में से दो सौ

सिफारिशें लागू कीं। अब किसान खुद तय करेंगे कि उन्हें अपनी उपज किस दाम पर और कब बेचनी है। मूल्य करार आश्वासन विधेयक में किसान की जमीन संबंधी कोई भी बिंदु डालने की स्पष्ट मनाही है, मतलब किसान की जमीन के स्वामित्व पर कोई प्रभाव नहीं होगा। नए कानून में प्रावधान होने से किसानों को कोर्ट-कचहरी के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। ऐसा मैकेनिज्म बना रहे हैं जिससे हर दिन कहां-क्या भाव है, किसानों को तुरंत पता चलेगा।

(विस्तृत@पत्रिकायन)

राज्यसभा में जो हुआ, वह बेहद शर्मनाक: राजनाथ

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्यसभा में जो हुआ, वह बेहद शर्मनाक था। राज्यसभा उपसभापति के साथ हुए दुर्व्यवहार को पूरे देश ने देखा है। उनके आसन तक जाना, उस पर खड़े हो जाना, रूल बुक और दूसरे कागजात को फाड़ देना... ऐसी घटना संसदीय इतिहास में कभी नहीं हुई है। संसदीय लोकतंत्र में मर्यादा का बड़ा स्थान होता है। लोकतंत्र की मर्यादा शर्मसार और तार-तार हुई है। अगर विपक्ष की बात नहीं भी सुनी गई तो क्या हिंसक हो जाना चाहिए था?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय : राज्यमंत्री ने लिखित जवाब दिया

सरकार ने लोकसभा में बताया लॉकडाउन में 1 करोड़ मजदूर लौटे

23/09/20

पत्रिका ब्यूरो
patrika.com

नई दिल्ली. सरकार ने मंगलवार संसद में बताया कि मार्च से जून के दौरान एक करोड़ से अधिक प्रवासी मजदूर अपने गृह राज्यों में वापस लौटे हैं। इसमें कोविड-19 महामारी के चलते लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान यात्रा करने वाले लोग भी शामिल हैं। मंगलवार को सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री वीके सिंह ने एक सवाल के लिखित जवाब में लोकसभा को बताया कि कोविड-19 के चलते बड़ी संख्या में श्रमिक अपने काम करने की जगहों से अपने गृह-राज्यों में चले गए।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार लॉकडाउन के दौरान पैदल यात्रा करने वालों सहित 1.06 करोड़ से अधिक प्रवासी कामगार अपने गृह राज्यों में लौटे। आखिरी उपलब्ध जानकारी के अनुसार मार्च-जून के दौरान सड़कों जिसमें नेशनल हाईवे भी शामिल हैं, पर 81,385 दुर्घटनाएं हुईं, जिसमें 29,415 लोगों की जान चली गई। हालांकि, मंत्रालय ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सड़क दुर्घटना में मारे गए प्रवासी श्रमिकों के संबंध में अलग-अलग डेटा नहीं तैयार किया गया है।

राज्यों ने मुहैया कराई थी मदद

वीके सिंह ने बताया कि गृह मंत्रालय ने राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को नियमित सलाह जारी की थी कि वे प्रवासी मजदूरों को भोजन, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं और उचित परामर्श दें। मंत्री ने बताया कि मंत्रालय ने देश के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर पैदल प्रवासी मजदूरों को खाना, पानी, बुनियादी दवाइयां और फुट वियर आदि चीजें उपलब्ध कराई थीं।

ट्रेनों की आवाजाही की दी गई अनुमति

सिंह ने बताया कि मजदूरों को आराम करने के लिए विश्राम स्थलों के साथ स्थानीय परिवहन की मदद से जाने की सुविधाएं भी दी गई थीं। उन्होंने कहा कि 29 अप्रैलऔर 1 मई, 2020 को गृह मंत्रालय के आदेशों के बाद प्रवासी श्रमिकों को अपने मूल स्थानों पर बसों और श्रमिक विशेष ट्रेनों से आवाजाही की अनुमति दी गई थी।

रफाल सौदा

दसॉल्ट एविएशन, एमबीडीए ने पूरे नहीं किए ऑफसेट दायित्व :सीएजी

24-09-2020

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. लड़ाकू विमान निर्माता फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन और यूरोप की मिसाइल निर्माता कंपनी एमबीडीए ने 36 रफाल जेट की खरीद से संबंधित सौदे के हिस्से के रूप में भारत को उच्च प्रौद्योगिकी की पेशकश के अपने ऑफसेट दायित्वों को अभी तक पूरा नहीं किया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है। संसद में पेश रिपोर्ट में सीएजी ने यह भी कहा कि उसे विदेशी विरेताओं द्वारा भारतीय उद्योगों को उच्च प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने का एक भी मामला नहीं मिला है, वहीं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) पाने वाले 63 क्षेत्रों में से रक्षा क्षेत्र 62वें स्थान पर रहा है।

19 | शेरगढ़ 05 व्यवस्थाओं का जायजा लेने के केन्द्र पहुंचे और वहां सैंपलिंग जानकारी ली।

शिकायत : ये लापरवाही और चूक कहां हो रही ? 26-9-2020

नेगेटिव मरीज की मौत के छह दिन बाद फोन आया कि 'होम क्वारंटाइन' कर दो

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जोधपुर. जोधपुर में इन दिनों कोरोना इलाज को लेकर आमजन की कई शिकायतें सामने आ रही हैं। कभी एक लैब में पॉजिटिव तो दूसरी लैब नेगेटिव होना बता रही हैं, और कभी मृतक मरीज को डिस्चार्ज किया जा रहा है। आखिर ऐसी गलतियों पर अधिकारी भी मुंह नहीं खोल रहे। वहीं अब एक नया मामला सामने आया है, जिसमें परिजन आरोप लगा रहे हैं कि मृतक की मौत के छह दिन बाद थाने व नगर निगम से फोन आ रहा है कि रिश्तेदार मृतक को होम क्वॉरंटाइन कर दो। ये फोन भी परिजन सरदारपुरा पुलिस थाना और नगर निगम से आना बता रहे हैं। मृतक के भाई आनंद जोशी व जवाई अमित जोशी ने बताया कि गौरीशंकर बोड़ा (70) की गत 20 सितंबर को घर में तबीयत खराब हो गई। उन्हें डायबिटीज थी। इस दौरान उन्हें चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें एमडीएम अस्पताल भेजा गया, एमडीएम ने उन्हें एमजीएच भेज दिया। इस बीच उनकी मौत हो गई। अस्पताल ने कोविड जांच कराई, जांच से पूर्व परिजनों ने सशर्त बॉडी ली कि वे कोविड पालना के तहत उनका दाह संस्कार करेंगे। हालांकि बाद में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। वहीं परिजनों ने कहा कि इसके बाद अब सरदारपुरा थाना व नगर निगम से फोन आ रहा है कि गौरी शंकर को आप होम क्वॉरंटाइन कर दीजिए। सरकारी विभाग की इस बातों से परिजन भी अचरज में पड़े हुए हैं।
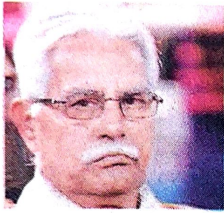
तीन बार बैठक : नहीं निकला हल, सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों को ही मिला लाभ

भटक रहे राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्जदार

25-09-2020

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. सहकारी बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों को ऋणमाफी का फायदा मिले डेढ़ वर्ष से अधिक हो गया, लेकिन अभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्जदार किसान मदद के इंतजार में हैं। इसको लेकर सरकार ने एक योजना का प्रारूप तैयार किया है। इसे लागू करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक व केन्द्र सरकार का सहयोग मांगा गया है। सरकार व बैंकों के बीच कई बैठकें हो गई, लेकिन हल नहीं निकला।

कांग्रेस ने चुनाव से पूर्व कर्ज माफ करने का वायदा किया था। सहकारी बैंकों के ऋण माफी योजना लागू हुई और वादे के मुताबिक सबके अल्पकालीन फसली ऋण माफ भी हो गए। हालांकि राष्ट्रीयकृत बैंकों के डिफाल्टर किसानों का मामला अभी लम्बित है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीयकृत बैंकों का कृषि क्षेत्र में करीब 59 सौ करोड़ रुपए एनपीए की श्रेणी में हैं। ऋण लेने वाले किसानों की जमीन बैंकों के पास गिरवी रखी हुई है। राष्ट्रीयकृत बैंक जमीन गिरवी रखने के बाद ही लोन देते हैं। कई किसान अपनी जमीन छुड़ाने में भी समर्थ नहीं हैं। सरकार ने इनमें से अल्पकलीन फसली ऋण को माफ करने की तैयारी की है। इसमें करीब 6 हजार करोड़ रुपए बकाया बताए जा रहें हैं। इसके लिए कई राज्यों की कर्जमाफी योजना का अध्ययन भी कराया है। सरकार ऐसे ही किसानों के लिए ओटीएस (वन टाइम सेटलमेंट) स्कीम लागू करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए सहकारी विभाग, वित्त विभाग, आयोजन विभाग व बैंकों की कमेटी के साथ बैठकें भी हो चुकी हैं। स्कीम पर चर्चा के लिए दो दिन पहले ही एसएलबीसी, सभी बैंक प्रशासन और सरकार की बैठक हुई थी।

50 प्रतिशत वहन करने को तैयार

सरकार पचास प्रतिशत खुद वहन करने को तैयार है तथा पचास प्रतिशत सम्बंधित बैंक को वहन करने का प्रस्ताव रखा है। अभी इस पर अन्तिम निर्णय होना बाकी है। पूर्व की बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया था। इसमें यह भी कहा है कि उन किसानों का कर्ज माफ नहीं होगा, जो पूर्व में सहकारी कर्जमाफी योजना का फायदा ले चुके हैं। अन्तिम निर्णय के लिए एसएलबीसी की बैठक जल्द होने वाली है।

कर्ज माफी पर सरकार ने कहा, अफसरों ने दी गलत जानकारी

भोपाल @ पत्रिका. प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में किसान केंद्र में हैं। पहले केंद्र सरकार के अध्यादेश और फिर किसान कर्ज माफी पर भाजपा-कांग्रेस में टकराव की स्थिति है। इस बीच बुधवार को सरकार के ही मंत्री ने किसान कर्ज माफी पर विधानसभा में सरकार के जवाब को ही गलत ठहरा दिया। इससे सियासत गरमा गई। आगामी दिनों में और हंगामा हो सकता है।

आंकड़ों के इस खेल की कराएंगे जांच

नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बुधवार को मीडिया से कहा कि किसान कर्ज माफी पर विधानसभा में गलत जानकारी दी गई है। जानकारी अधिकारियों ने दी है। जांच करके सही किया जाएगा।

कमल-दिग्विजय धोखेबाज : शिवराज

खंडवा/बुरहानपुर. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनसभाओं में कमलनाथ और दिग्विजय पर प्रहार किया। दोनों को धोखेबाज बताते हुए कर्जमाफी को फर्जीवाड़ा बताया।

खिलवाड़ न करे केंद्र: कमलनाथ

भोपाल. पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि भाजपा ने किसानों के साथ हमेशा विश्वासघात किया है। किसान लगातार उत्पादन बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको उचित दाम मिलने की व्यवस्था नहीं है। केंद्र सरकार के तीनों कानून किसानों की आजीविका का संरक्षण नहीं करते।

राज्य एम्पावर्ड कमेटी ने की अनुशंसा : अब कैबिनेट के पाले में गेंद, अडानी ग्रीन एनर्जी कंपनी 9700 मेगावॉट के पार्क करेगी विकसित

अडानी का 46 हजार करोड़ का सोलर प्रोजेक्ट, रियायत की तैयारी में सरकार

28/09/2020

यह है प्रोजेक्ट..

9,700 मेगावॉट का है प्रोजेक्ट
8,000 मेगावॉट सौर ऊर्जा के लिए
1,700 मेगावॉट का हाईब्रिड प्रोजेक्ट
46 हजार करोड़ का है प्रोजेक्ट
04 हजार के लिए रोजगार सृजन

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. अडानी ग्रुप राज्य में 9700 मेगावॉट के सोलर, हाईब्रिड और विंड एनर्जी पार्क विकसित करेगा। इसके लिए राज्य सरकार अडानी ग्रीन एनर्जी कंपनी को रियायत देने की तैयारी में है।

इसमें भूमि सुरक्षा राशि 5 लाख रुपए की बजाय 1 लाख रुपए प्रति मेगावॉट, राज्य जीएसएटी में हिस्सा राशि में से भरपाई करने से लेकर कई अन्य सुविधाएं शामिल हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य एम्पावर्ड कमेटी ने इसकी अनुशंसा की है। अब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के जरिए प्रस्ताव कैबिनेट में जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 46000 करोड़ के प्रोजेक्ट को प्रदेश में लाने के लिए सरकार कमेटी के प्रस्ताव को अशरक्षः मंजूरी दे सकती है।

कमेटी में 11 विभागों के मुखिया

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी में ऊर्जा विभाग, राजस्व, पर्यटन, माइन्स, वित्त, उद्योग, वन एवं पर्यावरण, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास, रीको, श्रम व अन्य विभागों के प्रशासनिक मुखिया शामिल हैं।

लक्ष्य मिला तो बड़े उपक्रमों पर नजर

राज्य सरकार ने अक्षय ऊर्जा के लिए अगले 4 साल में 30 हजार मेगावॉट क्षमता के सोलर प्लांट विकसित करने का लक्ष्य तय किया है। बड़े उपक्रमों के जरिए यहां निवेश पर काम तेज हुआ है।

अडानी ग्रुप सोलर का बड़ा प्रोजेक्ट लाना चाह रहे हैं। बड़ा निवेश है इसलिए एम्पावर्ड कमेटी ने कुछ छूट की अनुशंसा की है। **नरेशपाल गंगवार,** चेयरमैन, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन

शर्मनाक.... सूचना के डेढ़ घंटे बाद भी नहीं पहुंची एंबुलेंस तो 13 वर्षीय पुत्र

24-05-2020

लॉरी पर बीमार पिता को अस्पताल तक लेकर पहुंचा

यह तस्वीर बयां कर रही है चिकित्सा सेवाओं के हालात

अव्यवस्थाओं का दर्द

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

बागोड़ा (जालोर). ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, लेकिन मेडिकल सेवाओं के हालातों को भी बयां कर रही हैं। सरकारी और विभागीय दावों के विपरीत बागोड़ा उपखंड क्षेत्र पर बीमार पिता को अस्पताल पहुंचाने के लिए कॉलिंग के डेढ़ घंटे बाद भी एंबुलेंस नहीं पहुंची तो मजबूरी में बीमार की दृष्टिहीन पत्नी मंजू देवी और उसका 13 वर्षीय पुत्र दिनेश कुमार एक हाथ लॉरी पर मशक्कत के साथ उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल स्टाफ भी इन हालातों से भौचक्का सा रह गया और आनन फानन में उपचार शुरू किया, लेकिन मेडिकल सेवाओं पर सवालिया निशान है।

एंबुलेंस के नहीं पहुंचने पर परिजन लॉरी में मरीज को अस्पताल ले जाते हुए।

अस्पताल में मरीज को लॉरी में ही संभालता चिकित्सक।

बीपीएल परिवार है यहः वार्ड 11 में मनाराम जीनगर एक किराए की दुकान में अपनी पत्नी मंजू देवी के साथ रहता है। यह परिवार बीपीएल सूची में चयनित है और परिवार की स्थिति खराब है। रविवार सुबह मनाराम की तबीयत खराब होने से परिजनों ने 108 को फोन लगाकर अस्पताल ले जाने की गुहार लगाई, लेकिन डेढ़ घंटे बाद भी एंबुलेंस नहीं पहुंची तो मनाराम की पत्नी मंजू देवी व पुत्र हाथ लारी पर उसे लिटाकर करीब एक किलोमीटर दूर सरकारी अस्पताल तक उसे लेकर पहुंचे।

सीएमओ ने अटकी भर्तियों को जल्द पूरा करने का दिया फरमान, मांगी जानकारी

पवित्र दह में डूबने से युवक की मौत

राजमहल @ पत्रिका. बीसल...

मास्टर प्लान कुर्बान : भाजपा शासन में गुंजल की पत्नी के नाम की थी सरकारी जमीन

क्यों घटाई सड़क की चौड़ाई, क्यों न जमीन वापस ली जाए : हाईकोर्ट

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. भाजपा शासन में तत्कालीन विधायक प्रहलाद गुंजल के दबाव में मास्टर प्लान को कुर्बान कर सड़क की जमीन उनकी पत्नी के नाम दर्ज करने का केस अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन के भूरूपान्तरण के मामले में दायर जनहित याचिका की सुनवाई कर सरकार, भू उपयोग परिवर्तन कमेटी सहित अन्य को नोटिस भेज जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने पूछा, मास्टर प्लान के विपरीत सड़क की चौड़ाई घटाकर किया गया भूरूपान्तरण क्यों न रद्द किया जाए?

मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत माहान्ति और न्यायाधीश महेंद्र गोयल की खंडपीठ ने नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अनिल सुवालका की याचिका पर नोटिस जारी करने के आदेश दिए। याचिका में कहा है कि भाजपा सरकार के समय विधायक रहे गुंजल की पत्नी के मकान को बचाने के लिए मास्टर प्लान के विपरीत कोटा की दो प्रमुख सड़कों की चौड़ाई कम कर दी गई। पढ़ें **क्यों** @ पेज 09

कारनामा: कोटा यूआइटी की सिफारिश पर पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने किया उपकृत

गुंजल पर मास्टर प्लान 'कुर्बान', सड़क की जमीन करवा ली पत्नी के नाम

पत्रिका में प्रकाशित खबर

कोटा यूआइटी ने कराया था भू उपयोग परिवर्तन

याचिका में कहा गया कि यूआइटी ने भू उपयोग परिवर्तन के लिए आवेदन किया। इस पर एक दिसंबर 2015 को अतिरिक्त मुख्य सचिव यूडीएच की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक हुई। इसमें गैरकानूनी तरीके से इसे सहमति दी गई जबकि बैठक का कोरम ही नहीं था। ऐसे में इस फैसले को बदलते हुए सड़क की चौड़ाई पूर्ववत की जानी चाहिए।

खुलेआम भ्रष्टाचार : सच उगलते वीडियो आए सामने

08-10-2020

लोभ-प्रलोभन...लेन-देन वायरल

प्रदेश के सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार और राजकीय सुविधाओं के दुरुपयोग के दो बड़े मामले उजागर हुए हैं। दोनों मामलों (नागौर और भीलवाड़ा) से जुड़े वीडियो सामने आए हैं, जो फिर से यह कड़वा सच उगल रहे हैं कि नेताओं-मंत्रियों के दावे कोरे दिखावे हैं। प्रदेश में अवैध वसूली करने और जनता को प्रलोभन देने का सिलसिला अनवरत चल रहा है।

एसडीएम की सरकारी गाड़ी से बांटे शराब व रुपए!

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

डीडवाना . पंचायत समिति क्षेत्र में चार दिन पूर्व हुए सरपंच चुनाव के बाद अब एसडीएम की गाड़ी कार चुनाव में दुरुपयोग होने का आरोप लगा है। एक व्यक्ति ने उपखण्ड अधिकारी, पुलिस, जिला कलक्टर व निर्वाचन आयोग को शिकायत की है। मामले में सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ है। इसमें एसडीएम की गाड़ी का एक निजी गाड़ी द्वारा पीछा करते हुए वीडियो बनाने व डीडवाना पहुंचने के बाद पुलिस की गाड़ी सामने आने तक के दृश्य हैं। *वीडियो बनाने वाले गाड़ी को रुकवाने का प्रयास करते सुनाई दे रहे हैं। कुछ रास्तों पर अंधाधुंध दौड़ने के बाद गाड़ी डीडवाना के फव्वारा सर्कल पर पहुंचती है।*

पढ़ें एसडीएम @ पेज 08

चुनाव प्रक्रिया प्रभावित करने का आरोप

मुझे 6 अक्टूबर की शाम को शिकायत मिली। चालक को नोटिस देकर जबाब मांगा है। जांच कमेटी बना दी है। तथ्यात्मक रिपोर्ट बनाकर जिला कलक्टर को भेजेंगे।
अंशुल सिंह बेनीवाल, उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

भारी जुर्माने का भय दिखा हाइवे पर अवैध वसूली

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर . भीलवाड़ा . सड़क पर इंस्पेक्टर राज नहीं चलने देने के बार-बार बयानों के बाद भी प्रदेश में परिवहन विभाग के उड़नदस्तों की अवैध वसूली जारी है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भारी जुर्मानों का भय दिखाकर वाहन चालकों को परेशान किया जा रहा है। रिश्वत लेते ऐसा ही वीडियो बुधवार को सोशलमीडिया पर वायरल हुआ।

मामला भीलवाड़ा के शाहपुरा का है। वीडियो में नए मोटर व्हीकल एक्ट के जुर्माने का भय दिखा राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर खड़े ट्रकों से वसूली की जा रही थी। पढ़ें **भारी** @ पेज 08

खबर और फोटो के लिए लिंक पर क्लिक करें
https://bit.ly/2SCAPW8

परिवहन विभाग के दस्ते की करतूत

मामले में अधिकारियों और गार्डों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जनता जहां भी ऐसा घटना देखे, वीडियो बनाकर भेजें। संबंधितों पर कार्रवाई की जाएगी।
प्रताप सिंह, परिवहन मंत्री

मास्टर प्लान कुर्बान : यूडीएच सचिव, यूआइटी कोटा और जयकंवर गुंजल को दिए जाएंगे नोटिस

सुनवाई से पहले हाईकोर्ट से गायब हुई मूल फाइल

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर . भाजपा शासन में तत्कालीन विधायक प्रहलाद गुंजल के दबाव में मास्टर प्लान को कुर्बान कर सड़क की जमीन उनकी पत्नी के नाम दर्ज करने का मामला हाईकोर्ट तो पहुंचा लेकिन सुनवाई से पहले ही इस प्रकरण से जुड़ी फाइल हाईकोर्ट से गायब हो गई। अब हाईकोर्ट ने प्रशासन को फाइल पुनः तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वहीं यूडीएच सचिव, कोटा यूआइटी सचिव और पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल की पत्नी जयकंवर को नोटिस देकर पूछा कि क्यों नहीं अवैध निर्माण को हटाने का आदेश दिया जाए? हाईकोर्ट अब भू रूपांतरण करने वाली याचिका के साथ ही इस याचिका पर सुनवाई करेगा। दोनों याचिकाओं पर अब 18 नवंबर को सुनवाई होगी।

न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता और महेंद्र गोयल की खंडपीठ ने कोटा निवासी अनिल सुवालका की जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। उसी समय हाईकोर्ट से फाइल गायब होने का पता चला।

याचिकाकर्ता ने कहा कि जयकंवर ने एग्रीमेंट के जरिए एसटी वर्ग 1621 वर्गगज जमीन इकरारनामे के जरिए ली और 500 वर्ग गज जमीन गलत तरीके से सरकार से आवंटित कराई। साथ ही 388 वर्गगज

पत्रिका में प्रकाशित

मास्टर प्लान कुर्बान : भाजपा शासन में गुंजल की पत्नी के नाम की थी सरकारी जमीन

क्यों घटाई सड़क की चौड़ाई, क्यों न जमीन वापस ली जाए : हाईकोर्ट

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर . भाजपा शासन में तत्कालीन विधायक प्रहलाद गुंजल के दबाव में मास्टर प्लान को कुर्बान कर सड़क की जमीन उनकी पत्नी के नाम दर्ज करने का केस अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन के भूरूपान्तरण के मामले में दायर जनहित याचिका की सुनवाई कर सरकार, भू उपयोग परिवर्तन कमेटी

पत्रिका में प्रकाशित खबर

सड़क की चौड़ाई कम करने के साथ ही विधायक की पत्नी को आवंटन करने का राजस्थान पत्रिका ने सितंबर 2019 और जून 2020 में खुलासा किया था। इन्हीं को आधार बनाकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है।

10-10-20

जमीन पर अवैध निर्माण किया गया है।

याचिका में इस निर्माण को हटाने के साथ ही आवंटन को रद्द करने का आग्रह किया है। सरकार की ओर से दर्ज एफआइआर, यूडीएच विभाग के संयुक्त सचिव के पत्र सहित अन्य दस्तावेजों का हवाला दिया गया है। याचिका में कहा कि विधायक की पत्नी ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया। इसे हटाने के बजाय विधायक के दबाव में नियमित करते हुए आवंटित कर दिया। इस जमीन पर बने मकान को बचाने के लिए ही शहर की दो सड़कों की चौड़ाई भी कम कर दी गई।

पढ़ें **सुनवाई** @ पेज 12

नहीं की है। पिछले विधानसभा चुनाव इसके बाद से लगातार संविदाकर्मियों ऐसे में अब समिति ने वित्त विभाग के

patrika.com

रुपए लेन-देन का मामला, विधायक का ऑडियो वायरल

13-10-2020

टोडाभीम (करौली) @ पत्रिका. विधायक पृथ्वीराज मीणा का एक ठेकेदार से रुपए के लेनदेन का ऑडियो वायरल होने का मामला सामने आया है। ऑडियो में विधायक ने ठेकेदार से 20 लाख रुपए लेने की बात कह सड़क पुनर्निर्माण के लिए दबाव नहीं बनाने की बात कही है। टोडाभीम विस क्षेत्र में सड़क का पिछले दिनों निर्माण हुआ था, लेकिन सड़क बारिश से क्षतिग्रस्त हो गई। जिसकी ग्रामीण पुनर्निर्माण की मांग कर रहे थे। एक संगठन के पदाधिकारी ने विधायक मीणा से मोबाइल पर बात कर सड़क पुनर्निर्माण के आदेश देने का आग्रह किया। जिस पर विधायक ने कहा कि उन्होंने ठेकेदार से 20 लाख लिए हैं इसलिए ठेकेदार पर सड़क के दुबारा निर्माण के लिए दबाव नहीं बना सकते। वार्ता का ऑडियो वायरल हो रहा है। वहीं विधायक का कहना है कि ऑडियो काट छांट कर वायरल किया गया है। वह मेरे ऊपर कमेंट्स कर रहा था और मुझे गुस्सा दिलाकर मुझसे जबरदस्ती पैसे लेने की बात स्वीकार कराना चाहता था।

इधर, स्थानान्तरण के नाम पर मांगे पैसे

दौसा. राजकीय कर्मचारी के तबादले के नाम पर पैसे मांगने व ऑडियो वायरल होने पर दौसा विधायक के मीडिया प्रभारी ने स थाने में मामला दर्ज कराया है।

जेल में मिले आठ मोबाइल, 6 सिम

पुलिस लवाजमे ने ली जेल की सघन तलाशी, बीड़ी के नौ पैकेट, 5 हीटर, 6 हीटर स्प्रिंग व चाकू भी बरामद

जोधपुर. जोधपुर सेन्ट्रल जेल में बंदियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने एक बार फिर मंगलवार को सघन तलाशी लेकर आठ मोबाइल, छह सिम, नौ चार्जर, 11 ईयर फोन के साथ एक चाकू जब्त किया। इनमें से एक मोबाइल कैदी के पास और शेष सामग्री लावारिस मिली। उधर, लॉरेंस बिश्नोई के भाई व एक गुर्गे को मोबाइल बरामदगी के मामले में गिरफ्तार किया गया।

पुलिस उपायुक्त (पूर्व) धर्मेन्द्रसिंह यादव ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (पूर्व) भागचंद के नेतृत्व में एसीपी नूर मोहम्मद, नीरज शर्मा व लाबूराम के साथ नौ थानाधिकारी ने थानों के स्टाफ के साथ दोपहर में जेल की तलाशी शुरू की। बंदी व कैदियों के प्रत्येक बैरिक और वार्ड को खंगाला। बनाड़ निवासी कैदी असलम से एक मोबाइल जब्त किया गया। जबकि अन्य बैरिकों में लावारिस हालत में छिपाकर रखे सात अन्य मोबाइल, छह सिम, 11 ईयर फोन, 5 हीटर व हीटर की 6 स्प्रिंग, 1 ब्ल्यूटूथ, एक बैटरी, बीड़ी के नौ बण्डल, एक पेचकस व एक चाकू जब्त किया गया।

जेल अधीक्षक की शिकायत पर असलम व अज्ञात बंदियों के खिलाफ रातानाडा थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने पिछले पन्द्रह दिन में जेल की तीसरी मर्तबा तलाशी लेकर मोबाइल व अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की है।

जोधपुर सैंट्रल जेल। फाइल फोटो

लॉरेंस का भाई व गुर्गा गिरफ्तार

रातानाडा थानाधिकारी रमेश शर्मा के अनुसार गत 21 सितम्बर को जेल की तलाशी के दौरान मोबाइल बरामदगी के मामले में पंजाब के कुख्यात बदमाश लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल व गुर्गे हरीश प्रजापत को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया।

खबर को विस्तार से पढ़ें
https://bit.ly/3iVqxLh

पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर : वर्ष 2019 में 333 नकबजनी और चालान सिर्फ 7

उत्तरप्रदेश : मौके पर मौजूद सभी अफसर सस्पेंड

भाजपा नेता ने एसडीएम और पुलिस के सामने किया मर्डर

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com 16-10-20

बलिया. उत्तरप्रदेश के बलिया जिले में गुरुवार को भाजपा नेता ने दिनदहाडे एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। विवाद में कई लोग घायल हो गए। ग्राम सभा दुर्जनपुर व हनुमानगंज की कोटे की दो दुकानों के आवंटन के लिए पंचायत भवन पर बैठक बुलाई गई थी। इस दौरान एसडीएम बैरिया सुरेश पाल, सीओ बैरिया चंद्रकेश सिंह, बीडीओ बैरिया गजेन्द्र प्रताप सिंह के साथ ही रेवती थाने की पुलिस भी मौजूद थी। दुर्जनपुर की दुकान के लिए सहमति नहीं बन पाने पर दो पक्ष भिड़ गए। इनके बीच चली लाठी भाटा जंग में लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। स्थानीय भाजपा नेता धीरेंद्र सिंह ने गोलीबारी की जिसमें दुर्जनपुर निवासी जयप्रकाश पाल की गोली लगने से मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसडीएम, सीओ और वहां मौजूद सभी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया।

भरतपुर : आपसी झगड़े के बाद बदमाशों की हिमाकत

सरेराह अंधाधुंध फायरिंग, सात राहगीर घायल

16·10·2020
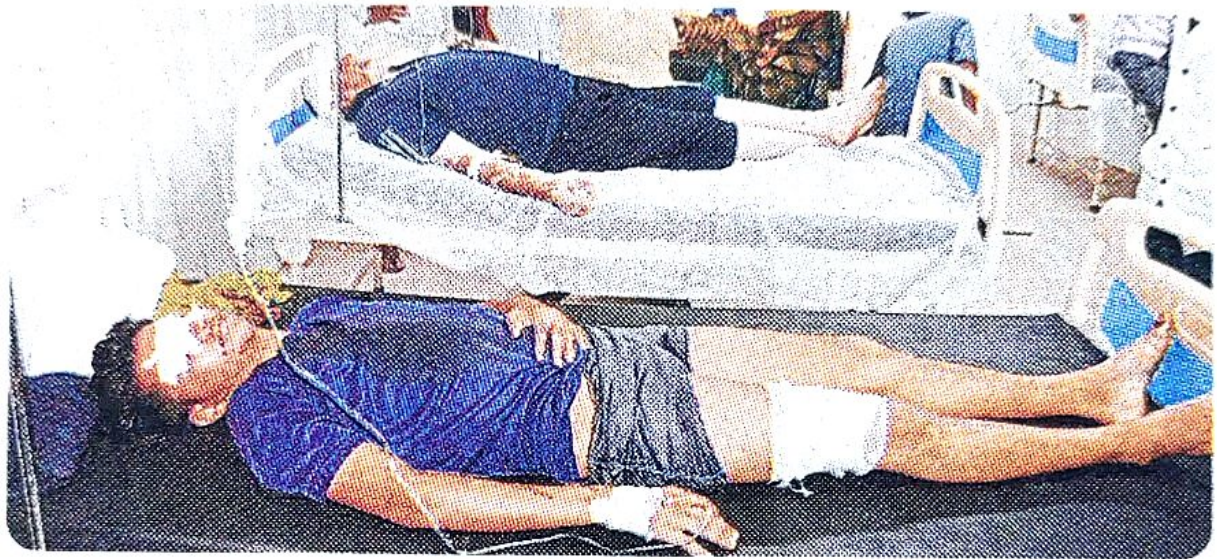
आरबीएम अस्पताल में भर्ती फायरिंग में घायल राहगीर।

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

भरतपुर. शहर में गुरुवार देर शाम कुछ बदमाशों ने सरेराह अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इससे 7 से अधिक राहगीर व लोग घायल हो गए। इनमें मंदिर दर्शन करने जा रहे बुजुर्ग, खेलने जा रहे बच्चे भी शामिल हैं।

पुलिस के अनुसार 12 अक्टूबर को श्यामनगर कॉलोनी टैंट हाउस की दुकान चलाने वाले अरुण का कुछ युवकों से विवाद हो गया था। पुलिस ने मामला शांत करा दिया था। राजीनामा नहीं हुआ तो दूसरे पक्ष के 12 से अधिक लोग हथियारों के साथ आए और सिमको कॉलोनी के फाटक नंबर 39 के पास राहगीरों पर फिल्मी स्टाइल में अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे। घायलों को आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। शहर में पिछले 10 दिन में फायरिंग की यह तीसरी वारदात है। पीड़ित पक्ष ने ने पुलिस पर आरोपी पक्ष की मदद करने का आरोप लगाया।

घायलों का झगड़े से सरोकार ही नहीं : फायरिंग में घायल हुए लोगों में से एक भी व्यक्ति का उक्त झगड़े से कोई लेना-देना नहीं है।

भ्रष्टाचार: रिश्वत में लिए 1.26 लाख बरामद

18-10-2020

घूस लेते संविदाकर्मी, एईएन और एक्सईएन गिरफ्तार

पहले ले चुके थे 68 हजार रुपए

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

patrika.com

जयपुर . भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में संविदा पर तैनात सहायक अभियंता जीएस चाहर को शनिवार को 1.26 लाख रुपए रिश्वत लेते झोटवाड़ा स्थित उसके निवास पर रंगे हाथ गिरफ्तार किया। रिश्वत की राशि मिलते ही उसने एईएन अशोक कुमार वर्मा को कॉल कर कहा कि रुपए मिल गए। वर्मा ने यह सुनते ही कह दिया कि आए तब रुपए लेते आना। इस पर ब्यूरो की टीम ने वर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया।

जी एस चाहर अशोक वर्मा

एसीबी के सत्यापन में सामने आया कि आरोपी 68 हजार रुपए पहले ले चुके थे। एसीबी डीजी बीएल सोनी ने बताया कि पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन आरएसी की सातवीं बटालियन के भरतपुर पहाड़ी में 35 क्वार्टर का निर्माण करवा रहा है।

पीडब्ल्यूडी अधिकारी निर्माण पर निगरानी रखे हुए थे। पीड़ित ठेकेदार ने शिकायत में बताया कि आरोपी बिल का भुगतान करने के लिए रिश्वत मांग रहे थे। तब एसीबी ने आरोपियों की घेराबंदी की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंचल मिश्रा ने ट्रेप की कार्रवाई की।

बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी

जयपुर . बीकानेर . राजकीय डूंगर कॉलेज की ओर से हुई प्रदेश स्तरीय द्विवर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम शनिवार को घोषित हुआ। विज्ञान में बाड़मेर के ओमप्रकाश बेनीवाल प्रथम, स.माधोपुर के हेमंत गोयल द्वितीय, कला में बाड़मेर के गजेंद्र सिंह भादू प्रथम, जयपुर के विवेक मोटवानी द्वितीय, वाणिज्य में बूंदी के हेमन्त पालीवाल प्रथम, जयपुर के युवराज चौधरी द्वितीय रहे।

मरीज की मौत, परिजन-चिकित्सक में हाथापाई

बीकानेर @ पत्रिका . पीबीएम अस्पताल में शनिवार को मरीज की मौत के बाद परिजन और रेजिडेंट डॉक्टर में मारपीट हो गई। रेजिडेंट ने काम छोड़कर अधीक्षक के समक्ष विरोध जताया, प्रदर्शन किया। मामला दर्ज कराने पर सहमति के बाद रेजिडेंट काम पर लौटे। जानकारी के अनुसार गंगाशहर रोड क्षेत्र निवासी पुष्पादेवी को गुरुवार को पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोरोना जांच नेगेटिव आने पर शनिवार सुबह जे वार्ड में शिफ्ट किया गया। दोपहर में मौत हो गई। परिजन ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया जबकि चिकित्सकों का आरोप है कि मरीज की मौत के बाद परिजन ने रेजिडेंट को थप्पड़ जड़ दिया। अधीक्षक डॉ. मोहम्मद सलीम का कहना है कि लापरवाही नहीं हुई, मरीज की हालत गंभीर थी। मारपीट का मामला दर्ज कराया जाएगा।

लोगों का उत्साह बरकरार है। एक दुकान पर खरीदारी करती युवतियां। फोटो : नौशाद अली को सजाने लगे हैं।

खुलासा : दो साथियों सहित गिरफ्तार, वारदात में प्रयुक्त पिस्तौल बरामद

जेल में बंद बलवाराम ने भाई से कराई थी चोटिया की हत्या

फरारी में मददगार रहे दो आरोपित भी पकड़े

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

मदनगंज-किशनगढ़ (अजमेर). बहुचर्चित भंवर सिनोदिया हत्याकांड के चश्मदीद गवाह भागचंद चोटिया की हत्या धौलपुर जेल में सजा काट रहे बलवाराम की शह पर उसके मौसेरे भाई हीरालाल ने की थी। हीरालाल सिनोदिया हत्याकांड में न्यायालय से बरी हो चुका है। पुलिस ने चोटिया की हत्या के आरोपी हीरालाल को उसकी फरारी में मददगार रहे रामदयाल जाट व देवाराम जाट के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने मंगलवार को इसका खुलासा किया। वारदात में नामजद फरार आरोपी हनुमान जाट समेत एक अन्य आरोपी की पुलिस को तलाश है। पुलिस धौलपुर जेल से बलवाराम को भी प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करेगी।

चोटिया की 18 अक्टूबर को शाम चार बजे किशनगढ़ के मुख्य बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मंगलवार को मुखबिर से हत्याकांड में शामिल व्यक्ति के रूपगनढ़ के पास होटल वीर तेजा में ठहरे होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने आरोपी बांदरसिंदरी थाना क्षेत्र के नयागांव निवासी हीरालाल को गिरफ्तार किया। आरोपी हीरालाल भागचंद चोटिया हत्याकांड के मुख्य आरोपी बलवाराम जाट का रिश्तेदार (मौसी का लड़का) है। पुलिस ने हीरालाल की फरारी में मददगार मंडोती निवासी रामदयाल जाट, रूपनगढ़ भदूण बरड़ा की ढाणी निवासी देवाराम जाट को भी गिरफ्तार किया।

किशनगढ़ . चोटिया हत्याकांड में पुलिस की गिरफ्त में आरोपी।

बलवाराम ने भेजा तीसरा सहयोगी

पूछताछ में हीरालाल ने बताया कि रामनेर की ढाणी निवासी हनुमान सपेड़िया व एक अन्य के साथ मिलकर चोटिया की हत्या की। तीसरे सहयोगी को धौलपुर में आजीवन कारावास की सजा काट रहे मुख्य षड्यंत्रकारी बलवाराम ने भेजा था।

दो पिस्तौल

चोटिया पर अंधाधुंध दागी गई गोलियां एक नहीं बल्कि दो जनों ने दो अलग-अलग पिस्तौल से चलाई थीं। इसमें एक पिस्तौल से हीरालाल जाट ने भागचंद चोटिया पर गोलियां चलाई थीं। यह बात पूछताछ में मुख्य आरोपित हीरालाल ने कबूल कर ली है। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त एक पिस्तौल बरामद कर ली है, जबकि दूसरी पिस्तौल से हनुमान जाट या फिर तीसरे शख्स ने गोलियां चलाई यह इनकी गिरफ्तारी के बाद ही पता चल सकेगा। आरोपी मुख्य बाजार

एक नहीं दो जनों ने चलाई थी गोलियां

मृतक भागचंद चोटिया

स्थित प्राचीन बालाजी मंदिर के पास 18 अक्टूबर को दिनदहाड़े लोगों की भीड़ के बीच मोटरसाइकिल पर तीन जने सवार होकर आए थे। इनमें से एक हीरालाल जाट खुद था और दूसरा हनुमान जाट। हनुमान का नाम हीरालाल ने पुलिस को बताया है, जबकि तीसरे व्यक्ति को भी पुलिस ने चिन्हित कर लिया है। फिलहाल उसके नाम का खुलासा नहीं किया गया है।

एटीएम क्लोनिंग : 23 शहरों में की वारदात

ठगी करने हवाई जहाज से जाते थे मामा-भांजा

सम्मान समारोह की तिथि 19 नवंबर प्रस्तावित

33 छात्राओं को इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार

इन्हें मिलेगा सम्मान

22-10-2020

1 सिनोदिया हत्या मामले में गवाह को सुरक्षा देने के दिए आदेश

जयपुर @ पत्रिका. हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक नाथूराम सिनोदिया के बेटे भंवर सिनोदिया के अपहरण और हत्या के मामले में गवाह जोराराम चौधरी की सुरक्षा के लिए सरकार को उचित कदम उठाने के आदेश दिए हैं। मामले में गवाह जोराराम ने सुरक्षा के लिए दायर याचिका में कहा कि घटना से जुडे एक अन्य चश्मदीद गवाह भागचंद चोटिया की गत दिनों हमलावारों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। इसी से उसकी जान के खतरे को समझा जा सकता है। उधर पुलिस ने मुख्य आरोपित हीरालाल जाट एवं इसके दो साथियों को कोर्ट ने तीन दिन के रिमांड पर सौंपे जाने के आदेश दिए।

2 सूचना दो, 51 हजार का इनाम

जयपुर @ पत्रिका. प्रदेश में 26 अक्टूबर से प्रस्तावित शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का खाका तैयार हो गया है। सरकार ने तय किया है कि मिलावट की सही सूचना देने वाले को 51 हजार का इनाम दिया जाएगा। अभियान में दूध, मावा, पनीर, सूखे मेवे, मसालों आदि की जांच की जाएगी।

3 घूसखोर दो दिन के रिमांड पर

कोटा @ पत्रिका. एसीबी ने एक लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में दिल्ली के यूआइडीएआई के सहायक निदेशक पंकज गोयल को गिरफ्तार करने के बाद बुधवार शाम को एसीबी विशिष्ट न्यायालय के आवास पर पेश किया, जहां से उसे दो दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया।

बेलगाम बजरी खनन माफिया

प्रतिदिन हो रहा सैंकड़ों डम्पर अवैध बजरी का परिवहन

विभाग की कार्रवाई बेअसर

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जोधपुर. सुप्रीम कोर्ट की ओर से बजरी खनन पर रोक के बाद खान एवं भू विज्ञान विभाग के लिए बजरी खनन सिरदर्द साबित हो रहा है। परिणामस्वरूप जिले में बजरी खनन माफिया हावी है। वर्तमान में प्रतिदिन करीब 100 से ज्यादा डम्पर अवैध बजरी का परिवहन हो रहा है। विभाग की ओर से बजरी खनन माफियाओं पर अंकुश लगाने में पसीना आ रहा है, प्रभावी कार्रवाई के अभाव में खनन माफिया खुलेआम बजरी खनन कर रहे हैं।

माफिया द्वारा एक ही रवन्ना में 4-4 ट्रिप बजरी परिवहन की जा रही है। बजरी खनन माफिया रात में धड़ल्ले से बजरी खनन कर शहरों में सप्लाई कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार जोधपुर में चल रहे कुछ सरकारी निर्माण कार्यों में माफियाओं द्वारा ही बजरी सप्लाई की जाती है।

समय-समय पर करते हैं कार्रवाई

सीमित संसाधनों के बावजूद समय-समय पर अभियान चलाकर अवैध बजरी खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं।

श्रीकृष्ण शर्मा, माइनिंग इंजीनियर जोधपुर

कार्रवाई ऊंट के मुंह में जीरे के समान

विभाग की ओर से संसाधनों के अभाव के बावजूद कार्रवाई तो की जाती है, लेकिन वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। कार्रवाई से पहले ही उन्हें खबर मिल जाती है। इससे वह सतर्क हो जाते हैं और प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाती है।

यहां हो रहा खनन

जोधपुर में लूणी नदी, कापरड़ा, सतलाना, पिचियाक, खेजड़ली, कांकाणी, सतलाना, शिकारपुरा, लाकड़धिन, भोपालगढ़, लूणावास, बावड़ी, पीपाड़, डांगियावास, जटियावास, बेंगन सोड़ा आदि क्षेत्रों में बजरी का अवैध खनन व सप्लाई हो रही है।

'आवाज' अभियान के तहत 'अपनी बात' का आयोजन

दो थानों के बीच तालमेल के अभाव का नतीजा 27-10-2020

शर्मनाक... 19 दिन मुर्दाघर में रखा रहा शव

जयपुर @ पत्रिका. आमजन में विश्वास के पुलिस के दावे का सच देखिए, आदर्श नगर व तूंगा थाने के बीच तालमेल नहीं होने से एक युवक का शव 19 दिन तक मुर्दाघर में लावारिस रखा रहा।

मृतक रविकांत

हुआ यों कि आदर्शनगर स्थित सूत्रखाना कॉलोनी के 35 वर्षीय रविकांत 7 अक्टूबर को घर से स्कूटी लेकर निकले थे। उसी दिन तूंगा थाना क्षेत्र के डूबली गांव में वाहन की टक्कर से गंभीर घायल रविकांत को 108 एम्बुलेंस ने एसएमएस अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची तूंगा पुलिस स्कूटी को थाने ले गई। अस्पताल से तूंगा पुलिस को युवक की मौत होने की सूचना दी गई लेकिन तूंगा पुलिस ने युवक की पहचान के प्रयास नहीं किए और ना ही स्कूटी के संबंध में अन्य थाना पुलिस को सूचना दी। रविकांत घर नहीं लौटे तो परिजनों ने 8 अक्टूबर को आदर्शनगर थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई। आदर्श नगर थाना पुलिस रविवार रात को परिजनों के साथ मुर्दाघर पहुंची और वहां शव देखकर रविकांत की पहचान की। पुलिस की लापरवाही पर परिजनों ने आक्रोश जताया।

https://bit.ly/37Pqsqw

चेक और फिर कैश से रिश्वत का पहला मामला

29-10-2020

रिश्वत में 50 हजार का चेक लेने पर महिला एलडीसी व मध्यस्थ गिरफ्तार

1.50 लाख रुपए धरोहर राशि का डीडी देने के बदले लिया था चेक

डीडी जमा होने पर चेक से 50 हजार रुपए निकाल एलडीसी को देने वाला था मध्यस्थ

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जोधपुर/बालेसर. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कार्य के बदले जमा 1.50 लाख रुपए धरोहर राशि लौटाने की एवज में पचास हजार रुपए का चेक लेने पर पंचायत समिति बालेसर की कनिष्ठ लिपिक और मध्यस्थ को बुधवार शाम गिरफ्तार किया। धरोहर राशि का डीडी बैंक में जमा होने के बाद मध्यस्थ को चेक से पचास हजार रुपए निकालकर एलडीसी को देने थे, लेकिन चेक लेते ही ब्यूरो ने पहले मध्यस्थ और फिर कनिष्ठ लिपिक को पकड़ लिया। ब्यूरो के उप महानिरीक्षक डॉ विष्णुकांत ने बताया कि जैसलमेर में सांकड़ा की फर्म संचालक की शिकायत पर पंचायत समिति बालेसर की कनिष्ठ लिपिक आगोलाई निवासी रानी कुमारी (30) पत्नी खरताराम जाट व बालेसर सुरेश माली को रिश्वत का चेक लेते गिरफ्तार किया गया है। परिवादी ने बालेसर कस्बे के बैंक में मध्यस्थ सुरेश को 50 हजार का चेक दिया था। वह सेल्फ चेक पर अपना नाम लिखकर बैंक से रुपए निकालकर एलडीसी को देने वाला था, लेकिन उससे पहले ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भोपालसिंह लखावत व टीम ने उसे पकड़ लिया। ब्यूरो ने मोबाइल पर उसकी बात एलडीसी से करवाकर रिश्वत लेने की पुष्टि कराई। फिर पंचायत समिति बालेसर से एलडीसी रानी कुमारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। रिश्वत के बदले चेक लेने का यह संभवतः पहला मामला है।

चेक इसलिए लिया ताकि रंगे हाथों पकड़ी न जा सके

ब्यूरो की ग्रामीण चौकी के एएसपी भोपालसिंह ने बताया कि परिवादी की फर्म ने वर्ष 2016-17 में ग्राम पंचायत बालेसर में निविदा कार्य के तहत गिट्टी व अन्य सामग्री सप्लाई की थी। 1.50 लाख रुपए धरोहर राशि जमा कराई गई थी। पंचायत समिति बालेसर की कनिष्ठ लिपिक रानी कुमारी जाट तत्कालीन ग्राम सेवक थी। वर्तमान में वह कनिष्ठ लिपिक है। धरोहर राशि प्राप्त करने के लिए फर्म संचालक ने कनिष्ठ लिपिक रानी कुमार से सम्पर्क किया। धरोहर राशि का डीडी लौटाने के बदले उसने पचास हजार रुपए मांगे। फर्म संचालक ने एसीबी से शिकायत की। गोपनीय सत्यापन कराया गया। एलडीसी ने रिश्वत के बदले नगद की जगह चेक मांगा। वो भी मध्यस्थ सुरेश को देना था। मध्यस्थ ही सेल्फ चेक से रुपए निकाल एलडीसी को देता। ताकि सीधे रुपए लेने पर वह रंगे हाथों पकड़ी न जा सके।

40 हजार लेने से इनकार, 50 हजार का दूसरा चेक बनाया

फर्म संचालक के रिश्वत देने को तैयार होने पर एलडीसी ने धरोहर राशि का डीडी मध्यस्थ सुरेश को दिया। जो उसने बैंक जाकर परिवादी के खाते में जमा कराया। जबकि नियमों के तहत डीडी फर्म संचालक को देना होता है। डीडी जमा कराते ही परिवादी ने कैमिकल लगा 40 हजार रुपए का सेल्फ चेक मध्यस्थ सुरेश को दिया। उसने एलडीसी से बात की। कनिष्ठ लिपिक ने 40 की जगह 50 हजार का चेक लेने का निर्देश दिया। तब परिवादी कार से दूसरा ब्लैंक चेक लाया। उसमें 50 हजार रुपए लि[खकर] मध्यस्थ को दिया। उस चेक पर पहले से कैमिकल लगा था। चेक लेते ही एसीबी ने बैंक में रेड दे[कर] मध्यस्थ सुरेश माली को पकड़ लिया।

स्कूल में कम्प्यूटर व प्रिंटर भेंट

'नो मास्क-नो वोट' की मुहिम

एक ही दिन में 70 हजार से अधिक मास्क वितरित

जोधपुर @ पत्रिका. कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन, नगर निगम की ओर से चलाया गए 'नो मास्क-नो वोट' की मुहिम का बड़ा असर नजर आया और नगर निगम ने एक ही दिन में रिकॉर्ड 70,000 से अधिक मास्क वितरित किए। नगर निगम आयुक्त रोहिताश्व तोमर ने बताया कि गुरुवार को मतदान करने आने वाले मतदाताओं की स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए इस बार जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर निगम में विशेष इंतजाम किए। प्रत्येक मतदान केंद्र में प्रवेश से पहले हाथों को सेनेटाइज करने और मास्क नहीं होने पर मास्क उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम में 2 कर्मचारी तैनात किए। तोमर ने बताया कि मतदान केंद्रों पर एक ही दिन में 70,000 से अधिक मास्क वितरित किए गए, जो अब तक एक ही दिन में सर्वाधिक मास्क वितरण का रिकॉर्ड है। आदर्श बूथ पर मास्क बैंक बनाया गया, साथ ही कार्टून करैक्टर के माध्यम से मतदाताओं को मास्क वितरित किए गए। वहीं गुरुवार को भी नगर निगम अधिकारियों ने श्रमिक मंडियों में श्रमिकों को निःशुल्क मास्क उपलब्ध कराए। 30-10-2020

ब्यूटी पेजेंट ऑडिशन 1 को

आने लगा है। गंदे पानी की बदबू से आमजन को समस्या हो रही है।

प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की और योजनाओं की जानकारी दी।

नैफेड ने खरीद केंद्रों को किया ब्लैक लिस्ट

मूंग-मूंगफली खरीद में करोड़ों के घोटाले के आरोपी बहाल

31-10-2020

जोधपुर@पत्रिका. राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर मूंग व मूंगफली की खरीद में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी करने के मामले में निलंबित तीनों कार्मिकों को बहाल कर दिया है। जोधपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति के निलंबित तत्कालीन व्यवस्थापक प्रेम सिंह चौधरी, जैतारण क्रय विक्रय सहकारी समिति के तत्कालीन व्यवस्थान पाबूराम चौधरी और फलोदी क्रय विक्रय सहकारी समिति के तत्कालीन व्यवस्थापक मुरली व्यास को बहाल किया गया है। जोधपुर समिति में वर्ष 2019-20 में मूंग खरीद में करीब 1300 क्विंटल और जैतारण में 700 क्विंटल से अधिक मूंग कम मिला था, उधर फलोदी समिति में करीब 2.75 करोड़ रुपए की मूंगफली कम मिली थी।

चारों खरीद केंद्रों पर रोक

राज्य सरकार के उलट केंद्र सरकार की खरीद एजेंसी नैफेड ने सरकारी माल को खुर्द-बुर्द करने और किसानों से माल खरीदकर वेयर हाउस में कम जमा कराने पर जोधपुर, फलोदी, बाप और जैतारण क्रय विक्रय सहकारी समिति पर पाबंदी लगा दी है। इनके अलावा नैफेड ने चूरू, सरदारशहर, सुजानगढ़, दंतौर, बीकानेर कोलायत, बीकानेर फल सब्जी समिति, बज्जू और श्रीडूंगरगढ़ समिति पर पाबंदी लगाई है।

विरोध

भारत स

सौंप
ऑ

मसा
रासा
प्रयो
लिए

अविन
patrika

जोधपु
संयुक्त
कहा ज
प्रतिशत
दो प्रदे
राजस्थ
जीरा,
फसलों
ऑर्गेनि
इसकी
वाणिज्य
स्पाइस

अलवर में उपाध्यक्ष, भाजपा ने हटाया

पुराने नोटों का जखीरा पकड़ा, भाजपा पदाधिकारी गिरफ्तार

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

05-11-20

भिवाड़ी . उत्तराखंड पुलिस ने 1000 की बंद भारतीय मुद्रा के जखीरे के साथ अलवर भाजपा जिला उपाध्यक्ष शशि यादव समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सूचना के बाद भाजपा ने यादव को पद से हटा दिया है।

पुलिस ने उत्तराखंड के रुद्रपुर खटीमा में 2 कारों की तलाशी ली तो सूटकेस में 1000 के नोटों की 32 गड्डियां मिलीं। अन्य 37 बंडल में प्रथम व आखरी 1000 का नोट नकली था, बीच में सफेद कागज लगाए हुए थे। इन नोटों को भारत सरकार ने 2016 में अवैध घोषित कर उन्हें रखना अपराध घोषित किया था। खटीमा कोतवाल संजय पाठक ने बताया कि कारों में सवार बरेली के प्रफुल्ल प्रधान व मुकेश, ततारपुर शीथल खुशखेड़ा अलवर के शशि यादव, हरियाणा के धर्मवीर, गाजियाबाद के दीपक कुमार को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दोनों कारों को भी जब्त कर लिया है।

पढ़ें **पुराने** @ पेज 11

ऐसे करते थे ठगी

पुलिस को आरोपियों ने बताया कि नोटों को वर्तमान मुद्रा से बदलने के लिए खटीमा, टनकपुर, बनबसा आते थे। नेपाल में भारतीय विमुद्रीकरण मुद्रा चलती है एवं लोगों को यह पैसे दिखाकर बदलने के नाम पर वर्तमान मुद्रा लेकर फरार हो जाते थे।

bit.ly/364GGtC सूचना दी।
ग्रामीण व परिजनों ने मृ

30 लाख के गबन के आरोप में 12 आशा सहयोगनियां गिरफ्तार

05.11.20

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

कुंभलगढ़. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केलवाड़ा में संचालित जननी सुरक्षा योजना के तहत रिकॉर्ड में हेराफेरी कर लाभान्वितों को भुगतान में लगभग 30 लाख रुपए की अनियमितता एवं फर्जी भुगतान के अरोप में पुलिस ने मंगलवार को 12 आशा सहयोगीनियों को गिरफ्तार कर लिया। सभी को कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया।

पुलिस ने बताया कि तत्कालीन खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी केलवाड़ा परसराम खींची ने 26 फरवरी 2010 को थाना केलवाड़ा पर डॉ. सुधीर शर्मा सहित 15 आशा सहयोगनियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी।

रिकॉर्ड में जबरन दिखाया प्रसव

पुलिस ने बताया कि प्रसव नहीं होने पर भी रिकॉर्ड में प्रसव दिखाकर राजकोष से राशि का गबन किया गया। जांच में पाया कि 53 प्रकरणों में प्रसव नहीं होने के बाद भी फर्जी रिकॉर्ड तैयार कर 89 हजार रुपए राजकोष से आहरित कर गबन किया गया। इसके लिए तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी व आशा सहयोगिनी उत्तरदायी हैं।

गुर्गों के जरिए वारदातों को अंजाम 8.11.2020

जेल में बंद कुख्यात बदमाश वसूली से बन गए करोड़पति!

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

मेरठ. विदेश में बैठकर दाउद जैसे डॉन अपने गुर्गों के जरिये भारत के लोगों से फिरौती वसूलने का काम करते हैं। ठीक उसी तरह वेस्ट यूपी 17 कुख्यात बदमाश जेल में बंद होने के बावजूद करोड़पति बन गए हैं। जेल में रहते हुए भी ये बदमाश अपने गुर्गों के जरिये हत्या, लूट, अपहरण, डकैती और फिरौती जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने करोड़ों की संपत्ति भी बना ली है।

इसका खुलासा अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई से हुआ है। बता दें कि सुनील राठी, सुशील मूंछ, सुंदर भाटी, अनिल दुजाना, रणदीप भाटी, सिंहराज भाटी, संजीव जीवा, धर्मेंद्र, योगेश भदौड़ा, मुकीम काला, उधमसिंह, भूपेंद्र बाफर, भूपेंद्र बाफर, सारिक, फाईक, मीनू और उमेश पंडित ये 17 बदमाश जेल बंद हैं।

इनकी सक्रियता का पता इसी से चलता है कि इनमें से कई बदमाश ऐसे हैं, जो पिछले दस साल से जेल में बंद हैं और करोड़पति बन चुके हैं। सरकार ने इन सभी बदमाशों की सूची तलब करते हुए अपराध के जरिये अर्जित की गई अवैध संपत्तियों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की, लेकिन अब कार्रवाई का अभियान वेस्ट यूपी में सुस्त नजर आ रहा है।

अंसारी के गुर्गों के नाम गायब करने का आरोप

लखनऊ. डॉन मुख्तार अंसारी के मामले में नया खुलासा हुआ है। मुख्तार अंसारी के सात गुर्गों के नाम पुलिस द्वारा ही गायब करने का आरोप है। ये सात गुर्गे लखनऊ के कई इलाकों में हैं। विवादित जमीन पर कब्जा, रंगदारी लेना, दंबगई दिखाने वालों पर पुलिस मेहरबानी दिखा रही है। आरोप है कि लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में जिस फ्लैट पर पुलिस ने छापा मारा था, वहां मुख्तार का करीबी बाबू सिंह मिला था। इसी के पास बुलेट प्रूफ गाड़ी की चाभी मिली थी। गाड़ी को पुलिस ने कब्जे में ले लिया था।

कांग्रेस विधायक रहीम ने तृणमूल का दामन थामा

कोलकाता. पश्चिम बंगाल के बदुरिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक अपने समर्थकों के साथ शनिवार को सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। विधायक काजी अब्दुर रहीम ने तृणमूल कांग्रेस के मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान वरिष्ठ मंत्री फिरहाद हकीम और पार्थ चटर्जी मौजूद थे। रहीम ने इस मौके पर कहा कि मैने यह महसूस कि भाजपा के खिलाफ संघर्ष में दीदी (ममता बनर्जी) ही उम्मीद की एकमात्र किरण है।

कानपुर के पूर्व... अनंतदेव पर ...

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

कानपुर. चौबेपुर के चर्चित बिकरू कांड

ों के अनुसार और प्रति कार्ड एक ऑफर उपलब्ध है, बिना किसी पूर्व सूचना के ...

सुप्रीम कोर्ट: अर्णब को अंतरिम जमानत, महाराष्ट्र सरकार को फटकार

'सरकार तानों को अनदेखा करे, आजादी पर अंकुश न लगाए'

12.11.20

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के एडीटर-इन-चीफ अर्णब गोस्वामी को 7 दिन बाद बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से कहा कि आदेश पर तत्काल अमल किया जाए। अर्नब की याचिका पर सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार तानों को अनदेखा करे, इस तरह किसी की व्यक्तिगत आजादी पर पाबंदी न लगाए।

पढ़ें **सरकार** @ पेज 17

इस शर्त पर मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अर्णब गोस्वामी और दो अन्य आरोपी सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले की जांच के दौरान पूरा सहयोग करेंगे।

रिहाई के बाद जोशीले अंदाज में जेल से बाहर निकले अर्णब।

यह है मामला

2018 में इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक व उनकी मां को खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में पुलिस ने अर्णब समेत तीन को 4 नवंबर को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने इन्हें 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बुधवार रात अर्णब को रिहा किया गया।

सुप्रीम कोर्ट: हाईकोर्ट अधिकारों का प्रयोग करे

लोकतंत्र: हमारा लोकतंत्र असाधारण रूप से लचीला है। महाराष्ट्र सरकार को यह सब (टीवी पर अर्णब के ताने) नजरअंदाज करना चाहिए।

आजादी: किसी की निजी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जाता है तो यह न्याय का दमन होगा। क्या महाराष्ट्र सरकार को इस मामले में कस्टडी में लेकर पूछताछ की जरूरत है?

हाईकोर्ट: हाइकोर्ट को एक संदेश देना होगा। कृपया, व्यक्तिगत आजादी को बनाए रखने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करें। हम बार-बार देख रहे हैं, अदालत अपने अधिकार क्षेत्र के इस्तेमाल में विफल हो रही हैं। लोग ट्वीट के लिए जेल में हैं।

दखल: आज अगर अदालत दखल नहीं देती है, तो हम विनाश के रास्ते पर जा रहे हैं। इस आदमी (अर्णब) को भूल जाओ। आप उसकी विचारधारा पसंद नहीं करते, हम पर छोड़ दें, हम उसका चैनल नहीं देखेंगे। सब कुछ अलग रखें।

राज्य सरकार: अगर हमारी राज्य सरकारें ऐसे लोगों के लिए यही कर रही हैं, इन्हें जेल में जाना है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना होगा।

10 दिन की पड़ताल : रेकॉर्ड व श्मशान के आंकड़ों में अंतर

महामारी से मौतों पर महाझूठ
रेकॉर्ड में 13, श्मशान में 200

विकास जैन
patrika.com

जयपुर . राजधानी सहित प्रदेशभर में कोविड मौतों के सरकारी और वास्तविक आंकड़ों में भारी अंतर सामने आ रहा है। बीते 10 दिन में चिकित्सा विभाग ने जयपुर जिले में 13 कोविड मौतें बताई हैं। जबकि पत्रिका ने शहर के प्रमुख श्मशानों से जानकारी जुटाई तो चौंकाने वाली तस्वीर नजर आई।

आदर्शनगर श्मशान में तो रोजाना 10-15 कोविड दाह संस्कार होने की जानकारी मिली। लालकोठी, चांद पोल, झालाना सहित शहर की बाहरी कॉलोनियों के श्मशानों में भी हर दूसरे दिन कोविड दाह संस्कार हो रहे हैं। गौरतलब है कि चिकित्सा विभाग काफी पहले ही कोरोना मृतकों के शव देने की गाइडलाइन बदल चुका है। इसके तहत अब परिजनों को प्रोटोकॉल के अनुसार दाह संस्कार के लिए कोविड मृतक के शव दिए जा रहे हैं। ऐसे में जयपुर से बाहर के अधिकांश मृतक अपने गांव व शहरों में जाकर दाह संस्कार कर रहे हैं। जयपुर के श्मशानों के कार्मिकों के अनुसार यहां आ रहे अधिकांश मृतक जयपुर के ही हैं। वहीं, कोरोना मौतों में यह गड़बड़झाला जयपुर जिले ही नहीं बल्कि प्रदेश के अधिकांश जिलों में सामने आ रहा है। पढ़ें **महामारी** @ पेज 17

कोरोना का बढ़ रहा वार न करें 'हद' पार

जयपुर. कोरोना को हराने के लिए जरूरी है कि हद यानी गाइडलाइन के भीतर रहें। मास्क लगाएं, उचित सामाजिक दूरी रखें। भाजपा कार्यालय में सामने आई इस तस्वीर की तरह नहीं, जहां गोले बने रह गए और बिहार में मिली जीत के उत्साह में कार्यकर्ता एक जगह जा जुटे। *फोटो: अनुग्रह सोलोमन*

5 जिलों में कोविड मौतों का सच

जिले	सरकारी रेकॉर्ड	वास्तविक मौतें
अजमेर	150	330
कोटा	116	704
उदयपुर	75	147
जोधपुर	196	553
पाली	135	76
अजमेर	150	330
कुल	672	2019

इन जिलों की पड़ताल में भी सामने आया झूठ

पत्रिका ने अजमेर, कोटा, उदयपुर, पाली और जोधपुर जिलों में भी पड़ताल की। इसमें सामने आया कि यहां वास्तविक मौतों की संख्या अब तक 2019 है जबकि विभाग ने इन जिलों में अब तक मात्र 672 मौतें बताई हैं।

महीनेभर बाद नए मरीज फिर 2,000 पार

जयपुर . प्रदेश में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या फिर तेजी से बढ़ रही है। बुधवार को महीनेभर बाद यह फिर 2 हजार को पार कर 2080 दर्ज हुई। वहीं, 11 नई मौतें दर्ज हुई हैं। सर्वाधिक 450 नए मरीज जयपुर, 310 जोधपुर, 175 बीकानेर, 141 अजमेर, 115 अलवर और 113 कोटा जिले में मिले हैं।

जयपुर में फिर विस्फोट, 450 नए संक्रमित मिले

प्रदेश में संक्रमितों की कुल संख्या 217151 और कुल मृतक संख्या 2019 हो गई है। रिकवर की कुल संख्या 1 लाख 98 हजार 139 हो गई है। इधर, जयपुर में सर्दी की शुरुआत के साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या में अचानक भारी इजाफा हुआ है। जयपुर जिले में बुधवार को कोरोना बम फूटा और 450 नए मरीज मिले हैं। राजापार्क, मुलरीपुरा, सोढाला, वैशाली नगर, मुरलीपुरा, सी-स्कीम व बनीपार्क में मरीज बढ़े हैं। पढ़ें **महीनेभर** @ पेज 17

कुंवारी रिश्तेदार को दिलाया जननी सुरक्षा का पैसा!

केस एक 12.11.20

लेहरो देवी की ननद लीला देवी पत्नी रावलराम दलपत नगर ने भी सीएसपी में खाता खुलवाया। सीएसपी ने उसे भी बैंक डायरी जारी खाता नम्बर आवटंन कर दिया। उस खाते के पैसों में हेराफेरी हुई। पड़ताल में उक्त खाता हनवंतनगर निवासी चन्द्री देवी के नाम से खुला है तथा हजारों का ट्रांजेक्शन हो रहा है। लीला देवी के प्रसूति होने पर जननी सुरक्षा के रुपए चन्द्री देवी के खाते में गए। जबकि चन्द्री देवी के उस समय प्रसूति हुई ही नहीं।

केस दो

हनवंतनगर निवासी हवादेवी पत्नी जालाराम ने भी नगसिंह के पास से बैंक में खाता खुलवाया। जिसको खाता नम्बर देकर बैंक डायरी दी गई। इसने सभी योजनाओं में ये खाता नम्बर जुड़वाए। बैंक में पड़ताल करने पर उक्त खाता कैलाश कंवर के नाम है जो रिश्ते में नगसिंह की पत्नी है।

शेरगढ़ @ पत्रिका. बैंकों में भीड़ कम करने तथा ग्राहकों को निकटतम सुविधा देने के उद्देश्य में सीएसपी ग्राहक सेवा केन्द्र खोले गए है। इनमें भी कई स्थानों पर अनियमितताओं के मामले में सामने आए हैं। ऐसा ही मामला हनवंतनगर में सामने आया। एसबीआई का सीएसपी हनवंतनगर में खोला, जिसका संचालन नगसिंह द्वारा किया जाता है। इसमें कई अनियमितताएं सामने आई हैं। इसके अलावा बैंक के फर्जी लेटर से ग्राम पंचायत भवन में कमरा लेने का मामला भी प्रकाश में आया है। इस मामले में ग्राम पंचायत हनवंतनगर सरपंच गुलाब कंवर ने बैंक अधिकारियों व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर सीएसपी नगसिंह पर बैंक खातों में हेराफेरी करने व पंचायत भवन में अतिक्रमण करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि ग्राम पंचायत हनवंतनगर की लेहरो देवी पत्नी मुन्नाराम मेघवाल ने सीएसपी सुविधा होने पर अपने दस्तावेज ले जाकर नगसिंह के पास खाता खुलवाया। नगसिंह ने एसबीआई का खाता खोल बैंक डायरी दे दी। लेहरो देवी ने विभिन्न सरकारी योजनाओं में अपने उक्त खाता नम्बर दे दिए। विभिन्न योजनाओं के रुपए भी उस खाते में जमा हुए। लेकिन, उसे रुपए नहीं मिले। बाद में लेहरो देवी ने सरपंच गुलाब कंवर के सामने व्यथा सुनाई तो बैंक में पता करने पर रुपए में हेराफेरी का मामला सामने आया। पड़ताल में उक्त खाता नम्बर छैलू कंवर जुड़िया के नाम से खोला है तथा उसी में ट्रांजेक्शन चलता रहा तथा रुपए भी उठा लिए। छैलू कंवर सीएसपी की भांजी है तथा ननिहाल में रहती है। अक्टूबर 2017 में लेहरो देवी के बच्चा हुआ था, जिसका जननी सुरक्षा के रुपए भी कुंवारी छैलू कंवर के खाते में जमा हुए।

पंचायत का कमरा लेने में किया फर्जीवाड़ा

सरपंच ने आरोप लगाया कि नगसिंह ने फर्जी तरीके से बैंक का लेटर बनाकर तत्कालीन बीडीओ भुवनेश्वरसिंह को दिया, जिसमें ग्राम पंचायत भवन में सीएसपी चलाने के लिए कमरा उपलब्ध करवाने का था। बीडीओ ने ग्राम विकास अधिकारी को लेटर देकर कमरा जारी करवा दिया। सरपंच का आरोप है कि कमरे का न तो किराया देता है ओर न बिजली बिल तथा अतिक्रमण कर रखा है। जबकि सीएसपी संचालक का कहना है कि किसी उपभोक्ता ने ऐसी कोई शिकायत नहीं की है न कोई ऐसा मामला है।

इन्होंने कहा

नगसिंह द्वारा रुपए के लेन देन में रुपए में हेराफेरी की शिकायतें मिली है। इसकी लिखित शिकायत बैंक प्रबन्धन को कर दी गई है। उसने फर्जी तरीके से पंचायत भवन में भी कब्जा कर रखा है।

गुलाब कंवर, सरपंच हनवंतनगर

सरपंच की शिकायत पर जांच करने पर कई खातों में गड़बड़ियां मिली है। खाताधारक दूसरे तथा डायरियां दूसरे के नाम से सीएसपी से आंवटित की गई है। बैंक ने भवन आंवटन का कोई पत्र नहीं लिखा है। सीएसपी निरस्त करने की कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को लिखा गया है।

मिथलेश कुमार रस्तोगी, शाखा प्रबन्धक एसबीआई शेरगढ़। निसं

बीमा का खेल : दो साल बाद किया बीमा, फिर उसी ग्रुप की दूसरी कंपनी पर जताया भरोसा

मंत्री की घोषणा भी दरकिनार... ब्लैक लिस्ट कंपनी बहाल

ओमप्रकाश शर्मा
patrika.com

जयपुर . सहकारी विभाग में किसानों के बीमा करने के नाम पर बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। सैकड़ों किसानों का क्लेम अटकाने पर विभाग ने तीन माह पहले ही एक कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया था।

अब दोबारा बीमा का नंबर आया तो ब्लैक लिस्ट की गई कंपनी वाले ग्रुप की ही किसी दूसरी कंपनी को दे दिया। हद तो तब हो गई जब विभाग ने बिना क्लेम निस्तारित किए ब्लैक लिस्ट कंपनी को 54 दिन में ही बहाल भी कर दिया। गौरतलब है कि इससे पहले विधानसभा में मामला उठने पर सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कम्पनी को ब्लैक लिस्ट करने की घोषणा की थी। पढ़ें **मंत्री** @ पेज 07

नियम की पालना हुई

कुछ दिन पहले रिव्यू किया था, उसमें लंबित क्लेम के निस्तारण पर चर्चा हुई थी। अब तो क्लेम के मामले कम ही रहे होंगे। बीमा के लिए कंपनी चुनने के लिए तो जो नियम हैं, उनकी पालना की है। **कुंजीलाल मीना,** प्रमुख सचिव सहकारिता

एसीबी की जयपुर, बूंदी, उदयपुर में कार्रवाई

बीमा का खेल : दो साल बाद किया बीमा, फिर उसी ग्रुप की दूसरी कंपनी पर जताया भरोसा

मंत्री की घोषणा भी दरकिनार... ब्लैक लिस्ट कंपनी बहाल

ओमप्रकाश शर्मा
patrika.com

जयपुर. सहकारी विभाग में किसानों के बीमा करने के नाम पर बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। सैकड़ों किसानों का क्लेम अटकाने पर विभाग ने तीन माह पहले ही एक कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया था।

अब दोबारा बीमा का नंबर आया तो ब्लैक लिस्ट की गई कंपनी वाले ग्रुप की ही किसी दूसरी कंपनी को दे दिया। हद तो तब हो गई जब विभाग ने बिना क्लेम निस्तारित किए ब्लैक लिस्ट कंपनी को 54 दिन में ही बहाल भी कर दिया। गौरतलब है कि इससे पहले विधानसभा में मामला उठने पर सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कम्पनी को ब्लैक लिस्ट करने की घोषणा की थी। पढ़ें **मंत्री** @ पेज 07

नियम की पालना हुई

कुछ दिन पहले रिव्यू किया था, उसमें लंबित क्लेम के निस्तारण पर चर्चा हुई थी। अब तो क्लेम के मामले कम ही रहे होंगे। बीमा के लिए कंपनी चुनने के लिए तो जो नियम हैं, उनकी पालना की है। **कुंजीलाल मीना,** प्रमुख सचिव सहकारिता

एसीबी की जयपुर, बूंदी, उदयपुर में कार्रवाई

तीन अधिकारियों के यहां मिली करोड़ों की संपत्ति

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर . भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने प्रदेश के तीन जिलों में तीन अधिकारियों के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति का मामला दर्ज किया है। शुक्रवार को एक साथ तीनों अधिकारियों के जयपुर, उदयपुर और बूंदी के केशोरायपाटन स्थित 10 ठिकानों पर सर्च अभियान शुरू किया गया। एसीबी के डीजी बीएल सोनी ने बताया कि अधिकारियों के यहां आय से अधिक सम्पत्ति की जानकारी मिलने के बाद गोपनीय शाखा ने यह कार्रवाई की। सर्च अभियान जारी है।

एडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि जयपुर में रीको के सीनियर डीजीएम सतीश गुप्ता (जो अधीक्षण अभियंता स्तर अधिकारी हैं) के दो ठिकानों पर सर्च की गई। उनके खिलाफ प्राथमिक तौर पर 4.13 करोड़ की अवैध सम्पत्ति अर्जित करने का अनुमान है। पढ़ें तीन @ पेज 07

एसई के घर-दफ्तर में छापा, मिली 25 करोड़ की संपत्ति

उदयपुर . भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर टीम ने अजमेर विद्युत वितरण निगम उदयपुर सर्कल के अधीक्षण अभियंता गिरीश जोशी के घर और दफ्तर सहित 5 ठिकानों पर शुक्रवार सुबह छापा मारा। जांच में बड़ी संख्या में जमीन और निवेश के दस्तावेज, नकदी और आभूषण मिले जिनका बाजार मूल्य करीब 25 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। एसई गिरीश कुमार जोशी और उनके परिवार के सदस्यों के नाम बेनामी कृषि भूमि खरीदना पाया गया। विभिन्न बैंकों के 23 खाते, बीमा और बॉण्ड में निवेश सहित 4.13 लाख की नकदी मिली। उदयपुर और नाथद्वारा के पोश एरिया में मकान हैं।

9 राज्य, 38 संस्करण | अजमेर • अलवर • अहमदाबाद • इंदौर • उज्जैन • उदयपुर • कोटा •

बाजरे की खरीद को लेकर राजस्थान, हरियाणा, मध्यप्रदेश और गुजरात में सियासत

बंपर बाजरे पर अब सियासी बाजीगरी

राजस्थान में अपने स्तर पर एमएसपी पर बाजरे की खरीद नहीं | **पड़ोसी राज्य** उपज बेचने के लिए किसानों को घुसने नहीं देते | **कांग्रेस से सवाल** राजस्थान में समर्थन मूल्य पर खरीद क्यों नहीं | **भाजपा से सवाल** कहीं भी बेच सकते तो हरियाणा में क्यों नहीं

सुनील सिंह सिसोदिया
patrika.com

जयपुर . किसान सबका पेटपालक है और बाजरा राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न। लेकिन दोनों ही दुत्कारे जा रहे हैं। बाजार के खरीद को लेकर अंतरराज्यीय सियासत शुरू हो गई है। बंपर उत्पादन होने के बावजूद राजस्थान में तो सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर बाजरे की खरीद कर नहीं रही, किसान हरियाणा, गुजरात और मध्यप्रदेश जाना चाहें तो वहां उन्हें उपज बेचने की अनुमति नहीं मिल रही। ऐसे में राजस्थान के किसान का बाजरा बिक नहीं पा रहा।

केन्द्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी की व्यवस्था बनाए रखने की मांग को लेकर किसान आन्दोलनरत हैं। इस बीच राजस्थान में बाजरे की फसल आ चुकी है लेकिन बाजार में किसान को इसका लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा।

ट्विटर पर सरकारों के बीच यों चली सियासी जंग

राजस्थान का बाजरा यहां हम बेचने नहीं देंगे

हरियाणा की मंडियों में बाजरा 2150 रुपए क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है जबकि राजस्थान में 1300 रुपए क्विंटल के भाव पर बाजरा बिक रहा है। ऐसे में वहां से बाजरा लाकर हरियाणा में बेचने की शिकायतें मिल रही हैं। वहां का बाजरा यहां बिकने नहीं दिया जाएगा।

मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री हरियाणा (ट्वीट)

केंद्र के कृषि बिलों की खुद ही खोल रहे पोल

नए कृषि कानूनों के तहत 'एक देश, एक बाजार' के झूठ का पर्दाफाश खुद भाजपा के सीएम कर रहे हैं। हम पहले से कह रहे हैं कि केन्द्र यह काला कानून अपने कारोबारी मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए लाया है। अन्नदाता आज सड़कों पर आंदोलन करने पर मजबूर है।

गोविन्द सिंह डोटासरा, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस, राजस्थान

राजस्थान-हरियाणा में यह अन्तर

1,300 रुपए क्विंटल की औसत दर से खुले बाजार में बिक रहा है राजस्थान में।

2,150 रुपए क्विंटल पर सरकारी खरीद हो रही है हरियाणा में। इतनी ही दर मंडियों में भी।

(राजस्थान के जिलों की मंडियों में बाजरा का भाव 1100 से 1500 रुपए क्विंटल के बीच है)

सतीश पूनिया-डोटासरा यों भिड़े

डोटासरा बोले.... डोटासरा ने ट्वीट किया, हरियाणा के सीएम के बयान पर सतीश पूनिया और गुलाबचंद कटारिया की चुप्पी यह साबित कर रही है कि किसानों के लिए 'एक देश, एक बाजार' का दावा खोखला है। यह अन्नदाता के साथ धोखा है।

पूनिया ने कहा... भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने ट्वीट किया, राज्य में बाजरा प्रचुर मात्रा में होता है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार बातें तो बड़ी-बड़ी करती है, किसानों के लिए कर कुछ नहीं रही। किसानों की हितैषी है तो एमएसपी पर बाजरा खरीदे।

बेकद्री न करें

पत्रिका व्यू

सियासत में पक्ष-विपक्ष के मतभेद स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है। लेकिन दल और सरकारें ध्यान रखें कि यह लड़ाई आपसी है, किसानों से नहीं। जो कांग्रेस एमएसपी को लेकर केन्द्र सरकार को कोस रही है, राजस्थान में उसी की सरकार एमएसपी पर बाजरा खरीदने से मुंह मोड़े हुए है। जबकि बाजरा यहां प्रचुरता में उपजता है? किसानों की बेकद्री हरियाणा सरकार भी कम नहीं कर रही। केन्द्र ने जब कह दिया कि किसान कहीं भी अपनी उपज बेच सकता है, तो रोक क्यों लगा रही है? सियासत का यह घटिया चेहरा लोकतन्त्र की सेहत के लिए कतई ठीक नहीं है। सियासत के फेर में किसानों को दुत्कारना आम आदमी के पेट पर लात मारने से कम नहीं है।

दो पुलिसकर्मियों का कारनामा : तीनों आरोपी गिरफ्तार

साथी कांस्टेबल को बजरी माफिया के घर बंधक बनाकर पीटा

07.12.20

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

फागी (जयपुर) . राज्य में बजरी माफिया बेलगाम क्यों हो रहे हैं और पुलिस की उनसे किस हद तक मिलीभगत है, इसकी चिन्ताजनक बानगी सामने आई है। जयपुर जिले के फागी थाने के हैड कांस्टेबल और कांस्टेबल ने साथी कांस्टेबल को बजरी माफिया के घर बुलाया और बंधक बना लिया। उसे लात-घूसों से पीटा और नाक तोड़ दी। उस पर रुपए फेंककर रिश्वत लेने का आरोप लेते हुए वीडियो भी बनाया। रातभर बंधक रहा पीड़ित कांस्टेबल तड़के जैसे-तैसे जान बचाकर भागा।

पीड़ित कांस्टेबल रींगस निवासी राजेश ने शनिवार रात मामला दर्ज कराया। इसमें उसने बताया कि शुक्रवार रात ड्यूटी के संबंध में उसने हैड कांस्टेबल अमीचन्द गुर्जर को फोन किया था। पढ़ें **साथी** @ पेज 10

पीड़ित कैलाश

बजरी माफिया पर कई मामले दर्ज

थाना प्रभारी रामधन सांडीवाल ने बताया कि मुकेश उर्फ गोगा के खिलाफ आगजनी, मारपीट, छेड़खानी को लेकर फागी थाने में 3 मामले दर्ज हैं। मासी नदी से मुकेश की जेसीबी व बजरी के कई वाहन जब्त हो चुके हैं। इन मामलों में जुर्माना किया था।

शर्मनाक साठगांठ, दंडनीय दुस्साहस

पत्रिका व्यू

पैसों के लालच में अंधे होकर कानून के रक्षकों का ऐसा रवैया! माफिया और अपराधियों से गठजोड़ का स्तर यहां तक जा पहुंचे कि माफिया से मिलकर खुद पुलिसकर्मी ही अपने साथी पुलिसकर्मी की जान लेने पर आमादा हो उठें? क्या शासन को नहीं लगता कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है? ईमानदारी को बंधक और निष्ठा को लहूलुहान कर दिया जाए तो लोकतन्त्र बच पाएगा? क्या सरकारी कुर्सियां ऐसे भ्रष्टों और आपराधिक प्रवृत्ति वालों के लिए हैं? शासन को जागना होगा। निलम्बन जैसे कदम छोटे पड़ने लगे हैं। भ्रष्टों को सीधे नौकरी से निकालकर जेल में डालना होगा।

तैयारी : सरकार गिराने की साजिश के बयान के बाद

सड़कों पर भीख मांगता मिला आइआइटी से मैकेनिकल इंजीनियर

ग्वालियर@पत्रिका. मध्यप्रदेश में ग्वालियर की सड़कों पर भीख मांगने वाले बुजुर्ग को आश्रम स्वर्ग सदन ने रेस्क्यू किया तो हैरान करने वाली कहानी सामने आई। बुजुर्ग ने अपना नाम सुरेंद्र वशिष्ठ बताते हुए खुद को आइआइटी कानपुर से 1969 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पासआउट होने का दावा किया है। अंग्रेजी में बात करने वाले वशिष्ठ अपनी आयु 89 बताते हैं। उन्होंने कहा, नाना-नानी ने मेरी परवरिश की। बरेली में रहता था। मेरा सामान चोरी चला गया। लेकिन वह नहीं बता पा रहे कि ग्वालियर कैसे पहुंचे।

हॉट न्यूज

सुधार : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा...

घाटे की चिंता किए बगैर देश करेगा खर्च

09.12.2020

■ **सेवा और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में हो रही रिकवरी**

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत अपने बजट घाटे के लक्ष्य को पूरा करने की चिंता नहीं कर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए खर्च जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सरकारी कंपनियां पूंजीगत खर्चों को जारी रखें। सीतारमण ने कहा कि मैं राजकोषीय घाटे के आंकड़े को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूं। क्योंकि मेरे लिए पैसा खर्च करना एक बड़ी जरूरत है।

एक इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र द्वारा घोषित राहत पैकेज जल्दबाजी में खाया हुआ कोई घाव साबित नहीं होगा। पिछले महीने केंद्र सरकार ने कंपनियों को उबारने और कोरोना महामारी के कारण खोई हुई नौकरियों को बचाने के लिए अर्थव्यवस्था की तुलना में 15 फीसदी (30 लाख करोड़ रुपए) का राहत पैकेज दिया। हालांकि केंद्र की ओर से इसे कई चरणों में दिया गया।

वार्षिक दृष्टिकोण में बदलाव

सीतारमण ने कहा, आरबीआइ के वार्षिक दृष्टिकोण में बदलाव में अक्टूबर में 9.5 फीसदी की गिरावट के अनुमान की तुलना में दूसरी तिमाही में जीडीपी में 7.5 फीसदी की गिरावट रही। आइएमएफ और आरबीआइ दोनों बहुत स्पष्ट रूप से रिकवरी देख रहे हैं।

राहत पैकेज ने फूंकी जान

वित्त मंत्री ने कहा , कई हाई फ्रीक्वेंसी संकेतकों से भी सेवाओं और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों की गतिविधियों में सुधार का पता चला है। यही क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्रमुख इंजन हैं। यह फिलहाल मंदी की चपेट में हैं।

आंकलन की जरूरत

सीतारमण ने एक फरवरी को पेश होने वाले अगले बजट से पहले कहा कि जहां तक आने वाले वर्ष का संबंध है, हमें इसका आंकलन करने की जरूरत है। मैं यकीन के साथ नहीं कह सकती हूं कि तुरंत खर्च में कटौती की जा सकती है। क्योंकि जिस गति से अर्थव्यवस्था चल रही है उसमें निरंतरता होनी चाहिए।

वी-शेप में बढ़ रही देश की अर्थव्यवस्था, सुधार जारी @बाजार पेज

अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस: एसीबी ने 4 जगह मारा भ्रष्टों पर पंजा

10-12-2020

कलक्टर से एएसपी तक घूस ही घूस

जयपुर. राज्य में पैसों के लालची घूसखोरों के लिए बुधवार को अन्तरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस भी बौना हो गया। इस दिवस पर भी घूसखोरी का खेल खेलने से नहीं चूके। एसीबी ने भी खूब पंजा मारा। एसीबी ने दिनभर में 4 जगह सवाईमाधोपुर, बारां, अलवर व टोंक में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सबसे बड़ी कार्रवाई बारां में की। वहां जिला कलक्टर इन्द्रसिंह राव के पीए महावीर नागर को 1.40 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। सवाईमाधोपुर में एएसपी और डीटीओ को दबोचा।

राव से पूछताछ के बाद होगा | आरोपी बनाने का फैसला

बारां: कलक्टर के लिए पीए ने वसूले 1.40 लाख, राव एपीओ

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

बारां. एसीबी की कोटा टीम ने बारां में बुधवार शाम जिला कलक्टर इन्द्रसिंह राव के पीए महावीर नागर को 1.40 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। कलक्टर की मौन स्वीकृति से पीए ने यह राशि पेट्रोल पम्प की एनओसी जारी कराने के लिए ली थी। इसमें से एक लाख रुपए कलक्टर राव को देने थे। शेष 40 हजार रुपए पीए को रखने थे। कार्रवाई के बाद सरकार ने कलक्टर राव को एपीओ कर दिया। मामले में राव से पूछताछ भी की जा रही है। इसके बाद एसीबी राव को आरोपी बनाने पर निर्णय करेगी।

एसीबी कोटा के एएसपी चंद्रशील ठाकुर ने बताया कि अटरू निवासी गोविंद सिंह अटलपुरी ने कोटा कार्यालय में शिकायत की थी। उसका कहना था कि पेट्रोल पम्प की लीज के नवीनीकरण के लिए जिला कलक्टर की ओर से उनका पीए महावीर नागर 2.40 लाख रुपए मांग रहा है। सत्यापन के बाद कोटा से ब्यूरो की टीम बारां पहुंची और कार्रवाई को अंजाम दिया। पीए नागर को रिश्वत की राशि लेते रंगेहाथ दबोच लिया गया।

कार्रवाई के दौरान बारां जिला कलक्ट्रेट परिसर पूरी तरह सील रहा। मीडिया को पुलिस जवानों ने अंदर नहीं जाने दिया। इस दौरान कुछ मीडिया कर्मियों से उनकी तकरार भी हुई। बाद में करीब साढ़े आठ बजे मीडिया कर्मियों को प्रवेश दिया गया।

कलक्टर की संलिप्तता, रात तक पूछताछ

एएसपी ठाकुर ने बताया कि मामले में जिला कलक्टर राव की संलिप्तता और मौन स्वीकृति सामने आई है। रात 9.30 बजे तक जिला कलक्टर से पूछताछ की जा रही थी। उन्हें आरोपी बनाने का निर्णय पूछताछ के बाद ही होगा।

पीए का कबूलनामा 2.40 लाख मांगे थे, इसमें से कलक्टर को देने थे 2 लाख

एएसपी चंद्रशील ठाकुर ने बताया कि प्रारम्भिक पूछताछ में पीए नागर ने रिश्वत की राशि में से एक लाख रुपए जिला कलक्टर राव तथा शेष 40 हजार रुपए खुद के लिए लेना स्वीकार किया है। शेष एक लाख रुपए जो मिलने बाकी थे, वह राशि भी कलक्टर को देनी थी। कार्रवाई के बाद बारां की एसीबी टीम नागर के बाबजीनगर स्थित आवास पर तलाशी शुरू की।

इंद्रसिंह राव छठी बार एपीओ

बारां. जिला कलक्टर इंद्र सिंह राव छठी बार एपीओ हुए हैं। एक बार उन्हें निलम्बित भी किया जा चुका है। वे मूल रूप में आरएएस सेवा के अधिकारी रहे हैं। बाद में उन्हें आइएएस के रूप में प्रमोशन मिला। उन्हें सबसे पहले डिप्टी सेक्रेटी ऑफ गवर्नमेंट जीएडी रहने के दौरान 25 नवम्बर 2011 को एपीओ किया गया था। इससे पहले उन्हें तीन बार एपीओ तथा एक बार निलम्बित भी किया गया। हर बार वे राजनीतिक रसूखात से वापस कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किए गए। बारां में कलक्टर नियुक्त किए जाने से पहले राव राजस्व मंडल अजमेर एवं नगर निगम में पदस्थ रह चुके हैं। रात 11 बजे तक टीम राव से उनके कार्यालय कक्ष में पूछताछ कर रही थी।

भ्रष्टाचार रोकने वाले ने | बांध रखी थी विभागों से बंधी

स.माधोपुर: एसीबी एएसपी को डीटीओ से वसूली करते दबोचा

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

सवाईमाधोपुर. एसीबी ने अपनी ही अति. पुलिस अधीक्षक (एएसपी) भैरुलाल मीणा को 80 हजार रुपए मासिक बंधी वसूलते रंगेहाथ पकड़ा है। ऐसा पहली बार हुआ जब एसीबी ने अपने ही अफसर को धरा है। वह भ्रष्टाचार निरोध दिवस पर सुबह अपने कार्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण दे रहा था। इसके 2 घंटे बाद ही वह पकड़ा गया। उसे यह राशि डीटीओ महेशचंद मीणा ने दी, जिसे भी एसीबी ने गिरफ्तार किया है।

डीटीओ

एसीबी के डीजी बीएल सोनी ने बताया कि आरोपी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) भैरुलाल मीणा सवाईमाधोपुर में एसीबी का चौकी प्रभारी है। दो महीने पहले शिकायत मिली थी कि भैरुलाल मीणा कुछ सरकारी विभागों के अफसरों से बंधी लेता है। तब से एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में एएसपी पुष्पेन्द्र सिंह शेखावत उस पर नजर रखे हुए थे।

एडीजी एमएन के अनुसार निगरानी में पता चला कि डीटीओ महेशचंद मीणा भ्रष्टाचार विरोधी दिवस पर दोपहर बाद एसीबी चौकी में भैरुलाल मीणा को घूस देने जाएगा। इस पर जयपुर मुख्यालय से एएसपी शेखावत सुबह 10 बजे टीम के साथ वहां पहुंचे। दोपहर 1.30 बजे डीटीओ महेशचंद मीणा चौकी पर पहुंचा और एएसपी भैरुलाल को घूस के 80 हजार दिए तो टीम ने उन्हें पकड़ लिया। पढ़ें स.माधोपुर @ पेज 08

11:30 बजे सीख | **01:30 बजे ट्रैप**

नंबर देकर बोले, कोई रिश्वत मांगे तो बताओ

सुबह 11:30 बजे ठींगला स्थित एसीबी कार्यालय परिसर में भैरुलाल मीणा लोगों को जागरूकता का पाठ पढ़ा रहा था। लोगों को फोन नम्बर दिए और कहा कि रिश्वत लेने वालों की सूचना दें। कुछ देर बाद खुद ही रिश्वतखोरी करते पकड़े गए।

04 बड़ी कार्रवाई

1. **बारां** कलक्टर का पीए [illegible] घूस लेते धरा।
2. **स.माधोपुर** एसीबी चौकी प्रभारी एएसपी भैरुलाल मीणा 80 हजार की घूस लेते, डीटीओ यह राशि देते गिरफ्तार।
3. **अलवर** बानसूर में ट्रांसफर बदलने के एवज में लाइनमैन सुभाष 28000 रुपए लेते गिरफ्तार।
4. **टोंक** ट्रैक्टर पर कार्रवाई नहीं करने की एवज में 25500 रुपए लेते फोरेस्ट गार्ड किरण सांसी गिरफ्तार।

जागरुकता की जरू

हमें भ्रष्टाचार के खतरे प जागरुकता बढ़ाने की जरूरत है। यह लोकतांत्रिक संस्था अ कानून के शासन को कमजोर करता है। आर्थिक विकास को धीमा करके देश की प्रगति में बाधक है। भ्रष्टाचार मुक्त समा ही विकास कर सकता है।
(अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस पर मुख्यमंत्री का ट्वीट

न...लापरवाही ने ले ली जान

11 केवी की लाइन का तार स्कूटर पर गिरा

कोताही का तार, शिक्षिका जिंदा जली

12-12-20

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

बांसवाड़ा . नौगामा . बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा की यह हृदय विदारक तस्वीर आपको विचलित कर सकती है लेकिन आपको जानना जरूरी है कि हंसते-खेलते एक परिवार की धुरी किस तरह सरकारी कारिन्दों की लापरवाही के कारण टूट गई।

सालभर पहले सरकारी शिक्षक बनी 25 साल की नीलम पाटीदार शुक्रवार सुबह रोजाना की तरह घर का काम-काज निपटाकर स्कूल जाने के लिए निकली लेकिन अजमेर डिस्कॉम की कोताही मौत बनकर आई और उसे जिंदा जला गई। ग्यारह केवी की ओवरहेड लाइन का तार टूटकर उस पर आ गिरा।

पढ़ें **कोताही** @ पेज 11

यह फोटो आपको विचलित कर सकता है। लेकिन हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों की गैर जिम्मेदारी को उजागर करने के लिए प्रकाशित करना जरूरी है।

लापरवाही नहीं ये हत्या

रोजाना बिजली गुल कर कहां रखरखाव कर रहे थे जिम्मेदार?

रखरखाव के बावजूद जरा सी

जिले में आए दिन घटनाएं, जिम्मेदा
जागे क्यों नहीं, फिर तार कैसे गिरा?

यह लाइन पहले भी ट्रिप हुई, तो

राजस्थान 2,91,289 (+1,290)
जयपुर 53,835 (+295)

भ्रष्टाचार को संरक्षण : 4 लाख की घूस लेने के आरोपी संयुक्त सचिव पर कार्रवाई से इनकार

घूसखोरी को सरकार का 'अभयदान'

पत्रिका डे-स्पेशल मंडे मेगा स्टोरी

ओमप्रकाश शर्मा
patrika.com

जयपुर. एक साल पहले 4 लाख रुपए की घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार खान विभाग के संयुक्त सचिव बीडी कुमावत को राज्य सरकार ने 'रिहा' कर दिया। कुमावत को सजा दिलाने के लिए एसीबी सबूत जुटाकर अदालती कार्रवाई में जुटी थी कि राज्य सरकार ने अभियोजन की इजाजत देने से ही मना कर दिया। एसीबी कुछ करती, उससे पहले सरकार ने अधिकारी को बहाल भी कर दिया। कुमावत पर यह 'कृपा' अन्तरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधी दिवस से कुछ दिन पहले हुई।

ऐसे एक नहीं बल्कि अनेक प्रकरण हैं, जिनमें एसीबी ने भ्रष्टाचार के आरोपी अफसरों को धरा लेकिन राज्य सरकार ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की इजाजत ही नहीं दी। इनमें से कई अफसरों के खिलाफ तो एसीबी ने पर्याप्त सबूत जुटाने का दावा किया। इसके बावजूद सरकार अभियोजन स्वीकृति के लिए आई फाइल पर या तो कुंडली मारकर बैठ गई या अफसर पर लगे दाग को खुद ही 'धो' दिया।

पढ़ें **घूसखोरी** @ पेज 18

विधासभा में रंगे हाथ पकड़ा, उसपर भी मेहरबानी

विधानसभा में ही रिश्वत लेते पकड़े गए एक्सईएन जितेन्द्र ढाका के खिलाफ भी सरकार ने अभियोजन की इजाजत नहीं दी। एसीबी ने उसे अगस्त 2019 में 70 हजार रुपए लेते रंगे हाथ पकड़ा था।

कार्यालय में पकड़े गए थे, नहीं होगी कार्रवाई

एसीबी ने अगस्त 2018 को पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में एक्सईएन डीपी सैनी और ऑफिसर सुपरिटेंडेंट गुलाबचंद गुप्ता को रिश्वत लेते पकड़ा था। सरकार ने डीपी सैनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ड्रॉप कर दी है।

सीओ को भी छोड़ा

झुंझुनू नगर परिषद आयुक्त विनयपाल को घूस लेने के आरोप में पार्षद के साथ पकड़ा। विनयपाल के खिलाफ अभियोजन की इजाजत नहीं मिली। सीकर में परिवहन निरीक्षक मुक्ता को 70 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था। एसीबी को इस मामले में भी कार्रवाई की इजाजत नहीं मिली।

40 से अधिक मामले सरकार के पास लंबित

अधिकारी	पद	लंबित
निशुकुमार अग्निहोत्री	सचिव, यूआइटी अजमेर	2016
नीरज के. पवन	अतिरिक्त निदेशक, एनएचएम	2017
अविनाश कुलदीप, गाइड सिंह, अनिल खमेसरा, प्रताप सिंह मीणा, अनुज गोयल	खनिज अभियंता, सीकर	2018
राजेन्द्र चौधरी, मनोजकुमार शर्मा	सहायक खनि अभियंता, सीकर	2018
कांतिलाल परमार, सुभाषचंद डांगी	खनिज कार्यादेशक, सीकर	2018

पढ़ें **40 से** @ पेज 18

पढ़ें एमएसपी @ पेज 18

गुजरात : 1932 कर्मचारियों से वापस ले लिए 14.80 करोड़ रुपए

डेयरी बोनस घोटाले में पूर्व मंत्री गिरफ्तार

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

14-12-20

अहमदाबाद. गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री और दूधसागर डेयरी के पूर्व अध्यक्ष विपुल चौधरी को 14.80 करोड़ के बोनस घोटाले में रविवार को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार दूधसागर डेयरी के 1932 कर्मचारियों को बैंक खाते के जरिए बोनस जारी किया गया था, लेकिन बाद में उनसे 14.80 करोड़ रुपए वापस ले लिए गए। ट्रिब्यूनल ने निश्चित अवधि में विपुल चौधरी को 9 करोड़ रुपए वापस करने के लिए आदेश दिए थे। चौधरी की गिरफ्तारी मेहसाणा दूधसागर डेयरी चुनाव से पहले हुई है। चुनाव 5 जनवरी को होने वाले हैं।

रिपब्लिक टीवी के सीइओ गिरफ्तार

मुंबई. टीआरपी घोटाले में रिपब्लिक टीवी के सीइओ विकास खानचंदानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले रिपब्लिक टीवी के वितरण प्रमुख घनश्याम सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है।

डल में डांवाडोल : 4 डिग्री पारा और पानी में चित

श्रीनगर. डीडीसी चुनाव के लिए गए भाजपा कार्यकर्ताओं की नाव डल झील में पलट गई। नाव में कुछ मीडियाकर्मी भी थे। सभी को सकुशल निकाला गया। डीडीसी चुनाव के छठे चरण में रविवार को 51.51% वोटिंग हुई।

कोरोना

45 करोड़ का सोना गायब, रिपोर्ट तलब

सीबीआइ की कस्टडी में थी 103 किलोग्राम पीली धातु

13.12.2020

चेन्नई @पत्रिका. तमिलनाडु में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) की कस्टडी में रखा 45 करोड़ रुपए का 103 किलो सोना गायब हो गया है। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस की सीबी-सीआइडी को 6 माह में रिपोर्ट के आदेश दिए है। सीबीआइ ने पुलिस जांच पर आपत्ति जताई। कोर्ट ने कहा कि ये सीबीआइ के लिए अग्नि-परीक्षा होगी, अगर एजेंसी के हाथ सीता की तरह साफ हैं तो और चमक कर बाहर आएंगे, नहीं तो सजा भुगतनी होगी। सीबीआइ ने मामले में आंतरिक जांच के आदेश दिए और कहा कि सोना हमारे मालखाने में नहीं रखकर कंपनी की वॉल्ट में सील किया था। उल्लेखनीय है, 2012 में एक रेड के दौरान सीबीआइ ने कुल 400.5 किलो सोना जब्त किया था।

चीन में छेड़ा अनूठा अभियान

आग उगलने वाले ड्रोन से ततैया के छत्ते स्वाह

बीजिंग @ पत्रिका. दक्षिण पश्चिम चीन के

...तो डॉक्टरों प

लखनऊ @पत्रिका. उत्तर प्रदे सरकार ने बड़ा फैसला किया है से कम 10 साल तक सरकारी यदि बीच में नौकरी छोड़ी तो ज़ सरकार को देने होंगे।

ई-सिस्टम से आंकड़े बढ़ रहे हैं, काम आज भी बिना एजेंट नहीं होता

ई-सिस्टम से पिज्जा 30 मिनट में, फाइल नहीं सरकती हफ्तों तक
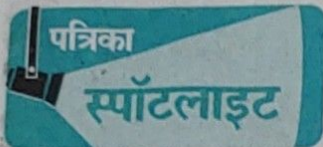
पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर . आधार कार्ड, प्रमाण-पत्र और मतदाता पहचान-पत्र बनवाने या इनमें संशोधन करवाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम है, लेकिन हकीकत में लोग आज भी ई-मित्र पर निर्भर हैं या इस ऑनलाइन सिस्टम ने एजेंट पनपा दिए हैं। कई सुविधाएं तो मुफ्त हैं, लेकिन उसके पैसे देने पड़ रहे हैं। दरअसल सॉफ्टवेयर पब्लिक फ्रेंडली नहीं होने से लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।

जवाबदेही कानून के प्रारूप के लिए पूर्व आइएएस अधिकारी रामलुभाया की अध्यक्षता में बनाई कमेटी के अध्ययन में सामने आया है कि सेवाओं की प्रदायगी की गारंटी अधिनियम के तहत 68 प्रतिशत सेवाएं समय पर नहीं मिल रही हैं।

. कमेटी ने इस बारे में चिंता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस कथन को दोहराया है जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि पिज्जा भले 30 मिनट में आ सकता है लेकिन सरकारी फाइल में कई दिन लग जाते हैं। हाल ही सरकार ने कहा कि शादी समारोह के लिए ऑनलाइन अनुमति ली जा सकती है, लेकिन ई-मेल का जवाब नहीं मिलने से लोगों में यह घबराहट रही कि पता नहीं फेरों के समय पुलिस न आ धमके। इसके चक्कर में लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एजेंटों के जरिए ही आवेदन किया।
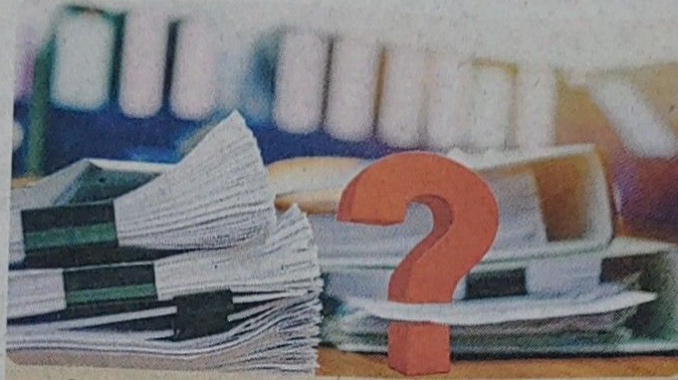
क्यों लेते हैं एजेंट का सहारा

- परीक्षा फॉर्म भरने में गलती से बचने के लिए लोग ई-मित्र जाते हैं। इसकी वजह है कि आवेदक को समझाने के लिए डेमो नहीं होता है।
- आधार बनवाना है तो लोगों को अटकने का डर रहता है, इसी कारण आधार केन्द्र के आसपास एजेंट पनप गए हैं।

खोली पोल

रामलुभाया कमेटी के अनुसार सरकार के विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र और सीमाज्ञान आदि के लिए 19 लाख 77 हजार आवेदन लम्बित थे, जिनमें से 13 लाख 30 के लिए निर्धारित समयसीमा बीत चुकी थी और लोगों को उनका प्रमाण पत्र या दस्तावेज नहीं मिल पाया था।

ई-गवर्नेंस का बजट

वर्ष	राशि
2010-11	102.84 करोड़ रुपए
2015-16	580.90 करोड़ रुपए
2016-17	659.60 करोड़ रुपए
2017-18	697.30 करोड़ रुपए
2018-19	798.07 करोड़ रुपए
2019-20	857.62 करोड़ रुपए
2020-21	806.31 करोड़ रुपए

दिल्ली हमसे बेहतर

कानून में अधिकांश कामकाज ई-गवर्नेंस से जोड़ा है और संपर्क पोर्टल भी इसी का हिस्सा है, लेकिन 57% लोग संतुष्ट नहीं हैं। राजस्थान

एक्सपर्ट व्यू : डिजाइन स्तर पर लोगों को जोड़ें

रक्षिता स्वामी, निदेशक, सोशल अकाउंटेबिलिटी फोरम फॉर एक्शन एंड रिसर्च

ई-गवर्नेंस से भ्रष्टाचार खत्म होने की सोच सही नहीं है, हां इससे पारदर्शिता अवश्य आ सकती है। प्रक्रिया को आसान बनाया जाए और किसी भी व्यवस्था को लागू करने से पहले डिजाइन के स्तर पर ही लोगों को सुना जाए, ताकि उसमें समस्याओं का समाधान पहले से ही किया जा सके। इसके अलावा डिजीटल के साथ ही लोगों को दफ्तर में आकर काम करवाने की छूट भी दी जाए।

आंकड़े : अप्रैल से जून तक | मिनट आटाटा पर बिता रह हा

किसान आंदोलन: सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, अगली सुनवाई आज

'किसानों का प्रदर्शन राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा, बातचीत से निपटाया जाए'

शीर्ष अदालत ने 5 पक्षों को नोटिस जारी किया है

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. कृषि कानूनों को लेकर चल रहे किसान संगठन और सरकार के गतिरोध के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाकर मामले की सुलह की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों का मामला राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा, इसे बातचीत से जल्द सुलझाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि वह विवाद का समाधान खोजने के लिए एक समिति का गठन कर सकती है। उधर, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से दर्शन पाल ने बुधवार को कृषि मंत्री को सरकार के प्रस्ताव का जवाब लिखित में दिया है। इसमें उन्होंने कहा कि उन्हें सरकार का प्रस्ताव नामंजूर है।

किसानों के आंदोलन पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाओं में प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने की अपील की गई। पढ़ें **किसानों** @ पेज 11

सिंघु बॉर्डर पर बुधवार को किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करते पूर्व सैनिक।

चिल्ला बॉर्डर फिर से जाम

चिल्ला बॉर्डर पर धरना दे रहे भाकियू(भानु) के ने बुधवार को फिर से नोएडा से दिल्ली जाने वाले मार्ग को रोक दिया। जयपुर- दिल्ली हाइवे पर शाहजहांपुर-खेड़ा बॉर्डर पर आंदोलन जारी है। भीलवाड़ा के 2 किसानों की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें घर भेज दिया गया।

बाबा राम सिंह ने खुद को गोली मारी

किसान आंदोलन के दौरान बुधवार को संत बाबा राम सिंह ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। यह घटना करनाल में बॉर्डर के पास हुई। बताया जा रहा है कि संत बाबा राम सिंह किसानों के बारे में सरकार के रवैये से आहत थे। वे कई दिन से दिल्ली के पास हो रहे आंदोलन में शामिल थे। उन्होंने एक शिविर की व्यवस्था की थी और कंबल बांटे थे। उनके पास मिले सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा है कि वे किसानों की हालत नहीं देख सकते। केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए वे चिंतित हैं।

सनी को वाइ कैटेगरी सुरक्षा... पंजाब के गुरदासपुर से भाजपा सांसद और अभिनेता सनी देओल को वाइ कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई है। उन्होंने हाल ही में कृषि कानूनों का समर्थन किया था।

मुख्य बिंदु

- ग्वालियर में आयोजित किसान सम्मेलन में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि जब किसानों को गुमराह किया जा रहा है और पंजाब के किसान देश के एक कोने में आंदोलन कर रहे हैं तो आप मोदी सरकार के कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं।
- यूपी गेट पर बुधवार शाम किसानों ने बैरिकेड लांघ दिल्ली में घुसने की कोशिश की।
- विजय दिवस के अवसर पर गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को पूर्व सैनिकों का भी साथ मिला है। *यूपी गेट पर पूर्व सैनिकों के वेटरन्स एसोसिएशन ने किसानों के साथ* राष्ट्रीय गान गाया।
- कृषि कानूनों का विरोध कर रहे राहुल गांधी पर तंज कसते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिवराज सिंह चौहान ने रीवा में हो रहे किसान सम्मेलन में कहा कि राहुल गांधी आखिर किस आधार पर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं।

शिक्षा मंत्री का ऐलान : 90 में से 75 सवाल जरूरी

विजय दिवस : शहादत को सलाम

अफसरों की गिरफ्त में सरकार का ई-गवर्नेंस

18.12.2020

नाम 'मित्र'... बर्ताव दुश्मनों जैसा अफसर सरकारी... काम टालमटोल

ई-मित्र संचालक कूट रहे चांदी, फिर भी उपलब्ध नहीं पूरी 300 सेवाएं

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. राज्य सरकार ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने का दावा रही है लेकिन सरकारी मशीनरी में ई-गवर्नेंस कहीं नजर नहीं आता। सरकार ई-मित्र कियोस्क का दायरा बढ़ाकर और सेवा शुल्क निर्धारित कर भूल गई। निगरानी नहीं होने से ई-मित्र संचालक चांदी कूट रहे हैं। रही-सही कसर सरकारी विभाग पूरी कर रहे हैं। डिस्कॉम, पीएचईडी आदि विभागों ने बिजली, पानी, टेलीफोन के बिल जमा करने तक सीमित कर दिया।

सरकारी नुमाइंदों की इस मनमानी पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (डीओआइटी) ने भी मुहर लगा दी। ऐसे में जनता को ई-गवर्नेंस की वह सुविधा नहीं मिल पा रही। जबकि सरकार ने ई-मित्र कियोस्कों पर 300 से ज्यादा सेवाएं दे रखी हैं। पत्रिका पड़ताल में सामने आया कि कियोस्क संचालक केवल बिजली-पानी के बिल जमा कर दूसरी फाइलों को 'निपटाने' के खेल में व्यस्त हैं।

फैक्ट फाइल

83759 ई-मित्र कियोस्क हैं राजस्थान में

8014 ई-मित्र कियोस्क हैं जयपुर में इनमें से

372 सेवाएं जुड़ी हैं ई-मित्र के जरिए

रामबाग सर्किल पर डिस्कोम कार्यालय में संचालित ई-मित्र में पुलिस वेरिफिकेशन आवेदन के लिए मना करने के बाद बाहर फाइल पर चर्चा करते हुए कियोस्क संचालक।

यहां धरी रह गई ई-गवर्नेंस

केस-01: पचास की जगह 300 रुपए

पत्रिका टीम भांकरोटा मुख्य बाजार में बालाजी ई-मित्र पर मूल निवास प्रमाण पत्र प्रक्रिया के लिए पहुंची। इसका शुल्क 50 रुपए निर्धारित है लेकिन संचालक ने 300 रुपए मांगे। सवाल किया तो उसने पूरे काम की प्रक्रिया गिना दी। प्रमाण पत्र जल्दी दिलाने की गारंटी भी दे दी। मामला हाथ से जाते देख बाद में कुछ कम-ज्यादा करने पर राजी होने लगा।

केस-02: बिल के अलावा कुछ नहीं

रामबाग सर्कल के पास जयपुर डिस्कॉम के दफ्तर में ई-मित्र कियोस्क पर पत्रिका टीम पुलिस वेरिफिकेशन फार्म भरने के लिए पहुंची। कियोस्क संचालक ने बाहर रोक दिया। बोला, यहां केवल बिजली-पानी के बिल जमा होते हैं। फिर गेट पर फाइल लेकर खड़े व्यक्ति के पास चला गया। इस कियोस्क पर सभी तरह की सुविधाओं का विकल्प उपलब्ध था।

(पत्रिका के पास इनकी रिकॉर्डिंग भी हैं)

ध्यान रखिए, 25 सेवाएं हैं नि:शुल्क

बिजली, पानी, टेलीफोन के बिल जमा करने सहित 25 सेवाएं शुल्क मुक्त हैं। इसमें नेशनल पेंशन स्कीम, प्रधानमंत्री किसान योजना व पीएम श्रम योगी योजना, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत राजस्थान स्वास्थ्य योजना, जन आधार नामांकन, ईईएसएल प्रोडक्ट रिप्लेस करने पर, रि-प्रिंट डिजिटल साइन सर्टिफिकेट सहित अन्य सेवाएं हैं। अन्य सेवाओं के लिए 2 से 260 रुपए तक शुल्क निर्धारित है।

डिस्कॉम और जलदाय विभाग ने कुछ शर्तों के आधार पर अपने कार्यालयों में ई-मित्र संचालन की अनुमति मांगी थी। जनता को हर ई-मित्र पर सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। दोनों विभागों से बात करेंगे, भले ही प्राथमिकता बिजली-पानी के बिलों को दें। जो ई-मित्र संचालक अधिक वसूली कर रहा है, उसका संचालन निलंबित कर रहे हैं। एसडीएम को भी अधिकार दिए हुए हैं।

आरके शर्मा, अतिरिक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग

लग सकता है जुर्माना, बंद हो सकता है कियोस्क

ई-मित्र संचालक निर्धारित सुविधा देने से मना नहीं कर सकता। वरना डीओआइटी सहित एसडीएम 1 से 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हैं। कियोस्क का संचालन बंद भी कर सकते हैं।

सीएमआइई सर्वे : देश नौकरी के मोर्चे पर लगातार खा रहा है झटका, जॉब की अभी भी भारी कमी

नवंबर में 35 लाख लोगों से छिन गई नौकरी

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

मुंबई. सीएमआइई के सर्वे के अनुसार, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच पहली तिमाही में रोजगार में 20.3% की गिरावट आई थी। दूसरी तिमाही में 3.5% की गिरावट दर्ज की गई। अक्टूबर में 50 हजार नौकरियां चली गईं, तो नवंबर में 35 लाख लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। नवंबर, 2020 में कुल 39.36 करोड़ नौकरियां थीं। यह मार्च, 2020 तिमाही की अपेक्षा 1 करोड़ कम है। इस साल की शुरुआत से ही रोजगार की स्थिति विकास के रास्ते से भटक गई है यानी रोजगार के मामले में स्थिति भयानक होती जा रही है।

रोजगार घटा, बेरोजगारी बढ़ी 29.12.2020
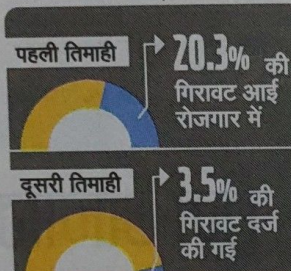
9.5% हो गई है बेरोजगारी की दर बढ़कर

39.5 करोड़ के लगभग होगी रोजगार की संख्या

तीसरी तिमाही में रोजगार में कमी

तीसरी तिमाही के अंत तक रोजगार की संख्या लगभग 39.5 करोड़ होगी। इसका मतलब यह है कि वित्त वर्ष 2020 की तीसरी तिमाही में 40.5 करोड़ के रोजगार की तुलना में वित्त वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही में रोजगार 2.5 प्रतिशत कम होगा।

इस बार जीडीपी में कम गिरावट

रोजगार और आर्थिक विकास का एक-दूसरे से गहरा नाता है। अनुमान है कि इस तिमाही में सितंबर, 2020 की तुलना में कम गिरावट दर्ज की जाएगी। पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था में 23.9% की रिकॉर्ड गिरावट दर्ज करने के बाद दूसरी तिमाही में इसमें 7.5 प्रतिशत की गिरावट आई थी। दोनों तिमाहियों में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) रोजगार से ज्यादा तेजी से गिर गया।

नौकरियों की तलाश में लोग: दिसंबर के पहले तीन हफ्तों में ज्यादा लोगों ने नौकरियों की तलाश की। हालांकि इससे नवंबर की तुलना में कुल रोजगार में मामूली सुधार हुआ, लेकिन इससे पहले तीन हफ्तों में बेरोजगारी की दर में भी वृद्धि हुई। एक तरफ रोजगार की दर नवंबर में 37.4 प्रतिशत से मामूली रूप से बढ़कर तीन सप्ताह के औसत 37.5 प्रतिशत पर हो गई, तो दूसरी ओर बेरोजगारी की दर 6.5% से बढ़कर 9.5% हो गई।

...गई है। मंत्री प्रमोद जैन भाया कोरोना संक्रमित हो गए हैं।

करवाकर उन्हें होटल या ... कैंप में रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि यूके से जयपुर कोई सीधी उड़ान नहीं आती और दिल्ली या अन्य शहरों में उतरने वाले प्रदेश के यात्रियों की स्क्रीनिंग भी वहीं हो रही है। ऐसे में

किसानों के पैसों से बंटी चांदी : सात में से ज्यादातर कलक्टर मौन

पावभर चांदी का कलदार, सिर्फ एक कलक्टर लौटाने को तैयार

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. किसानों के पैसों से पाव-पाव भर चांदी के सिक्के घर बैठे लेने वाले कलक्टरों में से ज्यादातर इस 'उपहार' को अपना हक समझ बैठे हैं। पत्रिका ने बात की तो सिर्फ एक कलक्टर ने कहा कि मैं सिक्का लौटा दूंगा। बाकी 7 में से ज्यादातर का रवैया सिक्का लौटाने का नहीं दिखा। किसी ने कहा कि इसमें इश्यू क्या है? किसी का जवाब था कि सिक्का तो बैंक ने दिया है, उसी से बात करनी पड़ेगी।

सहकारिता सचिव व प्रशासक कुंजीलाल मीणा की अध्यक्षता में पिछले दिनों राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की आमसभा हुई थी।

पढ़ें **पावभर** @ पेज 09

40 लोगों को बांटी 10 किलो चांदी

जागी सरकार : सीएम और मंत्री ने मांगी रिपोर्ट

किसानों के पैसे से बंटी 7 कलक्टर को पाव-पाव चांदी

प्रकाशित खबर।

पत्रिका ने मामले का खुलासा किया तो सरकार की नींद उड़ी है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सहकारिता सचिव कुंजीलाल मीना से रिपोर्ट मांगी है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने भी लिखित में पूछा है कि चांदी किसके आदेश से और क्यों बांटी गई?

पत्रिका का सवाल | कलक्टरों के जवाब

एक ने भरी हामी

नन्नूमल पहाड़िया, तब सवाई माधोपुर और अब अलवर: गिफ्ट आया था, मैंने अब देखा है। सिक्का लौटा दूंगा।

दो अड़े

यूडी खान, झुंझुनूं: इसमें इश्यू क्या है? मैं पता करता हूं...। **पीयूष सामरिया,** दौसा: सिक्का बैंक ने दिया है, उनसे बात करनी पड़ेगी।

दो मौन

शिवप्रसाद नकाते, भीलवाड़ा: फोन रिसीव किया, बात नहीं की। **महावीर प्रसाद वर्मा,** श्रीगंगानगर: फोन नहीं उठाया।

हमें नहीं मिला

अविचल चतुर्वेदी, सीकर: वर्चुअल बैठक में लॉगइन तो किया लेकिन किसी कारण से बैठक में बैठा नहीं। मुझे कोई सिक्का नहीं मिला।

ये भूमिगत

इंद्रसिंह राव, तब बारां और अब एपीओ: घूस मामले में उलझने के बाद से राव 'भूमिगत' हैं।

गोपालपुरा बायपास पर हादसा

पुमार शर्मा कम्पफाउंजी व योगेंद्र यादव   में धरने पर बैठेंगे।

टाइगर रिजर्व प्रबंधन को लिखा था पत्र

एशिया की पहली मैकेनाइज्ड खान बंद, अरबों के हीरे दफन

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
03 . 07 patrika.com 2020

पन्ना. मध्यप्रदेश में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनएमडीसी) के मझगवां डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट से उत्खनन का कार्य बंद कर दिया गया है। इसी के साथ एशिया की पहली यांत्रिक (मैकेनाइज्ड) हीरा खदान होने का तगमा मध्यप्रदेश के हाथों से छिन गया है।

पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर ने बताया कि हीरा खदान संचालन के लिए जरूरी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ संबंधी अनुमति 31 दिसंबर को समाप्त हो गई है। इसी को लेकर हमने प्रबंधन को पत्र लिखा था कि अगर अनुमति देने का एक्सटेंशन नहीं हुआ है तो हीरा खदान का परिचालन बंद कर दिया जाए।

50 साल से है खदान

यह एनएमडीसी खदान 1968 से शुरू हुई थी। अब तक करीब 13 लाख कैरेट हीरों का उत्पादन किया जा चुका है। अभी भी करीब 8.5 लाख कैरेट हीरों का उत्पादन बाकी है। यदि खदान संचालन की अनुमति नहीं मिलती है तो अरबों रुपए के हीरे दफन रह जाएंगे।

कार्रवाई करने कहा है।

उभरेगी।

मध्यप्रदेश : कंधा तो दूर, मिट्टी भी नसीब नहीं

लावारिस शवों को कचरे के ढेर में दफना रहे निगम कर्मचारी

04-01-2020

नगर निगम प्रशासन का अमानवीय चेहरा

सतना @ पत्रिका. शहर में मिलने वाले लावारिस शवों को यहां कंधा तो दूर, मिट्टी तक नसीब नहीं हो रहे हैं। निगम कर्मचारी ऐसी लाशों को कचरे के ढेर में दफना कर अमानवीयता की हद पार कर रहे हैं। ऐसी ही अमानवीयता की एक तस्वीर रविवार को धवारी स्थित मुक्तिधाम में देखने को मिली। हुआ यूं कि नगर निगम का शव वाहन मुक्तिधाम पहुंचा। वाहन से दो कर्मचारी उतरे और पॉलिथीन में लिपटे शव को घसीटते हुए मुक्तिधाम के पीछे कचरे के ढेर पर ले गए। वहां पहले से खुदे लगभग डेढ़ फिट के गड्ढे में शव को रखकर ऊपर से कचरा भर दिया। शव को दफनाते हुए निगमकर्मियों को जिसने भी देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां मौजूद लोगों ने जब शव दफनाने पहुंचे निगम कर्मचारियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि धवारी मुक्तिधाम के पीछे एक साल से लावारिस लाशें दफनाई जा रही हैं।

श्वान नोंच रहे शव

लोगों ने बताया कि कर्मचारियों द्वारा शव दफनाने के बाद आवारा श्वान कचरे में दबाए गए शव को नोंचते हैं। कई बार इन शवों के अंग निकाल कर सड़क पर ले आते हैं। इससे स्थानीय लोगों में भय एवं निगम प्रशासन के प्रति आक्रोश पनप रहा है।

निगम प्रशासन ने मुक्तिधाम के पीछे कचरे के ढेर में एक फीट गहरे गड्ढे खोद दिए हैं। कर्मचारी उन्हीं गड्ढों में लावारिस शवों को दफना रहे हैं।

डिस्कॉम जेईएन के लिए बीस हजार रिश्वत लेते दलाल गिरफ्तार

13.07.20

जोधपुर. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर की विशेष विंग ने बाड़मेर की सिवाना तहसील के पादरू के पास खलवाड़ा का नाडा में फार्म हाउस पर जोधपुर डिस्कॉम के लिए बीस हजार रुपए रिश्वत लेते एक मध्यस्थ को गिरफ्तार किया। जबकि जेईएन फरार हो गया। ब्यूरो के उप महानिरीक्षक डॉ विष्णुकांत ने बताया कि पादरू गांव के पास खलवाड़ा का नाडा निवासी गणपतसिंह पुत्र रघुनाथसिंह की शिकायत पर मूलतः खांखी हाल पादरू गांव निवासी मध्यस्थ नारायणसिंह (40) पुत्र इन्द्रसिंह को बीस हजार रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। उसने गणपतसिंह के खलवाड़ा का नाडा गांव में फार्म हाउस से यह रिश्वत ली। उसके पकड़े में आते ही पादरू स्थित डिस्कॉम के जेईएन जितेन्द्र सैनी फरार हो गया।

एसीबी की बड़ी कार्रवाई : राज्य में ऐसा पहली बार, पुलिस-प्रशासन के अफसर दोनों हाथों से बटोर रहे थे घूस

दो एसडीएम गिरफ्तार, एसपी का दलाल भी धरा

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर . दौसा . भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बुधवार को भ्रष्टाचार के बड़े गठजोड़ का भंडाफोड़ किया है। यह गठजोड़ दौसा जिले में पकड़ा गया, जहां पुलिस और प्रशासन दोनों के अधिकारी मिलकर दोनों हाथों से घूस बटोर रहे थे। वहां हाईवे निर्माता कम्पनी से 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते दौसा उपखंड अधिकारी (एसडीएम) पुष्कर मित्तल को और इतनी ही राशि की घूस स्वीकार करते बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा को गिरफ्तार किया है। एसीबी ने दौसा के ही तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (अब एसडीआरएफ के एसपी) मनीष अग्रवाल के दलाल नीरज मीणा को भी गिरफ्तार किया। वह मनीष अग्रवाल के लिए कम्पनी से 38 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था। दलाल की गिरफ्तारी के बाद एसीबी ने दौसा से मनीष का पीछा किया। बार-बार टालमटोल के बीच एसीबी ने मनीष को जयपुर में आ पकड़ा और उनके दोनों मोबाइल जब्त कर लिए। साथ ही पाबन्द भी किया कि जब भी बुलाएं, एसीबी दफ्तर में हाजिर हों।

एसीबी के डीजी भगवानलाल सोनी ने बताया कि दौसा में हाईवे निर्माता कम्पनी के मालिक ने शिकायत की थी। कम्पनी का कहना था भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा देने की प्रक्रिया में देर की जा रही है।

घूसखोरी...ये 3 चेहरे आए सामने

पिंकी मीणा पहली बार और पुष्कर मित्तल दूसरी बार बने थे एसडीएम

दौसा एसडीएम मित्तल

घर बुलाकर लिए 5 लाख रुपए

पुष्कर मित्तल ने रिश्वत लेने के लिए कम्पनी के प्रतिनिधि को अपने घर पर ही बुला लिया। वहां 5 लाख रुपए लेते ही एसीबी ने उसे पकड़ लिया।

बांदीकुई एसडीएम मीणा

5 लाख रुपए लाइजनर को दे दो, उससे ले लूंगी

पिंकी मीणा ने 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जबकि कम्पनी ने 5 लाख रुपए देने के लिए कहा था। इस पर पिंकी मीणा ने कहा कि ये रुपए अपने लाइजनर को दे दो, मैं उससे ले लूंगी। इस पर एसीबी ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया।

दौसा. एसीबी की गिरफ्त में रिश्वत लेने के आरोपी एसडीएम पिंकी मीणा और पुष्कर मित्तल (कुर्सी पर बैठे)।

मनीष को पीछाकर जयपुर में रोका, दो मोबाइल जब्त, पूछताछ कर छोड़ा

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर . एसीबी ने दलाल नीरज मीणा को गिरफ्तार करने के बाद साक्ष्य जुटाने के लिए एसपी मनीष अग्रवाल की तलाश शुरू की। एसीबी के पास दलाल और कपनी प्रतिनिधियों के सपर्क के पर्याप्त सबूत हैं।

अब दलाल व मनीष अग्रवाल के बीच सपर्क के साक्ष्य तलाशने थे। इसके लिए मनीष अग्रवाल की लोकेशन पूछी तो वह दौसा में मिले। वहां टीम भेजी तो पता चला कि वह जयपुर के लिए रवाना हो गए। फिर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र सिंह की टीम ने उनकी निगरानी शुरू की। पहले उन्होंने खुद को वैशालीनगर में बताया। वहां पहुंचे तो कहा कि श्यामनगर थाने की ओर जा रहा हूं। एसीबी टीम श्यामनगर क्षेत्र में पहुंची तब मनीष अग्रवाल मिले। टीम ने मोबाइल मांगे तो उन्होंने मना कर दिया। आखिर उच्चाधिकारियों ने दखल के बाद उन्होंने मोबाइल दिए। उनके दोनों मोबाइल एसीबी ने जब्त कर लिए। अब इनकी पड़ताल कर भ्रष्टाचार संबंधी साक्ष्य जुटाए जाएंगे। मनीष अग्रवाल का तबादला गत सप्ताह आई सूची में दौसा से पुलिस मुख्यालय किया गया है। वह श्यामनगर क्षेत्र में किराए का मकान देख रहे थे।

दंग रह गई एसीबी

परिवादी 35 दिन पहले मिला था। उसकी बात सुनकर विश्वास नहीं हुआ। फिर पूरी कहानी सुनी। परिवादी बोला, हम पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को रिश्वत की सामान्य राशि देते आए हैं लेकिन अधिकारियों की डिमांड अचानक बढ़ गई, जो पूरी करना संभव नहीं है।

बी.एल. सोनी,
डीजी (एसीबी)

तत्कालीन एसपी मनीष अग्रवाल के दलाल ने

एसीबी के डीजी ने बताया कि इसी कम्पनी के मालिक से तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल के नाम से दलाल नीरज मीणा 4 लाख रुपए मासिक बंधी मांग रहा था। इसके अलावा कम्पनी के खिलाफ दर्ज होने वाले मामलों के निस्तारण और वाहनों

उसने कुल 38 लाख रुपए मांगे। रिश्वत की राशि लेने से पहले ही अग्रवाल का तबादला हो गया। तस्दीक में डिमांड की पुष्टि होने पर एसीबी ने दोनों एसडीएम के साथ दलाल नीरज मीणा को भी गिरफ्तार कर लिया। साथ ही मनीष अग्रवाल के दोनों मोबाइल फोन जब्त कर लिए।

आइपीएस मनीष अग्रवाल

घूसखोरी: खुद रेंज आइजी ने भी की थी डीजी से शिकायत, एसपी ने नहीं दिया ध्यान

सीएम तक शिकायत, फिर भी एक इंच नहीं डिगे एसपी मनीष

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर . भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के घेरे में आए एसपी मनीष अग्रवाल ने घूसखोरी के लिए जिले में एक तरह से 'आतंक' मचा रखा था। मनीष के खिलाफ नामजद शिकायतें रेंज आइजी और डीजी से होते हुए मुख्यमंत्री तक पहुंचीं लेकिन मनीष का दुस्साहस एक इंच भी नहीं डिगा। वह घूसखोरी पर न सिर्फ कायम रहे बल्कि उनका लालच बढ़ता गया।

आइपीएस मनीष अग्रवाल

पत्रिका में प्रकाशित

दो एसडीएम गिरफ्तार, एसपी का दलाल भी धरा

एसपी ने मांगी 10 लाख रुपए की बंधी, दलाल ने 4 लाख में तय किया सौदा

सीएम को दी शिकायत में कम्पनी ने यह कहा

सीएम को दी शिकायत में कम्पनी के प्रतिनिधि ने बताया था कि दस्तावेज पूरे होने के बावजूद पुलिस निर्माण कार्य में जुटे वाहनों को घंटों रोकती है। चालान भरती है। इसके बाद भी वाहन नहीं छोड़ती। वाहन रोकने पर थानों में सम्पर्क करने पर जवाब मिलता है, एसपी साहब से बात कर लो। कम्पनी ने शिकायत में कहा, सम्भवत: एसपी के अप्रत्यक्ष निर्देश हैं कि इतना परेशान करो, कम्पनी दबाव में आ जाए और उनसे मिले।

तीसरा एसडीएम कौन, जिसने घूस के लिए किया फोन?

एसीबी की टीम 2 दिन पहले जब एसडीएम पुष्कर मित्तल को गिरफ्तार कर रही थी, तब दौसा के एक अन्य एसडीएम ने कम्पनी के प्रतिनिधि को फोन किया था। वह पूर्व में हुई 'बातचीत' को आगे बढ़ाने के लिए कह रहा था। कम्पनी जो हाईवे बना रही है, वह इस एसडीएम के क्षेत्र से भी गुजर रहा है। एसीबी टीम तब एसडीएम पिंकी मीणा को पकड़ने की तैयारी में थी इसलिए तीसरे आरएएस अधिकारी की खिलाफ कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई।

घूसखोरी से परेशान हुई हाईवे निर्माता कम्पनी: हाईवे निर्माता कम्पनी ने घूसखोरी से परेशान होकर पहले रेंज आइजी और पुलिस महानिदेशक से शिकायत की। पढ़ें **तीसरा** @ पेज 12

आरएएस पिंकी मीणा और पुष्कर मित्तल निलंबित

कार्मिक विभाग ने दो दिन पहले गिरफ्तार आरएएस पिंकी मीणा और पुष्कर मित्तल को शुक्रवार को निलंबित कर दिया। दोनों अधिकारियों का मुख्यालय कार्मिक विभाग रहेगा। विभाग की ओर से जारी निलंबन आदेश में कहा है कि दोनों निलंबित अधिकारी कार्मिक विभाग में उपस्थिति दर्ज करेंगे और बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

निर्माण सामग्री करा देते थे बर्बाद: पुलिस ने जब-जब वाहन रोके, कम्पनी ने चालान भर दिया। ऐसे में घूसखोरी के लिए पुलिस ने दूसरा रास्ता अपनाया। कम्पनी को आर्थिक फटका लगाने के लिए पुलिस चालान के बाद भी डम्पर नह[ीं] छोड़ती थी। डम्परों में बिटुमन ग्रीट मिक्स भरा होता था, जो तय समय बाद खराब हो जाता था। परेशान होकर कम्पनी ने आखिर उच्च स्त[र] पर शिकायत करना शुरू किया।

20 हजार कमीशन लेते सूचना सहायक गिरफ्तार

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जोधपुर. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की विशेष विंग ने शेरगढ़ में ई-मित्र संचालक से बीस हजार रुपए रिश्वत लेते सूचना, तकनीकी व संचार विभाग के सूचना सहायक व एक अन्य व्यक्ति को मंगलवार को गिरफ्तार किया। उसने ई-मित्र सेवा केन्द्र पर आधार कार्ड बनवाने के बदले बतौर कमीशन डरा-धमकाकर यह रिश्वत लेकर एसीबी से बचने के लिए निजी व्यक्ति की जेब में छुपाई थी।

एसीबी के उप महानिरीक्षक डॉ विष्णुकांत ने बताया कि शेरगढ़ में तहसील कार्यालय परिसर स्थित ई-मित्र संचालक हरीश पुत्र चैनाराम की शिकायत पर सूचना, तकनीकी व संचार विभाग के सूचना सहायक भालू राजवा निवासी रविन्द्र कुमार (32) पुत्र

मूलराम लखारा व देवीगढ़ निवासी निजी व्यक्ति रामूराम (33) पुत्र लालाराम मेघवाल को बीस हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी ई-मित्र सेवा केन्द्र पर अधिकारी है।

सूचना सहायक रविन्द्र ने एसडीएम कार्यालय परिसर स्थित ई-मित्र सेवा केन्द्र में परिवादी से बीस हजार रुपए रिश्वत ली। फिर एसीबी से बचने के लिए वह एक अन्य कमरे में गया, जहां मौजूद रामूराम मेघवाल की जेब में रिश्वत राशि छुपा दी। तभी विशेष विंग के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ दुर्गसिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में एसीबी ने दबिश देकर सूचना सहायक रविन्द्र के साथ रंगे हाथ होने से रामूराम मेघवाल को भी गिरफ्तार किया। दोनों को शेरगढ़ थाने ले जाकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

हर आधार कार्ड बनने की जानकारी पर नजर

एसीबी का कहना है कि सूचना, तकनीकी व संचार विभाग के सूचना सहायक को ई-मित्र केन्द्रों से बनने वाले प्रत्येक आधार कार्ड की जानकारी रहती है। ई-मित्र केन्द्रों से कितने आधार कार्ड बनते हैं वो उनका पूर्ण ब्यौरा सूचना सहायक के पास होता है। इसीलिए आरोपी हर आधार कार्ड के हिसाब से कमीशन की मांग कर रहा था।

प्रति आधार कार्ड साठ प्रतिशत कमीशन

एएसपी डॉ दुर्गसिंह राजपुरोहित ने बताया कि शेरगढ़ एसडीएम कार्यालय परिसर में दो-तीन ई-मित्र केन्द्र हैं, जहां आधार कार्ड सेवा केन्द्र भी संचालित होता है। सूचना सहायक प्रति आधार कार्ड पर साठ प्रतिशत कमीशन की मांग कर रहा था। शेरगढ़ के ई-मित्र संचालकों ने कमीशन देने से इनकार किया तो सूचना सहायक ने आधार कार्ड बनाने वाली मशीनें हटाने की धमकियां दी थी। उसने ई-मित्र संचालक से पिछले दो महीने के तेइस हजार रुपए मांगे। ई-मित्र संचालक ने एसीबी के टोल फ्री नम्बर 1064 पर शिकायत की। ब्यूरो ने सोमवार को गोपनीय सत्यापन कराया तो सूचना सहायक 23 हजार रुपए लेना तय किया और उसने दो हजार रुपए रिश्वत ले भी लिए। शेष बीस हजार रुपए मंगलवार को लेना तय किया गया था।

संधू सहित 3 अफसरों के खिलाफ केस वापस लेने के लिए कोर्ट में अर्जी

एकल पट्टा प्रकरण में तीन अफसरों को क्लीन चिट

ओम प्रकाश शर्मा
patrika.com

अगली सुनवाई 12 फरवरी को

जयपुर . जेडीए के बहुचर्चित एकल पट्टा प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने जिन 3 अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप साबित माने, उन्हें सरकार ने 'अभयदान' दे दिया है। सरकार ने तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव जीएस संधू सहित 3 अधिकारियों के खिलाफ केस वापस लेने के लिए मंगलवार को कोर्ट में अर्जी पेश की है। कोर्ट 12 फरवरी को सुनवाई करेगा।

एसीबी ने गणपति कंस्ट्रक्शन कंपनी को एकल पट्टा जारी करने में हुई धांधली की शिकायत पर कंपनी के प्रोपराइटर शैलेन्द्र गर्ग, यूडीएच के पूर्व सचिव जीएस संधू, जेडीए जोन-10 के तत्कालीन उपायुक्त ओंकारमल सैनी, निष्काम दिवाकर और गृह निर्माण सहकारी समिति के पदाधिकारी अनिल अग्रवाल व विजय मेहता को गिरफ्तार किया था। 2016 में इनके खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। एसीबी ने माना था कि अधिकारियों ने पट्टा नियम विरुद्ध जारी किया है। एसीबी की चार्जशीट के तथ्य के आधार पर कोर्ट ने इनके खिलाफ प्रसंज्ञान भी ले लिया था।

जीएस संधू

निष्काम दिवाकर

ओंकारमल सैनी

धारीवाल व मीणा को दी थी क्लीन चिट

मामले में नगरीय विकास मंत्री शान्ति धारीवाल व तत्कालीन यूडीएच उप सचिव एनएल मीणा (वर्तमान गृह सचिव) भी आरोपी थे। राज्य में गहलोत सरकार बनने के बाद एसीबी ने दोनों को क्लीन चिट दे दी थी। एसीबी की ओर से अदालत में पेश प्रगति रिपोर्ट में तब कहा गया था कि इनके विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र में लिप्तता के सबूत सामने नहीं आए हैं।

सरकार ने लिया यू-टर्न

मामले में राज्य सरकार ने यू-टर्न लिया है। सरकार ने माना है कि आपराधिक षड्यंत्र में अफसर लिप्त नहीं थे। यह फाइल विभागीय प्रक्रिया के तहत निस्तारित की गई थी। राज्य सरकार ने यह निर्णय एक जांच रिपोर्ट के आधार पर लिया है।

सरकारी अफसरों पर 'मेहरबानी'

सरकार ने अदालत में लम्बित जांच में मात्र सरकारी अधिकारी तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव जीएस संधू, आरएएस अधिकारी निष्काम दिवाकर व ओंकारमल सैनी के खिलाफ केस वापस लेने के लिए एसीबी मामलात की विशेष अदालत क्रम 1 में अर्जी दी है। अन्य आरोपी शैलेन्द्र गर्ग, विजय मेहता व अनिल अग्रवाल के खिलाफ मामला विधिवत जारी रहेगा।

भ्रष्टाचार का गठजोड़

दूसरी कम्पनी से एसपी ने दलाल के जरिए लिए थे 33 लाख रुपए!

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर . दौसा में भ्रष्टाचार के गठजोड़ में बुधवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने नया खुलासा किया। शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर एसीबी ने कोर्ट में कहा कि एसपी मनीष अग्रवाल ने हाईवे निर्माण में जुटी एक अन्य कम्पनी से दलाल के जरिए 33 लाख रुपए लिए थे। एसीबी ने इसी सन्दर्भ में पड़ताल के लिए दलाल नीरज मीणा को रिमांड पर मांगा। अदालत ने उसकी रिमांड अवधि 22 जनवरी तक बढ़ा दी।

एसपी के दलाल नीरज मीणा को एसीबी ने 13 जनवरी को गिरफ्तार किया था। रिमांड अवधि पूरी होने पर बुधवार को उसे कोर्ट में पेश किया। वहां एसीबी ने बताया कि मामले में हाईवे बनाने वाली कम्पनी ने शिकायत की थी। एसपी के नाम पर कम्पनी से रिश्वत मांगी जा रही थी।

शिकायतकर्ता ने बयान में बताया है कि हाईवे निर्माण में जुटी दूसरी कम्पनी से एसीपी के नाम 33 लाख रुपए लिए गए।

पढ़ें **दूसरी** @ पेज 04

संवेदनहीनता : आरोपी पटवारी निलंबित

बच्चियों का क्रियाकर्म करने को मिली राशि में से लिया कमीशन

पत्रिका ब्यूरो 22-01-21
patrika.com

कोरबा. छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में बरीडीह गांव में खेलते समय मिट्टी के टीले के नीचे दबकर पिछले साल 1 नवंबर को दो बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई थी। जिला प्रशासन ने परिजनों को क्रियाकर्म के लिए 10-10 हजार रुपए स्वीकृत किए थे। ये राशि मिलने से पहले ही पटवारी ने दबाव बनाकर बच्चियों के परिजनों से 25-25 सौ रुपए वसूल लिए। प्रशासन के पास जब शिकायत पहुंची तो एसडीएम ने तत्काल जांच कराई। शिकायत सही पाए जाने पर एसडीएम ने पटवारी दामोदर तिवारी को सस्पेंड कर दिया है। आरोपी जिला पटवारी संघ का जिलाध्यक्ष भी है। रामपुर विधायक ननकीराम कंवर की लिखित शिकायत के आधार पर प्रशासन ने जांच शुरू की गई थी।

जनवरी-मार्च 2017 में भूमिगत हो गए, विवि के डीन, एचओडी और असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल

एसीबी के डर से जेएनवीयू के 39 शिक्षकों ने 3 महीने का बंक मारा

एक्सक्लूसिव

अब पीएल और मेडिकल लीव से बंक को एडजस्ट करने की तैयारी

गजेन्द्र सिंह दहिया
patrika.com

जोधपुर. जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय (जेएनवीयू) के 39 शिक्षकों ने जनवरी 2017 से लेकर मार्च 2017 के दौरान करीब तीन महीने का बंक मारा। इसमें कुछ संकायों के तत्कालीन डीन, विभागाध्यक्ष और असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की कार्रवाई से बचने के लिए ये शिक्षक भूमिगत हो गए थे। विवि प्रशासन अब इन शिक्षकों के 'बंक' को पीएल और मेडिकल लीव से एडजस्ट करने की कोशिश में लगा है। विवि की 3 फरवरी को होने वाली सिण्डीकेट बैठक में यह मुद्दा रखा जाएगा।

विवि में वर्ष 2012-13 में हुई शिक्षक भर्ती में भारी अनियमितता सामने आने के बाद एसीबी ने मामला दर्ज किया था। जनवरी 2017 में एसीबी ने मामले से जुड़े 6 लोगों की गिरफ्तारी कर कैंपस में छापे मारे। एक शिक्षक को नया परिसर से सीधा ही पकड़ लिया। एसीबी के डर से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल 60 से अधिक शिक्षक भाग गए। इसमें 39 शिक्षकों ने दो महीने तक विवि में कदम नहीं रखा। वे सीधा अप्रेल 2017 में ही नौकरी पर पहुंचे।

3 साल बाद बनाई कमेटी

तत्कालीन कुलपति डॉ आरपी सिंह ने इन शिक्षकों पर कोई कार्यवाई नहीं की। इसके बाद कुलपति बने प्रो. गुलाब सिंह चौहान को भी मामले की जानकारी नहीं मिली। हाल ही में एक आरटीआई में विवि प्रशासन से इस संबंध में सवाल-जवाब पूछने पर विवि ने नवम्बर 2020 में तीन शिक्षकों प्रो. संगीता लुंकड़, प्रो. केआर गेनवा और प्रो. केआर पटेल की तीन सदस्यीय कमेटी बना दी। कमेटी ने सर्वसम्मति से इन 39 शिक्षकों के रिकॉर्ड में उपलब्ध पीएल/मेडिकल लीव से अवकाश एडजस्ट करने की अनुशंषा की है। अब 3 फरवरी को होने वाली सिण्डीकेट बैठक में इस आइटम का रखा गया है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में तीन माह के बंक को बहाल करने की तैयारी है।

न नोटिस, न सेवा अवरोध

विवि के हाजिरी रजिस्टर में इनके हस्ताक्षर खाली हैं। विवि प्रशासन ने अब तक किसी भी शिक्षक को नोटिस देकर विवि से गायब रहने का कारण नहीं पूछा और न ही उस समय तक विवि की सेवा में अवरोध माना है। बंक मारने वाले कुछ शिक्षक तो रिटायर भी हो गए और उनके पेंशन-ग्रेचुएटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

'मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकती। हमने रिपोर्ट बंद लिफाफे में दी है।'

प्रो संगीता लुंकड़, कमेटी समन्वयक, जेएनवीयू जोधपुर

तेज रफ्तार कार नाले मे

प्रदेश में कुल स्क्रीनिंग	5683441
कुल पॉजिटिव	316081
कुल मौतें	2756

जिला	कुल पॉजिटिव	एक्टिव केस	मौतें
जयपुर	58642	794	513
जोधपुर	44627	309	301
अलवर	21704	100	78
बीकानेर	19045	21	167
कोटा	19471	490	169
अजमेर	16932	201	221
उदयपुर	11714	369	113
पाली	10970	53	109
भीलवाड़ा	10154	202	40
नागौर	10091	321	95
भरतपुर	9061	21	120
सीकर	9044	66	100
श्रीगंगानगर	6712	87	42
जालौर	5607	25	52
बाड़मेर	5005	18	53

Digital Top 5
ये खबरें भी जरूरी

1. **जयपुर** : *येव सीरीज लांच के चलते गधों की लगी लाटरी, खाए गुलाब जामुन* bit.ly/3iFIuPG
2. **कोटा:** जेईई मेन 2021: 9 लाख स्टूडेंट्स ने किया आवेदन bit.ly/3iulYbe
3. **उदयपुर:** जनता ने बंटी बन्ना को दी अंतिम विदाई, बेटे विंध्यराज सिंह ने दी मुखाग्नि bit.ly/395J7yw
4. **जेसलमेर:** सरपंचों के साथ राज्य सरकार ने अन्याय किया : शेखावत bit.ly/39U34Yj
5. **बांसवाड़ा:** सूरत हादसे में दिवंगत मजदूरों की अंत्येष्टि में जुटे सैकड़ों लोग bit.ly/2Y0diAZ

बाबू ने तोड़ा दम

चित्तौड़गढ़ @ पत्रिका. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिपिक सुरेश शर्मा की गुरुवार को उदयपुर के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। चिकित्सा विभाग ने मौत का कारण कर्मचारी को गंभीर रोग होना बताया है। वह किडनी की बीमारी से पीड़ित थे। मृतक का गत 16 जनवरी को ही कोरोना का वैक्सीनेशन चित्तौड़गढ़

प्रशासन ने खोली 'पुलिस' की पोल, थाने के पीछे से बजरी की तस्करी

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

धौलपुर. जिन पर नियमों की पालना की जिम्मेदारी है, वे ही कानून तोड़ने लगें तो फिर जनता का क्या होगा। धौलपुर में गुरुवार को कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। प्रशासन ने रणनीति बना कर धौलपुर शहर के सदर थाने के पीछे से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित चंबल के स्टॉक को जब्त किया है। थाने के पीछे से रात आठ बजे से यहां से बजरी को ट्रकों में भरकर पड़ोसी जिलों में भेजा जाना सामने आया है। प्रशासन ने कार्रवाई से पहले जिला पुलिस को इस बात की भनक तक नहीं लगने दी। प्रशासन ने औचक कार्रवाई की।

जिला कलक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि शहर से गुजरने वाले चंबल बजरी से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के आवागमन पर खनन विभाग, राजस्व विभाग व वन विभाग की टीम को निगरानी रखने के निर्देश दिए गए थे। इस दौरान बजरी के ट्रैक्टरों के चालकों द्वारा सदर थाने के पास स्टॉक रखने की जानकारी मिली। सात-आठ दिन की निगरानी के बाद तीनों विभागों की टीम बुधवार रात मौके पर पहुंची। इस दौरान टीम ने यहां से एक डंपर व ट्रैक्टर को जब्त कर लिया।

धौलपुर सदर थाने के पास प्रशासन की टीम द्वारा जप्त किया गया अवैध बजरी का भंडार।

जब्त किया गया लोडर।

बजरी से भरा डंपर जब्त करती टीम।

ये उठ रहे सवाल

1. काफी समय से जब अवैध कारोबार चल रहा है तो पुलिस को सूचना क्यों नहीं
2. थाने से पास चल रहे इतने बड़े खेल की भनक पुलिस को क्यों नहीं लगी।
3. आखिर किस की देखरेख में तस्करी का खेल चल है।

यहां, माफिया का एसडीएम पर हमला

सवाई माधोपुर. चौथ थाना क्षेत्र में अवैध बजरी खनन व परिवहन के कारोबार से जुड़े लोगों ने गुरुवार को दुस्साहस दिखाते हुए कार्रवाई दल पर हमला कर दिया। इससे एसडीएम बद्रीनारायण मीणा घायल हो गए। एसडीएम गुरुवार सुबह पुलिस जाब्ते के साथ जस्ताना के पास दोराला गए थे। वहां पर सौ से अधिक ट्रैक्टर-ट्रॉलियां भरी हुई मिली। एसडीएम की टीम ने जैसे ही कार्रवाई करना शुरू की। कार्रवाई से भड़के माफिया ने एसडीएम पर हमला कर दिया। हमले में उनके हाथ व कंधे पर चोटें आई हैं। देर रात तक 15 से अधिक बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली व एक जेसीबी जब्त की गई।

युवती बोली थी, 'सर मुझे परेशान करते हैं'

भरतपुर/कुम्हेर. सरसई गांव के एक खेत में तीन दिन पहले मिले युवती के शव की शिनाख्त बुधवार रात हो गई। शव लेकर एम्बुलेंस भरतपुर पहुंचने पर परिजन और अन्य लोगों ने उसे शहर के कन्नी गुर्जर चौराहे पर रोक लिया और हंगामा कर दिया। मृतका के परिजनों ने बुधवार को मथुरा गेट थाने पहुंच कर युवती के मंगलवार रात से लापता होने की शिकायत करते हुए गुमशुदगी दर्ज कराई थी। परिजनों ने एक निजी स्कूल के शिक्षक और उसके कुछ साथियों पर शक जताया है। मृतका के पिता कासिम ने बिलखते कहा कि उसकी लड़की ने क्या बिगाड़ा था, जो उसकी इस तरह हत्या कर दी। जब वह कक्षा 10 में थी तो यह शिक्षक ही उसे परेशान करता था। बेटी ने उसे बताया भी था, लेकिन लोग कहां समझते हैं। इज्जत के डर से चुप हो गए।

सीकर: पति को बांधक की थी हत्या, मामा को भी दस साल की सजा

10 साल की बेटी की गवाही से मां को मिला आजीवन कारावास

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

सीकर. 10 साल की मासूम बेटी ने अपनी मां को आजीवन और मामा को दस साल के कठोर कारावास तक पहुंचा दिया। मामला सीकर जिले के पिपराली क्षेत्र के देवलानाड़ा का है। पति को बांधकर हत्या की आरोपी महिला और उसके भाई को कोर्ट ने यह सजा सुनाई है।

सेशन न्यायाधीश ज्ञानप्रकाश गुप्ता ने फैसला सुनाया कि कन्हैयालाल उर्फ राजू गुर्जर की हत्या के आरोप में पत्नी रेणुदेवी को आजीवन कारावास व साले कुलदीप को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मृतक की पुत्री हर्षिता को दो लाख रुपए दिलाए जाने के आदेश सुनाए। लोक अभियोजक किशोर कुमार सैनी ने बताया कि 18 जून 2017 को तेजाराम गुर्जर ने दादिया थाने में मामला दर्ज कराया था। उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि उसका बेटा कन्हैयालाल पैतृक भूमि देवलानाडा में मकान बना कर पत्नी रेणु व बच्चों के साथ रहता है। बेटे की पत्नी रेणु ने फोन कर कहा कि उसने व भाई ने मिलकर आपके बेटे को मार दिया है। आकर संभाल लो। वह तुरंत सीकर से खेत में आया तो उसका बेटा मकान में मृत मिला। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए दोनों भाई-बहन को गिरफ्तार कर लिया था।

बेटी बोली: मम्मी व मामा ने पापा को मारा

हर्षिता ने कहा कि पापा दुकान पर बैठे थे और शराब पी रखी थी। मम्मी मारपीट करते हुए पापा को ले गई और कमरे में बंद कर दिया। मम्मी ने आवाज लगाकर मामा को बुला लिया और कहा कि आज इसका इलाज करती हूं। मम्मी ने रस्सी लेकर पापा के हाथ-पैर बांध दिए। उसने खिड़की से देखा कि मामा व मम्मी लकड़ियों से मारपीट कर रहे है। कमरे में खून भी फैला था। पापा अंदर से चिल्ला रहे थे। तभी मम्मी गुस्से में दांतला लेकर गई और मार दिया।

5 क्विंटल डोडा पोस्त के साथ दो गिरफ्तार

बाड़मेर @ पत्रिका. बालोतरा क्षेत्र के मूलजी की ढाणी में गुरुवार को पाली के नामी तस्कर को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम पर तस्कर ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार कर करीब पांच क्विंटल अवैध डोडा पोस्त, कार, दो पिस्टल व कारतूस बरामद किए।

पुलिस ने बताया कि कुख्यात तस्कर व वांछित आरोपी जामाराम उर्फजगदीश देवासी के छिपे होने के स्थान की जानकारी ली गई। इस पर ढाणी की घेराबंदी कर दबिश दी गई। पुलिस के पहुंचने की भनक लगते ही कुख्यात अपराधी जामाराम व उसका साथी करनाराम ने भागने का प्रयास किया और तीन फायर किए। इस पर पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई में दो फायर कर दोनों आरोपियों को दबोच लिया।

पत्रिका जोधपुर

राजस्थान पत्रिका
जोधपुर, शनिवार, 30 जनवरी, 2021

मंडोर उद्यान में मारवाड़ के लोकदेवता-वीरों की 16 प्रतिमाएं नए स्वरूप में

मंडोर में 70 लाख खर्च होने के बाद भी देवताओं की साळ का कार्य अधूरा

पत्रिका लाइव रिपोर्ट

मंडोर गार्डन स्थित देवताओं की साल

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जोधपुर. ऐतिहासिक मंडोर उद्यान में स्थित देवताओं की साळ में मारवाड़ के वीरों, लोकदेवता और विभिन्न देवी देवताओं की विशालकाय प्रतिमाओं की मरम्मत व जीर्णोद्धार का काम अब भी अधूरा पड़ा है। राज्य सरकार ने इसके लिए 70 लाख रुपए जारी किए थे। इससे देवताओं की साळ के जर्जर छज्जे, सुरक्षा दीवार और प्रतिमाओं को तो नया स्वरूप प्रदान कर दिया गया है, लेकिन साळ में लाइटें और पारदर्शी कांच लगाने का कार्य अब भी पूरा नहीं हो सका है। सूत्रों के अनुसार पुरातत्व विभाग के जोधपुर वृत्त अधिकारी सेवानिवृत्त हो गए हैं तो मंडोर संग्रहालय के प्रभारी को पाली का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया गया है। ऐसे में काम की मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है।

हड़बूजी की प्रतिमा

पाबूजी की प्रतिमा

लोकदेवता बाबा रामदेव की प्रतिमा

गोगाजी की प्रतिमा

ये प्रतिमाएं हैं आकर्षण का केंद्र

देवताओं की साल में राठौड़ों की इष्ट देवी और परिहारों (ईंदों) की कुलदेवी मां चामुण्डा, महिषासुर मर्दिनी, गुंसाई सम्प्रदाय के महात्मा गुंसाईजी, रावल मल्लीनाथ, पाबूजी राठौड़, लोकदेवता बाबा रामदेव, हड़बूजी, मेहाजी, गोगाजी, ब्रह्माजी, सूर्यदेव, रामचंद्र, कृष्ण, महादेव, जलंधरनाथजी व गणेश आदि प्रतिमाएं आकर्षण का बनी हुई है।

उखड़ गई थी प्रतिमाएं

देवताओं और वीरों की प्रतिमाएं सीलन के कारण जगह जगह से उखड़ गई थी। जीर्णोद्धार के दौरान यथा स्थिति का प्रयास किया गया लेकिन मूर्तियों के स्वरूप में काफी बदलाव हुआ है। जोधपुर के महाराजा अजीतसिंह और महाराजा अभयसिंह के शासनकाल में सन 1707 से 1749 के मध्य निर्मित मूर्तियों में 7 देवताओं और 9 मारवाड़ के वीर पुरूषों की प्रतिमाएं शामिल है। करीब पंद्रह फीट ऊंची मूर्तियां मारवाड़वासियों की श्रद्धा का केन्द्र भी है।

अभी काम बाकी

देवताओं की साळ परिसर में पक्षियों के प्रवेश और मिट्टी को रोकने के लिए 15 एमएम का कांच तथा लाइटें लगाने का कार्य बाकी है। विभाग के जोधपुर वृत्त अधीक्षक सेवानिवृत्त होने के कारण काम शेष रह गया, जिसे जल्द ही पूरा किया जाएगा।

महेन्द्र कुमावत,
परिरक्षक, मंडोर पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग

सारण का खेड़ा में शराब दुखांतिका : आबकारी विभाग ने दिया जांच रिपोर्ट का हवाला 01-02-21

दावा : जांच में मिथाइल एल्कोहल नहीं मिला सवाल : फिर शराब पीने के बाद 4 मौतें कैसे

पांच जने अभी भी अस्पताल में भर्ती

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

भीलवाड़ा. आबकारी विभाग का दावा है कि माण्डलगढ़ थाना क्षेत्र के सारण का खेड़ा में चार जनों की मौत जिस जहरीली शराब के पीने से हुई, उसके नमूने की जयपुर के लैब में हुई जांच में मिथाइल एल्कोहल की मात्रा नहीं मिली है। मिथाइल एल्कोहल नहीं पाए जाने पर शराब जहरीली नहीं मानी जाती। हालांकि लैब ने रिपोर्ट में टिप्पणी की कि इस हथकढ़ में किसी विषाक्त पदार्थ या सेडेटिव ड्रग की उपस्थिति हो सकती है। वह जांच में पकड़ नहीं में नहीं आई। ऐसे में सवाल उठता है कि यह शराब जहरीली क्यों हो गई थी, क्योंकि इसके सेवन के बाद नौं जनों की तबीयत बिगड़ी और कुछ ही घंटों में उनमें से चार जनों की मौत हो गई। पांच जने अभी भी भीलवाड़ा अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस का कहना है कि शराब के जहरीली होने के कारणों की जांच के लिए अब मृतकों के विसरा रिपोर्ट का इंतजार है।

गौरतलब है कि 28 जनवरी की रात जहरीली शराब पीने से सारण का खेड़ा में दलेल सिंह, सरदार भाट,सत्तूड़ी पत्नी पप्पू व हजारी पुत्र कालू बैरवा की मौत हो गई थी। इन्होंने गांव के गुल्ला से हथकड़ शराब खरीदी थी। गुल्ला ने भी यह शराब पी थी। वह भी बीमार होकर अस्पताल में भर्ती है। मांडलगढ़ पुलिस ने मौके से हथकढ़ के सैम्पल लेकर जांच के लिए आबकारी प्रयोगशाला जयपुर भेजा था।

आबकारी दस्ते ने रविवार को हथकड़ में काम ली जा रही वॉश नष्ट की। वहीं मंत्री कुशलक्षेम पूछते हुए।

वॉश नष्ट, 14 सुलगती भट्टी ध्वस्त

अवैध शराब के खिलाफ आबकारी व पुलिस का अभियान रविवार को भी जारी रहा। जिलेभर में हथकढ़ ठिकानों पर दबिश दी गई। इस दौरान विभिन्न स्थानों से सात हजार लीटर वॉश नष्ट करके 14 सुलगती भट्टियों को ध्वस्त किया गया। अस्सी लीटर हथकढ़ और अन्य अवैध शराब बरामद किया गया। आबकारी निरोधक के उपायुक्त राजेन्द्र पारीक के नेतृत्व में पारोली, माण्डलगढ़ एवं बिजौलियां थाना क्षेत्र में पुलिस व आबकारी विभाग ने दबिश दी।

आबकारी अधिकारियों का कहना है कि चारों मृतकों का पोस्टमार्टम कराया गया था। शवों के विसरा जांच से ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकता है। अधिकारियों ने आशंका जताई कि जिस ड्रम या पात्र में शराब भरी, उसमें पहले कीटनाशक इस्तेमाल हुआ हो या किसी ने रंजिशवश शराब में जहर मिला दिया हो।

मंत्री ने पूछी कुशलक्षेम

जनजाति मंत्री अर्जुनलाल बामणिया रविवार को भीलवाड़ा आए। पहले एमजी अस्पताल गए व जहरीली शराब पीने से भर्ती पांच जनों की कुशलक्षेम पूछी। उन्होंने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. अरुण गौड़ से उनकी हालत और इलाज की जानकारी ली। फिर सारण का खेड़ा गए, जहां मृतकों के घर जाकर परिजनों को ढांढस बंधाया।

पुलिस की ओर से जांच को भेजे सैम्पल में मिथाइल एल्कोहल नहीं मिला है। हो सकता है कि जिस ड्रम या पात्र में शराब रखी, उसमें पहले से पेस्टीसाइड का उपयोग हुआ हो। पुलिस ने विसरा जांच को भेजा है। विसरा रिपोर्ट से मौत के कारण सामने आएंगे।

- राजेंद्र पारीक, उपायुक्त आबकारी निरोधक दल अजमेर जोन

सैम्पल जांच में मिथाइल एल्कोहल नहीं पाया गया है। इस बारे में विशेषज्ञों से राय ली तो सामने आया कि ज्यादा समय तक पदार्थ रखने पर हो सकता है कि उसके अंश समाप्त हो गए हों। अब विसरा रिपोर्ट से स्थिति साफ होगी।

-गजेन्द्र सिंह जोधा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा

चित्तौड़गढ़: 18 से अधिक राज्यों के फर्जी तरीके बनाए ड्राइविंग लाइसेंस व आरसी

आठ साल से चल रहा था फर्जी आरटीओ, छह हजार से ज्यादा लाइसेंस जारी

चित्तौड़गढ़ @ पत्रिका . जिले के मंगलवाड़ कस्बे में करीब 8 साल से फर्जी आरटीओ कार्यालय खोल लाइसेंस बनाने का गोरखधंधा चलाया जा रहा था। इसमें लिप्त लोगों ने 18 से अधिक राज्यों के करीब 6000 से अधिक फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस भी जारी कर दिए। अब पुलिस को पता चला तो ऑपरेशन चलाकर रविवार को मंगलवाड़ थानान्तर्गत सांगरिया निवासी और हाल

पुलिस गिरफ्त में आरोपी।

मंगलवाड़ चौराहा निवासी देवेन्द्रदास उर्फ देवराज व मंगलवाड़ चौराहा निवासी ऋषि अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से कई सामग्री व उपकरण जब्त किए हैं। आरोपी इस अवैध काम में इतने पारंगत हो गए थे कि फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी मात्र पन्द्रह-बीस मिनट में तैयार कर देते थे। इसके बदले वे एक हजार से पांच हजार रुपए तक की वसूली करते थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ षड्यंत्रपूर्वक धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है।

पढ़ें **आठ** @ पेज 07

पुलिस के लोगो का भी इस्तेमाल

आरोपी पुलिस का लोगो इस्तेमाल कर सीएलजी सदस्यों के कार्ड भी बनाते थे। इस तरह के कार्ड भी पुलिस ने जब्त किए हैं। आरोपी देवेन्द्र बैरागी ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह फर्जी तरीके से लेपटॉप व प्रिंटर की सहायता से लाइसेंस, वाहनों की आरसी व टोल नाकों की पर्चियां बनाता था।

एनसीटीई की मान्यता खत्म : पांच राजकीय बीएड कॉलेजों पर लगा ताला

सरकार ने कहा, पांच कॉलेजों में से किसी एक को जीवित कर लो

सरकार ने सभी शिक्षकों को एकत्र कर एक कॉलेज चालू रखने की बनाई रणनीति

500 सीटें कम हो जाएंगी, ग्रामीण छात्र प्रभावित होंगे

गजेन्द्र सिंह दहिया
patrika.com

जोधपुर प्रदेश के 7 राजकीय कॉलेजों में संचालित बीएड पाठ्यक्रम में से 5 कॉलेजों में इस साल बीएड की अंतिम परीक्षा होने के साथ ही यहां के शिक्षक और गैर शैक्षणिक कर्मचारी खाली हो गए हैं। पांचों बीएड कॉलेजों की मान्यता समाप्त हो चुकी है। एक बीएड कॉलेज को संचालित करने के लिए 16 शिक्षक चाहिए, जबकि पांचों को मिलाकर 16 शिक्षक हैं। पिछले सप्ताह कॉलेज आयुक्तालय ने पांचों कॉलेज के शिक्षकों को बुलाकर उनके विचार पूछे। उसके बाद सभी 16 शिक्षकों को किसी एक बीएड कॉलेज में स्थानांतरित करके उसको मान्यता दिलाने की योजना बनाई गई है। अगर ऐसा होता है तो पांच में से केवल एक कॉलेज में बीएड चलती रहेगी।

न कॉलेज में पढ़ा सकते न स्कूल में

इन पांचों कॉलेज के शिक्षकों का दुर्भाग्य यह है कि ये न तो स्कूल में पढ़ा सकते हैं और न ही कॉलेज में। कॉलेज में पढ़ाने के लिए संबंधित विषय में पीएचडी चाहिए, जबकि इनके पास शिक्षा में पीएचडी है। कॉलेज आयुक्तालय के तहत होने से इन्हें स्कूली शिक्षा में भी स्थानांतरित करना आसान नहीं है। प्रदेश के दो अन्य राजकीय बीएड महाविद्यालय राजकीय उच्चतर शिक्षा संस्थान बीकानेर व अजमेर स्कूली शिक्षा के तहत आते हैं।

दो साल पहले खत्म मान्यता

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने अक्टूबर 2018 में एसपीएम राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भोपालगढ़ (जोधपुर), एसजीएसजी राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद (अजमेर), राजकीय महाविद्यालय खेरवाड़ा (उदयपुर), बाबा भगवानदास राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा (जयपुर) और आरएल सहरिया राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा (जयपुर) की मान्यता रद्द कर दी। भोपालगढ़ व कालाडेरा में 5-5, खेरवाड़ा में 4 और चिमनपुरा व नसीराबाद कॉलेज में केवल 1-1 शिक्षक बीएड पढ़ा रहे हैं। नियमों के अनुसार 100 विद्यार्थियों पर एक प्रिंसिपल/एचओडी सहित 16 शिक्षक होने चाहिए। वर्ष 2019-20 के अंतिम बैच के जनवरी 2021 में लिखित परीक्षा समाप्त होने के साथ ही इन पांचों कॉलेज के शिक्षक खाली हाथ रह गए हैं।

हर कॉलेज से 55 लाख की आय

बीएड पाठ्यक्रम में छात्र की फीस 27 हजार रुपए सालाना है। प्रत्येक कॉलेज हर साल 55 लाख रुपए की आय सरकार को दे रहा है, जो बंद हो जाएगी। सरकार ने इन कॉलेजों में लंबे समय से बीएड शिक्षकों की भर्ती नहीं की। पांच राजकीय कॉलेजों में बीएड पाठ्यक्रम बंद होने से अब 500 सीटें कम हो गई हैं। सभी पांचों कॉलेज ग्रामीण इलाके में थे। ऐसे में गांवों से बीएड करने वाले छात्र-छात्राओं को अब नजदीक कॉलेज नहीं मिल पाएगा। वैसे सरकारी व निजी बीएड कॉलेजों का शुल्क एक समान ही है।

सरकारी जमीन के रूपान्तरण का मामला: जवाब पेश, सुनवाई आज

कोटा यूआइटी ने स्वीकारा, गुंजल की पत्नी के लिए मास्टर प्लान कुर्बान हुआ

जयपुर @ पत्रिका. कोटा नगर सुधार न्यास ने तत्कालीन विधायक प्रहलाद गुंजल की पत्नी के लिए सरकारी जमीन का भूरूपान्तरण कर मास्टर प्लान कुर्बान करने का आरोप स्वीकार लिया है। वहीं एसटी परिवार की जमीन के गुंजल परिवार को जारी पट्टे पर कहा है कि भूरूपान्तरण हो गया इसलिए पट्टा जारी कर दिया। उधर, राज्य सरकार व भू-उपयोग परिवर्तन कमेटी ने अधिकांश बिन्दुओं पर जवाब देने से बचते हुए याचिका में उठाए सवालों को टाल दिया है। दोनों मामलों पर मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत माहान्ती व न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की खण्डपीठ सोमवार को सुनवाई करेगी।

सड़क की जमीन के भूरूपान्तरण व एसटी की जमीन का पट्टा जारी होने को लेकर नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अनिल सुवालका ने हाईकोर्ट में दो जनहित याचिकाएं दायर की हैं। इनमें गुंजल के प्रभाव में उनकी पत्नी का अवैध कब्जा बचाने को सड़क की चौड़ाई घटाने और एसटी परिवार की जमीन का पट्टा जारी करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही मास्टर प्लान के विपरीत किए गए भू-रूपान्तरण को रद्द कर अवैध निर्माण ध्वस्त करने का आग्रह किया है। इन याचिकाओं पर लगभग तीन माह पहले नोटिस जारी किए गए थे। यातायात समस्या के बावजूद सड़क की चौड़ाई घटाने को लेकर राजस्थान पत्रिका में 20 सितंबर 2019 को प्रकाशित समाचार को भी याचिका में आधार बनाया है।

फॉलोअप

गुंजल पर मास्टर प्लान 'कुर्बान', सड़क की जमीन करवा ली पत्नी के नाम

राजस्थान पत्रिका
प्रकाशित खबर

याचिकाकर्ता का आरोप है कि भाजपा सरकार के समय विधायक रहे प्रहलाद गुंजल की पत्नी का मकान बचाने के लिए मास्टर प्लान के विपरीत कोटा की 2 प्रमुख सड़कों की चौड़ाई घटा दी गई। राज्य स्तरीय भूमि उपयोग परिवर्तन कमेटी ने कोटा के जीएडी सर्कल से शिवपुरा रोड की चौड़ाई 160 फीट से घटाकर 120 फीट कर दी। वहीं जीएडी सर्कल से केशवपुरा रोड की 100 से 80 फीट कर दी।

भू-रूपान्तरण गैर कानूनी होने का आरोप: याचिकाकर्ता के अनुसार यूआइटी ने भू-रूपान्तरण के लिए आवेदन किया, जिस पर दिसंबर 2015 में राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक हुई। इसमें बिना कोरम ही गैरकानूनी तरीके से सहमति दी गई। आमजन की समस्या को ध्यान में रखते हुए राजस्थान पत्रिका ने शहर की सबसे व्यस्त दोनों सड़कों की चौड़ाई घटाकर गुंजल परिवार को फायदा पहुंचाने का मुद्दा उठाया था।

विधायक ने जैसा चाहा, वैसा कर दिया: याचिका के अनुसार भाजपा सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन विधायक प्रहलाद गुंजल के दबाव में उनकी पत्नी के कब्जे वाली सरकारी जमीन को मास्टर प्लान के विपरीत आवासीय में बदल दिया, जबकि मास्टर में सड़क बताया था। मास्टर प्लान बदलने पर किसी की आपत्ति नहीं आने का हवाला देकर यूआइटी ने गुंजल ने जैसा चाहा, वैसा कर दिया।

जवाब के मुख्य बिन्दु

यूआइटी

- यूआइटी ने सड़क की चौड़ाई घटाने का प्रस्ताव भेजा लेकिन गलत था तो भू-उपयोग परिवर्तन कमेटी को अस्वीकार कर देना चाहिए था।
- एससी-एसटी की जमीन कोई दूसरा नहीं खरीद सकता लेकिन भू उपयोग बदल गया था इसलिए पट्टा जारी कर दिया।
- जमीन का आवंटन बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए किया गया।

राज्य सरकार व भू-उपयोग परिवर्तन कमेटी

- 30 में से 20 बिन्दुओं पर कोई जवाब नहीं दिया और जवाब देने की जरूरत भी नहीं समझी।
- यूआइटी ने जो प्रस्ताव दिया, उस पर प्रक्रिया अपनाते हुए निर्णय किया
- मास्टर प्लान में सड़क प्रस्तावित है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में उल्लेख नहीं है।
- राज्य स्तरीय कमेटी ने सर्वे रिपोर्ट के आधार 1 दिसम्बर 2015 को निर्णय किया।

भीलवाड़ा: थाना प्रभारी के डांस का वीडियो वायरल, जांच शुरू

एसपी थाने पहुंचे, नदारद एसएचओ पार्टी में नाचने में व्यस्त, निलम्बित

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

भीलवाड़ा. बजरी माफिया के खिलाफ सख्ती की परख के लिए पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा शनिवार रात बड़लियास व मंगरोप पुलिस थाने अचानक पहुंच गए। इस दौरान बड़लियास थाना प्रभारी सुरजीत गैर हाजिर मिले।

वे थाने से बाहर अपने जन्मदिन की पार्टी में डांस करने में व्यस्त थे। इसका वीडियो रविवार को वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने थानाधिकारी को निलम्बित कर दिया। आरोप है कि थानाधिकारी की जन्मदिन पार्टी में अवैध बजरी के धंधे से जुड़े लोग भी शामिल थे। पुलिस अधीक्षक ने इस समूचे मामले की जांच एसआईयूसीएडब्लयू सेल के उपाधीक्षक राहुल जोशी को सौंपी है।

एसपी शनिवार रात को बड़लियास थाना पहुंचे। बिना रपट डाले और सूचना दिए थाने से गैरहाजिर होने पर शर्मा ने थानाधिकारी की अनुपस्थिति दर्ज की। उन्हें थाना इलाके में राकेश व रामलाल संदिग्ध तरीके से लग्जरी गाड़ी में घूमते मिले। अवैध बजरी परिवहन से जुड़े होने की आशंका में दोनों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बड़लियास व मंगरोप थाना क्षेत्र में रास्तों में बजरी से भरे तीन वाहन भी जब्त किए।

- **आरोप:** थानाधिकारी की जन्मदिन पार्टी में अवैध बजरी के धंधे से जुड़े लोग भी थे शामिल
- **थाना** प्रभारी सुरजीत बोले जन्मदिन की पार्टी में शामिल उनके करीबी मित्र, बजरी माफिया से जुड़ा कोई व्यक्ति नहीं

डीजे पर थिरक रहे हैं थानाप्रभारी

बडलियास थाना प्रभारी की शनिवार को हुई जन्मदिन की पार्टी के वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुए। आशंका जताई गई कि इसमें थाना प्रभारी के साथ डांस कर रहे कुछ लोगों का सम्बन्ध बजरी माफियाओं से हो सकता है। इधर, थाना प्रभारी सुरजीत का कहना है कि जन्मदिन की पार्टी में उनके करीबी मित्र थे, बजरी माफिया से जुड़ा कोई व्यक्ति नहीं था।

नेपाल

गजेट्स के लिए विधायक कोष निर्धारित, फिर भी अलग से खरीद

खजाना खाली, फिर भी डिजिटल बजट के नाम पर लाखों का खर्चा

हालत ऐसी
40 हजार करोड़ से अधिक का राजकोषीय घाटे से जूझ रहा प्रदेश

बकाया ऐसा
कार्मिकों को 2020 का कोविड काल का 15 दिन का वेतन देना बाकी

ठाठ ऐसे
10-10 हजार के ब्रीफ केस में रखकर देंगे 30-30 हजार के टैबलेट

अरविन्द सिंह शक्तावत
patrika.com

जयपुर. कोरोना काल में सरकारी खजाने में हजारों करोड़ का घाटा होने के बावजूद राज्य सरकार ब्रीफकेस और टैबलेट की खरीद पर लाखों रुपए खर्च कर रही है। सरकार बचत के नाम पर विधानसभा में बुधवार को पहली बार डिजिटल बजट पेश करेगी लेकिन विधायकों को 10-10 हजार के ब्रीफकेस में 30-30 हजार के टैबलेट रखकर देगी। वह भी तब, जब लैपटॉप-टैबलेट जैसे गजेट्स के लिए विधानसभा ने पहले से 90 हजार रुपए प्रति विधायक खर्चे का प्रावधान कर रखा है। इन टैबलेट की खरीद इस प्रावधान से इतर की जा रही है। इधर, कोविड काल में सरकारी कर्मचारी 2020 का करीब 15 दिन का बकाया वेतन मांग रहे हैं।

प्रदेश 40 हजार करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व घाटे से जूझ रहा है। कोरोना से आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण बचत के मद्देनजर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहली बार बुधवार को डिजिटल बजट पेश करेंगे। वित्त विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव बना कर भेजा, जिसे विधानसभा से अनुमति मिल चुकी है। विधानसभा से जुड़े सूत्रों के अनुसार वित्त विभाग का प्रस्ताव था कि प्रिंटिंग का जो खर्चा आएगा, उसके बदले ये टैबलेट दिए जाएंगे ताकि विधायकों को बजट की कॉपी उपलब्ध करवाई जा सके। बजट भाषण पूरा होने के तत्काल बाद विधायकों को ये टैबलेट दिए जाएंगे।

खरीद अलग से क्यों, उठ रहा सवाल

नई विधानसभा का गठन होने के बाद प्रत्येक विधायक 90 हजार रुपए खर्च कर अपने लिए लैपटॉप, टैबलेट या कम्प्यूटर खरीद सकता है। पन्द्रहवीं विधानसभा में भी ज्यादातर ने इन गजेट्स की खरीद कर ली है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पहले से बजट दे रखा है तो अलग से टैबलेट देने की क्या जरूरत आ पड़ी है।

शामिल होना लक्ष्य है।

पीई दर्ज के लिए मुख्यालय भेजी रिपोर्ट

मण्डोर उद्यान के विकास कार्यों में गड़बड़झाला!

कार्यों में अनियमितता की शिकायत पर एसीबी ने शुरू की जांच

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जोधपुर. राज्य सरकार की ओर से मण्डोर उद्यान में चल रहे तेरह करोड़ रुपए के जीर्णोद्धार कार्य में गड़बड़ी की शिकायत सामने आने के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जांच शुरू कर पीई (प्राथमिकी जांच) दर्ज करने के लिए जयपुर स्थित एसीबी मुख्यालय भेजी है।

दरअसल, मण्डोर उद्यान की दुर्दशा को सुधारने के उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से तेरह करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। जिसके बाद उद्यान में जीर्णोद्धार कार्य चल रहे हैं। ठेकेदार और अधिकारी-कर्मचारियों में सांठ-गांठ से कार्यों में अनियमिमताएं व मिलीभगत होने का अंदेशा जताया गया है। जोधपुर शहर युवा कांग्रेस के जिला सचिव लक्ष्मणसिंह सोलंकी ने कार्यों में गड़बड़ी का आरोप लगाकर एसीबी के महानिदेशक के साथ जोधपुर में उप महानिरीक्षक से लिखित शिकयत की। आरोप है कि ठेकेदार व अधिकारी कार्य में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उद्यान में जो कार्य हो रहे हैं वो उनके नक्शे, निविदा व कार्य आदेश में फेरबदल किया गया है। कार्य आदेश व नक्शे के मुताबिक कार्य नहीं हो रहा है। शिकायत के आधार पर एसीबी ने मौका मुआयना किया तो गड़बड़ी का अंदेशा हुआ। ऐसे में परिवाद की जांच शुरू की गई है।

परिवाद दर्ज करने मुख्यालय भेजा है

'मण्डोर उद्यान में चल रहे कार्यों में अनियमितताओं की शिकायत मिली है। जांच शुरू की गई है। परिवाद को दर्ज करने के लिए मुख्यालय भेजी गई है।'

भोपालसिंह लखावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसीबी (ग्रामीण) जोधपुर।

सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के साथ पुलिस ने डीजी (जेल) को सुपुर्द की थी जांच रिपोर्ट

जेल में 17 मोबाइल व 18 सिम जब्त, नष्ट की थी तैयारी

एक्सक्लूसिव

जेल में डेढ़ सौ मोबाइल सक्रिय, डीजी ने फटकारा तो नष्ट करने का प्रयास!

रात 11 बजे पुलिस ने पहुंचकर जब्त किए 17 मोबाइल

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जोधपुर. जोधपुर सेन्ट्रल जेल में बंदी व कैदियों के पास करीब डेढ़ सौ मोबाइल सक्रिय हैं। इन्हीं के बूते पर बाहर अपराध करवा रहे हैं। बंदियों के मोबाइल उपयोग करने के सीसीटीवी फुटेज के साथ पुलिस ने जोधपुर दौरे पर आए पुलिस महानिदेशक (जेल) राजीव दासोत को अवगत तो जेल प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई गई थी व मोबाइल बंद करने के कड़े निर्देश दिए थे। पुलिस का कहना है कि जेल प्रशासन बुधवार रात मोबाइल, सिम व चार्जर नष्ट करने की तैयारी में था, लेकिन पुलिस को पता लग गया और देर रात जेल पहुंचकर 17 मोबाइल, 18 सिम व दो चार्जर जब्त कर लिए।

पुलिस सूत्रों के अनुसार जेल प्रशासन ने बुधवार रात 10.30 बजे तलाशी लेकर बड़ी तादाद में मोबाइल, सिम व चार्जर कब्जे में लिए थे। पुलिस उपायुक्त (पूर्व) धर्मेन्द्रसिंह यादव को पता लगा तो उन्होंने अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (पूर्व) भागचन्द्र मीणा व रातानाडा थानाधिकारी लीलाराम के साथ पुलिस को जेल में तलाशी लेने भेजा। रात ग्यारह बजे पुलिस को देख जेल प्रशासन भी चौंक गया। पुलिस ने जेल प्रशासन से 17 मोबाइल, 18 सिम व दो चार्जर जब्त किए। इनमें 13 मोबाइल एन्ड्रॉयड व शेष की-पेड वाले हैं। जेल प्रशासन की तरफ से मामला दर्ज कराया गया।

राशन की बोरियों में छुपाकर लाए थे मोबाइल

पुलिस का कहना है कि जेल में बंदी व कैदियों के खाने के लिए राशन सामग्री आती है। राशन ठेकेदार से मिलीभगत कर राशन की बोरियों में छुपाकर कुछ समय पहले सौ से डेढ़ सौ मोबाइल जेल के अंदर पहुंचाए गए थे। जो जेलकर्मियों की मिलीभगत से बंदी व कैदियों को दिए गए थे। जेल प्रशासन ने सारे मोबाइल व सिम लावारिस मिलने की जानकारी दी है। पुलिस सिम की कॉल डिटेल व मोबाइल के आइएमइआइ नम्बर से उपयोग करने वाले बंदियों का पता लगाएगी।

सीसीटीवी कैमरों ने खोली जेल प्रशासन की पोल

जेल में हर बैरिक व वार्डों पर निगरानी के लिए 135 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। हार्डकोर व कुख्यात बदमाशों के लिए खास तौर पर कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस अभय कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेंटर से पुलिस चौबीस घंटे सतत निगरानी रखे हुए है। यही वजह है कि पिछले दिनों पुलिस को बंदियों के मोबाइल उपयोग लेने की पुख्ता सूचना मिली। इन सीसीटीवी फुटेज के साथ पुलिस ने गत नौ फरवरी को जोधपुर आए जेल डीजी राजीव दासोत को रिपोर्ट सौंपी। जिसमें अवगत कराया गया कि जोधपुर जेल में करीब डेढ़ मोबाइल सक्रिय हैं। जेल डीजी ने नाराजगी जताकर कड़ी फटकार लगाई थी।

ऑपरेशन फ्लश आउट में मोबाइल मिलने की शून्य रिपोर्ट

मोबाइल व आपत्तिजनक सामग्री के खिलाफ जेल मुख्यालय ने गत वर्ष राज्य की जेलों में ऑपरेशन फ्लश आउट शुरू किया था। जेल प्रशासन ने दावा किया था कि अभियान के चलते जेलों में मोबाइल लगभग बंद हो गए हैं। मोबाइल जब्त होने की रिपोर्ट शून्य आने लगी थी। अब एक साथ 17 मोबाइल व 18 सिम बरामद होना भी जेल प्रशासन पर सवालिया निशान उत्पन्न कर रहा है।

गड्डों में छुपाकर रखे थे मोबाइल

जेल के सभी अधिकारी, प्रहरी व आरएसी के जवानों ने दो घंटे तक बंदियों के बैरिक व वार्डों की तलाशी ली थी। गड्डों व बरामदों में गाड़कर रखे 17 मोबाइल, 18 सिम व चार्जर जब्त किए गए।

ओमप्रकाश शर्मा,
जेल अधीक्षक,
जोधपुर सेन्ट्रल जेल।

भ्रष्टाचार को संरक्षण : आरोपियों में 3 आरएएस अफसर, 4 कनिष्ठ अधिकारी

महाराष्ट्र तक जालसाजी, फिर भी 8 अफसरों पर मुकदमा चलाने को सरकार नहीं राजी

671 एकड़ भूमि और करोड़ों के लोन का मामला

भ्रष्टाचार की धाराओं में केस चलाने के लिए राज्य सरकार नहीं दे रही मंजूरी

ओमप्रकाश शर्मा
patrika.com

जयपुर. अफसरों के भ्रष्टाचार और जालसाजी को संरक्षण देने का बड़ा मामला सामने आया है। राजस्थान के 3 आरएएस अफसरों सहित 8 अधिकारियों ने पहले तो 671 एकड़ जमीन के लिए निजी लोगों से मिलकर नियमों की धज्जियां उड़ाई। जमीन के टुकड़े कर डाले। फिर उसके नाम से खातेधारकों ने मुम्बई से करोड़ों का लोन ले लिया।

मुम्बई में घोटाला सामने आने पर महाराष्ट्र सरकार तो चाहती है कि उक्त जमीन नीलाम की जाए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चाहता है कि आरोपी अफसरों पर भ्रष्टाचार की धाराओं में कोर्ट में मुकदमा चले। लेकिन राजस्थान सरकार पिछले ढाई साल से मामला दबाए बैठी है। आरोपी अफसरों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दे ही नहीं रही।

संरक्षण के चलते ये ठाठ

जिन अफसरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी थी, वे सरकारी विभागों-एजेंसियों में अहम पदों पर तैनात हैं।

अभियोजन के लिए फाइल भेज दी थी। आगे क्या रहा, यह जानकारी अजमेर चौकी के अधिकारी ही दे सकते हैं।
सीपी शर्मा, तत्कालीन जांच अधिकारी

यह है मामला : जालसाजी का अटूट सिलसिला

20.02.21

बीकानेर के चकगर्बी गांव में 671 एकड़ भूमि एक ही व्यक्ति के नाम थी जबकि निर्धारित बीघा से अधिक जमीन एक व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए। इस पर वह जमीन सीलिंग एक्ट में आ गई। इसे सीलिंग से बचाने के लिए तत्कालीन उपपंजीयन अधिकारी से मिलकर 7 पक्षों में रजिस्ट्री करा दी गई।

पढ़ें **यह** @ पेज 11

वर्ष 2014 में मुम्बई में एनएसईएल घोटाला हुआ, जिसमें यह जमीन भी शामिल थी। मुम्बई की इकोनॉमी ऑफिस विंग ने इस जमीन को अटैच कर नीलामी की तैयारी कर ली। खाताधारकों ने इसकी सहमति भी दे दी। लेकिन फिर जमीन की कीमत बढ़ाने का खेल चला।

इसके लिए आरोपी पक्ष ने बीकानेर यूआइटी में गोल्फ रिसोर्ट के नाम पर जमीन की 90-ए करने का प्रस्ताव रखा। सीलिंग एक्ट में मामला लम्बित होने के बावजूद सचिव अरुणप्रकाश ने आवेदन स्वीकार कर लिया। अरुणप्रकाश के तबादले के बाद तत्कालीन एडीएम दुर्गेश बिस्सा ने अतिरिक्त चार्ज के दौरान ही 90-ए का आदेश जारी कर दिया। शिकायत होने पर उन्होंने आदेश खारिज भी कर दिए जबकि यह आदेश सम्भागीय आयुक्त ही जारी कर सकते थे।

एसीबी ने 2015 में केस दर्ज किया, 2018 में मांगी थी सरकार से इजाजत

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने वर्ष 2015 में एफआइआर दर्ज की थी। तत्कालीन जांच अधिकारी सीपी शर्मा ने 3 आरएएस सहित 8 अधिकारियों व कई निजी लोगों के खिलाफ आरोप साबित माने। जुलाई 2018 में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश करने के लिए अभियोजन की इजाजत मांगी लेकिन सरकार ने यह स्वीकृति आज तक नहीं दी। कार्मिक विभाग, विधि विभाग, राजस्व विभाग तथा स्वायत्त शासन विभाग फाइल दबाएं बैठे हैं। कहा जा रहा है कि सरकार से हरी झंडी मिलने पर ही आदेश जारी होंगे।

फेसबुक: ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने मांगी मोदी से मदद @ भीतर

सरकारी जमीन के रूपान्तरण का मामला : जवाब पेश, सुनवाई आज

कोटा यूआइटी ने स्वीकारा, गुंजल की पत्नी के लिए मास्टर प्लान कुर्बान हुआ

जयपुर @ पत्रिका. कोटा नगर सुधार न्यास ने तत्कालीन विधायक प्रहलाद गुंजल की पत्नी के लिए सरकारी जमीन का भूरूपान्तरण कर मास्टर प्लान कुर्बान करने का आरोप स्वीकार लिया है। वहीं एसटी परिवार की जमीन के गुंजल परिवार को जारी पट्टे पर कहा है कि भूरूपान्तरण हो गया इसलिए पट्टा जारी कर दिया। उधर, राज्य सरकार व भू-उपयोग परिवर्तन कमेटी ने अधिकांश बिन्दुओं पर जवाब देने से बचते हुए याचिका में उठाए सवालों को टाल दिया है। दोनों मामलों पर मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत माहान्ती व न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की खण्डपीठ सोमवार को सुनवाई करेगी।

सड़क की जमीन के भूरूपान्तरण व एसटी की जमीन का पट्टा जारी होने को लेकर नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अनिल सुवालका ने हाईकोर्ट में दो जनहित याचिकाएं दायर की हैं। इनमें गुंजल के प्रभाव में उनकी पत्नी का अवैध कब्जा बचाने को सड़क की चौड़ाई घटाने और एसटी परिवार की जमीन का पट्टा जारी करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही मास्टर प्लान के विपरीत किए गए भू-रूपान्तरण को रद्द कर अवैध निर्माण ध्वस्त करने का आग्रह किया है। इन याचिकाओं पर लगभग तीन माह पहले नोटिस जारी किए गए थे। यातायात समस्या के बावजूद सड़क की चौड़ाई घटाने को लेकर राजस्थान पत्रिका में 20 सितंबर 2019 को प्रकाशित समाचार को भी याचिका में आधार बनाया है।

फॉलोअप

22-02-21

गुंजल पर मास्टर प्लान 'कुर्बान', सड़क की जमीन करवा ली पत्नी के नाम

राजस्थान पत्रिका

प्रकाशित खबर

याचिकाकर्ता का आरोप है कि भाजपा सरकार के समय विधायक रहे प्रहलाद गुंजल की पत्नी का मकान बचाने के लिए मास्टर प्लान के विपरीत कोटा की 2 प्रमुख सड़कों की चौड़ाई घटा दी गई। राज्य स्तरीय भूमि उपयोग परिवर्तन कमेटी ने कोटा के जीएडी सर्कल से शिवपुरा रोड की चौड़ाई 160 फीट से घटाकर 120 फीट कर दी। वहीं जीएडी सर्कल से केशवपुरा रोड की 100 से 80 फीट कर दी।

भू-रूपान्तरण गैर कानूनी होने का आरोप: याचिकाकर्ता के अनुसार यूआइटी ने भू-रूपान्तरण के लिए आवेदन किया, जिस पर दिसंबर 2015 में राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक हुई। इसमें बिना कोरम ही गैरकानूनी तरीके से सहमति दी गई। आमजन की समस्या को ध्यान में रखते हुए राजस्थान पत्रिका ने शहर की सबसे व्यस्त दोनों सड़कों की चौड़ाई घटाकर गुंजल परिवार को फायदा पहुंचाने का मुद्दा उठाया था।

विधायक ने जैसा चाहा, वैसा कर दिया: याचिका के अनुसार भाजपा सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन विधायक प्रहलाद गुंजल के दबाव में उनकी पत्नी के कब्जे वाली सरकारी जमीन को मास्टर प्लान के विपरीत आवासीय में बदल दिया, जबकि मास्टर में सड़क बताया था। मास्टर प्लान बदलने पर किसी की आपत्ति नहीं आने का हवाला देकर यूआइटी ने गुंजल ने जैसा चाहा, वैसा कर दिया।

जवाब के मुख्य बिन्दु

यूआइटी

- यूआइटी ने सड़क की चौड़ाई घटाने का प्रस्ताव भेजा लेकिन गलत था तो भू-उपयोग परिवर्तन कमेटी को अस्वीकार कर देना चाहिए था।
- एससी-एसटी की जमीन कोई दूसरा नहीं खरीद सकता लेकिन भू उपयोग बदल गया था इसलिए पट्टा जारी कर दिया।
- जमीन का आवंटन बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए किया गया।

राज्य सरकार व भू-उपयोग परिवर्तन कमेटी

- 30 में से 20 बिन्दुओं पर कोई जवाब नहीं दिया और जवाब देने की जरूरत भी नहीं समझी।
- यूआइटी ने जो प्रस्ताव दिया, उस पर प्रक्रिया अपनाते हुए निर्णय किया
- मास्टर प्लान में सड़क प्रस्तावित है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में उल्लेख नहीं है।
- राज्य स्तरीय कमेटी ने सर्वे रिपोर्ट के आधार 1 दिसम्बर 2015 को निर्णय किया।

व्यक्तियों के टीके लगाए जा सकेंगे। किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ... प्रशिक्षित टीम को प्रमाणीकरण करेंगे।

जोधपुर सेन्ट्रल जेल में 17 मोबाइल व 18 सिम मिलने का मामला

मिलीभगत का पता लगाने को जेल कार्मिकों से पूछताछ

मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगालने में जुटी पुलिस

01-03-21

जोधपुर @ पत्रिका. रातानाडा थाना पुलिस ने जोधपुर सेन्ट्रल जेल में एक साथ 17 मोबाइल, 18 सिम व दो चार्जर जब्त करने के मामले में जेल कर्मचारियों की भूमिका की जांच शुरू की है। पुलिस का मानना है कि जेल में मोबाइल पहुंचने के पीछे जेल कार्मिकों की भूमिका है।

पुलिस के अनुसार प्रकरण में जेल प्रशासन की ओर से तीन एफआइआर दर्ज कराई गई है। इस संबंध में पुलिस ने जेल कार्मिक, राशन सामग्री सप्लाई करने वाले तीनों ठेकेदार व स्टोर प्रभारी की भूमिका संदेहास्पद है। पुलिस ने इन सभी के साथ ही जेल में ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों से पूछताछ की है। वहीं, जब्त होने वाले सिम की कॉल डिटेल्स भी पुलिस को मिली है। जिनके आधार पर मोबाइल उपयोग में लेने वाले बंदियों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मोबाइल में व्हॉट्सऐप मैसेज व कॉल की जांच भी की जा रही है।

जेलकर्मियों की भूमिका के लिए अहम सीसीटीवी फुटेज

गत 24 फरवरी की रात जेल में तलाशी के दौरान जेल प्रशासन ने मोबाइल व सिम जब्त किए थे। तभी पुलिस वहां पहुंच गई थी और 17 मोबाइल, 18 सिम व तीन चार्जर जब्त किए थे। जेल कार्मिकों से पूछताछ के अलावा पुलिस तलाशी के दौरान जेल में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी जांच रही है।

जोधपुर सेन्ट्रल जेल, पहली बार जेल अधिकारी पर हो सकती है कार्रवाई

जेल में मोबाइल मिलने पर जेलर शक के घेरे में

पत्रिका
क्राइम रिपोर्ट

अजमेर स्थानान्तरित जेलर को जोधपुर बुलाकर पुलिस ने की पूछताछ, जेल परिसर में क्वार्टर की तलाशी

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जोधपुर. जोधपुर सेन्ट्रल जेल के स्टोर रूम में मोबाइल से जुड़ी निषिद्ध सामग्री व हीटर स्प्रिंग के मामले की पुलिस जांच में जेलर जगदीश पूनिया के साथ-साथ दो उप कारापाल की भूमिका शक के घेरे में आ गई। रातानाडा थाना पुलिस ने नामजद कर जेलर पूनिया को अजमेर से जोधपुर बुलाकर न सिर्फ पूछताछ की, बल्कि वीडियोग्राफी करवाकर जेल परिसर में क्वार्टर की सघन तलाशी भी ली। जेल में बंदियों तक मोबाइल व निषिद्ध सामग्री पहुंचने के मामले में पहली बार जेल के किसी अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार जेल अधीक्षक ओमप्रकाश शर्मा ने गत 25 फरवरी को जेल के स्टोर का एक वीडियो मिलने और उसमें कुछ व्यक्तियों के पास मोबाइल व अन्य निषिद्ध सामग्री होने के संबंध में एफआइआर दर्ज कराई थी। स्टोर प्रभारी लक्ष्मणसिंह, राशन सामग्री सप्लाई करने वाले ठेकेदार श्याम सुंदर, सत्यनारायण व बाबूलाल पर संदेह जताया गया था। यह वीडियो चार फरवरी का था।

निषिद्ध सामग्री के बारे में पुलिस ने चारों से पूछताछ की तो जेलर जगदीश पूनिया, उप कारापाल सद्दाम हुसैन व श्रीचंद गिला के नाम लिए। मोबाइल व अन्य निषिद्ध सामग्री जगदीश पूनिया व जेल अधीक्षक को सौंपने की जानकारी दी। पुलिस ने अजमेर जेल में पदस्थापित जेलर जगदीश पूनिया को पूछताछ के लिए सोमवार को जोधपुर बुलाया। रातानाडा थाने में पूनिया से लम्बी पूछताछ की गई। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने जेलर की मौजूदगी में जेल परिसर में क्वार्टर की तलाशी ली। उप कारापालों के क्वार्टर की भी तलाशी ली गई। पुलिस का कहना है कि तलाशी में कोई खास वस्तु नहीं मिली है। फिर भी मामले में भूमिका के संबंध में विश्लेषण किया जा रहा है।

पूछताछ में जेलर ने बॉल उच्चाधिकारी के पाले में डाली

मामले की जांच और स्टोर प्रभारी व ठेकेदारों से पूछताछ के बाद पुलिस ने जेलर व अन्य को भी नामजद आरोपी बनाया है। पूछताछ में जेलर ने प्रतिबंधित सामग्री के बारे में खुद से पल्ला छाड़ने के लिए एसपी को जिम्मेदार ठहराया। जेलर ने बताया कि जेल के जिम्मेदार अधिकारी एसपी हैं और स्टोर रूम में प्रतिबंधित सामग्री मिलने के बारे में उन्हें भी जानकारी थी।

कॉल डिटेल्स से खाली हाथ, तकनीकी जांच के प्रयास

जेल में गत 24 फरवरी की रात 17 मोबाइल, 18 सिम व तीन चार्जर जब्त किए गए थे। पुलिस ने इनकी कॉल डिटेल्स मंगाई तो कोई खास सुराग नहीं मिल पाए। पुलिस का कहना है कि बंदी व्हॉट्सऐप कॉल करते हैं। ऐसे में तकनीकी जांच व विश्लेषण से पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

'जेल में मोबाइल बरामदगी के दो व स्टोर रूम में निषिद्ध सामग्री मिलने का एक मामला दर्ज है। अब तक नामजद और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ व मोबाइल की जांच की जा रही है। साक्ष्य जुटाने के लिए कुछ तलाशी भी ली गई है।'

धर्मेन्द्रसिंह यादव, पुलिस उपायुक्त (पूर्व) जोधपुर।

एसीबी की कार्रवाई: जेसीटीएसएल के ओएसडी और लेखाधिकारी ले रहे थे चार लाख रुपए की घूस...इससे पहले 50 मिडी बसों को भी दिखाई हरी झंडी

सुबह मंत्री से फीता कटवाने वाले दो अफसर दोपहर में घूस लेते दबोचे

07-03-21

रिश्वत देने वाला पारस ट्रैवल्स का मालिक भी गिरफ्तार

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर . भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड (जेसीटीएसएल) के ओएसडी वीरेन्द्र वर्मा को शनिवार को चार लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। उसके साथ लेखाधिकारी व रिश्वत देने वाले ट्रैवल्स कम्पनी के मालिक को भी गिरफ्तार किया है।

एडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि आरोपी वीरेन्द्र वर्मा ने रिश्वत की यह राशि अजमेर रोड स्थित जनकपुरी में अपने घर पर ली। जबकि लेखाधिकारी महेश गोयल को रिश्वत की राशि का लेन-देन

100 बसें चलवाने व 10 कमरे आवंटन के लिए मांगी राशि

बस का फीता काटकर उद्घाटन करते मंत्री। साथ में ओएसडी-लेखाधिकारी।

किया। रिश्वत तीसरे गिरफ्तार आरोपी दिल्ली स्थित पारस ट्रैवल्स के मालिक नरेश सिंघल ने दी थी। सिंघल के कर्मचारी अनुज अग्रवाल की भूमिका की जांच की जा रही है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2006 बैच के आरएएस अधिकारी वीरेन्द्र वर्मा

जयपुर में 100 मिडी बसों का संचालन के लिए आवंटन करवाने और जयपुर डिपो में कंपनी को 6 की बजाय 10 कमरे आवंटन करवाने के बदले में ली थी। ट्रेप की कार्रवाई एएसपी बजरंग सिंह शेखावत व उप अधीक्षक सचिन शर्मा की टीम ने की।

तकनीकी आधार पर किया पीछा

एसीबी को 3 माह पहले सूचना मिली थी कि दिल्ली निवासी नरेश सिंघल खुद की बसें लगवाने का प्रयास कर रहा है। सिंघल जेसीटीएसएल अधिकारियों को रिश्वत का प्रलोभन देगा और अधिकारी अधिक घूस देने वाले को प्राथमिकता देंगे। एसीबी की गोपनीय शाखा ने तकनीकी आधार पर आरोपियों को रडार पर ले रखा था।

गुरुवार सुबह से 8 टीम लगी थी पीछे

एसीबी ने गुरुवार सुबह 10 बजे ओएसडी के अजमेर रोड स्थित आवास को अपनी निगरानी में ले लिया। अन्य टीमों ने ओएसडी के विभिन्न ठिकानों को निगरानी में लिया था। एक टीम ओएसडी के पीछे चल रही थी, दूसरी टीम

कवायद: पीएम मोदी के निर्देशों के बाद नीति आयोग ने शुरू किया काम

रेलवे और टेलीकॉम से 1.3 लाख करोड़ जुटाएगा केंद्र

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. मोदी सरकार विनिवेश, निजीकरण और संपत्ति के मौद्रिकरण की नीति पर सवार होकर अर्थव्यवस्था में जान फूंकने की तैयारी में है।

पीएम नरेंद्र मोदी ने अगले तीन सालों में असेट मोनेटाइजेशन की मदद से 2.5 लाख करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा है। सरकार लक्ष्य का आधा यानी 1.3 लाख करोड़ रुपए रेलवे और टेलीकॉम सेक्टर में असेट मोनेटाइजेशन से इकट्ठा करना चाहती है। 2021-22 के लिए सरकार ने विनिवेश और निजीकरण का लक्ष्य 1.75 लाख करोड़ रखा है।

संपत्ति का सही उपयोग: पीएम मोदी ने कहा था कि सरकारी कंपनियों के निजीकरण से संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होगा। बेकार पड़ी संपत्ति का सही उपयोग किया जा सकेगा।

मोदी सरकार ने 100 से अधिक ऐसी संपत्तियों की पहचान कर ली है, जिसकी आने वाले समय में बिक्री की जाएगी। इसी सप्ताह नीति आयोग की तरफ से एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। इसकी अध्यक्षता वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी। उनके अलावा अलग-अलग मंत्रालयों के अधिकारी इसमें शामिल हुए थे।

नीति आयोग की कवायद शुरू

असेट मोनेटाइजेशन को लेकर पीएम मोदी की घोषणा के बाद नीति आयोग इस काम को अंजाम देने में जुट गया है। इसके लिए वह अलग-अलग मंत्रालयों और डिपार्टमेंट से संपर्क साधे हुए है। नीति आयोग ने रेलवे के असेट मोनेटाइजेशन की मदद से 90 हजार करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा बीएसएनएल और एमटीएनएल के टेलीफोन टावर और ऑप्टिकल फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेचकर 40 हजार करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है।

एसीबी को देख प्रहराधिकारी ने रिश्वत राशि हवालात में चटाई के नीचे छुपाई

शराब दुकान से 7 हजार बंधी लेते प्रहराधिकारी गिरफ्तार

जालोर के आबकारी थाने में एसीबी सिरोही की कार्रवाई

जोधपुर@पत्रिका. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की सिरोही चौकी के दल ने शनिवार सुबह जालोर में शराब की दुकान के निर्बाध संचालन की एवज में मासिक बंधी के सात हजार रुपए लेते आबकारी थाना के प्रहराधिकारी सवाईसिंह रतनू को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी टीम को देख प्रहराधिकारी ने रिश्वत राशि चटाई के नीचे छुपा दी।

ब्यूरो के उप महानिरीक्षक डॉ

विष्णुकांत ने बताया कि जालोर के भागली सिंघलान निवासी शराब व्यवसायी बागसिंह पुत्र लाखसिंह की शिकायत पर आबकारी थाने के प्रहराधिकारी जैसलमेर देवीकोट में सिरवा गांव निवासी सवाईसिंह (47) पुत्र उगमदान रतनू को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। राजस्थान पुलिस का निरीक्षक प्रहराधिकारी रतनू प्रतिनियुक्ति पर लगा है।

हर माह 5 हजार रुपए बंधी

एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नारायणसिंह के अनुसार बागसिंह जालोर के डूडसी गांव में अनुज्ञापत्रधारी अनेक कंवर की शराब की दुकान का सेल्समैन है। दुकान के सुचारू संचालन की एवज में प्रहराधिकारी ने बागसिंह से पांच हजार रुपए मासिक बंधी तय कर रखी थी। जनवरी 2021 से मार्च तक 15 हजार रुपए बंधी के बकाया थे। यह राशि मांगने पर शराब सेल्समैन ने एसीबी से शिकायत की। एसीबी ने शुक्रवार को गोपनीय सत्यापन कराया तो प्रहराधिकारी ने आठ हजार रुपए ले लिए। बागसिंह ने आबकारी थाने में जैसे ही बाकी 7 हजार रुपए रतनू को सौंपे, एसीबी टीम ने दबिश दे दी। घबराए प्रहराधिकारी ने रिश्वत राशि हवालात में चटाई के नीचे छुपा दी। गवाहों के समक्ष एसीबी ने यह राशि बरामद कर रतनू को दबोच लिया।

खबर को विस्तार से पढ़ें
https://bit.ly/3vjyS2J

भतीजे ने दोस्त से

भाजपा के मण्डल प्रशिक्षण शिविर का द्वितीय ...

बना सिरदर्द | संयंत्रों के आसपास बन रहे राख के पहाड़

ताप बिजलीघरों से निकली राख का नहीं हो पा रहा पूरा उपयोग

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

चेन्नई. ताप बिजलीघरों से निकलने वाले फ्लाई ऐश (राख) का पूरा लाभदायक उपयोग नहीं हो रहा है। इससे संयंत्रों के आसपास राख के पहाड़ खड़े हो रहे हैं। राख का सीमेंट, एस्बेस्टस और ईंट निर्माण में उपयोग होता है।

देश के कोयला संचालित आधे से ज्यादा बिजली संयंत्र उत्पादित फ्लाई ऐश के इस्तेमाल को लेकर तय मानकों का पालन नहीं करते हैं। यह तथ्य सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायर्नमेंट (सीएसई) की हालिया रिपोर्ट में सामने आया है। रिपोर्ट कहती है कि कुछ संयंत्रों में फ्लाई ऐश का 30-40 प्रतिशत भी इस्तेमाल नहीं हो पाता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 1999 में अधिसूचना जारी कर फ्लाई ऐश के इस्तेमाल का लक्ष्य तय किया है।

1.6 अरब टन फ्लाई ऐश

भारत के कोयला बिजली संयंत्रों से सालाना फ्लाई ऐश का उत्पादन 2009-10 के 12.3 करोड़ टन से बढ़कर 2018-19 में 21.7 करोड़ टन हो गया है। सीएसई ने कहा है कि पुराना पड़ा फ्लाई ऐश मार्च 2019 तक 1.6 अरब टन हो गया है। 2012-13 से 2016-17 के बीच फ्लाई ऐश के इस्तेमाल की मात्रा 10 करोड़ टन के करीब पर स्थिर रही है। बहरहाल इसी अवधि के दौरान सालाना उत्पादन 15 करोड़ टन के पार चला गया है।

फ्लाई ऐश उत्पादन 80 प्रतिशत बढ़ा

रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में कोयले की खपत व कोयला बिजली संयंत्रों से फ्लाई ऐश उत्पादन करीब 80 प्रतिशत बढ़ा है। इस दशक में औसतन 35% फ्लाई ऐश का उपयोग नहीं हो सका, इसकी वजह से राख के ढेर बढ़ रहे हैं। कई इलाकों से 2010 और 2020 के बीच राख के ढेर ढहने की घटनाएं हुईं व राख के असुरक्षित निपटान के मामले सामने आए हैं।

सीमेंट में इस्तेमाल

आइआइटी मद्रास के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर मनु संतानम के अनुसार पोर्टलैंड पोजोलन सीमेंट में फ्लाई ऐश का उपयोग होता है। भारत में सड़क निर्माण में प्रयुक्त सीमेंट में 35 फीसदी ऐश मिलाने की अनुमति है। कुछ मामलों में इसे 50.60 प्रतिशत तक भी मिलाया जाता है। इस सीमेंट से जुड़ी निर्माण लागत कम होती है। हालांकि, कई सड़क परियोजनाओं में राख का उपयोग होने लगा है। पिछले साल सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने सर्कुलर भी जारी किया था कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता से समझौता किए बगैर कृत्रि पदार्थ संबंधी प्रयोग को बढ़ाया जाए।

मंत्रालय दिल्ली, मुंबई, बेंगलूरु और

आरबीआइ : पूर्व गवर्नर राजन ने सरकार को चेताया

औद्योगिक घरानों को बैंक बेचना भारी गलती

■ मौद्रिक नीति के ढांचे में बदलाव से बॉन्ड बाजार होगा प्रभावित, सरकार का रेकॉर्ड अब तक उतार-चढ़ाव से भरा

नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि निजीकरण करने के मामले में सरकार का रेकॉर्ड उतार-चढ़ाव से भरा है। औद्योगिक घरानों को बैंक बेचना भारी गलती होगी। राजन ने चेताया है कि देश के मौद्रिक नीति के ढांचे में किसी तरह के बड़े बदलावों से बॉन्ड बाजार प्रभावित हो सकता है। राजन ने रविवार को कहा कि मौजूदा व्यवस्था ने मुद्रास्फीति को काबू में रखने और वृद्धि को प्रोत्साहन देने में मदद की है। रिजर्व बैंक को खुदरा मुद्रास्फीति को चार प्रतिशत पर रखने का लक्ष्य दिया गया है। केंद्रीय बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर नीतिगत दरें तय करती है। मौजूदा मध्यम अवधि का मुद्रास्फीति लक्ष्य अगस्त, 2016 में अधिसूचित किया गया था। यह इस साल 31 मार्च को समाप्त हो रहा है। अगले पांच साल के लिए मुद्रास्फीति के लक्ष्य को इसी महीने अधिसूचित किए जाने की उम्मीद है।

अर्थव्यस्था पर ये बोले

पूर्व गवर्नर ने कहा कि मौद्रिक नीति प्रणाली ने मुद्रास्फीति को नीचे लाने में मदद की है। इसमें रिजर्व बैंक के लिए अर्थव्यवस्था को समर्थन देने की गुंजाइश भी है। यह सोचना मुश्किल है कि यदि यह ढांचा नहीं होता, तो कैसे इतना ऊंचा राजकोषीय घाटा झेलते।

पत्रिका पड़ताल: जिसके नाम करोड़ों की खान-जमीनें, वह निकला नरेगा मजदूर

गरीबों के नाम से जमीनों-खानों का खेल, कई गरीब आदिवासी गायब

ओमप्रकाश शर्मा
patrika.com

11.03.2021

जयपुर. आदिवासी बहुल मेवाड़ के जिलों में अनुसूचित जनजाति के लोगों की जमीनें इसी वर्ग के गरीब लोगों के नाम से लेकर मोटी कमाई करने का खेल चल रहा है। कई धनाढ्य लोग कौड़ियों में जमीन खरीदकर खनन कर रहे हैं या बेचकर भारी मुनाफा कमा रहे हैं।

भीलवाड़ा के आसीन्द में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। एक मामले में तो जिस व्यक्ति के नाम करोड़ों की खान और जमीनें हैं, वह नरेगा मजदूर निकला। चौंकाने वाली बात यह भी है कि जमीनों के करोड़ों के खेल में जिन गरीबों का इस्तेमाल किया गया, उनमें से कई अब गायब हैं। कुछ मामले पुलिस तक भी पहुंचे हैं लेकिन खुलासा नहीं हो पाया है कि बेशकीमती जमीनों-खानों के असली मालिक कौन हैं।

ताजा मामले भीलवाड़ा के आसींद में सामने आए हैं। यहां तंगहाली में जी रहे कई आदिवासियों के नाम से करोड़ों की जमीनें खरीदी हुई हैं। लाखों का राजस्व जमा कराकर भूरूपांतरण कराया जा रहा है। इन्हीं में शामिल है आधी-अधूरी बनी कोटड़ी में रहने वाला मांगू भील, जिसके नाम भी करोड़ों की

जमीन व खान के इन सौदों पर संदेह

09 हैक्टेयर भूमि का रूपांतरण आसींद में

03 खनन पट्टे लसाड़िया में

100 बीघा जमीन की खरीद हुई लसाड़िया में ही
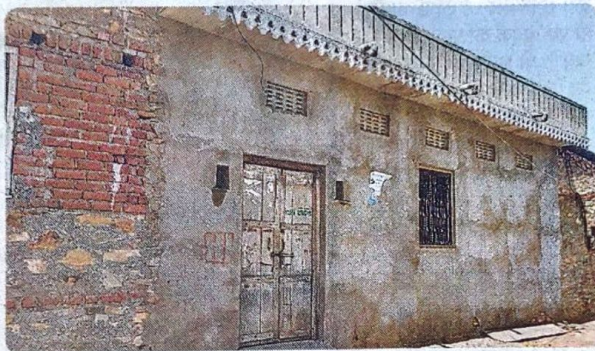
मांगू भील का मकान, जिसके नाम भी करोड़ों की खान व जमीन है।

बड़ा सवाल: असली मालिक कौन?

पुलिस ने बताया कि विवाद सामने आने के बाद मांगू और कुछ अन्य भील परिवार गायब हैं। उनके नाम से सम्पत्ति की जानकारी मिली है। आशंका है कि सम्पत्ति का उपयोग अन्य लोग कर रहे हैं। इन परिवारों के सामने आने के बाद ही साफ होगा कि इस खेल में कौन लोग शामिल हैं।

खान पर मालिकाना हक का दावा

मनरेगा मजदूर मांगू कुछ दिन पहले तक संभवत: खुद भी इससे अनजान था। पता लगा तो खान पर मालिकाना हक का दावा करते हुए पुलिस थाने जा पहुंचा। इस पर जो कहानी सामने आई, उसके बाद मांगू रहस्यमय तरीके से सपरिवार गायब है। मांगू की तरह इस खेल में अन्य कई गरीब भील परिवारों के नाम सामने आ रहे हैं। आसींद कस्बे में ही मांगू, रतन व अन्य भील लोगों के नाम कुछ वर्ष पहले लगभग 9 हैक्टेयर भूमि खरीदी गई।

पढ़ें **गरीबों** @ पेज 11

खातों में लाखों-करोड़ों का लेन-देन

इन आदिवासियों के नाम यह कारोबार आसींद से शुरू होकर उदयपुर की खानों तक पहुंच चुका है। इनके नाम से बैंक खातों में लाखों-करोड़ों का लेन-देन हो रहा है। हकीकत यह है कि ये आदिवासी मनरेगा के जरिए पेट पालने तक सीमित हैं। ऐसा ही एक मामला उदयपुर के लसाड़िया में सामने आया। यहां एक खान को शम्भू, रामप्रसाद व अन्य को एग्रीमेंट कर दिया। बाद में सामने आया कि खान तो मांगू भील के नाम है।

थाने पहुंचा मामला तो हुआ खुलासा

1 **सबसे** पहले एफआइआर उदयपुर के कानोड़ थाने में मांगू ने दर्ज कराई। उसने कहा कि लसाड़िया में 2.9215 है. खान का पट्टा मेरे नाम है। खान पर मांगीलाल गुर्जर अवैध रूप से खनन कर रहा है। उसने रामेश्वर गुर्जर, शंभूलाल गुर्जर व सत्येन्द्र मीणा को भी आरोपी बताया।

2 इसके बाद आसींद थाने में सत्येन्द्र ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि शम्भू व रामप्रसाद ने खान का एग्रीमेंट किया था लेकिन जिस फर्म के माध्यम से एग्रीमेंट किया, उसके नाम तो खान का लीज पट्टा ही नहीं है।

3 एक एफआईआर विनोद काठोत ने दर्ज कराई। इसमें भी शम्भू, रामप्रसाद व अन्य के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं।

4 आइएएस बने, चारों ही रसूखदार

मंत्री के पति डॉ. घनश्याम और सीएम के सलाहकार की बहन भी आइएएस

गैर प्रशासनिक सेवा के 4 अधिकारियों को पदोन्नति

सीताराम जाट

डॉ. घनश्याम

शरद मेहरा

हेमपुष्पा शर्मा

जयपुर @ पत्रिका . राज्य में गैर प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन को लेकर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों और राज्य सरकार के बीच महीनों से चल रहे विवाद का गुरुवार को पटाक्षेप हो गया। केन्द्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने राज्य के गैर प्रशासनिक सेवा के चार अधिकारियों को आइएएस में पदोन्नत करने की अधिसूचना जारी कर दी।

मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की केबिनेट में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश के पति डॉ. घनश्याम का गैर प्रशासनिक से आइएएस में चयन हुआ है।

पढ़ें 4 आइएएस @ पेज 13

फूटा लैटर बम

एंटीलिया केस: मुंबई के पूर्व कमिश्नर का सीएम को खत

'गृहमंत्री देशमुख ने वाझे को दिया था 100 करोड़ रुपए की मंथली वसूली का टारगेट'

सिंह ने कहा- देशमुख अपने घर में बुलाकर वाझे को उगाही के निर्देश देते थे

महाराष्ट्र के सीएम ठाकरे ने देर रात बुलाई गठबंधन दलों की आपात बैठक

मुंबई@पत्रिका. एंटीलिया मामले में अब सियासी बवाल शुरू हो गया है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है। इसमें आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाझे को हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूली का टारगेट दिया था। पत्र परमबीर सिंह के लैटरहैड पर लिखा गया है, लेकिन उस पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। इस पत्र के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने शनिवार देर रात महाराष्ट्र सरकार के गठबंधन दलों की बैठक भी बुलाई। गृहमंत्री देशमुख का इस्तीफा लिया जा सकता है।

पढ़ें गृहमंत्री @ पेज 14

परमबीर सिंह

1,750 बार-रेस्टोरेंट से कर लो उगाही

पत्र में परमबीर सिंह ने आरोप लगाया कि देशमुख ने सचिन वाझे को कई बार घर बुलाया और कहा था कि मुंबई में 1750 बार और रेस्टोरेंट हैं। सभी से 2 से 3 लाख रुपए उगाही की जाए तो 40 से 50 करोड़ हर महीने इकट्ठे किए जा सकते हैं। बाकी पैसा दूसरे स्रोतों से जुटाया जा सकता है। फरवरी में जब वाझे गृहमंत्री के घर गए तो वहां सचिव पलांडे के अलावा एक-दो अन्य स्टॉफ भी मौजूद थे।

देशमुख का इस्तीफा संभव

मामले में देशमुख पर इस्तीफे का दबाव है। सीएम ठाकरे ने गठबंधन सरकार की बैठक देर रात बुलाई। सूत्रों की मानें तो एनसीपी मुखिया शरद पवार ने सीएम से फोन पर बात की।

डेलकर केस पर भी असर

सिंह ने लिखा, देशमुख ने सांसद मोहन डेलकर खुदकुशी की जांच प्रभावित करने की कोशिश की थी। डेलकर 22 फरवरी को मृत मिले थे। देशमुख चाहते थे कि आत्महत्या केलिए उकसाने का केस मुंबई में दर्ज हो, ताकि लाभ मिले।

अनिल देशमुख गृहमंत्री महाराष्ट्र

खुद को बचा रहे हैं सिंह

एंटीलिया-हिरेन केस में वाझे का लिंक नजर आ रहा है। परमबीर सिंह खुद को बचाने के लिए मुझ पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं।

सीएम इस्तीफा लें

आरोप गंभीर हैं, देशमुख को खुद कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते तो सीएम को इस्तीफा ले लेना चाहिए।
–देवेंद्र फडणवीस, पूर्व सीएम

हिरेन केस अब एनआइए को

उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर मिली विस्फोटकों से भरी एसयूवी के मालिक मनसुख हिरेन की मौत की जांच एनआइए को सौंपी गई है। एनआइए ने शुक्रवार रात वाझे को एंटीलिया ले जाकर सीन रिक्रिएट किया।

घूस की हो'ली: तहसीलदार के लिए आरआइ ने ली थी एक लाख की घूस

घर के बाहर एसीबी, चूल्हे पर नोटों की गड्डियां जलाता रहा तहसीलदार

स्वरूपगंज में कार्रवाई की भनक लगी तो पिंडवाड़ा में किया खुद को मकान में बन्द

- लगभग 15-20 लाख रुपए जला देने का अंदेशा
- एसीबी-पुलिस पौने घंटे तक करती रही मशक्कत
- राजस्व निरीक्षक के बाद तहसीलदार भी गिरफ्तार

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

सिरोही/जोधपुर. होली से पहले भ्रष्टाचार का बुधवार को अलग ही रंग नजर आया। सिरोही जिले के स्वरूपगंज में सिरोही तहसीलदार कल्पेश जैन के लिए एक लाख रुपए की रिश्वत लेते राजस्व निरीक्षक (आरआइ) पर्वतसिंह पकड़ा गया।

इसकी भनक लगी तो पिंडवाड़ा में तहसीलदार ने खुद को अपने सरकारी मकान में बन्द कर लिया। एसीबी व पुलिस बाहर खड़ी रही और वह परिवार की महिला के साथ रसोई में गैस चूल्हे पर 500-500 के नोटों की गड्डियां जलाता रहा। अनुमान है कि उसने लगभग 15-20 लाख रुपए जलाए। घटनाक्रम लगभग पौन घंटे तक चलता रहा। आखिर भीतर घुसने के लिए एसीबी व पुलिस टीम को दरवाजा तोड़ना पड़ा। तब जाकर तहसीलदार पकड़ में आया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के उप महानिरीक्षक विष्णुकांत के अनुसार सिरोही में सरकारी भूमि पर आंवले के पेड़ों से छाल उतारने के ठेके हो रखे हैं। नए वित्तीय वर्ष में पुराने ठेकेदार का ठेका ही जारी रखने की एवज में ठेकेदार से 5 लाख रुपए मांगे गए।

पढ़ें **घर** @ पेज 04

रसोई में गैस चूल्हे पर जलाए गए अधजले नोट।

आरआइ ने हाइवे पर बुलाया, रंगेहाथों धरा

घूस की राशि लेने के लिए आरआइ ने ठेकेदार को बुधवार देर शाम स्वरूपगंज में कार्यालय से कुछ दूर हाइवे पर बुलाया। वहां जैसे ही ठेकेदार से एक लाख रुपए लिए, एसीबी पाली के एएसपी नरपतचंद ने उसे रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ के बाद एसीबी की टीम पिंडवाड़ा में सिरोही तहसीलदार बालोतरा (बाड़मेर) निवासी कल्पेश जैन के सरकारी आवास पर पहुंची। इसकी भनक लगते ही जैन ने खुद को मकान में बंद कर लिया।

तहसीलदार कल्पेश

आरआइ पर्वतसिंह

नहीं खोला गेट

चूल्हे पर मिली अधजली मुद्रा

एसीबी के अधिकारी ने समझाते हुए दरवाजा खोलने का आग्रह किया लेकिन तहसीलदार ने दरवाजा नहीं खोला। पौने घंटे तक मशक्कत के बाद आखिर पुलिस और एसीबी ने कटर से दरवाजा तुड़वाया। टीम अंदर पहुंची तो तहसीलदार रसोई में गैस के चूल्हे पर नोटों की गड्डियां जलाता मिला। मौके से लाखों की अधजली मुद्रा जब्त हुई है। एसीबी को अंदेशा है कि 15-20 लाख रुपए जलाए गए हैं।

तहसीलदार के घर में प्रवेश के लिए मशक्कत करती एसीबी टीम।

तबादले के बाद भी तहसीलदार के लिए ली घूस

एसीबी का कहना है कि आरआइ पर्वतसिंह स्वरूपगंज से पहले सिरोही में पदस्थापित रहा था। वह तहसीलदार कल्पेश जैन के अधीन कार्यरत था। स्वरूपगंज स्थानान्तरण होने के बाद भी वह तहसीलदार के लि[ए] रिश्वत लेता रहा।

24 बॉर्डर इंटेलिजेंस चैकियां पुनः शुरू करने का प्रस्ताव

[खं]डपीठ में सीमा जनकल्याण [स]मिति की ओर से दायर जनहित [या]चिका की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता संदीप शाह ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश किया जा चुका है, जिस पर याची के अधिवक्ता ने राज्य के प्रत्युत्तर पर अपना पक्ष रखने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने इस अवधि में केंद्र को भी अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। राज्य ने अपने जवाब में कहा कि सीमावर्ती जिलों में बॉर्डर से 500 मीटर की दूरी तक जिप्सम खनन की कोई माइनिंग लीज या परमिट जारी नहीं किए गए हैं। यहां तक कि सीमा से 1700 मीटर दूरी तक भी कोई माइनिंग लीज नहीं है। सरकार के अनुसार श्रीगंगानगर, बाड़मेर तथा जैसलमेर जिले में सीमा से दस किमी तक कोई लीज नहीं है, केवल बीकानेर जिले में 1700 मीटर से 10 किमी के दायरे में छह माइनिंग लीज हैं और 108 परमिट जारी किए गए हैं। खनन अनुमति प्रभावी नियमों की सख्त अनुपालना करते हुए दी गई है। जब भी अवैध खनन पाया जाता है, तत्काल कठोर कार्रवाई की जाती है।

पढ़ें **राज्य** @ पेज 04

रेवन्यू बोर्ड में 'रेवन्यू' का खेल: दलाल शशिकांत करता था मोबाइल पर बेखौफ डील

आप तो इसी रेट में करो फाइनल, नहीं होने दूंगा कोई दिक्कत...

एक-एक कर खुल रही कई परतें
शर्मा-मेहरड़ा सहित कई थे नेटवर्क में शामिल

अजमेर@ पत्रिका. राजस्व मंडल घूसकांड की परत-दर-परत कलई खुल रही है। मंडल के दोनों निलंबित सदस्य सुनील शर्मा व बी.एल.मेहरडा, दलाल शशिकांत जोशी और अन्य मनमाफिक फैसले कराने और मनमानी कीमत वसूलने में जुटे थे। एसीबी पूरे मामले पर करीब पांच महीने से नजर बनाए हुए थी। गिरफ्तार सदस्यों और दलाल सहित अन्य लोगों के मोबाइल सर्विलांस पर थे। इनके बीच वार्ता को एसीबी ने एफआईआर में शामिल किया है। रिकॉर्डिंग में लेन-देन का खेल चलने की जानकारी मिली है।

दलाल जोशी और परिजन के खातों में मिले ₹16.95 लाख

एसीबी ने शुक्रवार को दलाल शशिकांत जोशी के और उसके परिजनों के चार खातों की जांच की। जिसमें 16 लाख 95 हजार रुपए जमा मिले। अभी एक खाता नहीं खोला गया है। दलाल का एक लॉकर भी है, लेकिन वो चार साल से ऑपरेट नहीं किया गया। लॉकर में कोई सामग्री भी नहीं मिली है।

दलाल शशिकांत और राजस्व मंडल के सदस्यों की बातचीत

■ 4 लाख तैयार रखना..
(31 मार्च, 5.25 बजे)

शशिकांत व उसकी पत्नी के बीच बातचीत होती है। शशिकांत पत्नी को कहता है एक बार होटल जाकर आओ और स्टोर में रखे सूटकेस से 4 लाख रुपए अलग रख देना। लेकिन बाद में कहता है कि टोकरी में रखे पूनम वाले साढ़े तीन लाख में से 50 हजार रुपए मिलाकर कुल 4 लाख रुपए तैयार रखना।

■ ऐसी बातें आउट नहीं होनी चाहिए
(1 अप्रेल, 2.04 बजे)

शशिकांत के मोबाइल से आशुतोष नाम के व्यक्ति से बातचीत होती है। शशिकांत कहता है...तुमने योगेंद्र को शशिकांत से मिलने की बात कह कर मरवा दिया...। योगेंद्र ने पीए को आकर कहा कि मेरी पार्टी साहब (सुनील शर्मा) के पास गई... तो साहब ने यह दिया कि शशिकांत से मिल लेना। योगैन्द्र ने पीए से पूछा...उनके (सुनील शर्मा) के फैसले वही टाइप करवाता है क्या..? फिर शशिकांत फोन से पीए से आशुतोष की बात कराता है। पीए कहता है... वकील साहब मेरे पास आए थे, उन्होंने ये बात कही थी...ऐसी बातें आउट नहीं होनी चाहिए।

■ आप तो फाइनल कर दो... *(4 अप्रेल 2021, 5.54 बजे)*

शशिकांत जोशी और बी.एल.मेहरडा के बीच बातचीत हुई। मेहरडा फोन पर कहता है...प्रकरण में काफी सिफारिश आ रही हैं। उसमें कॉम्पलीकेसी बढ़ने वाली है। इस पर शशिकांत बोलता है...कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, आप तो इसी रेट में फाइनल कर दो। मेहरडा कहता है...इसमें दूसरे पक्ष ने कुछ नहीं किया...। शशिकांत कहता है...उसे छोड़ो आप तो मैं अपने वाले को बुला लूंगा। आप तो फाइनल कर दो। इस पर मेहरडा कहता है... डीबी चेयरमैन की रहेगी, मुझे निकलना पड़ेगा। मेरे पास कोई बड़ा फोन आया तो समस्या हो जाएगी।

■ आप तो 2 लाख की कहना, उसे क्या छोड़ना

4 अप्रेल को बातचीत में शशिकांत कहता है..आप तो अख्तर को बुलाकर लिखवा लो और मैं आ जाता हूं। पार्टी को बुला लेंगे। इस पर मेहरडा कहता है..अख्तर को बुला लिया है, आप बताओ उसमें करना क्या है...। चाहे मुझे हाथ से लिखना पड़े... पर आज इसको फाइनल कर देना ही बेस्ट होगा। शशिकांत कहता है...आप तो कर दो...दिक्कत नहीं आने दूंगा...। मेहरडा कहता है...आप तो पार्टी से ढंग से बात कर लो...अपने पास ही रख लेना...आप दो लाख का कहना...जाट है जाट को क्या छोड़ना।

■ ब्यावर वाले मामले ले आओ... करवा देते हैं
(7 अप्रेल, 7.53 बजे)

शशिकांत के मोबाइल पर हितेश से बातचीत हुई। शशिकांत हितेश को कहता है कि उन मामले में जो ब्यावर पड़े हैं ना कुछ वो ले आओ... करवा देते हैं। फिर साहब लम्बी छुट्टी पर जा रहे हैं। इस पर हितेश ने रजनीकांत या अन्य व्यक्ति से बात कराई तो शशिकांत कहता है... हितेश को भेज दो वो लेकर और जीतू बन्ना वाला भी डिस्कस कर लेंगे।

■ आप आरटीजीएस करवा दो... अकाउन्ट नंबर भेज रहा हूं...
9 अप्रेल 2021 (7.06 बजे)

दलाल शशिकांत और रजनीकांत के बीच बातचीत हुई। शशिकांत कहता है. 4-5 दिन की छुट्टी आएगी। ब्यावर से वो पहुंचवा दो। दूसरे ने कहा आरटीजीएस करवा देता हूं। आप अपने पास से व्यवस्था करवा लो। मैं जब आऊंगा आप को दे दूंगा। शशिकांत कहता है...मैं यहां कपड़े वाले से ले लेता हूं..आप आरटीजीएस करवा दो...अकाउन्ट नंबर हितेश को कर रहा हूं...।

भ्रष्टाचार: नौ माह की नौकरी, वसूली के लिए शिक्षक को रखा दलाल

एसडीएम बोला...मेरी तनख्वाह बहुत कम है, एक लाख की बंधी तो दो

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर . रिश्वत मांगने के मामले में एसीबी के घेरे में आया लसाड़िया एसडीएम (आरएएस) सुनीलकुमार जिंगोनिया खान व्यवसायी से बंधी मांगते हुए सरकार और अपनी ही नौकरी को कोस रहा था। खान व्यवसायी से उसने कहा था, मेरी तनख्वाह बहुत कम है, महीने के एक लाख रुपए बंधी तो दो। यही नहीं, वसूली के लिए जिंगोनिया ने एक शिक्षक को दलाल के रूप में रखा हुआ था।

एसीबी में दर्ज एफआइआर में परिवादी खान व्यवसायी ने बताया, एसडीएम जिंगोनिया ने कहा था कि इतनी सी तनख्वाह में क्या होता है। तीस हजार रुपए मिलते हैं। ऐसी तनख्वाह से घरवाले और रिश्तेदार तक नाराज हैं। तुम एक लाख रुपए महीने की बंधी तो दो। बाद में मामला 50 हजार रुपए में तय हुआ था।

अभी दूसरी पोस्टिंग: जिंगोनिया 2019 बैच का आरएएस है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद पहली पोस्टिंग जुलाई 2020 में खंडार एसडीएम के रूप में हुई। उदयपुर के लसाड़िया में उसकी यह दूसरी ही पोस्टिंग है।

पढ़ें **एसडीएम** @ पेज 11

खंडार से यहां भेजा, अब कहां भेज देंगे?

एसडीएम जिंगोनिया ने बंधी की रकम तय करने के लिए परिवादी को अपने क्वार्टर पर ही बुला लिया। परिवादी को पहले तो हिदायत दी कि मुझे किसी से फोन कराने से कुछ नहीं होगा। खंडार में शिकायत होने पर मुझे यहां भेज दिया, अब और कितनी दूर भेजेंगे? बातचीत आगे बढ़ी तो जिंगोनिया ने दुखड़ा रोया, तुम्हें पता है कि मुझे कितना वेतन मिलता है? केवल 30 हजार रुपए मिलते हैं (जिंगोनिया अभी प्रोबेशन पर है)। मुरलीपुरा (जयपुर) से इतनी दूर यहां पड़ा हूं। एक लाख रुपए की बंधी तो दो।

सिस्टम की लापरवाही 23.04.2021

अस्पताल में नहीं मिली मदद, रैन बसेरे में हो गया प्रसव

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

बांसवाड़ा. भटकते हुए जीवन बसर कर रही एक महिला के प्रसव पीड़ा को सरकारी सिस्टम ने गुरुवार को बढ़ा दिया। एमजी अस्पताल के एमसीएच विंग तक पहुंचने के बाद भी उपचार नहीं मिलने से महिला चीखती-चिल्लाती रही। आखिर में बैरंग लौटने पर रैन बसेरे के स्टाफ की मदद से उसका प्रसव हुआ।

नापला निवासी इंदिरा बताने वाली 35 वर्षीया महिला को गुरुवार दोपहर में प्रसव पीड़ा बढ़ी, तो वह रैन बसेरे लौटी। यहां इंदिरा रसोई के प्रबंधन से जुड़े वेलनेस फाउंडेशन ट्रस्ट के कविंद्र जोशी और मुकेश प्रसाद ने उसकी हालत खराब देखी तो टैम्पो से एमजी अस्पताल भेजा। अस्पताल में उसे एकबारगी बैड पर लिटाया गया, फिर किसी स्टाफ सदस्य ने आधार कार्ड नहीं होना बताकर वापस लौटा दिया। इस पर महिला उसी

ऑटो चालक के साथ वापस रैन बसेरा लौटी। कुछ देर पीड़ा सहती रही महिला के बारे में बाद में जानकारी ट्रस्ट सचिव विनोदकुमार यादव को दी गई तो वे खुद मेल नर्स होने से प्रसव कराने में जुटे। यहां ट्रस्ट अध्यक्ष गोविंदकुमार यादव व अन्य सहयोगियों की मदद से महिला का प्रसव करवाया गया।

बातचीत में महिला अपना और गांव का नाम ही बता पाई। उसे बेटा हुआ, जो पूरी तरह स्वस्थ है। बाद में फिर प्रयास करने पर एंबुलेंस से मदद मिली तो करीब डेढ़ बजे उसे एमजी अस्पताल भेजा गया।

के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से मजबूत होना जरूरी है।

जैसलमेर नाचना स्थित उपनिवेशन उपायुक्त कार्यालय में लगाई आग

जहां करोड़ों का फर्जीवाड़ा, वहां आग लगाकर जलाया रिकॉर्ड

एसीबी ने चार साल पहले शुरू की फर्जीवाड़े की जांच

कुछ रिकॉर्ड चुराने की भी आशंका

नाचना (जैसलमेर) @ पत्रिका . जैसलमेर जिले के नाचना में उपनिवेशन विभाग के उपायुक्त कार्यालय में शुक्रवार रात खिड़की तोड़कर किसी ने आग लगा दी। यहां फर्जीवाड़ा कर करोड़ों की सरकारी जमीनों को खुर्द-बुर्द करने का मामला सामने आने के बाद पिछले 4 साल से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) जांच कर रहा था। पिछले दिनों यह भी खुलासा हुआ था कि राजस्व अदालत के फर्जी आदेश से बड़े स्तर पर जमीनें आवंटित कर दी गई। इन बड़े फर्जीवाड़ों की जांच के बीच अब किसी ने आग लगाकर रिकॉर्ड जला दिया। आशंका है कि जलाने से पहले कुछ रिकॉर्ड चुराए भी गए हैं।

पढ़ें जहां @ पेज 14

नाचना. कमरे में आग से जला सामान। पत्रिका

नियम विरुद्ध लाभ देने का मामला

उपायुक्त अरुणप्रकाश शर्मा के कार्यकाल में 2014 से 2016 के बीच नहरी क्षेत्र में भूमि के दावों में निर्णय देकर डिक्रियां जारी करने व लोगों को गलत तरीके से लाभ देने के आरोप में एसीबी में मामला दर्ज किया गया था। एसीबी ने डिक्रियों से जुड़ी 234 पत्रावलियां 11 अप्रेल 2017 को कब्जे में लेकर जांच शुरू की थी। यह जांच अभी जारी है। फिर मार्च 2021 में विभाग में भूमि आंवटन संबंधी मामलों में अनियमितताओं को लेकर उपनिवेशन आयुक्त बीकानेर ने कार्रवाई कर वरिष्ठ लिपिक को निलंबित किया था। उपनिवेशन तहसील नाचना नंबर-1 के पटवारी को भी एपीओ कर उसका मुख्यालय बीकानेर किया गया था।

जांच नहीं बढ़ाई तो बदला अफसर

नाचना उपनिवेशन उपायुक्त कार्यालय में पूर्व में कई बार अनियमितता के मामले सामने आ चुके हैं। चार साल पहले एसीबी ने मामल दर्ज किया था। हालांकि जांच अधिकारी अनिल पुरोहित ने लम्बे समय तक जांच ही आगे नहीं बढ़ाई। शिकायत पर एसीबी मुख्यालय ने उन्हें हटाकर जांच अब अन्नराज राजपुरोहित को दी है।

बरामदे में बिखरे पड़े थे कुछ कागजात

नायब तहसीलदार की सूचना पर थानाधिकारी रमेश ढाका मौके पर पंहुचे। वहां रीडर कक्ष के बाहर स्थित खिड़की के सरिए व जाली टूटी हुई थी। कुछ कागजात कार्यालय के बरामदे में बिखरे पड़े थे। पुलिस ने आशंका जताई कि आग जान-बूझकर लगाई गई और इससे पहले कुछ कागजात चुराए गए। नायब तहसीलदार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

24-04-2021

तीन जगह भ्रष्टाचार पर धावा | अजमेर, अलवर व हनुमानगढ़ में एसीबी की कार्रवाई

वीडीओ, वकील व ऑपरेटर घूस लेते गिरफ्तार

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

स्टेट डेस्क. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मंगलवार को प्रदेश में तीन जगह भ्रष्टाचारियों पर धावा बोला। अजमेर, अलवर व हनुमानगढ़ में कार्रवाई में वीडीओ, वकील व कम्प्यूटर ऑपरेटर को रंगे हाथ घूस लेते पकड़ा गया। कहीं पट्टे तो कहीं ठेका देने के नाम पर मांगी रिश्वत मांगी गई।

हनुमानगढ़: एमडी के नाम पर मांगी घूस

हनुमानगढ़. दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड में गाड़ी लगवाने के एवज में 40 हजार रुपए की रिश्वत लेते डेयरी के कम्प्यूटर ऑपरेटर योगेश पारीक को एसीबी ने मंगलवार को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी ने डेयरी एमडी के नाम पर घूस की मांग की थी। परिवादी आमोद सिहाग ने शिकायत दी थी। उससे टेंडर करने के एवज में एमडी के लिए आरोपी ने 50 हजार रुपए घूस मांगी। दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड हनुमानगढ़ जंक्शन में मंगलवार को परिवादी को 40 हजार रुपए देकर भेजा गया। आरोपी ऑपरेटर योगेश पारीक ने रिश्वत राशि ले ली। इसके बाद इशारा मिलते ही एसीबी टीम ने धावा बोल दिया। आरोपी के कब्जे से घूस के 40 हजार रुपए बरामद कर लिए।

अलवर: सरकारी वकील बता 15000 मांगे

तिजारा (अलवर). एडीजे कोर्ट तिजारा में चल रहे एक प्रकरण में जमानत कराने के नाम पर सरकारी वकील बनकर अन्य वकील ने परिवादी से 15000 रुपए रिश्वत लेने के मामले में मंगलवार को एसीबी ने आरोपी वकील को दबोच लिया। आरोपी एडवोकेट प्रमोद कुमार है। मामले के अनुसार परिवादी महिला मीना के पुत्र सुमित के खिलाफ भिवाड़ी थाने में प्रकरण दर्ज है। तिजारा कोर्ट कैंपस के एडवोकेट प्रमोद कुमार ने सरकारी वकील त्रिलोकचंद बनकर परिवारी महिला के पुत्र की जमानत कराने के नाम पर 15 हजार रुपए रिश्वत की मांग की।

अजमेर: पट्टा बनवाने की एवज में मांगे 9 हजार

रूपनगढ़ (अजमेर). समीपवर्ती ग्राम पनेर के कार्यवाहक ग्राम विकास अधिकारी कृष्ण मीणा को मंगलवार रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। मीणा ने परिवादी से मकान का पट्टा बनवाने की एवज में नौ हजार रुपए की मांग की थी। रूपनगढ़ उपखण्ड के ग्राम पनेर निवासी पहलवान खान से उसके मकान का पट्टा बनवाने के लिए ग्राम विकास अधिकारी कृष्ण मीणा ने 9 हजार रुपए की मांग की।

66 दिन बाद... पेट्रोल 22 और डीजल 25 पैसे महंगा 05-05-2021

चुनाव खत्म, पेट्रोल के दाम बढ़ना शुरू

जयपुर @ पत्रिका . पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव पूरे होते ही आम आदमी की जेब का भार बढ़ा दिया गया। तेल कंपनियों ने मंगलवार को पेट्रोल 22 पैसे और डीजल 25 पैसे महंगा कर दिया। अब जयपुर में पेट्रोल 96.98 और डीजल 89.45 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोलियम डीलर्स का कहना है कि कंपनियों ने दाम बढ़ाने का सिलसिला जारी रखा तो पेट्रोल के दाम फिर शतक का आंकड़ा छू लेंगे। जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम लंबे समय से स्थिर बने हुए हैं।

चुनावी घमासान शुरू होने के बाद 27 फरवरी को तेल कंपनियों ने पेट्रोल पर 25 पैसे और डीजल पर 17 पैसे बढ़ाए थे।

पढ़ें **चुनाव** @ पेज 13

भारत की इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं होगा।

महुआ से बनेगी यूके में एनर्जी ड्रिंक-शराब

05.05.2021

जगदलपुर. बस्तर का महुआ अब विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा, वहां इससे शराब के साथ औषधि व कई तरह के खाद्य उत्पाद बनाए जाएंगे। वन विभाग इसकी तैयारियों में जुट गया है। इंग्लैंड, आयरलैंड सहित यूरोप के कुछ देशों में बस्तर के महुआ की भारी मांग है। इस वर्ष लगभग 200 क्विंटल महुआ विदेश भेजा जाएगा। स्थानीय वनोपज समितियों को एक्सपोर्ट क्वालिटी के महुआ संग्रहण के लिए प्रशिक्षण दिया गया है।

कुपोषण दूर: फूडग्रेड महुआ संग्रहण के लिए वन विभाग ने दरभा, लोहण्डीगुड़ा और बस्तर ब्लॉक की दो दर्जन से अधिक वन समितियों की मदद ली। महुआ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन पाए जाते हैं, देश में इसका उपयोग कुपोषण दूर करने में किया जा रहा है।

165
मूंग
600
मक
730
तार
505
दल
मोग
86
94
का
मो
95
81
मौ
वि
ध

मौत या हत्या

एमबीएस अस्पताल में आइसीयू में बेड व वेंटिलेटर खाली होने के बावजूद नहीं दिया

डॉक्टर बोला, नेता से फोन करवा दो तभी मिलेगा बेड

मरीज की मौत

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

कोटा. एमबीएस अस्पताल में एक महिला मरीज के इलाज में बड़ी लापरवाही सामने आई है। परिजन का आरोप है कि आइसीयू में बेड व वेंटिलेटर खाली होने के बावजूद उनके मरीज को नहीं दिया। वार्ड में मौजूद डॉक्टर ने मना करते हुए कहा कि आपकी किसी नेता से जान पहचान है तो उनसे फोन करवा दो, आपका काम हो जाएगा।

बीना देवी

आइसीयू में खाली बेड।

दो घंटे तक गिड़गिड़ाते रहे

परिजन ने आइसीयू में जाकर खाली बेड व वेंटिलेटर की फोटो खींचकर डॉक्टर को दिखाई और दो घंटे तक डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन बेड नहीं दिया। आखिरकार महिला की मौत हो गई। घटना बुधवार तड़के की है, गुरुवार को मामला सामने आने पर जिम्मेदार अधिकारी पल्ला झाड़ते रहे। मृतका के नाती चंदन ने बताया कि उसकी नानी महात्मा गांधी कॉलोनी माला फाटक गली नम्बर-2 निवासी बीना देवी (60) की 19 अप्रेल को रात 2 बजे तबीयत खराब हो गई। जांच में कोरोना पॉजिटिव होने पर एमबीएस के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया था। वे ऑक्सीजन पर थीं। बुधवार रात 2 बजे उनकी तबीयत बिगड़ गई। 2 घंटे तक गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन डॉक्टर का दिल नहीं पसीजा। तड़के करीब 4 बजे नानी ने दम तोड़ दिया।

ऐसा हुआ है तो जांच करवाएंगे

इस मामले की कोई सूचना नहीं है। आपने बताया है, इसे दिखवाता हूं। किसी डॉक्टर ने नेता की सिफारिश पर बेड मिलने की बात कही है तो यह गलत है। बेड खाली था तो मरीज को मिलना चाहिए था, नहीं मिला। इसकी जांच कर संबंधित डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

डॉ. नवीन सक्सेना,
अधीक्षक, एमबीएस अस्पताल

9 राज्य, 38 संस्करण | अजमेर • अलवर • अहमदाबाद • इंदौर • उज्जैन • उदयपुर • कोटा • कोलकाता • खंडवा • गंगापुरसिटी • ग्वालियर • चेन्नई • छिंदवाड़ा • जगदलपुर • जबलपुर • जयपुर • जोधपुर • दिल्ली • नागौर • पाली • बाड़मेर • बांसवाड़ा • बिलासपु

हॉट न्यूज

चूरू जिले में सर्वाधिक लापरवाही

प्रदेश में वैक्सीन की करीब 11.5 लाख डोज खराब

बाड़मेर. जिले की विष्णु कॉलोनी स्थित टीकाकरण केंद्र पर अपनी बारी का इंतजार करती महिलाएं, यहां 18+ समूह को टीका लगाया जा रहा है। व्यवस्था बनाए रखने के लिए हाथ पर नंबर लिखा है।

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर . प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सरकार की ओर से अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ जिले वैक्सीन के उपयोग में लापरवाही बरत रहे हैं।

प्रदेश में अब तक 7 प्रतिशत यानी करीब 11.5 लाख डोज खराबे की भेंट चढ़ी हैं। केन्द्र ने खराबे की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत मानी है। चूरू जिले में वैक्सीन के उपयोग में सर्वाधिक लापरवाही बरती गई। जिले में कुल डोज में से 39.7 प्रतिशत वैक्सीन खराब हो गई। वहीं जयपुर प्रथम में खराबे का प्रतिशत 4.67 और द्वितीय में 1.31 रहा है। उपयोग के लिहाज से रेड जोन में चूरू के साथ 13 जिले शामिल हैं। जहां 6.31 से 39.37% तक वैक्सीन खराब कर दी गई। चिकित्सा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक श्रीगंगानगर, उदयपुर, बांसवाड़ा, झुंझुनूं और जैसलमेर जिलों में उपयोग अधिक हुआ।

पढ़ें **प्रदेश** @ पेज 09

जिलेवार वेस्टेज%

जिला	%	जिला	%
चूरू	39.37	नागौर	5.43
हनुमानगढ़	24.60	बीकानेर	5.07
भरतपुर	17.13	जयपुर प्रथम	4.67
कोटा	16.71	करौली	4.59
चित्तौड़गढ़	11.81	टोंक	4.36
जालोर	9.63	डूंगरपुर	3.41
सीकर	8.83	बारां	3.38
अलवर	8.32	पाली	2.92
धौलपुर	7.89	जोधपुर	2.75
अजमेर	6.75	राजसमंद	2.07
दौसा	6.65	भीलवाड़ा	1.72
स.माधोपुर	6.43	प्रतापगढ़	1.36
झालावाड़	6.31	सिरोही	1.33
बूंदी	5.81	जयपुर	1.31
बाड़मेर	5.78		

यहां वेस्टेज नहीं

जिला	
श्रीगंगानगर माइनस	0.26
उदयपुर माइनस	1.27
बांसवाड़ा माइनस	1.93
झुंझुनूं माइनस	3.32
जैसलमेर मानइस	10.2

ये जिले रेड जोन में

चूरू, हनुमानगढ़, भरतपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, जालोर, सीकर, अलवर, धौलपुर, अजमेर, दौसा, सवाईमाधोपुर और झालावाड़।

बड़ा झांसा : बालियां तो खूब आईं, लेकिन दाने नहीं

'नर-नारी' धान के बीज के नाम पर ठगे गए किसान, मुआवजे पर साधी चुप्पी

बीरेन्द्र शर्मा
patrika.com

भिलाई. छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक में 40 गांवों के 250 किसान, बीज उत्पादन करने वाली बायर सीड प्रोडक्शन कंपनी के झांसे में फंस गए हैं। कंपनी के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में इन किसानों ने करीब 1200 एकड़ में हाइब्रिड धान नर- नारी की खेती की। शुरुआत में फसल अच्छी रही। भरपूर बालियां भी निकलीं। जब कटाई की पारी आई तो देखा बालियों में दाने ही नहीं पड़े। करार पर बीज की खेती कराने वाली कंपनी अब किसानों से बीज खरीदने में दिलचस्पी नहीं ले रही है। मुआवजा देने में भी टालमटोल कर रही है।

ऐसी होती है नर-नारी धान की खेती

रबी के मौसम में खेती की जाती है। कंपनी ने किसानों को नर-नारी धान की दो किस्म के बीज बुआई के लिए दिए। नर को एक कतार में और नारी धान को तीन से चार कतार में लगाया जाता है। जब धान में गर्भ का समय आता है तो प्रजनन की प्रक्रिया कराई जाती है। 15 दिनों तक प्रतिदिन नर-नारी धान को रस्सी के सहारे मिलाते हैं। मजदूरी का भुगतान किसान करता है।

एक एकड़ में तीन किलो पैदावार हुई

रहटादाह के किसान मुकुतराम मरकाम ने बताया कि पहली बार 6 एकड़ में खेती की। प्रति एकड़ 2-3 किलो ही पैदावार हो रही है। किसान सरपंच भूषण सिंह ने बताया कि कंपनी के कहने पर 20 एकड़ में खेती की। नारी धान में बालियां आई हैं, दाने नहीं आए।

छत्तीसगढ़ में बायर सीड प्रोडक्शन कंपनी ने धमधा, धमतरी, जांजगीर जिले में सीड प्रोडेक्शन कार्यक्रम की अनुमति ली है। बड़ी कंपनी है, इंश्योरेंस किया होगा। अभी फसल कटिंग शुरू नहीं हुई होगी। फिलहाल, गांव में विभागीय अधिकारियों को भेजकर जांच करवाता हूं। किसानों का नुकसान हुआ है तो कंपनी मुआवजा देगी। **-रविन्द्र चौबे,** कृषि मंत्री, छत्तीसगढ़

बॉम्बे हाईकोर्ट में 12 घंटे में 80 मामलों की सुनवाई

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट में बुधवार को मैराथन सुनवाई का दौर चला। इस दौरान हाईकोर्ट की बेंच ने 12 घंटे से ज्यादा समय 80 मामलों की सुनवाई की। जस्टिस एस.जे. काथावाला व जस्टिस एस.पी. तावड़े की बेंच सुबह 10:45 बजे बैठी। वह बिना ब्रेक लिए देर रात 11:15 बजे तक सुनवाई करती रही। जिन मामलों की सुनवाई की, उनमें एलगार परिषद मामले के आरोपी स्टेन स्वामी व हनी बाबू की फाइल, पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआइ जांच के संबंध में महाराष्ट्र सरकार की याचिका शामिल है। जस्टिस काथावाला ने तीन साल पहले भी 16 घंटे बैठकर आधी रात बाद 3:30 बजे तक सुनवाई की थी।

मध्य प्रदेश : मास्क नहीं लगाने पर महिला से पुलिस की बर्बरता

सागर. मास्क नहीं लगाने पर बेटी के सामने मां से पुलिस द्वारा बर्बरता किए जाने का वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद एक एएसआइ और महिला आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही डीएसपी को जांच सौंपी गई है। घटना तीन दिन पुरानी है।

सिरोही

शराब का जखीरा पकड़ने का मामला

01-06-2021

पुलिस अफसर ही करा रहा था शराब की तस्करी!

ओमप्रकाश शर्मा
patrika.com

जयपुर . आबकारी टीम ने रविवार को सिरोही के सरूपगंज में शराब का जो जखीरा पकड़ा, वह पुलिस की मिलीभगत से दूसरे राज्यों से यहां पहुंचा था। फिर मिलीभगत से कई जगह पहुंचाने की तैयारी थी। पकड़े गए आरोपियों से ये तथ्य सामने आने के बाद पुलिस मुख्यालय ने रेंज आइजी नवज्योति गोगोई को जांच के निर्देश दिए हैं। गोगोई ने जालोर की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुकृति उज्जेनिया को जांच सौंपी है।

दरअसल, आबकारी विभाग को पहले से सूचना थी कि गिरोह के तार पुलिस से जुड़े हैं। इसी कारण 5 जिलों से दस्ता बुलाया लेकिन सिरोही में किसी को भनक नहीं लगने दी। वहां भुजेला में हरियाणा समेत अन्य राज्यों से लाई गई शराब से भरे 15 वाहन जब्त किए। आबकारी अधिकारियों ने वाहनों समेत बरामद शराब की कीमत 5 करोड़ बताई है। मिलीभगत के कारण ही उक्त कार्रवाई से शराब तस्करों से कहीं अधिक हड़कम्प जिला पुलिस में मचा।
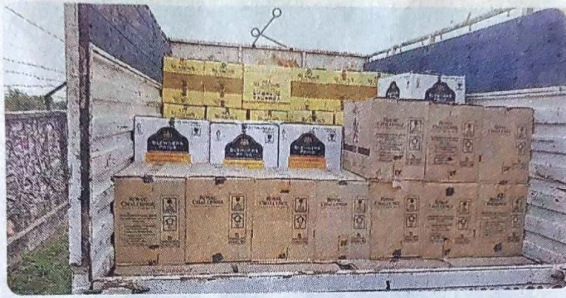
पढ़ें **पुलिस** @ पेज 06

लम्बे समय से चल रहा था खेल

कार्रवाई डूंगरपुर, भीनमाल, अलवर व अजमेर की संयुक्त टीम ने की थी। यहां 2 आइचर ट्रक, 4 पिकअप मिनी ट्रक व 9 लग्जरी कारों में भारी मात्रा में शराब पकड़ी। मौके से 1880 कर्टन हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश व दिल्ली निर्मित शराब जब्त की। यहां लम्बे समय से शराब डम्प कर छोटे वाहनों व ट्रकों में लाइन के रूप में गुजरात ले जाने का अवैध कारोबार चल रहा था था।

अधिकारी की भूमिका कई मामलों में संदिग्ध

प्राथमिक रूप से मामले में जिले के उच्च पदस्थ अधिकारी की संदिग्ध भूमिका सामने आ रही है। उक्त उच्चाधिकारी की भूमिका पहले भी कई मामलों में संदिग्ध रही है।

जांच में खुलासा होगा

कुछ जानकारियां सामने आई हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जांच सौंपी है। उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि किस-किस की मिलीभगत है। **नवज्योति गोगोई,** रेंज महानिरीक्षक, जोधपुर

मीटर या चीटर

मीटर वितरण पर लगाई रोक, टेस्टिंग में मिली कई गड़बड़ी

02-06-2021

यह कैसा चमत्कार : बिजली बंद पर मीटर चालू

भवनेश गुप्ता
patrika.com

जयपुर. जयपुर डिस्कॉम में सिंगल फेज मीटरों में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। टेस्टिंग में कुछ मीटरों ने बिना उपभोग ही यूनिट दिखा दी तो कुछ ने उपभोग से अधिक यूनिट दर्शाई। प्राथमिक स्तर पर की गई जांच में दस मीटरों में तो विद्युत सप्लाई बंद करने के बाद भी रीडिंग दर्ज की गई। गड़बड़ी सामने आने के बाद डिस्कॉम के अधिकारियों की नींद टूटी और 13 जिलों में स्टोर से मीटर वितरण पर रोक लगा दी।

पढ़ें यह @ पेज 07

13 जिलों में लगाए जा चुके सभी मीटर की होगी जांच

रेण्डम जांच : इन मीटर में रीडिंग का गड़बड़झाला

डिस्कॉम ने अनुबंधित कंपनी से (अनुबंध खरीद संख्या टीएन 2355) मीटर खरीदे और इनके प्रतिनिधियों के सामने मीटर की रेण्डम जांच कराई। इनमें मीटर संख्या 4169482, 4169140, 4297628, 4220049, 4194741, 4199785, 4291492, 4290304, 4198838, 4166352 के ये मीटर भी हैं। इनमें सप्लाई बिना भी एकाएक रीडिंग आने की स्थिति सामने आने का दावा किया गया है। सही मीटर और इस मीटर में 8 यूनिट तक का अंतर आया है।

मीटर में गड़बड़ी होने की रिपोर्ट के आधार पर सभी जिलों के सर्किल ऑफिस में मीटर जारी नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे ज्यादा जानकारी अधीक्षण अभियंता (एमएम) दे सकते हैं। **विनय शर्मा,** अधीक्षण अभियंता (आइएण्डएस), जयपुर डिस्कॉम

मैं जानकारी देने के लिए अधिकृत नहीं हूं। निर्णय उच्च स्तर पर होना है। **आर.के शर्मा,** अधीक्षण अभियंता (एमएम), जयपुर डिस्कॉम

जवाब मांगते सवाल...

- **इन** मीटरों में गड़बड़ी मिली है तो क्या 13 जिलों में लगाए जा चुके सभी मीटरों की जांच होगी। क्योंकि इसके बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी कि कुछ ही मीटर खराब हैं या सभी में गड़बड़ी है।
- **खरीद** के समय ही मीटर की जांच की जाती है। तो क्या उस समय जो मीटर टेस्टिंग के लिए भेजे गए थे, उनके अलावा बचे मीटर की अच्छी तरह से जांच नहीं की गई।
- **यह** मामला दो माह पहले सामने आ चुका है तो अब तक प्रभावी एक्शन क्यों नहीं लिया गया।

करीब-करीब प्रदेश के सभी लॉकडाउन लगाया था।

शर्मनाक: खेल प्रतियोगिता में चयन कराने के नाम पर फंसाया 02-06-2021

नाबालिग खिलाड़ी से बलात्कार, कोच गिरफ्तार

टूर्नामेंट का झांसा दे उदयपुर ले गया, होटल में भी किया बलात्कार

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. ज्योतिनगर थाना पुलिस ने नाबालिग खिलाड़ी से बलात्कार के मामले में सवाई मानसिंह स्टेडियम के एक कोच को गिरफ्तार किया। कोच ने खेल प्रतियोगिता में चयन करवाने का झांसा देकर नाबालिग से नजदीकी बढ़ाई, फिर बलात्कार किया।

पुलिस ने बताया कि 17 वर्षीय पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसमें बताया कि गत वर्ष नवम्बर में बेटी को स्टेडियम में भेजा था। दिसम्बर में आरोपी कोच मदद करने का झांसा देकर बेटी से अधिक बातचीत करने लगा। खेल प्रतियोगिता में चयन करवाने के बहाने नजदीकी बढ़ाई। आरोपी ने खेल प्रतियोगिता में चयन करवाने का झांसा दिया और पीड़िता से बलात्कार किया। फिर मार्च में एक टूर्नामेंट होने का बहाना बनाकर नाबालिग को उदयपुर ले गया। वहां दो दिन तक पीड़िता को एक होटल में रखा और बलात्कार किया।

मोबाइल से खुलासा

पीड़िता कुछ दिन से गुमसुम और सहमी हुई थी। तब पीड़िता की मां ने बेटी से पूछताछ की और उसका मोबाइल देखा तो कोच की करतूत का पता चला। पीड़िता के परिजन ने सोमवार रात थाने पहुंचकर कोच के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने अनुसंधान के बाद मंगलवार को उसे गिरफ्तार कर लिया।

15 जून से लागू होगी हॉलमार्किंग, ज्वैलर्स कर रहे कोड हटाने की मांग

कानून इतना सख्त कि छोटी ज्वैलरी तक का देना होगा हिसाब

एक्सक्लूसिव

पोर्टल पर देनी होगी यूआईडी और जेवर की फोटो

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जोधपुर. केन्द्र सरकार 15 जून से स्वर्णाभूषणों के लिए हॉलमार्क की अनिवार्यता लागू कर रही है। इसके तहत लागू किए जा रहे हॉलमार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड (एचयूआइडी) को लेकर देशभर के ज्वैलर्स असमंजस में हैं। ये लोग हॉलमार्किंग का तो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन यूआईडी कोड इनके गले नहीं उतर रहा। ज्वैलर्स के मुताबिक एचयूआईडी के साथ ज्वैलर्स को 2 ग्राम से ज्यादा वजनी ज्वैलरी खरीदने वाले ग्राहक का नाम, पता और मोबाइल नंबर की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। ज्वैलरी खरीद का पूरा ब्यौरा सरकार के पास होगा। इससे सबसे बड़ा नुकसान रिटेल व्यापार को होगा, क्योंकि जेवर यदि किसी थोक व्यापारी से खरीदा गया है तो वह जानकारी भी लीक होगी। इसके साथ ही, ज्वैलर्स इन कानून के उल्लंघन पर न्यूनतम एक लाख रुपए और वस्तु के मूल्य का पांच गुना तक जुर्माना, लाइसेंस रद्दीकरण व इसके साथ एक साल जेल का प्रावधान से भी चिंतित हैं।

सोने की शुद्धता अब तीन ग्रेड में

सोने की शुद्धता अब तीन ग्रेड में होगी। पहला 22 कैरेट, दूसरा 18 और तीसरा 14 कैरेट। इससे कस्टमर और ज्वैलर दोनों को फायदा होगा। क्वालिटी को लेकर किसी के मन में संशय नहीं रहेगा।

हॉलमार्किंग अनिवार्यता से किसी को आपत्ति नहीं, मगर यूआईडी कोड लागू नहीं होने देंगे। इस कानून के उल्लंघन पर गिरफ्तारी की धारा व लाइसेंस रद्द करने के प्रावधान स्वीकार्य नहीं है। सरकार हॉलमार्किंग की आड़ में गोल्ड कंट्रोल एक्ट जैसे सख्त नियम लाद रही है।

नवीन सोनी, उपाध्यक्ष, इंडिया बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन, राजस्थान

कोरोना से बिक्री व हॉलमार्किंग में आई कमी

राजस्थान में 21 और देशभर में करीब 900 हॉलमार्किंग सेंटर हैं। इनमें असम-त्रिपुरा को छोड़ पूर्वोत्तर राज्यों व सात केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली-पुडुचेरी को छोड़ कहीं भी हॉलमार्क सेंटर नहीं है। वर्ष 2018-19 में करीब 4.50 करोड़ गहनों की हॉलमार्किंग की गई थी। कोविड के कारण 2020-21 में गहनों की बिक्री और हॉलमार्किंग में भारी कमी आई है।

स्वास्थ्य से खिलवाड़

होली पर लिए खाद्य पदार्थों के 19 में से 6 नमूने मिलावटी
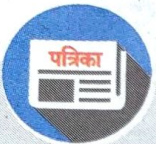
एक्सक्लूसिव

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जोधपुर. चिकित्सा विभाग की ओर से होली पर लिए गए खाद्य पदार्थों के 19 नमूनों में से 6 मिलावटी शामिल हुए। विभाग के 22 से 29 मार्च तक चले शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के लिए गए नमूनों में से 3 सब-स्टैण्डर्ड व 3 अनसेफ पाए गए हैं। सब स्टैण्डर्ड यानी अमानक पाए गए नमूनों के लिए विभाग संबंधित व्यापारियों पर जुर्माना लगाएगा, जबकि अनसेफ पर पाए गए नमूनों के लिए अदालत में चालान पेश किया जाएगा।

घी में सर्वाधिक गड़बड़

जानकारों का कहना है कि पूरे देश में सर्वाधिक घी की खपत वाले जोधपुर में मिलावट आम है, लेकिन घी में मिलावट करने वालों पर कार्रवाई के बहुत कम मामले सामने आते हैं। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग व पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठते रहे हैं।

ये सैंपल हो गए फेल

अभियान के दौरान बिलाड़ा में लिया गया सौंफ का नमूना सब स्टैण्डर्ड निकला। नागौरी गेट क्षेत्र में लिए गए पेड़े के नमूने अनसेफ पाए गए। सरदारपुरा बी रोड पर एक नमकीन से लिया गया नमूना भी अनसेफ पाया गया। झालामंड बायपास सर्किल की दुकान से लिए गए मिल्क केक के नमूने को अनसेफ माना गया। इसी तरह कृषि मंडी मंडोर में कोकोनट पाउडर और माता का थान से लिए गए मिर्ची पाउडर के नमूने सब स्टैण्डर्ड निकले।

शेष वाहनों को वापस लौटा दिया। अचानक पुलिस की सख्ती को लेकर चर्चाएं रही। ऐसे में पुलिस के अधिकारी भी अचानक से बढ़ाई सख्ती को लेकर संतोष जन

रसद विभाग की बड़ी लापरवाही: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर लेने का दबाव

केन्द्र से पिछले साल आया चना, बंटा नहीं, अब हो गया खराब

2000 क्विंटल से अधिक बंटा नहीं और गोदामों में पड़ा सड़ता रहा

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

सीकर. *पिछले लॉकडाउन में केन्द्र सरकार की ओर से भेजा गया चना राज्य में अब तक नहीं बंट सका है। रसद विभाग की लापरवाही से कई* जिलों में यह चना गोदामों में पड़ा सड़ रहा है। अब महिला एवं बाल विकास विभाग के ध्यान में यह मामला आया तो जिला कलक्टरों को अलर्ट किया गया है।

दरअसल, पिछले साल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 19963 मैट्रिक टन और आत्मनिर्भर योजना में 3970 मैट्रिक टन साबूत चना भेजा गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के कार्डधारियों को भी एक-एक किलो चना दिया गया था। अब रसद विभाग ने बचे हुए चने आंगनबाड़ी केन्द्रों के जरिए गर्भवती महिलाओं को बांटने के आदेश दिए हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार प्रदेश के 15 जिलों में अभी भी दो हजार क्विंटल से अधिक चना पड़ा हुआ है।
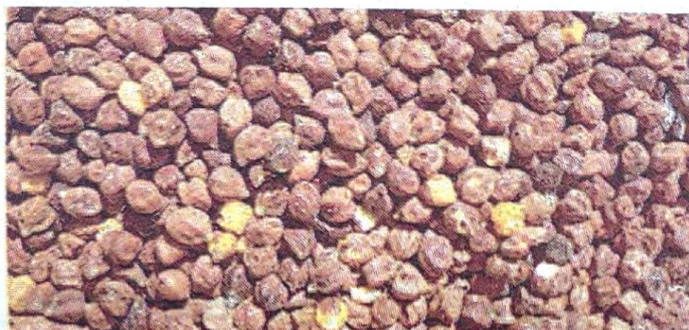
राशन दुकानों में एक साल से पड़ा चना। जो अब खाने योग्य नहीं है।

आदेशों का इंतजार करते रहे राशन डीलर

इधर, ज्यादातर राशन डीलरों का कहना है कि हमारे पास चना पड़ा रहा, लेकिन सरकार की ओर से कोई आदेश नहीं दिए गए। नवम्बर महीने में पॉश मशीने से चने का ऑप्शन भी हटा दिया गया। डीलर भी चने के नए आदेशों को लेकर इंतजार करते रहे। सालभर से पड़े हुए चने से बदबू आने लगी लगी है।

कलक्टरों से कराई जा रही ऑडिट

रसद विभाग ने अब जिला कलक्टरों से चने की ऑडिट कराने की तैयारी शुरू कर दी है। कलक्टरों की ओर से जारी आदेश में बताया कि जो चना खाने योग्य है उसको नजदीकी आंगनबाड़ी केन्द्र पर दिया जाए। यदि खाने योग्य नहीं है तो उस पर फैसला बाद में लिया जाएगा।

पिछले साल जो चने आए थे उसका ज्यादातर स्टॉक सीकर में बंट गया था। किसकी लापरवाही से यह रखा रहा, इसकी जांच भी होगी। अब सभी सेंटरों के जरिए खाने योग्य चने का पता लगाया जा रहा है। इसके बाद ही पता लग सकेगा कि कितना चना खराब हो गया। **-अविचल चतुर्वेदी,** जिला कलक्टर, सीकर

जो चना खाने योग्य नहीं है वह कार्यकर्ताओं को लेना ही नहीं है। सभी को यही निर्देश दिए है कि जो खाने योग्य चना है और केन्द्र पर आवश्यकता है तो आवंटन कराए। विभाग के पास पहले कोई स्टॉक नहीं था। **-सुमन पारीक,** उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग

कई स्थानों पर रसद विभाग बना रहा दबाव

प्रदेश में कई स्थानों पर अब रसद विभाग की ओर से महिला एवं बाल विकास विभाग की मानदेय कर्मचारियों के उपर खराब चना लेने का दबाव भी बनाया जा रहा है। सवाईमाधोपुर, बांसवाडा, जोधपुर, उदयपुर सहित कई जिलों में इस तरह की शिकायत भी उच्च अधिकारियों तक पहुंची है।

कोरोना वॉरियर्स दम्पती की मौत, बेटियों को मदद की दरकार   चित्तौड़गढ़: भाजपा नेत

ग्रेटर नगर निगम : शहरी सरकार में तख्तापलट की तैयारी!

आधी रात महापौर निलंबित

सौम्या समेत 4 पार्षदों की सदस्यता निलंबित

न्यायिक जांच करने का फैसला, दोष साबित तो सदस्यता से हटा सकेंगे

आगामी 6 साल तक पुनर्निर्वाचन पर भी लग सकती है रोक

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com 07-06-2021

जयपुर. राज्य सरकार ने रविवार देर रात बड़ा कदम उठाते हुए जयपुर के ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर (बतौर सदस्य) और तीन पार्षदों को निगम की सदस्यता से निलम्बित कर दिया।

तीनों पार्षद पारस जैन, शंकर शर्मा और अजय सिंह चौहान को प्रारंभिक जांच में निगम के आयुक्त से मारपीट, धक्का-मुक्की करने, अभद्र बोलते हुए राजकीय कार्य में बाधा डालने का दोषी माना है। महापौर सौम्या गुर्जर को अभद्र बोले, राजकीय कार्य में बाधा डालने, उनकी उपस्थिति व सहमति से पार्षदों द्वारा मारपीट, धक्का-मुक्की करने का दोषी माना गया है।

स्वायत्त शासन मंत्री की लिखित स्वीकृति के बाद विभाग के निदेशक दीपक नंदी ने निलंबन आदेश जारी किए। इससे राज्य के राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। इसे कांग्रेस सरकार द्वारा शहरी सरकार के तख्ता पलट की तरफ बढ़ाए गए पहले कदम की तरह देखा जा रहा है। यहां अभी भाजपा का बोर्ड है।

पढ़ें **आधी** @ पेज 06

टाइम लाइन

- **दोपहर 2 बजे** तक का समय दिया जांच अधिकारी क्षेत्रीय उप निदेशक रेणु खण्डेलवाल ने बयान दर्ज कराने के लिए।
- **शाम 6 बजे** जांच रिपोर्ट सौंपी।
- **शाम 6.30 बजे** स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक को सौंपी जांच रिपोर्ट।
- **रात 8 बजे** निदेशक दीपक नंदी विधि विशेषज्ञों और अफसरों की टीम के साथ ऑफिस पहुंचे।
- **रात 10.15 बजे** स्वायत्त शासन मंत्री से निलंबन की स्वीकृति ली।
- **रात 11.30 बजे** निदेशक ने निलंबन के आदेश जारी किए।

कोर्ट का रास्ता खुला है। जनता ने भाजपा का बोर्ड चुना, उसे राज्य सरकार पचा नहीं पा रही। आयुक्त भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनका सरकार समर्थन कर रही है। पक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक भी कार्य दिवस का समय दिए बिना विधि विरुद्ध एक तरफा कार्रवाई की गई है, यह न्याय संगत नहीं है। **सौम्या गुर्जर**, महापौर

इन पार्षदों को किया निलंबित

पारस जैन

अजय चौहान

शंकर शर्मा

इस धारा के तहत जांच

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (1) (घ) (द्वद्व) में उल्लेखित कृत्य होने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 39 (1) के तहत जांच की गई। क्षेत्रीय उपनिदेशक रेणु अग्रवाल ने जांच रिपोर्ट सौंपी।

इस प्रावधान के तहत दोषी माना

राज्य सरकार ने धारा 39 (1) (घ) (ii) (iii) (iv) के तहत दोषी माना। इसमें तीन बिन्दु अंकित हैं।

सदस्य अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी पाया गया।

निकृष्ट आचरण का दोषी।

सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ रहा।

अब न्यायिक जांच, सदस्यता पर तलवार

1. **धारा** 39 (3) के तहत जिला न्यायाधीश रैंक के किसी न्यायायिक अधिकारी से जांच कराई जाएगी।
2. **न्यायिक** जांच अधिकारी सदस्य को सुनवाई का पूरा मौका देगा और जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। इस आधार पर राज्य सरकार चाहे तो दोबारा जांच करा सकती है या अंतिम आदेश पारित करेगी।
3. **अध्यक्ष** (महापौर) को हटाने से पहले उसे सुनवाई-स्पष्टीकरण का पूरा अवसर देना होगा।
4. **राज्य सरकार** के स्तर पर पारित प्रत्येक अंतिम आदेश राजपत्र में प्रकाशित होगा और यह अंतिम होगा। ऐसे किसी भी आदेश को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

छह साल तक पुनर्निर्वाचन पर रोक

जिस सदस्य को धारा 39 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन हटा दिया गया हो, वह 6 वर्ष तक पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य नहीं रहेगा।

विनाश काले विपरीत बुद्धि...। इतिहास गवाह है, देश में जून में ही आपातकाल लगा था और कांग्रेस के पतन की शुरुआत हुई। महापौर और पार्षदों का निलंबन दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, यह राजस्थान में कांग्रेस के पतन का कारण भी बनेगा। पार्टी हर तरीके से न्याय की लड़ाई लड़ेगी। **सतीश पूनिया,** प्रदेशाध्यक्ष, भाजपा

मशहूर कव्वाल मईद साबरी

कोरोना : प्रदेश में 904 नए मरीज मिले, 25 की मौत

राजस्थान पत्रिका patrika.com

जोधपुर, मंगलवार, 08 जून, 2021

तेल-दाम पर देस भी, खूब बजा ली बीन !!

मजबूरी और प्यास की यह कैसी तस्वीर: जालोर के रानीवाड़ा में रोडा गांव का मामला

पानी नहीं मिला तो भरी दोपहरी बीच रास्ते मासूम ने दम तोड़ा

पैदल ही 15 किमी के सफर पर निकली नानी और नातिन

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

जालोर/ रानीवाड़ा. पानी अब भी आम व्यक्ति के हलक से कितना दूर है, ये रानीवाड़ा की इस घटना से स्पष्ट हो गया। घर-घर, गांव-गांव पानी उपलब्ध कराने का सरकारें लाख दावा करें, आम व्यक्ति तक पानी की पहुंच अब भी दूर को कोड़ी ही है। रानीवाड़ा कस्बे से मात्र 10 किमी की दूरी पर पानी की कमी से एक मासूम की जान चली गई।

घटनाक्र म रविवार दोपहर का बताया जा रहा है। इस दौरान बुजुर्ग महिला सुकी देवी और बच्ची को बेसुध देखकर ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन को सूचित किया, जिसके बाद दोनों को रानीवाड़ा अस्पताल लाया गया। जहां पर अंजली (5) पुत्री सरवन भील को मृत घोषित कर दिया गया। जबकि बुजुर्ग महिला की हालत ठीक है।

रानीवाड़ा क्षेत्र का रोडा गांव में रेतीला है। नानी और नातिन रायपुर से डूंगरी गांव की तरफ भरी दोपहरी में लौट रहे थे। रविवार दोपहर में गर्मी का असर बहुत अधिक था। जिसके कारण दोनों की तबीयत खराब होने लगी। रास्ते में पानी के लिए बुजुर्ग महिला ने मशक्कत की, लेकिन आस पास पानी नहीं मिला। जिससे दोनों बेसुध हो गईं। मौत के बाद बच्ची का शव ननिहाल पक्ष को सुपुर्द कर दिया गया।

ये फोटो आपको विचलित कर सकते हैं, लेकिन हकीकत बताने के लिए फोटो प्रकाशित करना जरूरी है।

मौसम की मार और लंबे समय डि-हाईड्रेशन

पुलिस के अनुसार बुजुर्ग महिला बच्ची के साथ पैदल ही करीब 15 किमी के सफर कर रही थी। गर्मी के चलते दोनों को डिहाईड्रेशन हुआ। बुजुर्ग सुकी देवी का मायका रायपुर में है। यहां से यह बच्ची को साथ लेकर डूंगरी अपने गांव आ रही थी। बच्ची की मां का शादी के बाद विवाद होने से पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी। बच्ची नानी के पास ही रह रही थी। बच्ची का पिता रानीवाड़ा खुर्द में रहता है। इधर, इस बुजुर्ग महिला की बहन का निवास भी रोडा गांव में ही बताया जा रहा है और इसी गांव में यह घटनाक्रम घटित हुआ है। पुलिस के अनुसार धोरे की ऊंचाई ज्यादा थी और गर्मी के दौरान दोनों की तबीयत खराब हो गई।

किसान ने दी जानकारी

खेत में काम करने वाला एक किसान लौट रहा था तो उसने बुजुर्ग महिला और बच्ची को बेसुध अवस्था में देखा तो पुलिस को सूचित किया।

बुजुर्ग महिला और उसकी नातिन पैदल गुजर रहे थे। गर्मी और उमस के कारण डिहाइड्रेशन के चलते बच्ची की मौत हो गई, बुजुर्ग महिला की तबीयत अब ठीक है।

-प्रकाशचंद्र अग्रवाल, एसडीएम, रानीवाड़ा

बांसवाडा के पाटन थाने में एसीबी की कार्रवाई

मदद को आगे आए जनप्रतिनिधि

हॉट न्यूज

कोटा : जेके लोन अस्पताल में नवजात की मौत के बाद हंगामा

अस्पताल अधीक्षक की टेबल पर शव रख दादी ने पूछा-बच्चा मरा कैसे?

स्टाफ पर लगाया पैसे मांगने का भी आरोप
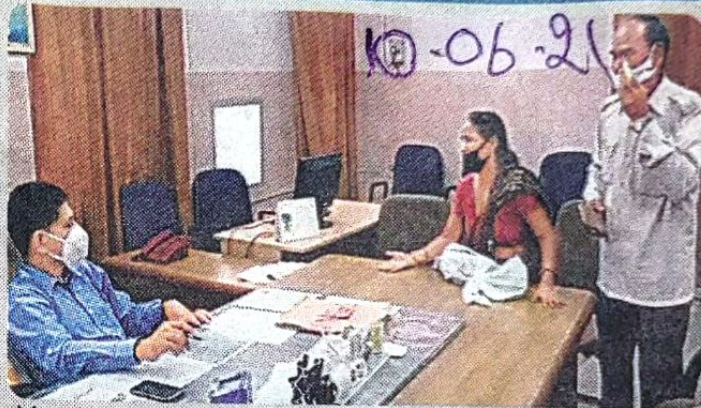
जेके लोन अस्पताल अधीक्षक की टेबल पर रखा नवजात का शव।

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

कोटा. जेके लोन अस्पताल में बुधवार को हंगामा हुआ। डिलेवरी के दौरान एक नवजात की मौत के बाद शव को लेकर दादी पहले कलक्ट्री पहुंची। कलक्टर के नहीं मिलने पर वह जेके लोन अस्पताल अधीक्षक के चैम्बर में चली गई।

वहां टेबल पर नवजात का शव रखकर अधीक्षक से पूछा कि हमारा नवजात कैसे मरा। उन्होंने पूरे मामले में जांच का आश्वासन दिया। उसके बाद परिजन नवजात का शव लेकर रवाना हुए। बाद में मामले की सूचना जिला कलक्टर ने अस्पताल अधीक्षक से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की। इंदिरा गांधी नगर निवासी माधुरी (28) को 8 जून को जेके लोन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुधवार दोपहर डेढ़ बजे उसकी नॉर्मल डिलेवरी हुई, लेकिन बाद में बच्चे की मौत हो गई। पढ़ें **अस्पताल** @ पेज 05

नवजात के परिजन आए थे। उनसे लिखित में शिकायत मांगी थी, लेकिन उन्होंने शिकायत नहीं दी और बिना पोस्टमार्टम के नवजात का शव ले गए। पहले लैबर रूम में स्टाफ पर पैसे मांगने का आरोप लगा रहे थे, बाद में मना कर दिया। गायनिक विभाग से रिपोर्ट मांगी है। **डॉ. अशोक मूंदड़ा,** अधीक्षक, जेके लोन अस्पताल

एक दादी नवजात के शव को लेकर कलक्ट्री पहुंचने की सूचना मिली थी, लेकिन मैं लंच पर गया था। जेके लोन अस्पताल अधीक्षक से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। **उज्ज्वल राठौड़,** जिला कलक्टर, कोटा

ग्रेटर नगर निगम : हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले वीडियो-ऑडियो वायरल होने से सनसनी

बिल पास कराने की एवज में निलंबित महापौर के पति ने मांगा 10% कमीशन

पहले महापौर निलंबन अब ऑडियो व वीडियो बम

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर . निलंबित महापौर सौम्या गुर्जर के मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले गुरुवार को सोशल मीडिया पर वायरल 3 वीडियो और 5 ऑडियो क्लिपिंग ने सनसनी फैला दी। वीडियो व ऑडियो में सौम्या के पति राजाराम गुर्जर निगम क्षेत्र का कचरा उठाने का ठेका लेने वाली कम्पनी बीवीजी के प्रबंधक संदीप चौधरी से 276 करोड़ रुपए के बकाया बिलों के भुगतान के बदले 10 प्रतिशत कमीशन को लेकर बातचीत कर रहे हैं।

वीडियो में संदीप भुगतान में अपनी कई तरह की परेशानियां गिनाते हुए कह रहा है कि कम्पनी पर कुछ जुर्माना भी लगेगा, जो कटेगा भी और ऐसे में 10 प्रतिशत कमीशन 20 करोड़ रुपए होता है। आप दो महीने, छह महीने या साल भर में भुगतान करवा दो, तो जैसे-जैसे भुगतान होता रहेगा, कमीशन टुकड़ों में देते रहेंगे। संदीप यह शिकायत भी कर रहा है कि मैडम (निलंबित महापौर) नए टेंडर कर हमें भगाने के लिए कह रही हैं। मैडम नाराज हैं। हैरिटेज में कम्पनी काम कर रही है। यहां भी अध्यक्षों से बात हुई है। ये तीनों वीडियो 20 अप्रेल के बताए जा रहे हैं। बातचीत के वीडियो में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े निम्बाराम भी नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि बीवीजी कंपनी हैरिटेज नगर निगम में भी काम कर रही है। निलम्बित महापौर सौम्या गुर्जर के पति राजाराम और बीवीजी कंपनी के प्रतिनिधियों के खिलाफ एसीबी ने गुरुवार रात प्रारम्भिक जांच के लिए रिपोर्ट दर्ज कर दी है।

पढ़ें बिल @ पेज 07

एक साथ नहीं दे सकते पांच करोड़

इसी वीडियो में कम्पनी के प्रतिनिधि कहते हैं कि पांच करोड़ बड़ी रकम है। 276 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। चार साल में सिर्फ दो वर्ष का ही भुगतान हुआ है। प्रति माह 5 करोड़ रुपए तो डीजल और वेतन में चले जाते हैं। दिसम्बर से अब तक भुगतान नहीं हुआ है। पांच करोड़ टुकड़ों में दे देंगे। जैसे-जैसे आता रहेगा हम देते रहेंगे। भाईसाहब से कहा तो मना कर दिया किस्तों में देने के लिए। इस पर कहा गया कि वो कोई दिक्कत नहीं है। नया टेंडर निकालने के लिए क्यों कहा?

सौम्या गुर्जर के पति राजाराम व कचरा उठाने वाली कंपनी प्रबंधक संदीप के बीच बातचीत के 3 वीडियो व 5 ऑडियो वायरल

एसीबी ने दर्ज की रिपोर्ट
276 करोड़ के बिल
वीडियो 20 अप्रेल के

ऑडियो 01 आप अपने हिसाब से काम करो...

- **राजाराम:** तुम्हारा तरीका दूसरा ही चल रहा है। क्या पता आपके दिमाग में क्या चल रहा है।
- **संदीप:** जो ऊपर से आदेश मिला है वही कर रहे हैं।
- **राजाराम:** बेवकूफ नहीं हूं। कमजोर भी नहीं हूं। इतने बड़े आदमी के सामने .... कर रहे हो। लापरवाह नहीं हैं हम। मैसेज नहीं पढ़ा।
- **संदीप:** कम्पनी के अधिकारियों का कहना है कि सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट हो जाए तब करेंगे।
- **राजाराम:** इधर आने की जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से काम करो। कोई मतलब नहीं है। आप लोगों पर विश्वास नहीं कर सकते। सिस्टम गलत है।
- **संदीप:** मैं तो कर्मचारी हूं। कम्पनी जो कहेगी, मैं तो वही करूंगा।
- **राजाराम:** अब वो किसी के ... से फोन करा दें। उनको औकात का पता चल जाएगा। इतने बड़े स्तर पर बात करके लौट जाओ। बचपना हो जाता है। मैडम (सौम्या) नाराज हैं। इधर, किसी को भी आने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई फोन नहीं आना चाहिए। बात खराब करवा दी। हम अलग टाइप के आदमी हैं। बीवीजी की जांच कराएंगे। भ्रष्टाचार कितना है। हूपर कितने लगे हैं। आप बदलाव करें सफाई को लेकर। बंटाधार हो रहा है शहर की सफाई का। लिख रखा है दो हूपर हैं और मिलता एक भी नहीं है।

ऑडियो 02 मैडम को फोन नहीं करें

- **संदीप:** मैं तो सीकर रोड की तरफ हूं। वैसे तो आने का नहीं है, लेकिन आप कहो तो आ जाता हूं।
- **राजाराम:** मेरे घर पर आना ही नहीं है। आप भले आदमी कितने हो, यह तो मुझे भी पता है। कुछ लोग परेशान हो रहे हैं।
- **संदीप:** मैं आ जाता हूं।
- **राजाराम:** आ जाओ। एक नाम लेते हुए उनकी गलतफहमी निकल गई, गड़करी और फड़नवीस की। उनसे कह देना कि मेरी मैडम को फोन नहीं करें। मैसेज करते हैं। भुगतान करवाने के लिए। ऑफिस का काम ऑफिस में ही होगा। आप अभी एनआरआइ कॉलोनी आ जा जाओ, नीरज के पवन के यहां पर।

(अन्य वीडियो और ऑडियो में पांच बत्ती स्थित एक संस्था के कार्यालय चलने का जिक्र है।)

ऑडियो 03

- **राजाराम:** क्या हाल हैं संदीप
- **संदीप:** बढ़िया। आपने कहा था व्हाट्सऐप पर बात करने के लिए। इसलिए फिर मैंने फोन नहीं किया।
- **राजाराम:** भाईसाहब का कहीं जिक्र मत करना। तुम्हें बच्चों की कसम है। भाईसाहब ने कहा था कि संदीप को बोल देना। मैं उस मराठी को जानता नहीं हूं। संदीप तो अपना ही बच्चा है। किसी से जिक्र मत करना, उनको बुरा लगेगा। विश्वास की वजह से मिल लिए। वो किसी से मिलते नहीं है। वो देश के लिए जीते हैं।

ऑडियो 04

- **संदीप:** मैडम से एग्रीमेंट की बात हुई क्या भाईसाहब।
- **राजाराम:** स्वायत्त शासन विभाग (डीएलबी) से एग्रीमेंट करवा लाओ।
- **संदीप:** डीएलबी से आदेश ला सकता हूं।
- **राजाराम:** वहां से आदेश आ जाएंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। फिर तो इनको करना ही पड़ेगा। ये भी पल्ला झाड़ लेंगी। अब क्या करें? ऑर्डर ऐसे करवाना कि जब तक भुगतान नहीं होता, तब तक काम कैसे छोड़ सकते हैं।

आरएसएस त्याग-तपस्या का पर्याय

सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि वीडियो में कई बातें स्पष्ट नहीं हैं। किसी फैसले पर पहुंचना गलत होगा। आरएसएस त्याग, तपस्या, निस्वार्थ देश भक्ति के जीवन का पर्याय है। ऐसे में देशभक्त संगठन को बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश है जो सफल नहीं होगी।

राजाराम ने कहा रिपोर्ट दी, पुलिस ने कहा नहीं दी

राजाराम गुर्जर का कहना है कि कंपनी प्रतिनिधि के खिलाफ सांगानेर थाने में झूठा वीडियो बनाने की रिपोर्ट दी है। वहीं सांगानेर थानाधिकारी हरि सिंह का कहना है कि इस संबंध में थाने में कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाई गई है।

बीवीजी ने की डैमेज कंट्रोल की कोशिश

वायरल वीडियो में बीवीजी का एक अधिकारी दिख रहा है और दूसरे अधिकारी ओमकार का जिक्र है। रात 10:45 बजे कंपनी के राजस्थान हेड ओमकार सप्रे ने एक वीडियो जारी किया। जिसमें कहा कि बीवीजी की किसी भी संस्था या व्यक्ति से किसी भी प्रकार के लेन देन की कोई बात नहीं हुई है।

पढ़ें बीवीजी @ पेज 07

रीयल हीरो सोनू सूद

दिल में छेद, जालोर की 10 दिन की बच्ची का मुंबई में होगा इलाज

एक ट्वीट पर सहयोग को तैयार, मुंबई से जालोर भेजी एंबुलेंस

कोरोना : एक्टिव केस 10 हजार से कम होने पर वीकेंड कर्फ्यू हटाने के थे संकेत

राजस्थान : अब वीकेंड की ढील पर नजर

राज्य में एक्टिव केस 10,079

जयपुर @ पत्रिका . राज्य में एक्टिव केस 10079 रह गए हैं। शुक्रवार को इनके 10 हजार से कम होने की संभावना है। राज्य सरकार ने जून माह की शुरुआत में जारी गाइडलाइन में कहा था कि 10 हजार से कम एक्टिव केस होने पर वीकेंड कर्फ्यू हटा लिया जाएगा। हालांकि इसके बाद गत सोमवार को जारी गाइडलाइन में इसका हवाला नहीं दिया गया था। अब वीकेंड कर्फ्यू में ढील, इसे हटाने या अभी भी कायम रखने के सरकार के फैसले पर सबकी नजर है।

पढ़ें राजस्थान @ पेज 07

538 नए मामले, 23 की मौत

प्रदेश में गुरुवार को कोरोना के 538 नए मरीज मिले। 23 संक्रमितों की मौत हुई है। अब 45980 नई जांचों पर 1.11 प्रतिशत संक्रमण दर रही है। कुल संक्रमित 948562, कुल मृतक 8772 हैं।

मृत्यु दर चिंताजनक

2268 नए रिकवर के साथ रिकवरी दर अब 98.01 प्रतिशत पहुंच गई है। प्रदेश में बीते दो दिनों में मृत्यु दर का ग्राफ भी अधिक रहा। बुधवार को यह दर नए संक्रमितों पर 5.82 और गुरुवार को 4.27 प्रतिशत रही। हालांकि प्रदेश की सकल मृत्यु दर 1 प्रतिशत से कम है।

मामला बहुत लम्बा जाएगा... कड़ी से कड़ी जुड़ेगी : धारीवाल

कचरा संग्रहण कंपनी और राजाराम गुर्जर से जुड़े कथित वायरल वीडियो के मामले में स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने इशारों ही इशारों में इस घटनाक्रम से कई तार जुड़ने की आशंका जता दी। पत्रिका ने उनसे बात की तो उन्होंने ये जवाब दिए...।

Q वायरल वीडियो मामले में आपका क्या कहना है।

एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज की है, अब वह पता लगाएगी कि आखिर कहानी क्या है।

Q क्या इस कथित प्रकरण में कोई और भी शामिल है।

मुझे संभावना है कि यह मामला बहुत लम्बा जाएगा। कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और हकीकत सामने आती जाएगी।

Q तो क्या बीवीजी कंपनी से अफसरों की सांठगांठ नहीं है।

सब कुछ नजर आ रहा है कि किसकी सांठगांठ है। बाकी एसीबी तलाश लेगी।

झुंझुनूं: कांकरिया गांव की घटना, शव रखकर प्रदर्शन, ग्रामीणों ने दो जेसीबी फूंकी

अवैध खनन का विरोध करने पर महिला की जीप से कुचलकर हत्या, परिजन को पीटा

पत्रिका न्यूज नेटवर्क 12.06.21
patrika.com

झुंझुनूं/खेतड़ी. कांकरिया गांव में शुक्रवार सुबह सात बजे बजरी का अवैध खनन करने पहुंचे लोगों ने विरोध करने पर जीप से कुचलकर 60 वर्षीय महिला की हत्या कर दी। परिवार के सदस्यों को घायल कर दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने अवैध खनन के लिए लाई गई दो जेसीबी मशीनों को आग लगा दी। ग्रामीण महिला के शव को लेकर धरने पर बैठ गए। शाम सात पहुंचे एसपी मनीष त्रिपाठी ने आश्वासन देकर धरना समाप्त करवा दिया। पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है तथा काम में ली गई जीप भी कब्जे में ले ली है।

मृतका सोना देवी

झुंझुनूं. आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा जलाई गई जेसीबी।

इसलिए किया विरोध

मृतका सोना देवी के पति मुखाराम सैनी ने 31 मई 2021 को खेतड़ी थाने में बलाराम सैनी व रतनलाल सैनी के खिलाफ खातेदारी भूमि में जबरन एलएण्डटी मशीन लगाकर बजरी चोरी का मामला दर्ज करवाया था। लेकिन पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों का कहना है कि शुक्रवार सुबह फिर से आरोपी बलराम सैनी व अन्य लोग खेत से बजरी खनन करने पहुंच गए। पुलिस यदि 31 मई को ही सचेत हो जाती तो यह घटना नहीं होती।

पुलिस छावनी बना कांकरिया

सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र कुमार मीणा, उपखण्ड अधिकारी राजपाल यादव सहित पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। गांव में क्यूआरटी टीम, जिला स्पेशल टीम व आरएसी का जाप्ता तैनात किया गया है।

हवाई फायर कर अपहरण

थानाधिकारी सुरेन्द्र सिंह देगड़ा ने बताया कि कांकरिया निवासी सुरेश कुमार सैनी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। कांकरिया निवासी मुकेश गुर्जर, रतन गुर्जर, हरिराम, सुरेश गुर्जर, गोपीराम गुर्जर, धोलुराम गुर्जर व बलराम सैनी शुक्रवार सुबह दो जीपों में आए। इनके हाथों में लाठी सरिया थे। पढ़ें **अवैध** @ पेज 09

सियासत

पाकिस्तान

गरीबों के हक पर लालच का 'संक्रमण', परिजन कर्मचारी फिर भी उठा रहे पेंशन

12-06-2021

द्धश्चस्त्रद्धप्रदेशभर में 198 से अधिक केस आ चुके सामने

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

सीकर. एक तरफ पात्र लोग पेंशन के लिए सरकारी सिस्टम के चक्कर काटने पर मजबूर हैं, दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके परिजन सरकारी सेवा में हैं फिर भी पेंशन से मोह नहीं छूट रहा है। अब ताजा मामला सीकर जिले की खंडेला इलाके की गोविन्दपुरा ग्राम पंचायत में सामने आया है। यहां एक सामाजिक कार्यकर्ता ने राजस्थान सम्पर्कपोर्टल पर पेंशन के दुरुपयोग की शिकायत दर्ज कराई। इस पर जिला कलक्टर ने खंडेला विकास अधिकारी को मामले की जांच के आदेश दिए।। शुक्रवार को ग्राम पंचायत ने अपनी रिपोर्ट में माना कि गांव के पांच लोग ऐसे हैं, जिनके पुत्र सरकारी सेवा. में मिले हैं। हालांकि एक व्यक्ति का नाम सही भी पाया गया है। अब अपात्र लोगों के नाम पेंशन सूची से काटने के साथ वसूली भी जिला प्रशासन की तरफ से की जाएगी। लगातार शिकायत बढ़ने पर दुबारा से सत्यापन के लिए अभियान शुरू किया जा रहा है।

बिना सत्यापन मिल गए दो-दो हजार रुपए

पिछले साल केन्द्र व राज्य सरकार की ओर से जरूरतमंद परिवारों को दो-दो हजार रुपए दिए गए थे। इस दौरान जांच में प्रदेश में 23 हजार परिवार ऐसे सामने आए, जिनके परिवारों में कोई न कोई सरकारी सेवा में था। इसके बाद वसूली अभियान शुरू हुआ लेकिन 20 फीसदी परिवारों से भी वसूली नहीं हो सकी है।

राशन उठाने की सात हजार शिकायत दर्ज

कोरोनाकाल में सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं के जरिए बांटे गए राशन के दौरान भी प्रदेश में सात हजार से अधिक शिकायत दर्ज हुई। इसमें चार हजार से अधिक परिवार ऐसे निकले जिनके परिवार का कोई न कोई सदस्य सरकारी सेवा में था। प्रदेश के 23 से अधिक जिलों में वसूली हो चुकी है। अन्य जिलों में मामला जांच में उलझा हुआ है। दस्तावेज में हेरफेर से लेकर परिजनों के सरकारी सेवा में होने के बाद भी पेंशन उठाने की पिछले छह महीनों में सम्पर्क पोर्टल पर प्रदेशभर में 198 से अधिक शिकायत दर्ज हुई है। पंचायतीराज विभाग की जांच के बाद ऐसे अपात्र लोगों के नाम हटाए भी गए हैं।

कोई पटवारी तो कोई पुलिस में

सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया कि पेंशन उठाने वाले एक जने का बेटा पटवारी है। जबकि किसी का बेटा पुलिस में कांस्टेबल तो किसी का राजस्थान रोडवेज में परिचालक है। वहीं एक परिवार में पुत्रवधू सरकारी सेवा में है।

सरकारी सेवा में होने के बाद भी कुछ लोगों के पेंशन उठाने की शिकायत दर्ज हुई थी। इसमें पांच परिवार ऐसे मिले हैं, जिनके सदस्य सरकारी सेवा में हैं। इसके बाद भी पेंशन उठाई जा रही थी। इसकी रिपोर्ट मुख्यालय भिजवा दी है।

-ममता नारनोली, ग्राम विकास अधिकारी, गोविन्दपुरा ग्राम पंचायत, सीकर

...रहे हैं। राहत के इन दो घंटों में लोग सोशल डिस्टेंस के साथ वॉक करते देखे जा सकते हैं। फतहसागर...

15.06.2021

महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा

अरबों ₹ खर्च फिर भी राज्य के 709 गांव में नहीं पहुंची बिजली!

एक्सक्लूसिव

जयपुर के 371, जोधपुर के 231 और अजमेर के 107 गांवों में भी अंधेरे का आलम

भूपेन्द्र सिंह
patrika.com

अजमेर. आजादी के बाद भी राज्य के 709 गांव अभी भी रोशनी से दूर हैं। एजी ऑडिट की रिपोर्ट यह सच बयां कर रही है। राजस्थान में 44 हजार 672 गांवों में से 43 हजार 963 गांवों में बिजली पहुंच चुकी है। जबकि 709 गांवों के ग्रामीण अभी भी बिजली की राह तक रहे हैं। इन गांवों तक केंद्र की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना, 12 प्लान, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, आरएपीडीआरपी और सौभाग्य योजना में अरबों रुपए की राशि खर्च करने के बावजूद बिजली नहीं पहुंच सकी है।

क्या है विद्युतीकरण की परिभाषा

विद्युत मंत्रालय के अनुसार अक्टूबर 2004 के बाद उन गांवों को विद्युतीकरण माना जाता है जहां आबादी वाली बस्तियों, दलित व कच्ची बस्तियों में विद्युत तंत्र के सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हों अथवा सार्वजनिक स्थान अस्पताल, स्कूल सरकारी हॉस्पिटल, विद्यालयों, पंचायतों आदि में विद्युत कनेक्शन हो तथा गांव के कम से कम 10 प्रतिशत घरों में विद्युत कनेक्शन हों।

प्रमुख सचिव ने जताई नाराजगी

राज्य के प्रमुख सचिव (ऊर्जा) ने बिजली कम्पनियों के अधिकारियों की वीसी में राज्य के 709 गांवों में बिजली नहीं पहुंचने पर नाराजगी जताई है। इसके बाद बिजली कम्पनियों में इसे लेकर हलचल है।

इनका कहना है

हमारे हिसाब से डिस्कॉम के सभी गांव इलेक्ट्रीफाइड हैं। फिर भी सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है। अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। सरकार को जवाब भेजा जाएगा।

आर.एल.जैन, एसई (प्रोजेक्ट), अजमेर डिस्कॉम

अजमेर डिस्कॉम

ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार अजमेर डिस्कॉम के वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 107 गांव विद्युतीकरण से वंचित हैं। इनमें करीब 8 हजार लोगों तक बिजली नहीं पहुंची है। निगम का दावा एक भी गांव बिजली से अछूता नहीं होने का है। अजमेर में 15,379 गांवों में से 15,272 गांव विद्युतीकत हो चुके हैं तथा 107 गांव अभी भी बाकी हैं।

जयपुर डिस्कॉम

जयपुर डिस्कॉम में 15 हजार 143 गांव में से तक 14 हजार 774 गांव विद्युतीकृत थे तथा 371 गांव अभी भी बिजली की पहुंच से दूर हैं।

जोधपुर डिस्कॉम

जोधपुर डिस्कॉम में 14 हजार 148 गांवों में से 13 हजार 917 गांव में बिजली पहुंच चुकी है तथा 231 गांव अभी भी बिजली की बाट जोह रहे हैं।

खाने में बीमारी को दावत : पैकेटबंद पर फ्रंट ऑफ पैक चेतावनी

बीमार करने वाली कंपनियों से ही पूछा जा रहा, उनसे बचें कैसे

बैठक में 28 में से 22 प्रतिनिधि कंपनियों के

पत्रिका ब्यूरो
patrika.com

17-8-21

नई दिल्ली. सरकार ने अपनी ताजा रिपोर्ट में पाया है कि देश में बिक रहे पैकेटबंद खाने-पीने के सामान में 95.6 प्रतिशत सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। लेकिन इन उत्पादों पर सेहत संबंधी चेतावनी की व्यवस्था के लिए बुलाई गई बैठक में 28 में से 22 प्रतिनिधि इन कंपनियों के ही थे, जो ये उत्पाद बनाती हैं।

'पत्रिका' ने रविवार को प्रकाशित खबर में बताया था कि देश में बिक रही पैकेटबंद खाने-पीने की चीजों में से 95.6% में वसा, नमक या चीनी की मात्रा खतरनाक स्तर पर है। यह खुलासा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) की रिपोर्ट में हुआ है। अब इनसे सावधान करने के लिए बाकी देशों जैसे भारत में भी उत्पादों के ऊपरी हिस्से (फ्रंट ऑफ पैक) पर चेतावनी छापने की तैयारी है। एफएसएसएआइ ने 25 मई को इस व्यवस्था के लिए बुलाई बैठक में कुल 28 लोगों को आमंत्रित किया। इनमें 22 लोग कंपनियों के ही प्रतिनिधि थे।

बैठक में शामिल... मीतू कपूर, एक्जी. डायरेक्टर, सीआइआइ, निरुपमा शर्मा, ज्वाइंट डायरेक्टर एंड हेड, फूड प्रोसेसिंग एंड एफएमसीजी, एसोचेम, पढ़ें **बीमार**@ पेज 05

हानिकारक तत्वों की सीमा बहुत ज्यादा

एफएसएसएआइ के वर्किंग ग्रुप ने नुकसानदेह तत्वों की जो मात्रा तय करने की सिफारिश की है वह अंतरराष्ट्रीय मानकों से बहुत अधिक है।

अब होगी चीनी ज्यादा

चीनी की मात्रा का प्रतिशत

	डब्ल्यूएचओ	एफएसएसएआइ
केक और बिस्किट	6%	20%
जूस	6%	12%
हार्ड कैंडी	6%	50%
चॉकलेट	6%	35%

क्या कहा कंपनियों के प्रतिनिधियों ने

कंपनियों के प्रतिनिधियों का कहना था कि शुरुआत सिर्फ कैलरी चेतावनी से की जाए। आगे चल कर 3 से 5 साल की अवधि में क्रमिक रूप से वसा, चीनी और नमक जैसे अवयवों की चेतावनी दी जाए। इसी तरह इनका कहना है कि पैकेट पर सकारात्मक लोगो भी लगाए जाएं।

बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि

'पत्रिका' के पास उपलब्ध बैठक के ब्योरे के मुताबिक इसमें कोका कोला, पेप्सी, हिंदुस्तान यूनीलीवर और नेस्ले इंडिया जैसी कंपनियों के साथ ही उद्योग संगठनों फिक्की, सीआइआइ, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स, एसोचैम के प्रतिनिधि भी शामिल थे। पढ़ें बड़ी@ पेज 05

13 जून 2021 को प्रकाशित

सरकारी रिपोर्ट में खुलासा: सिर्फ 4.4 फीसदी पैकेटबंद उत्पाद ही सेहतमंद

14 जून 2021 को प्रकाशित

पैकेट के ऊपर चेतावनी से बदल जाएगा 6 लाख करोड़ का बाजार

चेतावनी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

पैकेटबंद खाने-पीने के पैकेटबंद सामान में ऊपर की तरफ सरल (फ्रंट ऑफ पैक) चेतावनी प्रकाशित के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाई है। वरिष्ठ वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने इसमें मांग की है कि वसा, नमक और चीनी की मात्रा के लिहाज से कोई समझौता नहीं किया जाए।

उपभोक्ता संगठन बोले...

बैठक में उपभोक्ता संगठनों ने कहा, चेतावनी तुरंत लागू हो। कंपनियां जिस स्वरूप में चेतावनी लागू करने कह रही हैं वह लोगों को आसानी से समझ नहीं आएगा। मैक्सिको का उदाहरण भी दिया।

किसानों को राहत

अनूठा प्रदर्शन : विरोध में उतरे पुजारी...

किया। फोटो: दिनेश डाबी

अलवर ईएसआइसी भर्ती घोटाला : बोर्ड बिना दस्तावेज कर रहा था भर्ती! एसीबी करेगी पूछताछ

कम्पनी ने सौ अभ्यर्थी भर्ती किए, बोर्ड के पास 80 की सूची, दस्तावेज 12 के ही मिले

19.06.21

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. अलवर के ईएसआइसी हॉस्पिटल के संविदा भर्ती घोटाले में डीन की अध्यक्षता में गठित बोर्ड भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) जांच के घेरे में है। प्लेसमेंट एजेंसी ने सौ कर्मचारी भर्ती किए।

एसीबी ने मेडिकल कॉलेज में दबिश दी तो वहां अस्सी कर्मचारी भर्ती करने की जानकारी मिली, जबकि वहां दस्तावेज मात्र 12 के ही मिले। एसीबी अब कॉलेज एवं अस्पताल की डीन डॉ. हरनाम कौर, नर्सिंग अधीक्षक डॉ. विवेक तिवाड़ी, असिस्टेंट मैनेजर मुकेश कुमार की कमेटी से पूछताछ करेगी। पढ़ें कम्पनी @ पेज 06

अलवर. ईएसआइसी मेडिकल कॉलेज के नर्सिंगकर्मी भर्ती घोटाले के आरोपी।

सांसद का पीए नहीं, उनका फूफा : यादव

बहरोड़ विधायक बलजीत यादव ने कहा कि भर्ती घोटाले में जिसका नाम आ रहा है वह सांसद का पीए नहीं है उनका निकट रिश्तेदार (फूफा) है। वह दलालों के साथ मिलकर नर्सिंग स्टाफ भर्ती मामले में युवाओं से राशि वसूल रहा था।

मैं साधु, मेरा कोई फूफा नहीं : बालकनाथ

अलवर सांसद बालकनाथ का कहना है कि मैं साधु हूं। मेरा कोई फूफा या अन्य रिश्तेदार नहीं है। साधु के सभी भक्त हैं और कुलदीप भी उन्हीं भक्तों से एक है। मेरा पीए कुलदीप नहीं, कोई और है।

ये गिरफ्तार

- **मिनेश पटेल:** गुजरात निवासी आरोपी एमजे कंपनी का निदेशक है। उसके पास जोधपुर एम्स हॉस्पिटल का भी ठेका है।
- **भरत पूनिया:** एमजे कंपनी का फील्ड इंचार्ज अलवर में रहकर अभ्यर्थियों से वसूली के लिए दलाल नियुक्त कर रहा था।
- **कानाराम चौधरी:** कंपनी का सुपरवाइजर अलवर में आरोपी भरत के साथ रहकर दलालों से रुपए एकत्र करने का काम कर रहा था।
- **महिपाल यादव:** अलवर निवासी और जोधपुर एम्स में नर्सिंगकर्मी, एमजे कंपनी के लिए रुपए लेकर अभ्यर्थियों की भर्ती करवा रहा था।

देशी लक्ष्मी विदेश में : काला धन नहीं लौटा पर...

स्विस बैंक: भारतीयों का धन 20,700 करोड़ बढ़ा

एसएनबी ने जारी किए सालाना आंकड़े

पत्रिका न्यूज नेटवर्क 19.06.21
patrika.com

नई दिल्ली. स्विस बैंकों में जमा काला धन भारत लाने की राह अब तक नहीं खुल पायी है। इन बैंकों में भारतीय धन और बढ़ गया है। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक के हाल ही जारी सालाना आंकड़ों के मुताबिक स्विस बैंकों में भारतीयों का व्यक्तिगत तथा कंपनियों का धन 2020 में बढ़कर 2.55 अरब स्विस फ्रैंक (करीब 20,700 करोड़ रुपए) पर पहुंच गया। यह बढ़ोतरी जमा के बजाय प्रतिभूतियों, बॉन्ड और अन्य वित्तीय मदों के जरिए रखी गई होल्डिंग से हुई।

धन स्विस बैंकों की भारतीय शाखाओं और अन्य वित्तीय संस्थानों के जरिए रखा गया। ग्राहकों की जमा राशि में इस दौरान गिरावट दर्ज की गई। स्विस नेशनल बैंक (एसएनबी) स्विस बैंकों में भारतीय ग्राहकों का सकल कोष 2019 में 89.9 करोड़ स्विस फ्रैंक (6,625 करोड़ रुपए) था। एक वर्ष में इसमें 14,075 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। यह 13 वर्ष में सर्वाधिक बढ़ोतरी है।

ग्राहकों की जमा राशि में कोरोना काल में गिरावट
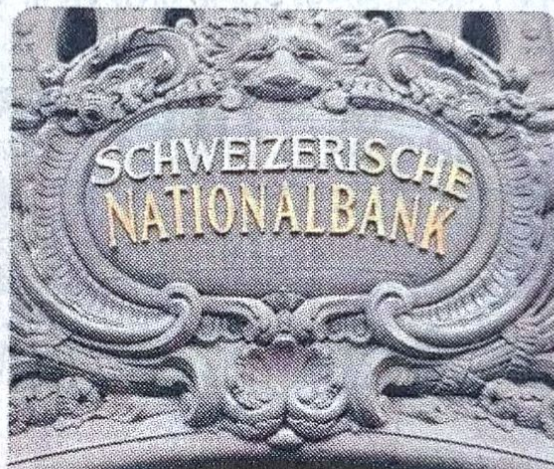
2020 में भारतीयों का खाता

मद	राशि
बॉन्ड, प्रतिभूति	13,500
ग्राहक जमा	4,000
अन्य बैंकों से	3,100
न्यास के जरिए	16.5

(राशि करोड़ रुपए में)

काले धन के कोई संकेत नहीं

एसएनबी के आंकड़े स्विस बैंकों में भारतीयों के काले धन के बारे में कोई संकेत नहीं देते। वह राशि भी शामिल नहीं है, जो भारतीय स्विस बैंकों में प्रवासी भारतीय या तीसरे देशों की इकाइयों के जरिए रख सकते हैं। स्विस प्राधिकरण कहता रहा है, उसके बैंकों में जमा संपत्ति को काला धन नहीं माना जा सकता।

सबसे ज्यादा कोष ब्रिटेन का

स्विस बैंकों में कोष के मामले में ब्रिटेन अव्वल है। उसके नागरिकों के स्विस बैंकों में 377 अरब स्विस फ्रैंक जमा हैं। अमरीका 152 अरब स्विस फ्रैंक के साथ दूसरे नंबर पर है। शीर्ष 10 अन्य देशों में वेस्टइंडीज, फ्रांस, हांगकांग, जर्मनी, सिंगापुर, लक्जमबर्ग, केमैन आईलैंड व बहामास शामिल हैं। भारत 51वें स्थान पर है।

कई तेल निर्माता इकाइयों में उत्पादन बंद: सरकार ने दे रखा था पहले लाइसेंस

सरसों तेल में अन्य तेल मिलाने पर रोक से बड़े कारखानों पर लगे ताले

विदेशी तेल सस्ता होने से सरसों के तेल के भावों में भी गिरावट

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

अलवर. खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने 8 जून से सरसों तेल में अन्य खाद्य तेलों की मिलावट पर पूर्णत प्रतिबंध लगा दिया है। इस नए आदेश से अलवर के प्रतिष्ठित कई तेल निर्माता इकाइयों में उत्पादन रुक गया है। ये इकाइयों सरसों तेल में 90 प्रतिशत अन्य खाद्य तेलों की मिलावट करते थे और इन्हें सरकार ने इसका लाइसेंस तक दे रखा था। अब ब्लैंडिंग सरसों तेल की इकाइयों का निरीक्षण कर इस तरह की उत्पादक इकाई पर एफएसएल एक्ट 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में सबसे अधिक सरसों तेल का उत्पादन अलवर, भरतपुर और श्री गंगानगर करते हैं। वहीं इस आदेश के आते ही कारखानों पर ताले लग गए। इस समय सरसों तेल के भाव प्रति किलो 140 रुपए हो गए हैं जबकि सरसों के भाव प्रति क्विंटल घटकर 6600 रुपए हो गए हैं, जो 7500 रुपए तक पहुंच गए थे। सरसों के तेल के भावों में गिरावट विदेश से आने वाले सस्ते तेल से हुई है।

यहां बनता है देश के प्रतिष्ठित ब्रांड का तेल

अलवर जिले में बाबा रामदेव की कम्पनी पतंजलि और अध्यात्म गुरु श्रीश्री रविशंकर के श्रीश्री के सरसों तेल की पैकिंग होती है। यहां धारा ब्रांड का उत्पादन भी यहां होता है। यहां प्रदेश के प्रमुख ब्रांडों की उत्पादन इकाई है। अलवर में सरसों तेल की मिल की संख्या 70 और भरतपुर में 60 हैं।

फैक्ट फाइल

- एक क्विंटल सरसों में औसतन करीब 35 लीटर तेल तैयार होता है।
- शुद्ध तेल का दाम रिटेल में 150 रुपए प्रति किलो है।
- तेल निकालने के दौरान खली निकलती हैं, जो 22 रुपए किलो है।
- इस तरह एक क्विंटल सरसों में 1320 रुपए की खली होती है।

कब क्या रहा सरसों तेल का भाव

2017 में	80 रुपए
2018 में	90 रुपए
2019 में	100 रुपए
2020 में	120 रुपए
2021 में	175 रुपए तक आया

(रु. प्रति लीटर भाव बाजार पर आधारित).

पूर्वोत्तर राज्यों में कोल्हू के तेल की मांग

पूर्वत्तर राज्यों असम, अरूणाचल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैण्ड के साथ पश्चिम बंगाल में अलवर और भरतपुर के कच्ची घानी के तेल की बहुत मांग है। कच्ची घानी सरसों तेल बनाने का वही परम्परागत रूप कोल्हू से तेल निकालना है। तेल में झाग के कारण तीखापन अधिक होता है, जिससे मछली का स्वाद बढ़ जाता है।

सरसों पैदावार में नम्बर वन राजस्थान

आंकड़ों के मुताबिक देश में सरसों की पैदावार में राजस्थान पहले पायदान पर है। देश में सरसों की पैदावार करीब 90 लाख टन होती है। राजस्थान में 2020 में 32 लाख टन सरसों की पैदावार हुई थी। राजस्थान में वर्ष 2019-20 में 27 लाख 65 हजार 251 हैक्टेयर क्षेत्र में सरसों बोई गई थी।

मांडलगढ़ पालिका चेयरमैन की करतूत

पिछले माह लिए 12 लाख, अब 4.20 लाख की घूस लेते गिरफ्तार

ठेकेदार से बिल पास कराने की एवज में मांगी रिश्वत

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

मांडलगढ़. (भीलवाड़ा). भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने सोमवार को मांडलगढ़ नगर पालिका चेयरमैन संजय डांगी को 4 लाख 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। यह राशि ठेकेदार का बकाया बिल पास करने की एवज में मांगी थी। चार माह पहले ही मांडलगढ़ में भाजपा का बोर्ड बनने पर डांगी चेयरमैन बना था। आरोपी पिछले महीने 48 लाख के भुगतान के बदले परिवादी से रिश्वत के 12 लाख रुपए ले चुका था।

ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बृजराजसिंह ने बताया कि थलखुर्द (काछोला) निवासी ठेकेदार प्यारचंद रेगर ने 18 जून को एसीबी को शिकायत दी। परिवादी ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में कराए निर्माण कार्य का भुगतान और एसडी राशि जारी करने की एवज में पालिका चेयरमैन संजय डांगी 23 प्रतिशत कमीशन के हिसाब से 4 लाख 50 हजार रुपए रिश्वत मांग रहा है।

सत्यापन में ले लिए 30 हजार

19 जून को एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया। इस दौरान चेयरमैन डांगी ने परिवादी ठेकेदार से 30 हजार रुपए ले लिए। एसीबी ने सोमवार को दोपहर में केमिकल लगे नोट परिवादी को देकर चेयरमैन के पास भेजा। चेयरमैन मांडलगढ़ स्थित मोटरसाइकिल के अपने शोरूम में बैठा था। वहां 4 लाख 20 हजार रुपए लेकर टेबल की दराज में रख लिए। इशारा मिलते ही टीम ने चेयरमैन डांगी को गिरफ्तार कर लिया। दराज से रिश्वत की राशि बरामद कर ली। हाथ धुलाने पर नोटों पर लगा रंग निकल आया।

13 फरवरी को संभाला था पदभार

निकाय चुनाव के दौरान मांडलगढ़ नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड बना था। 13 फरवरी 2021 को ही संजय डांगी ने चेयरमैन का पद संभाला था। चार माह आठ दिन में ही संजय एसीबी के हत्थे चढ़ गया।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना: राज्य सरकार ने रसद अधिकारियों को लताड़ा, सभी जिलों के निकलवाए आंकड़े

चार लाख गरीबों को दुकानों से टरकाया, नहीं दिया फ्री का गेहूं

एक्सक्लूसिव

भरतपुर में सर्वाधिक गड़बड़ी, 31 हजार से अधिक लोगों को नहीं मिला मुफ्त गेहूं

गजेंद्रसिंह दहिया
patrika.com
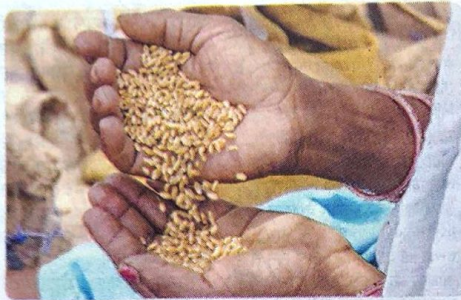
जोधपुर. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के अंतर्गत इस महीने से आवंटित पांच किलो फ्री गेहूं राशन की दुकानों पर बड़ी मुश्किल से दिया जा रहा है। गरीबों को यह कहकर लौटाया जा रहा है कि गेहूं खत्म हो गया है। राज्य सरकार ने इसकी भनक लगने पर 13 जून तक प्रदेश के सभी 33 जिलों के आंकड़े निकलवाए तो पैरों तले जमीन सरक गई। करीब 4 लाख 37 हजार गरीबों को पीएमजीकेवाई का गेहूं दिए बगैर ही लौटा दिया गया। सरकार ने सख्ती दिखाते हुए सभी जिला रसद अधिकारियों, प्रवर्तन अधिकारियों और प्रवर्तन निरीक्षकों को लताड़ते हुए इसकी जांच कराने के आदेश दिए हैं।

योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने 2 रुपए किलो के हिसाब से प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं मिलता है। कोविड से तंगी से जूझ रही जनता के लिए केंद्र ने नियमित आवंटन के साथ पांच किलो गेहूं प्रति माह फ्री देने की घोषणा की है। लाभार्थियों को इस महीने से 10 किलो गेहूं मिलेगा। पांच किलो फ्री और पांच किलो दो रुपए प्रति किलो के भाव से।

किस जिले से कितने लोगों को नहीं मिला फ्री गेहूं

जिला	लाभान्वित	जिला	लाभान्वित	जिला	लाभान्वित	जिला	लाभान्वित
भरतपुर	31239	सीकर	16727	सिरोही	12066	श्रीगंगानगर	8472
अलवर	29042	जोधपुर	16605	अजमेर	11694	जालोर	8378
जयपुर	21167	पाली	16176	टोंक	11665	डूंगरपुर	8056
नागौर	19478	करौली	16088	उदयपुर	11285	धौलपुर	6689
बाड़मेर	19036	बांसवाड़ा	14926	कोटा	10090	हनुमानगढ़	6577
बारां	18840	दौसा	14702	भीलवाड़ा	9643	राजसमंद	5723
स. माधोपुर	17941	बीकानेर	14444	बूंदी	9633	चितौड़गढ़	5293
झालावाड़	17562	चूरू	13409	झुंझनूं	9338	प्रतापगढ़	3915
						जैसलमेर	1564

नहीं दे रहे गेहूं

जयपुर, जोधपुर सहित अन्य जिलों में जांच में पता चला कि राशन डीलर्स जनता को केवल नियमित आवंटन का पांच किलो गेहूं दे रहे हैं। पीएमजीकेवाई का पांच किलो फ्री गेहूं यह कहकर नहीं दे रहे कि स्टॉक खत्म हो गया।

यह अलार्मिंग सिचुएशन

मैं यह देखकर हैरान हूं कि कई लोगों को एनएफएसए का गेहूं तो दिया गया है लेकिन पीएमजीकेवाई का नहीं। यह अलार्मिंग सिचुएशन है। जब डीलर्स को एक जून तक दोनों तरह का गेहूं दे दिया है तो क्या कारण है कि डीलर एक तरह का ही गेहूं उपभोक्ताओं को दे रहा है। इसमें जो भी जिम्मेदार है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

- **नवीन जैन,** शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

(जैसा कि नवीन जैन ने सभी डीएसओ को भेजे अपने वॉयस मैसेज में कहा।)

एसीबी की प्रदेशभर में कार्रवाई

एफसीआइ के दो कर्मचारी एक लाख रुपए लेते पकड़े

भरतपुर . भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) आगार पर गुरुवार को एसीबी ने एफसीआइ के सहायक श्रेणी प्रथम कर्मचारी विनोद कुमार कश्यप व प्रबंधक गुण नियंत्रण मुन्नूलाल मौर्य को रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। इसमें विनोद से 80 हजार और मुन्नूलाल से 20 हजार रुपए बरामद किए हैं। रिश्वत एक फर्म से गेहूं के गोदाम में जमा कराए प्रति कट्टे के हिसाब से मांगी थी। फर्म ने 91 हजार कट्टे जमा कराए थे, जिसकी रसीद देने के लिए एक लाख रुपए बतौर कमीशन मांगे थे। एसीबी एएसपी महेश मीणा ने बताया कि आदित्य अग्रवाल की महावीर ट्रेडिंग कंपनी के नाम से फर्म है। जिसके पास रूपवास कस्बे की अनाज मण्डी में गेहूं की हैण्डलिंग एवं परिवहन का कार्य है। जो भारतीय खाद्य निगम अलवर द्वारा दिया गया है। एफसीआइ भरतपुर आगार द्वारा अनाज मण्डी रूपवास में 91000 हजार कट्टे दिए गए थे। कट्टों की तुलाई करवा कर फर्म द्वारा परिवहन करवाकर एफसीआइ आगार भरतपुर पहुंचाने थे। जिस पर फर्म ने 91 हजार कट्टों को एफसीआइ आगार भरतपुर में जमा करवा दिया। गत शुक्रवार परिवादी आदित्य अग्रवाल से एफसीआइ गोदाम भरतपुर में कार्यरत सहायक श्रेणी प्रथम कर्मचारी विनोद कुमार कश्यप ने एक रुपया प्रति कट्टे के हिसाब से कमीशन मांगा। इसके बाद ही जमा रसीद देने की बात कहीं। परिवादी आदित्य ने एसीबी कार्यालय में शिकायत दी। जिस पर एसीबी ने सत्यापन कराया। इसके बाद कार्रवाई की गई।

बंधी एकत्र करने वाला आयुक्त... दलाल भी पकड़ा

श्रम आयुक्त सरकारी आवास पर तीन लाख ले रहा था बंधी, एसीबी ने दबोचा

मजदूरों को परेशान करने वाली शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करने के एवज में श्रम निरीक्षकों से वसूलते थे बंधी

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की जयपुर टीम ने श्रम आयुक्त प्रतीक झाझड़िया को तीन लाख रुपए की बंधी वसूलते शुक्रवार रात रंगे हाथों गिरफ्तार किया। झाझड़िया गांधी नगर स्थित सरकारी आवास पर आर्थिक परिषद में ओएसडी रवि मीना और निजी दलाल से बंधी ले रहे थे। डीजी बीएल सोनी ने बताया कि एसीबी को कई माह से शिकायत मिल रही थी कि फैक्ट्री और औद्योगिक इकाइयों में मजदूरों को परेशान करने की शिकायतें यूनियन की तरफ से श्रम विभाग में की जाती रहीं हैं। लेकिन मालिकों से रुपए लेकर श्रम विभाग के अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं।

पढ़ें **श्रम** पेज 07

एसीबी की देर रात कार्रवाई

जयपुर. इसी कार में बंधी पहुंचाने आए थे दलाल। 26.06.2021

प्रतीक झाझड़िया | अमित शर्मा | रवि मीना

एक बार देकर चले गए थे रकम

एडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि श्रम आयुक्त पर छह माह से नजर रखी जा रही थी। एक बार दलाल रकम देकर चले गए। तीन दिन पहले करौली के श्रम निरीक्षक से दलाल रवि मीना और अमित शर्मा ने बंधी के तीन लाख रुपए एकत्र किए थे। अमित करौली से रकम लेकर जयपुर पहुंचा और यहां से रवि मीना के साथ शुक्रवार रात 8 बजे श्रम आयुक्त के घर पहुंचा।

सरकारी क्वार्टरों से देखने लगे लोग

एसीबी की कार्रवाई को देखने के लिए स्थानीय लोग सरकारी क्वार्टरों से बाहर वॉकिंग करते हुए श्रम आयुक्त के घर के बाहर से निकलने लगे। कुछ लोग खुद के क्वार्टर से नजर रखे हुए थे।

अमित कार में बैठा रहा, रवि अंदर गया

श्रम आयुक्त प्रतीक झाझड़िया के गांधी नगर स्थित आवास के बाहर कार रोककर अमित उसी में बैठा रहा। जबकि रवि तीन लाख रुपए लेकर घर में चला गया। कुछ मिनट बाद ही एसीबी की टीम ने अमित को कार में ही पकड़ लिया और घर में घुसकर टेबल पर रखे तीन लाख रुपए के साथ श्रम आयुक्त प्रतीक झाझड़िया और रवि मीना को पकड़ लिया।

तीन श्रम अधिकारियों के आवास पर सर्च

सवाईमाधोपुर में सवाईमाधोपुर/चित्तौड़गढ़ के श्रम कल्याण अधिकारी शिवचरण मीणा और करौली के श्रम कल्याण अधिकारी रमेश मीणा, श्रम आयुक्त प्रतीक झाझड़िया, विशेषाधिकारी दलाल रवि मीना और निजी दलाल अमित के आवास पर टीमें सर्च में जुटी थी। श्रम आयुक्त के आवास पर उप अधीक्षक मांगीलाल के नेतृत्व में कार्रवाई की गई।

घबरा गए, एसीबी ने दी सांत्वना: एसीबी टीम ने बताया कि श्रम आयुक्त आवास पर दबिश देते ही घबरा गए। हालांकि बाद में उनको सांत्वना दी गई। एसीबी की रात करीब 11.30 बजे तक कार्रवाई चली। इसके बाद श्रम आयुक्त के घर की सर्च की गई, जो देर रात तक जारी थी।

रार बढ़ी : अमरीका...

चार वर्ष पू... पर मंत्री का ...

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. सरकार और ट्विटर के बीच लंबे समय से जारी तनातनी में शुक्रवार को एक और मोड़ आया। यूएस डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट कानून के कथित उल्लंघन को लेकर ट्विटर ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद के खाते को लगभग एक घंटे तक ब्लॉक कर दिया गया। मंत्री ने इसे मनमाना और आइटी नियमों का घोर उल्लंघन बताया। लेकिन देर रात सूत्रों ने बताया ये कार्रवाई 2017 में रविशंकर द्वारा एक ट्वीट में एआर रहमान के गाने 'जय हो' के इस्तेमाल पर की गई थी। इसके अधिकार सोनी म्यूजिक

कोरोना अपडेट

- देशभर में *सर्वाधिक तीन करोड़ वैक्सीन डोज* लगाने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र।
- इजरायल में *अचानक बढ़े कोरोना केस*, इनडोर में फिर मास्क लगाना अनिवार्य किया।
- बिहार: नर्स ने वैक्सीन की जगह *खाली सिरिंज लगाई*।
- सीरम इंस्टीट्यूट ने अमरीकी कंपनी *नोवावैक्स के कोवोवैक्स टीके का उत्पादन* शुरू किया।
- उत्तर प्रदेश में एक से 24 जून के बीच लगाई गई *कोरोना वैक्सीन की 2.88 करोड़ डोज।*

खुलासा : पांच ठिकानों पर ईडी की छापेमारी

बार मालिकों ने देशमुख को 3 महीने में दिए चार करोड़

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

मुंबई. महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की मुसीबत बढ़ गई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने खुलासा किया कि मुंबई के 10 बार मालिकों ने देशमुख को 3 महीने में चार करोड़ रुपए दिए थे।

ईडी ने शुक्रवार को देशमुख के मुंबई के 4 ठिकानों व नागपुर निवास पर छापा मारा। पढ़ें **बार@** पेज 07

महामंथली के आरोप

पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि देशमुख ने पुलिस पर रेस्टोरेंट्स व बार मालिकों से प्रति माह 100 करोड़ रु. वसूली के लिए दबाव बनाया था। सीबीआइ इसकी जांच कर रही है। इसी आधार पर ईडी ने भी केस दर्ज किया।

ईडी ने राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में की कार्रवाई

आदर्श ग्रुप की 365 करोड़ की संपत्ति जब्त, 11 लोग गिरफ्तार

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. नई दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को मनी लॉड्रिंग कानून के तहत राजस्थान के करीब 20 लाख लोगों को ठगने वाली आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी की 365 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है। ईडी ने कहा कि ये संपत्तियां राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में स्थित कृषि, आवासीय व व्यावसायिक भूमि, एफडी और बैंक बैलेंस के रूप में हैं।

संपत्तियां आदर्श ग्रुप ऑफ कंपनीज, रिद्धि सिद्धि ग्रुप ऑफ कंपनीज तथा इससे जुड़े लोगों की हैं। ईडी ने यह कार्रवाई एसीसीएसएल और इसके निदेशकों मुकेश मोदी, राहुल मोदी और अन्य के खिलाफ राजस्थान पुलिस में दर्ज प्राथमिकी के बाद की। ईडी का आरोप है कि मुकेश मोदी ने अपने रिश्तेदार वीरेंद्र मोदी, राहुल मोदी, रोहित व समिति के अधिकारियों सहित अन्य सहयोगियों के साथ सांठगांठ कर एसीसीएसएल से जमाकर्ताओं के पैसों का आपस में जुड़े फर्जी लेन-देन के जरिए हेर-फेर किया।

भीलवाड़ा. पुलिस गिरफ्त में आरोपी।

जयपुर व भीनमाल जेल से लिया हिरासत में

भीलवाड़ा. आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी के निदेशक समेत 11 जनों को शुक्रवार शाम को विभिन्न जेलों से गिरफ्तार कर लिया गया। सुभाषनगर थाना पुलिस ने बताया कि इनमें आठ जनों को जयपुर से तथा तीन को पाली के भीनमाल जेल से प्रोडक्शन वारंट से हिरासत में लिया। आरोपियों के खिलाफ सुभाषनगर थाने में 25 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने मुम्बई निवासी प्रियंका मोदी, उसके पति वैभव लोढ़ा, सुनारवाड़ा (सिरोही) निवासी समीर मोदी, भरत मोदी, जयपुर निवासी रोहित मोदी, राजेश्वरसिंह जाट, गुड़गांव निवासी विवेक पुरोहित, सिरोही निवासी भरत दास वैष्णव, राहुल मोदी, मुकेश मोदी तथा ईश्वरसिंह सिंघल को गिरफ्तार किया।

संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव: 3 जने गिरफ्तार

मौलासर. संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी घोटाले के तीन आरोपियों को पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर जोधपुर जेल से गिरफ्तार किया। ग्राम रसीदपुरा निवासी बुजुर्ग बदन सिंह पुत्र मदन सिंह ने मौलासर थाने में रिपोर्ट दी थी। पुलिस ने शुक्रवार को सोसायटी के तत्कालीन अध्यक्ष नरेश सोनी, पूर्व अध्यक्ष देवी सिंह राजपूत और शैतान सिंह राजपूत को प्रोडक्शन वारंट के तहत जोधपुर की जेल से हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया।

विशेष सवारी : राष्ट्रपति की कानपुर यात्रा का आरंभ

नई दिल्ली. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी पत्नी के साथ शुक्रवार को दिल्ली के सफदरगंज स्टेशन से विशेष प्रेसिडेंशियल ट्रेन में सवार होकर कानपुर पहुंचे। कोविंद रविवार को अपने पैतृक गांव परौंख जाएंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद कोविंद की अपनी गांव की यह पहली यात्रा है।
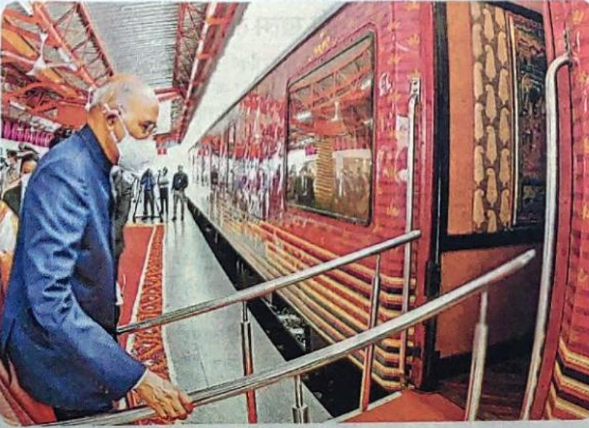
टी-20 वर्ल्ड कप ... | किसान आंदोलन ... | धमकी का आरोप — अभिनेत्री पायल रोहतगी गिरफ्तार

ग्गी अपने स्तर पर रोस्टर प्रणाली बनाई है। पूरे गांव की ढाणियों को तीन

पढ़ाई कराई जा रही है।
पढ़ें **मोबाइल** @ पेज 09

आकर पढ़ाई शुरू कराई तो सभी भाई-बहन अब कक्षा में आते हैं।

अब दोनों भाई घर के पास कक्षा में रोज पढ़ रहे हैं।

शुरू पढ़ा

जयपुर, चित्तौड़गढ़ और जोधपुर में एसीबी की कार्रवाई

तीन अधिकारियों के 14 ठिकानों पर छापा, काली कमाई उजागर

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर . भ्रष्टचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने गुरुवार को प्रदेश में तीन अधिकारियों के 14 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। तलाशी में एसीबी को नकदी, आभूषण और करोड़ों की सम्पत्ति के कागजात मिले हैं।

कार्रवाई से पहले एसीबी ने तीनों के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने की एफआइआर दर्ज की थी। एसीबी डीजी बीएल सोनी ने बताया कि जयपुर में जेडीए के अधिशाषी अभियन्ता (एक्सईएन) निर्मल कुमार गोयल के 4 ठिकानों पर, चित्तौड़गढ़ के परिवहन अधिकारी मनीष कुमार शर्मा के 6 ठिकानों पर और जोधपुर में सूरसागर थानाधिकारी प्रदीप कुमार शर्मा के 4 ठिकानों पर सुबह करीब साढ़े सात बजे एक साथ सर्च शुरू हुआ। एसीबी एक साल से जानकारी जुटा रही थी।

रात को टीम तैयार सुबह होते ही छापा

एसीबी अधिकारियों ने जहां-जहां दबिश देनी थी, वहां एक अधिकारी के नेतृत्व में 7 से 9 सदस्यों को गुरुवार तड़के ही तैनात कर दिया गया। सर्च के लिए एसीबी ने इसके लिए संबंधित न्यायालयों से सर्च वारंट पहले ही जारी करवा लिए थे। सुबह होते ही एक साथ सभी स्थानों पर दबिश दी गई।

एक साल से जानकारी जुटा रही थी एसीबी

एक्सईएन निर्मल कुमार गोयल: वैध आय से 1450% अधिक सम्पत्ति

लंबे समय से पृथ्वीराज नगर जोन के एक्सईएन गोयल के यहां सेवाकाल में खर्च व परिसम्पत्तियों पर करीब 6 करोड़ का निवेश करना पाया गया, जो कि उनकी वैध आय का लगभग 1450% अधिक है।

यह मिली सम्पत्ति

- **मानसरोवर** मध्यम मार्ग स्थित आवास पर 2 हजार डॉलर व 245 यूरो, 2 लाख 27 हजार 790 रुपए, 2 कार व विदेशी शराब की 23 बोतलें।
- **मानसरोवर** में दूसरे निवास पर एक कार, 1.60 लाख रु., 323.8 ग्राम सोना,4.4 किलोग्राम चांदी, एक लॉकर की चाबी।
- **सुमेर नगर** में 1100 वर्गगज के 2 निर्माणाधीन मकान, डीग में एक हवेली के कागजात, 2 लॉकर की चाबी, 318 ग्राम सोना व 3.5 किलोग्राम चांदी। पढ़ें **तीन** @ पेज 09

पुलिस निरीक्षक प्रदीप शर्मा: आय से 333% अधिक सम्पत्ति

जोधपुर के सूरसागर थानाधिकारी प्रदीप कुमार शर्मा के जोधपुर, भोपालगढ़ व बीकानेर स्थित 4 स्थानों पर कार्रवाई की। 4.43 करोड़ का निवेश करना पाया, जो वैध आय का 333% अधिक है।

यह मिली सम्पत्ति

क्रशर के लिए जमीन खरीद के इकरारनामे की प्रति, **भोपालगढ़** में 10 बीघा परिसर में स्कूल, **पाली** के रोहट कस्बे में 5 बीघा जमीन, सोजत में पत्नी के नाम खनिज स्टोन की लीज, जाडन गांव में क्रशर प्लांट के लिए 12 बीघा जमीन के दस्तावेज मिले।

यहां ली गई तलाशी : रातानाड़ा पशु चिकित्सालय के सामने स्थित फ्लैट, थाना आवास, भोपालगढ़ में निजी स्कूल व बीकानेर में एक मकान में तलाशी ली गई।

डीटीओ मनीष कुमार शर्मा: आय से 232% अधिक सम्पत्ति

चित्तौड़गढ़ के जिला परिवहन अधिकारी मनीष के जयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर व जोधपुर में 6 ठिकानों पर सर्च की कार्रवाई चल रही है। मनीष के अपने सेवाकाल में खर्च व परिसम्पत्तियों पर 1.84 करोड़ रुपए का निवेश करना पाया गया है, जो वैध आय से 232 प्रतिशत अधिक है।

यह मिली संपत्ति:
- चितौड़गढ़ स्थित फ्लैट की तलाशी में 99 हजार 500 रुपए, महंगी बाइक, कार, विदेश यात्राओं से संबंधित दस्तावेज, एप्पल फोन व अन्य सामान मिला है।
- जोधपुर स्थित आवास व बाड़मेर स्थित ट्रेवल्स एजेन्सी की तलाशी चल रही है।
- जयपुर व उदयपुर स्थित एक फ्लैट को सील किया गया है।

उत्तर भारत तपा : राजस्थान, मप्र, दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने चेताया

75 नए मरीज मिले,

अधिकतम 38.1°c न्यूनतम 29.5°c **सूर्यास्त:** आज शाम 07:35 बजे **सूर्योदय:** कल सुबह 05:50 बजे **चन्द्रोदय:** आज

03.07.2021

संभागीय आयुक्त ने दिए विशेष एक्शन प्लान के साथ रोकथाम के निर्देश

बेलगाम बजरी खनन, कोरोनाकाल में 350 से ज्यादा मामले

जोधपुर @ पत्रिका. अवैध बजरी खनन भी कोरोनाकाल में बेलगाम हो गया है। पूरे संभाग में 350 से ज्यादा मामले पिछले 15 माह में सामने आए हैं। इनसे ढाई करोड़ से अधिक का जुर्माना वसूला गया है। इसके अलावा ऐसे भी कई मामले हैं जो खान विभाग व पुलिस के नाक के नीचे संचालित है, लेकिन पकड़े नहीं जाते। संभागीय आयुक्त डॉ. राजेश शर्मा ने विभागों की समीक्षा बैठक में अधीक्षण खनि अभियंता धर्मेन्द्र लोहरा ने यह आंकड़े साझा किए।

बजरी खनन के मामले

वर्ष	पकड़े	एफआइआर	जुर्माना
2020-21	154	4	104.99 लाख
2021-22	216	9	164.96 लाख

खनन के विरुद्ध एक्शन प्लान : सेंडस्टोन अवैध खनन क्षेत्र में जेडीए परिधि में अवैध खनन रीको के निकटवर्ती क्वारी लाइसेंस, खानों से मलबा डालकर खनन मिलों को भरवाया जाए। खनन माफियाओं के विरूद्ध थानो में एफआरआइ दर्ज करवाई जाए। बॉर्डर होमगार्ड का भी उपयोग लें। अवैध खनन से नदी नालों में प्रयुक्त रास्ते जो उन तक पहुंचने के होते है उनको जेसीबी से कटवाया जाकर नदी, नालों को संरक्षित करने का कार्य करें।

सभी को राहत मिले

बैठक में संभागीय आयुक्त ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अधिनियम (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत देय राहत राशि के लम्बित प्रकरणों का समय पर निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पालनहार योजना का समय पर लाभ दिलाने के लिए लाभान्वितों को समय पर योजना से जोड़ा जाना चाहिए। साथ ही कोरोना राहत पैकेज का लाभ भी जरूरतमंदों को दिलाने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना में 165 व्यक्तियो के प्रकरण प्राप्त हुए हैं। इनकी पात्रता की जांच की जा रही है।

बीकानेर : सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाने पर युवक की हत्या, हंगामा

विरोध पर पुलिस ने भांजी लाठियां

पीड़ितों को लाठी।
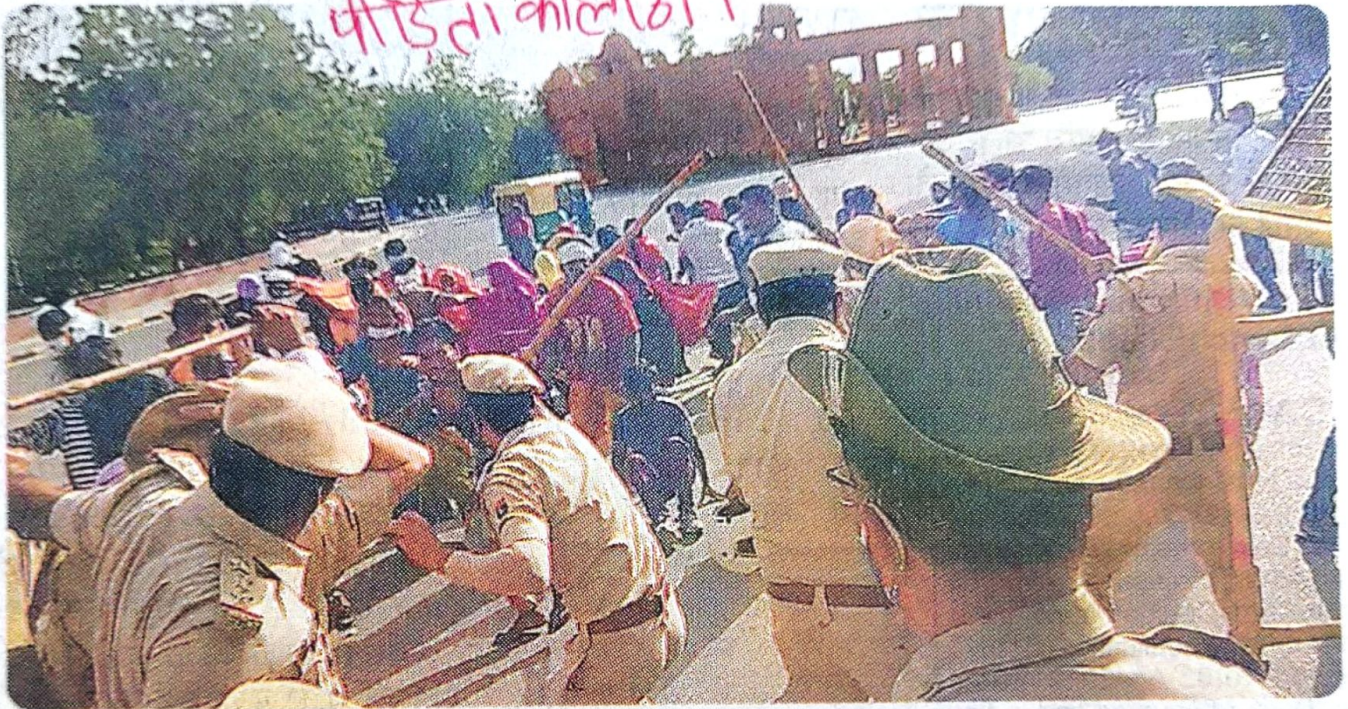
पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

बीकानेर. गंगाशहर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाने के बाद विवाद में कुछ लोगों ने एक युवक की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। घटना गुरुवार रात की है। हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर मोर्चरी एवं जिला कलक्ट्रेट के आगे प्रदर्शन किया गया। कलक्ट्रेट में प्रदर्शनकारी और पुलिस में झड़प हुई। पुलिस ने पहले प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया लेकिन वे माने नहीं। इस पर पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजनी पड़ी। कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्रसिंह इंदौलिया ने बताया कि सोशल मीडिया पर स्टेट्स लगाने को लेकर विक्रम नायक व युवराज का कुछ लोगों से विवाद हो गया था। गुरुवार रात को युवराज व विक्रम भीनासर गए थे। यहां विक्रम व युवराज का दूसरे पक्ष के लोगों में झगड़ा हुआ। दूसरे पक्ष के लोगों ने विक्रम को लाठी-सरियों से बेरहमी से पीटा। बाद में उसकी मौत हो गई।

में कोरोना सेवा में जुटी इंडियन कल्चरल एसोसिएशन

फिर निकला रफाल का जिन्न | विमान खरीद सौदे में कथित भ्रष्टाचार, जज नियुक्त

फ्रांस में जांच, यहां सियासी आंच

घेरे में तत्कालीन फ्रांसीसी राष्ट्रपति ओलांद भी

नई दिल्ली @पत्रिका. रफाल लड़ाकू विमानों के सौदे को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद में अब एक नया मोड़ आ गया है। फ्रांस ने सौदे से जुड़े कथित भ्रष्टाचार की न्यायिक जांच का आदेश देकर जज की नियुक्ति की है। फ्रांसीसी ऑनलाइन जर्नल मीडियापार्ट के अनुसार, सौदे की संवेदनशीलता को देखते हुए औपचारिक तौर पर 14 जून से जांच शुरू कर दी गई थी। 2 जुलाई को फ्रांसीसी लोक अभियोजन की वित्तीय अपराध शाखा ने इसकी पुष्टि की है। फ्रांस के एनजीओ शेरपा की शिकायत पर मीडियापार्ट ने कई रिपोर्ट प्रकाशित की थीं। फ्रांस के घटनाक्रम के चलते भारत में भी सियासत गरमा गई है।

पढ़ें फ्रांस@ पेज 12

पहली स्क्वाड्रन अंबाला, दूसरी बंगाल के हाशिमारा में

2022 तक भारत को सभी 36 रफाल लड़ाकू विमान मिल जाएंगे

2016 में भारत और फ्रांसीसी सरकार ने रफाल विमान सौदे पर हस्ताक्षर किए थे

सौदे का बही-खाता

56 हजार करोड़ रुपए का है रक्षा सौदा

36 रफाल मिलेंगे फ्रांस से भारत को

30 लड़ाकू और 6 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट

14 रफाल भारत को अबतक मिले हैं

जांच रोकी, अब फिर शुरू

मीडियापार्ट ने अप्रैल, 2021 में दावा किया था कि *सार्वजनिक अभियोजन सेवाओं की वित्तीय अपराध शाखा* के पूर्व प्रमुख इलियाने हाउलेट ने कथित तौर पर इसकी जांच रोकी थी। हालांकि, अब वर्तमान प्रमुख जीन-फ्रेंकोइस बोहर्ट जांच में दिलचस्पी ले रहे हैं। इस डील पर तत्कालीन फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद, मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (तब वित्त मंत्री) और विदेश मंत्री जीन-यवेस ले ड्रियन (तब रक्षा मंत्री) ने हस्ताक्षर किए थे।

आमने-सामने

कांग्रेस हमलावर

सौदे के तथ्यों के सामने आने के बाद अब संयुक्त संसदीय कमेटी (जेपीसी) से भी जांच होनी चाहिए। क्या प्रधानमंत्री देश की जनता को इसका जवाब देंगे? रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस प्रवक्ता

भाजपा का पलटवार

फ्रांस में शिकायत पर जांच होना स्वाभाविक है। इस जांच को भ्रष्टाचार की नजर से देखना ठीक नहीं है। इस पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं वह दुखद है। संबित पात्रा, भाजपा प्रवक्ता

अनिल अंबानी से भी विवाद

सौदे को लेकर अनिल अंबानी की रिलायंस कंपनी विवादों में रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कई बार सवाल उठा चुके हैं। विमान निर्माता कंपनी दसॉ ने भारत को 126 विमानों की डिलीवरी के लिए 2012 में डील शुरू की। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) से बातचीत की जा रही थी। आरोप है कि 2016 में रिलायंस ग्रुप आ गया। नए सौदे में 36 विमानों की डिलीवरी तय की गई।

जयपुर, चित्तौड़गढ़ और जोधपुर में एसीबी की कार्रवाई

तीन अधिकारियों के 14 ठिकानों पर छापा, काली कमाई उजागर

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

09.07.21

एक साल से जानकारी जुटा रही थी एसीबी

जयपुर . भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने गुरुवार को प्रदेश में तीन अधिकारियों के 14 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। तलाशी में एसीबी को नकदी, आभूषण और करोड़ों की सम्पत्ति के कागजात मिले हैं।

कार्रवाई से पहले एसीबी ने तीनों के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने की एफआइआर दर्ज की थी। एसीबी डीजी बीएल सोनी ने बताया कि जयपुर में जेडीए के अधिशाषी अभियन्ता (एक्सईएन) निर्मल कुमार गोयल के 4 ठिकानों पर, चित्तौड़गढ़ के परिवहन अधिकारी मनीष कुमार शर्मा के 6 ठिकानों पर और जोधपुर में सूरसागर थानाधिकारी प्रदीप कुमार शर्मा के 4 ठिकानों पर सुबह करीब साढ़े सात बजे एक साथ सर्च शुरू हुआ। एसीबी एक साल से जानकारी जुटा रही थी।

रात को टीम तैयार सुबह होते ही छापा

एसीबी अधिकारियों ने जहां-जहां दबिश देनी थी, वहां एक अधिकारी के नेतृत्व में 7 से 9 सदस्यों को गुरुवार तड़के ही तैनात कर दिया गया। सर्च के लिए एसीबी ने इसके लिए संबंधित न्यायालयों से सर्च वारंट पहले ही जारी करवा लिए थे। सुबह होते ही एक साथ सभी स्थानों पर दबिश दी गई।

एक्सईएन निर्मल कुमार गोयल : वैध आय से 1450% अधिक सम्पत्ति

लंबे समय से पृथ्वीराज नगर जोन के एक्सईएन गोयल के यहां सेवाकाल में खर्च व परिसम्पत्तियों पर करीब 6 करोड़ का निवेश करना पाया गया, जो कि उनकी वैध आय का लगभग 1450% अधिक है।

यह मिली सम्पत्ति

- **मानसरोवर** मध्यम मार्ग स्थित आवास पर 2 हजार डॉलर व 245 यूरो, 2 लाख 27 हजार 790 रुपए, 2 कार व विदेशी शराब की 23 बोतलें।
- **मानसरोवर** में दूसरे निवास पर एक कार, 1.60 लाख रु., 323.8 ग्राम सोना,4.4 किलोग्राम चांदी, एक लॉकर की चाबी।
- **सुमेर नगर** में 1100 वर्गगज के 2 निर्माणाधीन मकान, डीग में एक हवेली के कागजात, 2 लॉकर की चाबी, 318 ग्राम सोना व 3.5 किलोग्राम चांदी। पढ़ें **तीन** @ पेज 09

पुलिस निरीक्षक प्रदीप शर्मा : आय से 333% अधिक सम्पत्ति

जोधपुर के सूरसागर थानाधिकारी प्रदीप कुमार शर्मा के जोधपुर, भोपालगढ़ व बीकानेर स्थित 4 स्थानों पर कार्रवाई की। 4.43 करोड़ का निवेश करना पाया, जो वैध आय का 333% अधिक है।

यह मिली सम्पत्ति

क्रशर के लिए जमीन खरीद के इकरारनामे की प्रति, **भोपालगढ़** में 10 बीघा परिसर में स्कूल, **पाली** के रोहट कस्बे में 5 बीघा जमीन, सोजत में पत्नी के नाम खनिज स्टोन की लीज, जाडन गांव में क्रशर प्लांट के लिए 12 बीघा जमीन के दस्तावेज मिले।

यहां ली गई तलाशी : रातानाड़ा पशु चिकित्सालय के सामने स्थित फ्लैट, थाना आवास, भोपालगढ में निजी स्कूल व बीकानेर में एक मकान में तलाशी ली गई।

डीटीओ मनीष कुमार शर्मा : आय से 232% अधिक सम्पत्ति

चितौड़गढ़ के जिला परिवहन अधिकारी मनीष के जयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर व जोधपुर में 6 ठिकानों पर सर्च की कार्रवाई चल रही है। मनीष के अपने सेवाकाल में खर्च व परिसम्पत्तियों पर 1.84 करोड़ रुपए का निवेश करना पाया गया है, जो वैध आय से 232 प्रतिशत अधिक है।

यह मिली संपत्ति:
- चितौड़गढ़ स्थित फ्लैट की तलाशी में 99 हजार 500 रुपए, महंगी बाइक, कार, विदेश यात्राओं से संबंधित दस्तावेज, एप्पल फोन व अन्य सामान मिला है।
- जोधपुर स्थित आवास व बाड़मेर स्थित ट्रवेल्स एजेन्सी की तलाशी चल रही है।
- जयपुर व उदयपुर स्थित एक फ्लैट को सील किया गया है।

तर भारत तपा : राजस्थान, मप्र, दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने चेताया

75 नए मरीज मिले,

तलाशी में मिले क्रेशर के लिए जमीन का इकरारनामा, भोपालगढ़ में 10 बीघा में स्कूल

थानाधिकारी पर छापों में उजागर हुआ साढ़े 4 करोड़ का निवेश

पत्रिका क्राइम रिपोर्ट

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जोधपुर. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पुलिस कमिश्नरेट के सूरसागर थानाधिकारी पुलिस निरीक्षक प्रदीप शर्मा के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज करने के बाद पांच ठिकानों पर दी दबिश में लगभग साढ़े चार करोड़ रुपए का निवेश उजागर किया है। तलाशी में फिलहाल नगद राशि तो नहीं मिली, लेकिन एसीबी के हाथ लगे सम्पत्ति संबंधी कई दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

ब्यूरो के उप महानिरीक्षक डॉ विष्णुकांत के अनुसार शर्मा के खिलाफ गुरुवार को एसीबी मुख्यालय में मामला दर्ज होने के बाद अलग-अलग टीमें गठित कर एक साथ तलाशी ली गई। प्रारम्भिक जांच में खर्च व परिसम्पत्तियों में 4.43 करोड़ रुपए निवेश पाया गया है। इंस्पेक्टर के खिलाफ करोड़ों रुपए की सम्पत्ति अर्जित करने का आरोप है।

थानाधिकारी के घर पर जांच करती एसीबी की टीम।

आरटीआई कार्यकर्ता ने की शिकायत

आरटीआइ कार्यकर्ता नंदलाल व्यास ने सात जुलाई 2019 और 11 फरवरी 2020 को शर्मा के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने की लिखित शिकायत दी थी। जिसमें शर्मा की अलग अलग स्थानों पर अर्जित सम्पत्ति का पूरा ब्यौरा दिया गया था। इस परिवाद की जांच के बाद एसीबी ने शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

ये सम्पत्तियां जुटाने का आरोप

- 31 अगस्त 2010 को भोपालगढ़ में 8 बीघा कृषि भूमि पत्नी के नाम खरीदी। इसके कुछ हिस्से को निजी स्कूल के लिए कन्वर्जन करवा कर साठ लाख रुपए में स्कूल बनवाई।
- पाली जिले रोहट कस्बे में पांच बीघा जमीन- नवम्बर 2014 में पाली के सोजत में पत्नी के नाम 40 लाख रुपए में खनिज स्टोन की लीज खरीदी। इसके पास जाडन गांव में क्रेशर प्लांट के लिए 12 बीघा जमीन खरीदी गई।
- जनवरी 2015 में कार खरीदी। यह भोपालगढ़ के एक व्यक्ति के नाम है।
- बीकानेर की आदर्श कॉलोनी में बीस लाख रुपए का भूखण्ड खरीदा।

तलाशी में मिले दस्तावेज

एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भोपालसिंह लखावत ने बताया कि रातानाडा पशु चिकित्सालय के सामने बहुमंजिला इमारत में शर्मा के फ्लैट, पुलिस स्टेशन सूरसागर में थानाधिकारी चैम्बर व आवासीय क्वार्टर, जिले के भोपालगढ़ में थानाधिकारी की पत्नी के नाम निजी विद्यालय व बीकानेर में मकान में एक साथ दबिश दी गई। फ्लैट में क्रेशर के लिए जमीन खरीद के इकरारनामे प्रति मिली। भोपालगढ़ में दस बीघा परिसर में निजी स्कूल तीन बसें, 22 हजार वर्ग फुट निर्माण व फर्नीचर का पता चला है।

यौद्धाओं के घर-घर जाएगी मशाल, एकत्रित होगी हर घर की मिट्टी

इलाज के बहाने महिला

पढ़ें बिजली @ पेज 07

फोटो: अनुग्रह सालोमन

कोर्ट में सरेंडर: मीणा ने फर्जी मार्कशीट से लड़वाया था पत्नी को चुनाव

भाजपा विधायक को भेजा जेल, कांग्रेस विधायक की 17 माह से तलाश

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

सराड़ा (उदयपुर). फर्जी मार्कशीट पेश कर पत्नी को सरपंच का चुनाव लड़वाने वाले सलूम्बर विधायक अमृतलाल मीणा ने सोमवार को सराड़ा न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। पीठासीन अधिकारी नगेन्द्र कुमार मीणा ने जमानत याचिका खारिज कर उन्हें जेल भेज दिया। पुलिस ने उन्हें सलूम्बर उपकारागृह में दाखिला दिलाया। मामले में उनकी पत्नी शांतादेवी अभी अग्रिम जमानत पर हैं।

विधायक मीणा

शांतादेवी वर्ष 2015 में सेमारी ग्राम पंचायत में चुनाव लड़कर तीसरी बार सरपंच बनी थीं। आवेदन के साथ शांता ने पांचवीं की जो मार्कशीट पेश की, उसे पराजित प्रत्याशी सुगनादेवी ने फर्जी बताते हुए सेमारी थाने में मामला दर्ज कराया था। मार्कशीट पर अभिभावक के रूप में विधायक मीणा के हस्ताक्षर थे। सहायक अभियोजन अधिकारी प्रकाश परमार ने बताया कि मार्कशीट अजमेर के नसीराबाद के स्कूल की थी। सीआइडी सीबी की जांच में वहां के प्रधानाध्यापक ने मार्कशीट अपने यहां की होने से इनकार कर दिया। वहीं, एफएसएल जांच में हस्ताक्षर विधायक के ही मिले। उधर, शांतिदेवी को आरोप पत्र पेश करने के दौरान ही अग्रिम जमानत मिल गई।

अग्रिम याचिका भी खारिज

विधायक मीणा ने एडीजे सलूम्बर व हाईकोर्ट में अग्रिम याचिका लगाई थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। उसके बाद विधायक ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की। न्यायालय ने पुलिस को 21 दिन तक गिरफ्तार नहीं करने तथा अधीनस्थ न्यायालय में आत्मसमर्पण के आदेश दिए थे। अधीनस्थ न्यायालय को उसी दिन जमानत पर सुनवाई के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में सुबह विधायक मीणा अपने अधिवक्ताओं के साथ न्यायालय पहुंचे और आत्मसमर्पण किया।

थाने के अधिकारियों का जानकारी होने से इनकार

सत्रह माह से लम्बित है स्थाई वारंट, पुलिस को मिल ही नहीं रहे भाकर

जयपुर. लाडनूं से कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को पुलिस तलाश रही है लेकिन वह मिल नहीं रहे। अदालत से उनके खिलाफ जारी स्थाई वारंट 17 माह से लम्बित है। हालांकि भाकर अपने क्षेत्र में सार्वजनिक रूप से जन सुनवाई तक कर रहे हैं।

भाकर के खिलाफ यह वारंट जयपुर के गांधीनगर थाने में दर्ज मामले से जुड़ा है। वर्ष 2010 के उक्त मामले में अदालत ने उनके खिलाफ फरवरी 2020 में स्थाई वारंट जारी किया था। उनके साथ राजेन्द्र तिवाड़ी, योगेश शर्मा, घासीलाल व अमित शर्मा के खिलाफ भी वारंट जारी हुआ था। पुलिस ने इसकी सूचना वेबसाइट के जरिए सार्वजनिक तो की लेकिन तामील के प्रयास नहीं किए। वांटेड पर्सन सर्च में उनकी यह जानकारी दी हुई है। वारंट को लेकर उनके गृह क्षेत्र के थाने के अधिकारियों ने तो जानकारी होने से ही इनकार कर दिया।
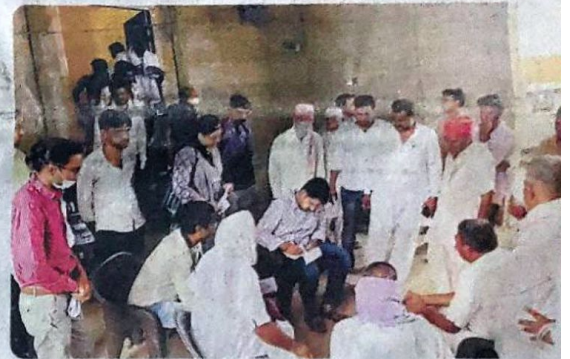
लाडनूं विधायक अपने निवास पर सोमवार को जन सुनवाई करते हुए

इधर पुलिस ने अभियान छेड़ा

इस बीच स्थाई वारंटों की तामील कराने के लिए पुलिस मुख्यालय ने 5 जुलाई से अभियान छेड़ा है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अपराध) रविप्रकाश मेहरड़ा ने विस्तृत आदेश जारी किया है। अब पुलिस ने मशक्कत शुरू की है। अन्य आरोपियों को तो वह तलाश रही है लेकिन विधायक के वारंट की तमील के प्रयास अब तक समने नहीं आए हैं। इनमें से एक आरोपी राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व महासचिव अमित शर्मा तो कोर्ट में पेश भी हो गए।

क्षेत्राधिकार के नाम पर लगवा रहे चक्कर

पति के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए एक साल से भटक रही महिला

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com 15-07-21

चाकसू/जयपुर. गांव थली निवासी सम्पति देवी पति के मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर गत एक साल से दर-दर भटक रही है। वह जिला कलक्टर, उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी, विधायक समेत पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी से कई बार गुहार लगा चुकी है। शादी के चार साल बाद पति की मौत के बाद उस पर दो बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी है।

पीड़िता ने पत्रिका को बताया कि उसके पति दिनेश (24) की गत वर्ष गांव नया निमोड़िया में सड़क निर्माण के दौरान करंट से मौत हो गई थी। जिसके मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर वह कई कार्यालयों के चक्कर लगा कर थक चुकी है। पत्रिका ने एक पखवाड़े पहले इस मामले को उजागर भी किया था। पीड़िता का आरोप है कि मौत के दो दिन बाद ही ग्राम पंचायत निमोड़िया में प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर दिया था। ग्राम विकास अधिकारी ने विकास अधिकारी को मौत पंचायत क्षेत्र में नहीं होना बताकर प्रमाण पत्र बनाने में असमर्थता जाहिर कर दी। विकास अधिकारी ने नगर पालिका चाकसू के अधिशासी अधिकारी को पत्र लिखा। ईओ ने अस्पताल का हवाला देकर मौत नगर पालिका क्षेत्र में नहीं होना बता प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार कर दिया। बाद में पीड़िता की परेशानी देख विकास अधिकारी ने ग्राम विकास अधिकारी निमोड़िया को मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं और आदेशों की पालना नहीं करने पर नोटिस भी जारी किया है। हालांकि बुधवार तक भी प्रमाण पत्र नहीं बना है।

> प्रमाण पत्र बनाने को लेकर ग्राम विकास अधिकारी को आदेश दिए हुए हैं। लेकिन ग्राम विकास अधिकारी के अनुसार पीड़िता की ओर से थाने में दर्ज करवाए गए परिवाद में मौत चाकसू अस्पताल में होना बताया गया है। इसलिए ग्राम विकास अधिकारी इस कार्य को नहीं कर रहा।
>
> **- कृष्णा माहेश्वरी,** विकास अधिकारी चाकसू

कोटा में एसीबी की कार्रवाई: अफीम काश्तकारों से अवैध वसूली

18-07-21

आइआरएस की कार से मिले 16.32 लाख रुपए, गिरफ्तार

- उत्तरप्रदेश के गाजीपुर स्थित अफीम फैक्ट्री में है महाप्रबंधक

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

कोटा. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा की टीम ने शनिवार सुबह उत्तरप्रदेश के गाजीपुर स्थित अफीम फैक्ट्री के महाप्रबंधक (आइआरएस) शशांक यादव को 16.32 लाख रुपए के साथ पकड़ा। जांच के बाद देर रात गिरफ्तार कर लिया। एसीबी को जानकारी मिली थी कि यह राशि अफीम काश्तकारों से अवैध रूप से वसूली गई है। एसीबी कोटा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ठाकुर चन्द्रशील ने बताया कि शशांक यादव के पास नीमच स्थित अफीम फैक्ट्री का भी अतिरिक्त चार्ज है।

नीमच अफीम फैक्ट्री का भी है अतिरिक्त चार्ज

कोटा. एसीबी कार्रवाई के दौरान शनिवार को कार से मिठाई के डिब्बे में मिले रुपए व इनसैट में आरोपी आइआरएस शशांक यादव।

मिठाई के डिब्बे में मिले 15 लाख

एसीबी को सूचना मिली थी कि शशांक नीमच में काश्तकारों से लगभग 15 लाख रुपए वसूल कर पुलिस का लोगो लगी कार से चित्तौड़गढ़ से कोटा होते हुए गाजीपुर जा रहा है। इस पर शनिवार सुबह साढ़े दस बजे उदयपुर-कोटा मार्ग पर हैंगिंग ब्रिज टोल नाके के पास एसीबी कोटा के पुलिस निरीक्षक अजीतसिंह बगडोलिया ने टीम के साथ चैकिंग शुरू की। इस दौरान पुलिस का लोगो लगी कार की जांच की तो शशांक के बैग में मिठाई का डिब्बा मिला। डिब्बे में 15 लाख रुपए मिले। लैपटॉप के बैग व पर्स से 1 लाख 32 हजार 410 रुपए मिले। कुल 16 लाख 32 हजार 410 रुपए मिले। शशांक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। एसीबी ने शशांक को गिरफ्तार कर राशि जब्त कर ली।

30 से 36 करोड़ रुपए एडवांस वसूले

एसीबी के अनुसार शशांक ने नीमच में अफीम फैक्ट्री में कार्यरत अन्य कर्मचारी अजीत सिंह व कोडिंग टीम के दीपक कुमार के माध्यम से दलालों के जरिए अफीम की बढ़िया गाढ़ता एवं मारफीन प्रतिशत ज्यादा बताकर 60 से 80 हजार रुपए प्रति किसान वसूले। ये वसूली चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, कोटा एवं झालावाड़ के अफीम किसानों से की। जो काश्तकार रुपए नहीं देते, ये लोग उसकी अफीम को घटिया बताकर गाढ़ता एवं मारफीन प्रतिशत कम कर देते हैं। अजीत सिंह और दीपक ने दलालों के माध्यम से 6000 से अधिक अफीम किसानों से 10-12 आरी के पट्टे दिलवाने के नाम पर 30 से 36 करोड़ रुपए एडवांस वसूल लिए। शेष चालीस हजार से अधिक किसानों की अफीम की जांच होना बाकी है।

बंद करें अफीम की खेती: भरत सिंह

विधायक भरतसिंह कुंदनपुर ने कहा, केन्द्र सरकार को अफीम की खेती बंद कर देनी चाहिए। इसमें नियोजित तरीके से भ्रष्टाचार होता है। उन्होंने कहा, सांसदों को इस दिशा में पहल

गाढ़ापन एवं मारफीन प्रतिशत पर देते पट्टे

अफीम फैक्ट्री नीमच में पूरे मध्यप्रदेश एवं राजस्थान के नारकोटिक्स विभाग के लाइसेंसी अफीम काश्तकारों की अफीम जमा की जाती है। इस फैक्ट्री में वर्तमान में इस वर्ष अफीम देने वाले मप्र व राजस्थान के काश्तकारों की अफीम के सेम्पल की जांच का कार्य चल रहा है। जांच के बाद ही अफीम के गाढ़ापन व मारफीन प्रतिशत के हिसाब से काश्तकारों को भुगतान किया जाता है। गाढ़ापन एवं मारफीन प्रतिशत के हिसाब से ही नारकोटिक्स विभाग ... 6 आरी, 10 आरी एवं 12 आरी के पट्टे वितरित किए जाते हैं।

जिस कम्पनी के कारण मासूम की मौत, उसी से दो लाख ले परिजन को देने पहुंचीं महापौर

ये कैसा न्याय : लिफाफा निगम का और मदद का चेक लापरवाह कम्पनी से

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर . मानसरोवर स्थित सेक्टर-42 के पार्क में करंट से 11 साल के मासूम गौरव की मौत के बाद मुआवजे को लेकर मंगलवार को विवाद खड़ा हो गया। संवेदनाओं को नेताओं ने तार-तार कर दिया।

कार्यवाहक महापौर शील धाभाई और विधायक अशोक लाहोटी उसी आरसी एंटरप्राइजेज से दो लाख रुपए का चेक लेकर पीड़ित परिवार के घर पहुंच गए, जिसकी लापरवाही ने मासूम की जान ले ली थी। पहले चेक दिया और सभी ने फोटो खिंचवाई। इसके बाद महापौर ने परिजनों को डेयरी का भी लालच दिया। इसके बाद सभी चले आए।

पढ़ें **ये** @ पेज 07

डेयरी का लालच भी दिया, परिजन ने चेक लौटाया
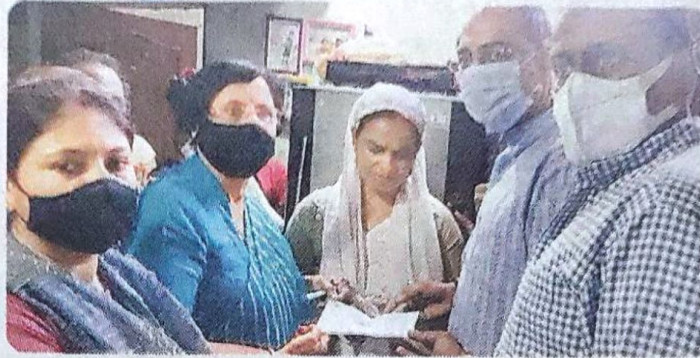
जयपुर . मृतक बालक के परिजन को चेक देते विधायक लाहोटी और मेयर।

घटना के बाद विधायक लाहोटी सहित कई पार्षद निगम आए थे। मांगों पर कार्रवाई की। हम आर्थिक सहायता जल्द देना चाहते थे, लेकिन प्रक्रिया में थोड़ा समय लग गया। आज दो लाख रुपए का चेक दिया है। आर्थिक सहायता और होती रहे, इसका प्रयास करूंगी। डेयरी की भी व्यवस्था कर देंगे। पालनहार योजना के तहत लाभ दिलाने का प्रयास करूंगी। **शील धाभाई,**
कार्यवाहक महापौर ग्रेटर निगम

नेताओं की बातों में मत आओ, वकील पैसा खा जाएंगे : महापौर

मंगलवार को कार्यवाहक महापौर शील धाभाई का एक **ऑडियो भी वायरल** हुआ। जिसमें वे कभी पत्रकारों पर निशाना साधती हैं तो कभी उन नेताओं के लिए बुरा-भला कहती हैं, जो गौरव की मौत के बाद सांत्वना देने घर पहुंचे थे। इतना ही नहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहुजा को लेकर उन्होंने यहां तक कहा कि उनकी बातों में मत आओ। कोर्ट केस करोगे तो पैसा तो आप का ही खर्च होगा और वकील भी पैसा खा जाएंगे। हादसे के जिम्मेदारों पर मुकदमा दर्ज कराने के सवाल पर वे कहती हैं कि उससे क्या होगा। आपने सोचा ही कैसे। जो लापरवाह थे, उन्हें निलम्बित कर दिया। आपको कौन सलाह दे रहा है। किसी की भी मत सुनो। आप तो कह दो, महापौर से बात हो गई है।

एक लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार

महिला पटवारी ने एसीबी को देख फेंके नोट

06.08.21

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जोधपुर . भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पत्थर की खान ट्रांसफर करने के लिए मौका रिपोर्ट बनाने की एवज में एक लाख रुपए रिश्वत लेने पर एक महिला पटवारी को गुरुवार सुबह चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में सेक्टर 9 स्थित मकान से गिरफ्तार किया।

एसीबी को देख पटवारी ने रिश्वत राशि मकान की प्रथम मंजिल से फेंक दिए थे। जो पड़ोसी के लगी प्लास्टिक जाली में अटक गए। महिला कर्मचारी के रिश्वत लेते पकड़ में आने की यह दूसरी कार्रवाई है।

पढ़ें **महिला** @ पेज 07

खबर का वीडियो देखें
patrika.com

आरोपी पटवारी।

पड़ोसी मकान में लगी नेट की जाली पर गिरे नोट

परिवादी को रिश्वत देने के लिए गुरुवार को पटवारी के घर बुलाया गया। भूतल पर माता-पिता व प्रथम मंजिल पर पटवारी रहती हैं। परिवादी ने प्रथम मंजिल पर पटवारी को एक लाख रुपए दिए। तभी एसीबी जालोर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महावीर सिंह राणावत के नेतृत्व में निरीक्षक राजेन्द्रसिंह व टीम ने दबिश दी। जिसे देख घबराई पटवारी ने पहली मंजिल से रुपए फेंक दिए। जो पड़ोसी मकान में लगी नेट की जाली पर गिरे, जहां से एसीबी ने बरामद किए।

लॉक डाउन व पटवारी हड़ताल से कार्रवाई में देरी

एसीबी का कहना है कि परिवादी ने अप्रेल में एसीबी की जालोर चौकी में शिकायत दी थी। फिर लॉक डाउन हो गया था। उसके बाद राज्य में पटवारी हड़ताल पर चले गए थे। ऐसे में कार्रवाई में देरी हुई।

भ्रष्टाचार की बेल : जिन कार्यों को ऑनलाइन करने का दावा, उनमें भी हो रहा जमकर भ्रष्टाचार

ऑनलाइन में भी 'रंगे हाथ', जनता को नहीं मिल रही काम की गारंटी

आशीष जोशी/अजय शर्मा
patrika.com

सीकर. सरकार की ओर से 15 विभागों के 108 कार्यों को पूरी तरह ऑनलाइन करने का दावा किया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि इनमें भी भ्रष्टाचार की बेल पनपने लगी है। कांग्रेस सरकार की ओर से पिछले कार्यकाल में आमजन को काम की गारंटी देने के लिए लोकसेवा गारंटी अधिनियम लागू किया गया था। इसके एक दशक बाद भी कुछ सेवाओं को छोड़कर अधिकांश में फरियादियों को काम की गारंटी नहीं मिल रही।

अलबत्ता, रिश्वत का खुला खेल जरूर खेला जा रहा है। इस साल अब तक एसीबी की ओर से 270 से ज्यादा ट्रैप की कार्रवाई की जा चुकी है। पिछले चार साल में हुई एसीबी की कार्रवाई में आइएएस, आइपीएस, आरएएस, लिपिक, शिक्षक, अभियंता सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के दाग लगे हैं। इनमें से कई भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए संबंधित सरकारी महकमों की ओर से एसीबी को अभियोजन स्वीकृति नहीं दी जा रही है। राजस्व, कार्मिक व पंचायतीराज विभाग के 150 से अधिक अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की फाइल जांच के नाम पर उलझी हुई है।

महामारी में भी पनपा भ्रष्टाचार

वर्ष	मामले
2021	270
2020	128
2019	169
2018	158
2017	158

(2021 में अब तक के मामले)

रिश्वत के लिए हर बार टरकाया

केस 01: बिल में तीन बार ऑब्जेक्शन, फिर ली घूस

अलवर जिले में सीडीपीओ प्रदीप कुमार गिलोटिया ने बकाया बिलों के भुगतान की एवज में 50 हजार रुपए रिश्वत ली। जबकि महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बिलों का भुगतान ऑनलाइन किया जा चुका है। सीडीपीओ ने बिल में तीन बार ऑब्जेक्शन लगाए।

केस 02: ऑनलाइन व टोल फ्री, फिर भी घूस

हिण्डौनसिटी में पांच मार्च को रीडिंग कम करने के एवज में फीडर इंचार्ज शिवकेश मीणा व सहायक रविन्द्र कुमार आठ हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए। जबकि जयपुर डिस्कॉम की ओर से रीडिंग में सुधार की व्यवस्था ऑनलाइन कर रखी है। यह त्रुटि निगम के टोल फ्री नंबर के जरिए भी ठीक हो सकती है।

अभियोजन स्वीकृति के लंबित मामले

विभाग	मामले	विभाग	मामले	विभाग	मामले
पंचायतराजः	54	कृषिः	05	आबकारीः	05
कार्मिकः	52	जल संसाधनः	11	समाज कल्याणः	04
राजस्वः	52	चिकित्साः	16	महिला एवं बाल विकासः	03
पुलिसः	36	स्वायत्त शासनः	28		
शिक्षाः	21	ऊर्जाः	14		

(जुलाई 2021 तक)

काम की गारंटी देने में सबसे आगे, जमीनी हकीकत कुछ और

1. जमाबंदी-नकलः तीन दिन का समय तय

काम की गारंटी अधिनियम में दावा किया गया कि पटवारी जमाबंदी व नकल के लिए अधिकतम तीन दिन फाइल रोक सकते है। तय समय में सुनवाई नहीं होने पर पीड़ित एसडीएम कार्यालय में अपील कर सकता है।

हकीकतः पिछले 12 महीने में 22 कार्रवाई हो चुकी है। ऑनलाइन व्यवस्था के बाद भी फरियादियों को टरकाया जा रहा है।

2. बिजली बिल में गलतीः 3 घंटे से 7 दिन में ठीक

सरकार का दावा है कि पानी व बिजली बिल में गलती होने पर यदि फोन से सूचना दी जाती है तो उसी दिन तीन घंटे में बिल ठीक करना होगा। यदि बिल डाक के जरिए कार्यालय भेजा गया है तो अधिकतम 7दिन लग सकते हैं।

हकीकतः कनेक्शन से लेकर गलती सुधारने सहित कई मामलों में एक साल में 17 अधिकारी-कर्मचारी ट्रैप हो चुके हैं।

3. पंचायतीराजः 10 से 45 दिन में भुगतान का दावा

पंचायतीराज विभाग की 11 योजनाओं में 10 से 45 दिन में भुगतान का दावा किया गया है। निविदा की राशि जमा कराने पर अधिकतम तीन दिन, अनुमति के मामलों में 30 दिन का प्रावधान है। विवाह पंजीयन के लिए सात दिन का समय तय है।

हकीकतः प्रदेश में एक साल में 29 मामलों में रिश्वत इस तरह के कार्यों के लिए ली गई।

जिन पर मॉनिटरिंग का जिम्मा, वे भी रिश्वतखोर

चिंताजनक बात यह है कि आमजन को राहत देने के लिए जिन पर ऑनलाइन कामकाज की मॉनिटरिंग का जिम्मा है, वे भी रिश्वत लेते पकड़े गए हैं। इस साल ही 40 राजपत्रित अधिकारी ट्रैप हुए हैं। अगस्त के पहले सप्ताह में ही एसीबी की 8 कार्रवाई हो चुकी है। जुलाई 2021 में ट्रैप के 38 मामले हुए।

लोकसेवा गारंटी अधिनिय[म] हो या सम्पर्कपोर्टल, निश्चि[त] तौर पर सरकार की अच्छी पहल है। लेकिन इनकी कमजोर मॉनिटरिंग की वजह से कुछ कामि[क] इसका गलत फायदा उठा लेते हैं। कई मामलों में फरियादियों को अपना काम निकलवाने के लिए भ्रष्टाचारियों की डिमांड भी पूरी करनी पड़ती है। **-जीएल कटारिया,** सेवानिवृत्त आरएएस अधिकारी

मीणा हाईकोर्ट में

हादसे में हुई थी दो भाइयों व उनकी पत्नियों व बच्ची की मौत

09.08.21

अब नई तकनीक से सुधरेगी शहर की सीवरेज लाइनें

न तो सड़कें खुदेंगी और न ही ट्रेफिक रुकेगा

राजेश दीक्षित
patrika.com

जोधपुर. जोधपुर शहर में अब स्मार्ट सिटी की तर्ज पर क्षतिग्रस्त सीवर लाइनों को सुधारा जाएगा। साथ ही पुरानी सीवर लाइन को निकाले बगैर ही नई पाइप लाइन डाल दी जाएगी। इसमें सबसे बड़ी सुविधा यह रहेगी कि इन दोनों कामों में सड़क खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रेफिक भी बाधित नहीं होगा। अब तक इन दोनों कामों से शहरवासी खासे परेशान होते रहे हैं। जोधपुर नगर निगम में इन दिनों 309 करोड़ रुपए से क्षतिग्रस्त सीवर लाइन सुधारने, डेमेज सीवर लाइन के पाइप बदलने व जोधपुर के बाहरी इलाकों में नई सीवर लाइन डालने के लिए डीपीआर बना रहा है। इसमें नई तकनीक का उपयोग किया जाएगा। ये सीवर लाइनें वर्ष 2055 की आबादी को ध्यान में रखकर डाली जाएंगी।
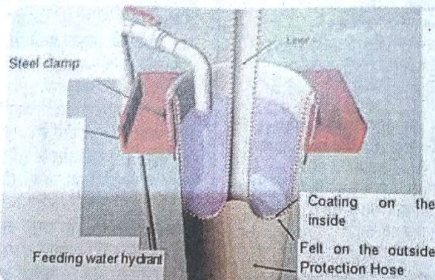
अब इसलिए जरुरत है आधुनिक तकनीक की

1. ये दोनों तकनीकें ट्रेंच लेस यानी बिना खुदाई से पाइप लाइन को दुरुस्त करने व साइज बड़ी करने में काम आएगी।
2. शहर में एक ही जगह सीवर, पानी, टेलीफोन की लाइन डली हुई हैं। खुदाई में सभी लाइन डिस्टर्ब हो जाती हैं।
3. पुराने शहर में कई सीवर लाइन 30-40 साल पुरानी हैं। इन्हें नए सिरे से बदलने का मतलब हैं पूरी खुदाई करना।
4. पुराने शहर में कई जगह भूजल स्तर काफी अधिक है। ऐसे में सामान्य खुदाई से पानी आ जाता है।
5. पाइप लाइन बदलते ही शहर की गलियां जाम हो जाती हैं।

समय कम लगेगा

ये दोनों तकनीक का उपयोग अब जोधपुर शहर में किया जाएगा। हालांकि ये तकनीकें कुछ महंगी हैं। इन तकनीकों का एक फायदा यह भी होगा कि पहले जहां खुदाई करके पाइप लाइन सुधारने व बदलने में 15-20 दिन लगते थे, वहीं अब 2-3 दिन में यह कार्य हो जाएगा। सड़क खुदाई, रास्ता जाम, ट्रेफिक की परेशानी से राहत मिलेगी। ये तकनीकें केवल पुरानी व डेमेज पाइप लाइन में काम आएगी।

पीएस तंवर, अधीक्षण अभियंता, नगर निगम (उत्तर)

ऐसे होगा नई तकनीक का उपयोग

पहली तकनीक
सीआईपीपी (क्यूर इन पाइप प्लेसमेंट)

इस तकनीक का उपयोग उन सीवर लाइनों में किया जाएगा, जो फूट गई हैं या लीकेज हैं। इसमें पुरानी सीवर लाइन के अंदर एक गुब्बारेनुमा पीबीसी मेटेरियल का पाइप डाला जाएगा। पाइप में गर्म हवा दी जाएगी। इससे पाइप भीतरी सतह को मजबूत कर देगा। अंदरुनी सतह नई हो जाएगी। इससे पानी की प्रवाह क्षमता बढ़ जाएगी। यह तकनीक शहर की संकड़ी गलियों में ज्यादा उपयोग में की जानी है, ताकि सड़क खुदाई से होने वाली परेशानी से बचा जा सके।

दूसरी तकनीक
पाइप ब्रंसटिंग टेक्नोलॉजी (पीबीटी)

इस तकनीक का उपयोग उन इलाकों में किया जाएगा, जहां पाइप लाइन छोटी है, लेकिन आबादी के अनुसार पानी का फ्लो सही नहीं है। यहां पाइप लाइन बड़ी डाली जाती है तो खुदाई व ट्रेफिक की परेशानी होगी। इस तकनीक में पाइप निकाले बिना पाइप साइज को बड़ा किया जाएगा। इसमें छोटे पाइप को मशीन से सीवर लाइन में डाला जाएगा। यह पाइप पहले से ही डले हुए पाइप की सतह को खुरच देगा। इससे पाइप की साइज बड़ी जाएगी। प्रवाह क्षमता तेज हो जाएगी।

हंसमुख थी, जिसे वहशी ने बेदर्दी

ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया तथा

पढ़ें **4 साल** @ पेज 06

जहां गई 7 जानें...वहां दूसरे दिन भी अवैध खनन

भीलवाड़ा . लाछुड़ा में बुधवार को अवैध खनन के दौरान 7 लोगों की जान चली गई। पत्रिका टीम ने गुरुवार को समोरडी क्षेत्र का जायजा लिया तो वहां धड़ल्ले से अवैध माइनिंग करते हुए लोग नजर आए। अवैध खनन करने वालों में किसी तरह का खौफ नजर नहीं आया।

खिलवाड़: 15 प्रतिशत खाद्य सामग्रियों में जानलेवा मिलावट

घर की थाली में 'जहर' परोस रहे मिलावटखोर, जिम्मेदार मौन

14-8-2021

किडनी, लिवर और कैंसर संबंधी गंभीर बीमारियों का बढ़ा खतरा

वर्ष 2020 में लिए गए नमूनों में से 18 प्रतिशत निकले मिलावटी

विकास जैन
patrika.com

जयपुर . घर की थाली में 'जहर'। कुछ ऐसा ही कर रहे हैं प्रदेश की जनता के साथ मिलावटखोर। राज्य सरकार भी इन पर प्रभावी अंकुश नहीं लगा पा रही है।

कोरोना के दौरान वर्ष 2020 में मिलावटखोरों ने घरों की थाली तक जमकर जानलेवा श्रेणी की मिलावट की। उक्त पूरे साल में मिलावटी पाई गई खाद्य सामग्रियों में से 15 प्रतिशत जानलेवा श्रेणी की मिली हैं। प्रदेश में मिलावटखारों के हौंसले बुलंद होने का मुख्य कारण कमजोर कानून और कमजोर कार्रवाई सामने आया है। राज्य सरकार ने करीब दो वर्ष पूर्व विधानसभा में मिलावट को गैर जमानती अपराध घोषित कर देशभर में नजीर पेश करने का दावा किया, लेकिन अब तक न कानून मजबूत हुआ और न ही मिलावट को गैर जमानती अपराध घोषित किया गया।

कोरोना के समय अधिक जानलेवा

विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना के दौरान लोगों की सेहत सही रहना सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छी खाद्य सामग्रियों का उपयोग ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में सहायक होता है। वरिष्ठ डॉक्टर वीरेन्द्र सिंह के अनुसार एक तरफ जहां लोग महामारी के वर्ष में जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उस समय मिलावटी खाद्य सामग्रियां अधिक जानलेवा साबित हो सकती हैं।

खाद्य सामग्रियों की जांच करती टीम। - फाइल फोटो

इतनी मिली मिलावट

- **पूरे** वर्ष के दौरान टीम ने विभिन्न जिलों में 10175 फर्मों-संस्थानों से 7439 नमूने लिए।
- **इनमें** से 18.61 प्रतिशत यानी 1385 में मिलावट मिली।
- **इन 1385** में से भी 210 नमूनों यानी 15.16 प्रतिशत की मिलावट जानलेवा (अनसेफ) श्रेणी की हैं। शेष मिलावटी नमूने सब स्टैंडर्ड और मिस ब्रांड श्रेणी के हैं।

सजा या कमाई का जरिया! 28 लाख पेनल्टी से मिले

विभाग की टीमों ने जो नमूने लिए हैं उनमें 1185 सब स्टेंडर्ड और मिसब्रांड श्रेणी के हैं। इनमें 741 को एडीएम के समक्ष पेश किया व 142 पर ही निर्णय अभी तक आया है। इनके आधार पर 28 लाख की पेनल्टी लगाई गई है। जबकि अनसेफ श्रेणी के 210 नमूनों में से 95 को ही सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया।

पत्रिका व्यू

हम भी रहें जागरूक

मिलावटी पदार्थों से बचने और अपमिश्रण की पहचान के लिए गृहिणियों का जागरूक होना भी अतिआवश्यक है। मिलावट की रोकथाम में उपभोक्ताओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक उपभोक्ता (विशेषकर गृहिणियों) को अपमिश्रण से बचने के लिए जागरूक होना चाहिए। इसके लिए कुछ आवश्यक बिंदु ध्यान में रखना चाहिए, जैसे खुली खाद्य सामग्री न खरीदें। अधिकतर मानक प्रमाण चिन्ह (एगमार्क, एफपीओ,आइएसआइ, हॉलमार्क) अंकित सामग्री खरीदें तथा सामग्री के गुणों, रंग, शुद्धता आदि की समुचित जानकारी रखें। जानकार दुकानदारों व सत्यापित कम्पनियों से सामग्री लें। पैकेज्ड सामान का उपयोग करते समय कम्पनी का नाम, पता, खाद्य पैकिंग व समाप्ति की तिथि, सामग्री का वजन, गुणवत्ता लेबल का ध्यान रखें।

नमूने मिलावटी मिलते ही होती है कार्रवाई

जो भी नमूने मिलावटी मिलते हैं, उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है। अधिकांश मामले कोर्ट में पेश किए जा चुके हैं।

डॉ. रविप्रकाश शर्मा,
अतिरिक्त निदेशक, ग्रामीण स्वास्थ्य, चिकित्सा विभाग

Phase 2 - 1st Sept | Phase 2 - 1st Sept

शीर्ष कोर्ट सख्त: ईडी-सीबीआइ कारण बताए, पूछा सुप्रीम सवाल

'सांसदों-विधायकों के खिलाफ केस की चार्जशीट में देरी क्यों'

एजेंसियों की रिपोर्ट अनिर्णायक

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा (सीबीआइ) जांच की धीमी गति पर गंभीर चिंता व्यक्त की। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड़ और न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने बुधवार को सुनवाई के दौरान 15 वर्ष बाद भी कई मामलों में चार्जशीट दाखिल नहीं करने के कारणों का उल्लेख नहीं करने पर ईडी-सीबीआइ की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। ईडी और सीबीआइ की रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा, हमें यह कहते हुए खेद है कि रिपोर्ट अनिर्णायक है।

पढ़ें **सांसदों** @ पेज 07

मनोबल गिराना उद्देश्य नहीं

हम एजेंसियों का मनोबल गिराना नहीं चाहते हैं। उन पर न्यायाधीशों की तरह अधिक बोझ हैं। लेकिन रिपोर्ट बहुत कुछ कहती है।
– एनवी रमना, सीजेआइ

मनी लॉन्ड्रिंग में बस संपत्तियां कुर्क

■ **सीजेआइ रमना:** मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामलों में ईडी ने बस संपत्तियां कुर्क कीं, चार्जशीट दायर नहीं की।

■ **सॉलिसिटर जनरल:** ईडी के कई मामलों में अक्सर विदेशों से जानकारियों की जरूरत होती है। ऐसे में देरी होती है।

■ **सॉलिसिटर जनरल:** अदालत सुनवाई समाप्त करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित कर सकती है।

■ **सीजेआइ:** हमारे लिए यह कहना आसान है कि ट्रायल में तेजी लाएं लेकिन जज कहां हैं?

■ **सीजेआइ:** वर्कफोर्स एक वास्तविक मुद्दा है। हमारी तरह जांच एजेंसियां भी इस मुद्दे से पीड़ित हैं। सभी सीबीआइ जांच चाहते हैं। पढ़ें **मनी** @ पेज 07

ये है माननीयों का रिपोर्ट कार्ड...

- ■ ***51 सांसद, 71 विधायक/एमएलसी*** पर मनी लॉन्ड्रिंग केस
- ■ 28 मामले मनी लॉन्ड्रिंग के जिनमें ***8-10 साल से जांच*** जारी
- ■ ***121 सीबीआइ केस*** लंबित हैं मौजूदा विधायकों पर
- ■ 58 पर ***आजीवन कारावास*** की सजा के प्रावधान वाली धाराएं
- ■ 37 मामलों की ***सीबीआइ जांच*** जारी

हाई कोर्ट की मंजूरी से ही मामला वापस

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ केस वापसी के लिए संबंधित हाई कोर्ट की मंजूरी जरूरी है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि मामले केवल दुराग्रहपूर्ण अभियोजन के नाम पर वापस नहीं लिए जा सकते हैं।

■ कामगार जा सकेंगे सऊदी अरब

नई दिल्ली @ पत्रिका. सऊदी अरब ने भारत समेत 20 देशों के प्रवासी कामगारों पर से यात्रा प्रतिबंध हटा लिया है। कोरोना के कारण फरवरी में प्रतिबंध लगाया गया था। सऊदी आने वाले कामगारों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए।

■ पूर्व विधायक को 25 साल की जेल

शिलांग@ पत्रिका. मेघालय के पूर्व निर्दलीय विधायक जूलियस डोरफांग को 2017 में एक किशोरी से रेप के मामले में 25 साल जेल की सजा सुनाई गई है। डोरफांग ने 2017 में विधायक रहते बालिका से रेप किया था।

■ फैसले के लिए हाई कोर्ट को 2 हफ्ते

नई दिल्ली @ पत्रिका. राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्ति को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने की छूट दी। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट को दो हफ्ते में मामले का फैसला करने को कहा है।

■ ऑनलाइन शादी पर विचार करेगी अदालत

कोच्चि @ पत्रिका. केरल हाई कोर्ट विशेष विवाह कानून के तहत शादी को वीडियो कॉन्फ्रेंस से कराने की संभावना तलाशेगा। याचिकाकर्ताओं का तर्क है इस कानून के तहत दूल्हा-दुल्हन की व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी नहीं है।

ाली: चौकी प्रभारी का आरोप थाना प्रभारी-सीओ का बजरी माफिया से गठजोड़

बजरी पर बवाल
मंत्री के सामने पूर्व स्पीकर बोले... अफसर ले रहे बंधी

29.07.2021

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

पपुर . सीकर . पाली . सीकर जिले [ा] डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट [ा] गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शिक्षा [मं]त्री गोविंद सिंह डोटासरा के सामने पूर्व [वि]धानसभा अध्यक्ष व विधायक दीपेन्द्र [सिं]ह शेखावत ने अवैध खनन को लेकर [बं]धी लेने का मामला उठाया। इधर, [पा]ली जिले में जेतपुर पुलिस चौकी प्रभारी [ने] पुलिस उपअधीक्षक व रोहट एसएचओ [प]र बजरी माफिया से गठजोड़ का आरोप [ल]गा दिया है। जानकारी के अनुसार [प्र]देश में बजरी का सालाना 2 हजार [क]रोड़ से अधिक का अवैध कारोबार [हो]ता है।

पढ़ें **मंत्री** @ पेज 16
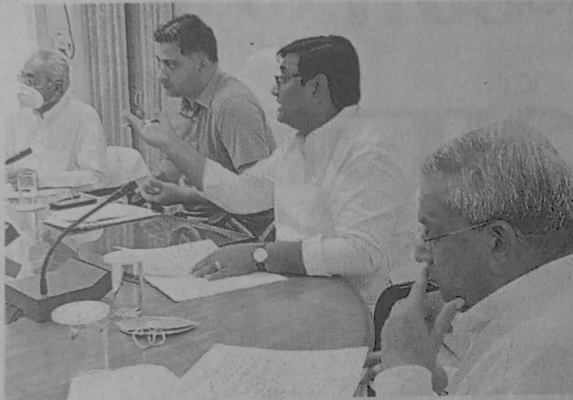
सीकर . बैठक में शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत एवं सभापति राजेंद्र पारीक (दाएं)।

अधिकारी बोले, हमारे पास गाड़ी नहीं

बैठक में शिक्षा मंत्री डोटासरा ने अवैध खनन रोकने के लिए एक्शन प्लान के लिए पूछा तो अधिकारियों ने कार्रवाई के लिए गाड़ी नहीं होने की बात कर हाथ खड़े कर दिए। जब मंत्री ने एसडीओ की अध्यक्षता में टास्कफोर्स बनाकर कार्रवाई की बात कही तो विधायक दीपेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि नीमकाथाना में एसडीओ, तहसीलदार, पुलिस व खान विभाग के अधिकारी मंथली बंधी ले रहे हैं। एक विधायक ने कहा कि रोज अवैध खनन की खबरें मीडिया में आ रही हैं। बैठक में विधायक राजेन्द्र पारीक, सुरेश मोदी और विधायक हाकम अली खां सहित तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

स्कैन करें

भरी सभा में बोले विधायक, बंधी होने के कारण अफसर नहीं करते कार्रवाई

पुलिस सब इंस्पेक्टर ने ही सीओ और थानाप्रभारी पर लगाए आरोप

बताएं किसको कितना मिला: भाजपा

विधायक शेखावत का मंथली बंधी के आरोप का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भाजपा के आइटी सेल के राष्ट्रीय प्रमुख अमित मालवीय ने वीडियो ट्वीट कर कहा कि राजस्थान में किसको कितना मिलता है? इसका जवाब जनता को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देंगे या स्वयं राहुल गांधी? इन लोगों ने देश को इसी तरह 70 सालों में खोखला कर दिया।

[चौ]की प्रभारी ने कहा- माफिया का काम नहीं करने पर किया लाइनहाजिर

[ब]जरी माफिया से गठजोड़ के चलते [पा]ली जिले के रोहट थाना क्षेत्र की [जे]तपुर पुलिस चौकी प्रभारी [म]नोहरलाल विश्नोई को लाइन [हा]जिर कर दिया गया। विश्नोई का एक वीडियो वायरल हुआ है, इसमें पुलिस उप अधीक्षक (पाली ग्रामीण) श्रवणदास संत व रोहट थानाधिकारी जसवंत सिंह राजपुरोहित पर बजरी माफिया से गठजोड़ का आरोप लगाया है। माफिया का काम नहीं करने पर उन्हें लाइन हाजिर किया है। इसकी जांच भी सीओ संत को ही सौंपी गई है, जो गलत है।

पढ़ें **चौकी** @ पेज 16

लद्दाख दौरा: लोकसभा अध्यक्ष ने दुर्गम क्षेत्र में जाने ग्रामीणों के हाल

कोरोना

रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स मामला: ब्रिटिश कंपनी को केंद्र सरकार का एक अरब डॉलर का प्रस्ताव मंजूर

भारत के खिलाफ केस वापस लेगी केयर्न, सरकार भी राजी

1.1 लाख करोड़ रुपए के टैक्स दावे को छोड़ने का फैसला किया भारत सरकार ने

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

लंदन. ब्रिटिश कंपनी केयर्न एनर्जी फ्रांस से लेकर अमरीका तक में भारतीय परिसंपत्तियों को जब्त करने से जुड़े सभी मुकदमे वापस लेगी। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स मामले में कंपनी ने भारत सरकार पर केस किया था।

केंद्र सरकार ने पिछले महीने ही रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स यानी पिछली तारीख से टैक्स लगाने के कानून को खत्म किया। इसके बाद केयर्न एनर्जी ने मामले को खत्म करने का कदम उठाया है। केयर्न ने भारत सरकार की एक अरब डॉलर वापस करने की पेशकश मान ली है। कंपनी रिफंड मिलने के तुरंत बाद इन मामलों को वापस लेने की कार्यवाही शुरू कर देगी। कंपनी ने फ्रांस और अमरीका सहित अन्य देशों में एयर इंडिया सहित भारतीय परिसंपत्तियों को जब्त करना शुरू कर दिया था।

सरकार करेगी रिफंड

₹8,100 करोड़ वापस किए जाएंगे कंपनियों को, इनमें ब्याज और जुर्माना भी शामिल

₹7,900 करोड़ अकेले केयर्न एनर्जी का बकाया है भारत सरकार पर

कई कंपनियों के साथ टैक्स विवाद

रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स की वजह से वोडफोन, केयर्न एनर्जी, फ्रेंच फार्मा कंपनी सनोफी, अमरीकी कंपनी एटी एंड टी और क्राफ्ट के अलावा बेल्जियम और मॉरीशस की कंपनियों से भारत का विवाद चल रहे है।

1.1 लाख करोड़ की टैक्स दावेदारी छोड़ी

रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स रद्द कर भारत ने कई कंपनियों पर 1.1 लाख करोड़ रुपए टैक्स देनदारी के दावे को छोड़ दिया। सभी कंपनियां भारत के खिलाफ मामलों को वापस लेने पर सहमत हो जाती हैं तो उन्हें 8,100 करोड़ रुपए वापस कर दिए जाएंगे। इनमें ब्याज और जुर्माना शामिल हैं।

ये है पूरा मामला

केयर्न एनर्जी ने 2007 में भारतीय इकाई केयर्न इंडिया को सूचीबद्ध कराया। 2011 में कंपनी की 10% हिस्सेदारी अपने पास रखकर शेष हिस्सा वेदांता लिमिटेड को बेच दिया। आयकर विभाग ने 2012 में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाते हुए कंपनी से 10,247 करोड़ रुपए कैपिटल गेन्स टैक्स मांगा। इसकी वसूली के लिए तत्कालीन सरकार ने वेदांता में केयर्न की 5% हिस्सेदारी बेच दी और 1,140 करोड़ का लाभांश और 1,590 करोड़ का टैक्स रिफंड भी जब्त कर लिया था।

क्या था रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कानून

इसके तहत आयकर विभाग को 50 साल तक पुराने मामलों में कैपिटल गेन्स टैक्स लगाने का अधिकार था। कंपनी के मालिकाना हक में बदलाव विदेश में हुआ, लेकिन कारोबार भारत में हैं, तो उस पर भी यह कानून लागू होता था।

चौपासनी रोड की चौड़ाई 200 फीट सुनिश्चित करने का मामला

जवाब के लिए समय मांगता रहा निगम, अब कॉस्ट के साथ अंतिम अवसर

पत्रिका कोर्ट न्यूज

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में चौपासनी रोड की चौड़ाई 200 फीट सुनिश्चित करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर कई मौके देने के बावजूद जवाब दाखिल नहीं करना नगर निगम को भारी पड़ गया। कोर्ट ने राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में दस हजार रुपए जमा करवाने की शर्त पर निगम को जवाब के लिए आखिरी मौका दिया है। अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।

वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा तथा न्यायाधीश विनित कुमार माथुर की खंडपीठ में डा.चंद्रशेखर कल्ला की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान निगम की ओर से जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा गया। कोर्ट ने पाया कि 8 अप्रैल को भी बार बार मोहलत मांगे जाने का तथ्य उल्लेखित करते हुए दो सप्ताह का मौका दिया गया था। खंडपीठ ने न्याय हित में प्राधिकरण में दस हजार रुपए जमा करवाने की शर्त पर निगम को जवाब के लिए आखिरी मौका दिया है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने पहले ही जोधपुर विकास प्राधिकरण तथा नगर निगम को अग्रिम आदेश तक 200 फीट के दायरे में किसी तरह का पट्टा जारी करने से रोक दिया था। याची के अधिवक्ता विनित दवे ने कोर्ट को बताया था कि ज्वाला विहार कॉलोनी से बाइपास तक चौपासनी रोड की चौड़ाई 200 फीट निर्धारित की गई थी। वर्ष 1985 में खसरा नं-92 एवं 92/2 में निजी आवासीय योजना का ले-आउट अनुमोदित किया गया था, जिसमें वरिष्ठ नगर नियोजक ने चौपासनी रोड की चौड़ाई 200 फीट उल्लेखित करते हुए भूखंड संख्या 1 से 42 रोड के लिए आरक्षित किए थे। वर्ष 1985 में एक व्यक्ति ने भूखंड संख्या 1 से 42 में से एक का रूपांतरण करने के लिए आवेदन किया था, लेकिन तब उसका आवेदन 200 फीट चौड़ाई में आने के कारण निरस्त कर दिया गया था। वर्ष 2011 से लगातार 200 फीट चौड़ाई में किए गए अतिक्रमण हटाने के लिए ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन जेडीए और निगम एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं।

प्रस्तावित मास्टर डलवपमेंट प्लान में भी चौड़ाई 200 फीट ही है। हाल ही जेडीए ने एक प्रस्ताव के तहत 200 फीट की चौड़ाई कम करते हुए 160 फीट की चौड़ाई को उचित बताया है। इसके लिए निदेशक आयोजना ने दलील दी है कि केवल विवाह समारोहों के दिनों में यातायात का दबाव ज्यादा रहता है। यदि 200 फीट चौड़ाई रखी जाती है तो जेडीए को भूमि अवाप्त करनी होगी। आवासीय इलाकों के लिए 160 फीट चौड़ाई उचित है। इस निर्णय को जनहित में बाधक और अनुचित बताते हुए याचिका में चौड़ाई 200 फीट बहाल करने की मांग की गई है।

अलवर का मामला : आम आदमी के लिए 21 साल से नहीं निकाला लाटरी

यूआइटी वालों ने खुद ही बांट लिए 35 करोड़ के 47 प्लॉट

पत्रिका पड़ताल

गुपचुप ट्रस्ट की बैठक में करवा दिया अनुमोदन

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

अलवर. अलवर शहर में यूआइटी ने पिछले 21 साल से आवेदन करवाने के बाद एक भी प्लॉट लाटरी में नहीं निकाला है। ऐसे में ही यूआइटी अलवर में 35 करोड़ के प्लॉट पुरानी विकसित कॉलोनियों में अपने ही 47 कर्मचारियों को दे दिए। इसकी लाटरी तक निकाल ली गई, जिससे पहले इसे गुपचुप में यूआइटी ट्रस्ट की बैठक में पास कर दिया।

अलवर यूआइटी में बुधवार को नगरीय विकास विभाग के मूल कर्मचारियों और अधिकारियों के आवासों की लाटरी निकाली गई। इसमें 20 से 25 साल पुरानी आवासीय योजनाओं में लाटरी निकाल कर प्लॉट बांट दिए गए। किस के नाम कौनसे नम्बर का और किस योजना में प्लॉट निकला, इसको भी नोट शीट पर ले लिया गया। अब इनको रियायती दरों पर प्लॉट दिए जाने के लिए आवंटन पत्र दिया जाना है। यह पत्र मिलते ही ये कुछ घंटों में ही उसकी राशि जमा कराके रजिस्ट्री कराने की तैयारी की जा रही है। मुहिम में सब अधिकारी और कर्मचारी शामिल हो गए हैं।

लॉटरी निकालने की तैयारी शुरू

उप सचिव जितेन्द्र सिंह नरुका को बुधवार को ही यूआइटी के कार्यवाहक सचिव का चार्ज मिला। कार्यभार मिलने के 10 मिनट बाद ही यूआइटी में लॉटरी निकालने की तैयारी शुरू हो गई। यूआइटी के कर्मचारियों को प्लॉट देने के लिए पहले ही सचिव अर्तिका शुक्ला ने साफ इनकार कर दिया था।

35 करोड़ की कीमत के प्लॉट कौड़ियों के भाव

इन 47 प्लॉटों की कम से कम कीमत 35 करोड़ है। इनको जिस कॉलोनियों में प्लॉट दिए हैं और इन्होंने अपने लिए मौके के प्लॉट लिए हैं। इनका साइज 200 से 350 वर्गमीटर तक है। वर्तमान में इनकी कीमत प्रति वर्गमीटर की 25 हजार से 50 हजार प्रति वर्ग मीटर की है जो इनको रिजर्व प्राइज से बहुत कम रेट पर दिए गए हैं। इसे सभी कर्मचारियों और अधिकारियों ने पूरी तरह गोपनीय रखा। **वर्तमान में यूआइटी के चेयरमैन जिला कलक्टर नन्नू मल पहाड़िया हैं।**

47 प्लॉटों की लाटरी निकाली गई है। यह लाटरी मेरे सचिव पद पर कार्य ग्रहण करने के बाद निकाली है। यह प्लॉट रियायती दरों पर किसी को रिजर्व प्राइज के 80 प्रतिशत तो किसी को 50 प्रतिशत छूट के साथ मिला है।

-जितेन्द्र नरूका, कार्यवाहक सचिव यूआइटी

नगरीय विकास विभाग के मूल कर्मचारियों और अधिकारियों के आवासों की लाटरी निकाली गई। इसमें 20 से 25 साल पुरानी

किस के नाम कौनसे नम्बर का और किस योजना में प्लॉट निकला, इसको भी नोट शीट पर ले लिया गया। अब इनको रियायती दरों पर

एसीबी की कार्रवाई

डीआइजी स्टाम्प कार्यालय में 2 हजार की रिश्वत लेते कार्मिक पकड़ा

भरतपुर @ पत्रिका. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) टीम ने गुरुवार सुबह उप महानिरीक्षक (पंजीयन एवं मुंद्राक) विभाग के कार्यालय में कार्रवाई कर कार्यालय के कनिष्ठ सहायक केहरी जाट को 2 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। आरोपी ने रिश्वत राशि मकान को रजिस्टर्ड एवं स्टाम्प ड्यूटी कम कराने की एवज में ली थी। अचानक हुई कार्रवाई से कार्यालय में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के समय कार्यालय में डीआइजी स्टाम्प मौजूद नहीं थे। एसीबी सीओ परमेश्वर लाल ने बताया कि परिवादी दुलीचंद पुत्र प्रेम सिंह जाटव निवासी गांव त्योंगा ने एसीबी चौकी पर शिकायत दी थी। इसमें बताया कि उप महानिरीक्षक (पंजीयन एवं मुंद्राक) कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ सहायक केहरी सिंह उसके मकान को रजिस्टर्ड एवं स्टाम्प ड्यूटी कम करने की एवज में रिश्वत मांग रहा है। जिस पर एसीबी ने 8 सितम्बर को सत्यापन कराया जिसमें दो हजार रुपए की रिश्वत मांग की गई। एसीबी ने आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया।

आरटीओ कार्मिकों पर एक साल में दूसरी कार्रवाई

परिवहन उपनिरीक्षक सहित तीन को अवैध वसूली करते दबोचा

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

डूंगरपुर. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर की टीम ने गुरुवार रात नेशनल हाइवे 48 पर बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के बोखला रिजवा घाटी के समीप परिवहन विभाग के उपनिरीक्षक सहित दो हेल्पर को ट्रक चालकों से अवैध वसूली करते धरदबोचा। कार्रवाई के लिए टीम उदयपुर से कंनेटर्स में सवार होकर पहुंची थी।

जानकारी के अनुसार गत दिनों कुछ कंटेनर व ट्रक चालकों ने हाइवे पर रतनपुर चेकपोस्ट पर परिवहन कार्मिकों की ओर से अवैध वसूली की शिकायत की थी। इस पर उदयपुर एससीबी की टीम गुरुवार शाम को प्लास्टिक दानों से भरे तीन कंटेनर में बैठकर डूंगरपुर आई। इस दौरान बोखला रिजवा घाटी के समीप परिवहन उपनिरीक्षक तौसिफ खान व ठेका कार्मिक बंशीलाल व राकेश मीणा ट्रक चालकों से वसूली कर रहे थे। जिन कंटेनर में एसीबी टीम बैठी हुई थी उन चालकों ने भी 200-200 रुपए निकालकर दिए। इस दौरान कंटेनर में सवार टीम ने उनके वीडियो बनाए तथा रुपए देने के बाद टीम ने मौके से उपनिरीक्षक तौसिफ व हेल्पर्स को धरदबोचा। वहां से उन्हें बिछीवाड़ा थाना लाया गया। बताया जा रहा है कि कार्मिकों के पास कुल एक लाख 11400 रुपए बरामद हुए हैं। इसमें चालान की राशि भी शामिल है। देर रात तक बिछीवाड़ा थाने में एसीबी की कार्रवाई जारी थी।

पिछले साल भी मारा था छापा

गौरतलब है कि एसीबी की टीम ने गत वर्ष दिसम्बर माह में रतनपुर परिवहन कार्यालय पर छापामार कार्रवाई कर कुछ कार्मिकों को वसूली करते पकड़ा था।

घरेलू कनेक्शन के लिए डिमाण्ड नोटिस जारी करने की एवज में ली रिश्वत

डिस्कॉम का एक्सइएन 25 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार

एसीबी को देख खुद को घर में बंद किया, समझाइश कर दरवाजा खुलवाया

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जोधपुर. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए डिमाण्ड नोटिस जारी करने की एवज में 25 हजार रुपए रिश्वत लेने पर पाली जिले के जैतारण में जोधपुर डिस्कॉम के अधिशाषी अभियंता (एक्सइएन) को शुक्रवार को गिरफ्तार किया। एसीबी को देख एक्सइएन ने खुद को घर में बंद कर लिया। काफी समझाइश के बाद उन्होंने दरवाजे खोले।

एसीबी के उप महानिरीक्षक डॉ विष्णुकांत ने बताया कि पाली जिले की जैतारण तहसील में पातसू रोड निवासी हेमंत पुत्र बंशीलाल की शिकायत पर कोट में बोरखेड़ा के आकाश नगर निवासी जैतारण में जोधपुर डिस्कॉम के अधिशाषी अभियंता (एक्सइएन) महेन्द्र कुमार पुत्र पांचुलाल मीणा को 25 हजार रुपए रिश्वत लेने पर गिरफ्तार किया गया। रसोई में फ्रिज के ऊपर कागज के बॉक्स में रखी रिश्वत राशि बरामद की गई।

पाली जिले के जैतारण में 25 हजार रुपए रिश्वत लेने का आरोपी डिस्कॉम का अधिशाषी अभियंता एसीबी की गिरफ्त में।

एसीबी को देख होश उड़े, दरवाजे बंद किए

परिवादी शुक्रवार को जैतारण में एक्सइएन के घर गया और रिश्वत के 25 हजार रुपए दिए। जो उसने रसोई में फ्रिज पर कागज के बॉक्स में रखे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भोपालसिंह लखावत के निर्देशन में निरीक्षक अमराराम खोखर वहां पहुंचे। यह देख एक्सइएन ने मकान के दरवाजे बंद कर दिए। चारों तरफ लोहे की जाली से पैक होने से वो घर में बंद हो गए। तब एसीबी ने काफी समझाइश कर दरवाजा खुलवाया और एक्सइएन को गिरफ्तार किया।

सत्यापन में 25 हजार की पुष्टि

परिवादी ने हेमंत ने नवनिर्मित मकान में घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए जैतारण स्थित डिस्कॉम कार्यालय में आवेदन कर रखा है। इस संबंध में गत वर्ष 5 नवम्बर और गत 24 जून को रसीदें कटवाई थी। नए कनेक्शन से पहले बिजली के पोल लगाए जाने हैं। जिसके लिए डिमाण्ड नोटिस जारी करना होता है। यह नोटिस जारी करने की एवज में एक्सइएन ने 15 हजार रुपए रिश्वत मांगे थे। जिसकी शिकायत एसीबी जोधपुर ग्रामीण चौकी में की गई। 8 सितम्बर को सत्यापन कराने पर एक्सइएन के 25 हजार रुपए रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई।

एसाबी की कार्रवाई: आइएएस नीरज के.पवन-प्रदीप गवड़े की भूमिका संदिग्ध

कौशल विकास निगम के अफसरों ने घूस में दिखाया कौशल, 5 लाख लेते गिरफ्तार

आरएसएलडीसी का स्कीम को-ऑर्डिनेटर व प्रबंधक को दबोचा

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

patrika.com

जयपुर . भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने राजस्थान राज्य कौशल विकास निगम (आरएसएलडीसी) के झालाना स्थित कार्यालय में शनिवार शाम स्कीम को-ऑर्डिनेटर अशोक सांगवान और सहायक आचार्य (हाल प्रबंधक) राहुल कुमार गर्ग को 5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

आरोपियों ने रिश्वत की राशि आला अधिकारियों तक पहुंचाने की भी बात कही। एसीबी के डीजी बी.एल. सोनी ने बताया कि प्रकरण में आरएसएलडीसी के चेयरमैन नीरज के. पवन (आइएएस) और मुख्य प्रबंधक (आइएएस) प्रदीप कुमार गवड़े की भूमिका की भी जांच की जा रही है। आइएएस नीरज के. पवन जोधपुर स्थित कुड़ी भगतासनी स्थित निजी कॉलेज में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे, एसीबी ने वहां से उनके दो मोबाइल फोन जब्त किए। जबकि आइएएस गवड़े के वैशाली नगर आवास से उनका मोबाइल फोन जब्त किया। दोनों अधिकारियों के मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच करवाई जाएगी।

एसीबी के एडीजी दिनेश एम.एन. ने बताया कि गुरुवार को परिवादी ने आरोपी सांगवान व गर्ग को रिश्वत में उसकी कार बेचकर 5 लाख रुपए देना तय किया। इसके बाद उसकी फाइल ने भी 'यू-टर्न' ले लिया।

पढ़ें **कौशल** @ पेज 10

पवन व गवड़े के मोबाइल फोन जब्त

जयपुर . झालाना स्थित आरएसएलडीसी कार्यालय।

जयपुर . नीरज के.पवन व अन्य अधिकारियों के सील कमरे।

70 कंपनी ब्लैकलिस्ट, 45 की बहाल

एसीबी की जांच में सामने आया है कि आरएसएलडीसी के अधिकारियों ने परिवादी की जैसे ही 70 कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया था। लेकिन बाद में 45 कंपनियों को बहाल भी कर दिया।

प्रशिक्षण के सबूत मांग कर रहे थे परेशान

एसीबी के एडीजी दिनेश एम.एन. ने बताया कि आरएसएलडीसी के जरिए बेरोजगारों को प्रशिक्षण देने वाली दौसा की कंपनी के संचालक ने 7 जनवरी को एसीबी में शिकायत की। शिकायत में बताया कि प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना में किए गए कार्य के 1.50 करोड़ रुपए के लंबित बिल पास करने, उसकी फर्म को ब्लैक लिस्ट से हटाने, परिवादी को जवाब देने की समय सीमा बढ़ाने और बैंक गारंटी जब्त नहीं करने की एवज में अशोक सांगवान व राहुल कुमार गर्ग 5-6 लाख रुपए रिश्वत मांग रहे हैं। आरोपी परिवादी की फर्म द्वारा 139 लोगों को प्रशिक्षण दिए जाने के सबूत मांगकर परेशान भी कर रहे थे। एसीबी के सत्यापन में भी रिश्वत मांगने की पुष्टि हो गई।

आरोपियों के आवास खंगाले

राहुल कुमार गर्ग

अशोक सांगवान

गिरफ्तार आरोपी गर्ग के गुर्जर की थड़ी स्थित पंचवटी कॉलोनी आवास तथा सांगवान के इंदिरा गांधी नगर आवास सहित दोनों के कुल पांच ठिकानों पर एसीबी का सर्च शनिवार रात तक चल रहा था।

श्रम विभाग में कार्रवाई के बाद भी नहीं चेते रिश्वत लेने वाले अधिकारी

एसीबी आरएसएलडीसी अधिकारियों के लिए उगाही करने वाला अमित श्रम आयुक्त प्रतीक झाझड़िया मामले से भी जुड़ा था। अमित श्रम विभाग के अधिकारियों के लिए भी बंधी की उगाही कर रहा था। अमित श्रम विभाग के आयुक्त के घर बंधी की राशि देने पहुंचा। तब एसीबी ने आयुक्त के खिलाफ भी कार्रवाई की। अमित के गिरफ्तार होने के बाद आरोपी अधिकारी दूसरे चैनल के जरिए रिश्वत वसूल रहे थे।

पैसे लेकर नीट पास कराने का मामला

लागा का झांसा दे रहा था। | से इनकार कर दिया। माहौल बैठ गए।

उदयपुर: तेज बारिश से देवेन्द्र एनिकट का पुल बहा 14-07-2021

खाट पर डाल पार कराई नदी, अस्पताल से पहले नवजात की मौत

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

परसाद (उदयपुर). उदयपुर जिले के सराड़ा उपखण्ड में ग्राम पंचायत परसाद के आसावाणिया ग्राम को जोड़ने वाली सम्पर्क सड़क पर देवेन्द्र एनिकट पर बना पुल पानी के तेज बहाव में टूट गया। पुल बहने के साथ ही लगभग 100 परिवारों का पंचायत मुख्यालय से सम्पर्क टूट गया। इस दौरान गांव के जगदीश मीणा की पत्नी केसरी देवी के प्रसव पीड़ा होने लगी।

कुछ समय तक तो ग्रामीणों ने नदी के बहाव को कम होने का इंतजार किया लेकिन केसरी देवी की प्रसव पीड़ा बढ़ती जा रही थी। इस पर परिजनों व पड़ोसियों ने तेज बहाव में जिन्दगी बचाने के लिए धात्री को खाट पर डाल कर नदी पार करवाई। इसके बाद महिला को परसाद सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचाया लेकिन तब तक नवजात ने गर्भ में ही दम तोड़ दिया। ग्रामीणों ने बताया कि नदी में तेज बहाव होने से गर्भवती को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा पाए।

विस्तृत जानकारी के लिए अपने फोन के कैमरे से QR कोड को स्कैन करें

हिंदी दिवस पर सरकार ने दी 348 अंग्रेजी स्कूलों की सौगात

सरकार: अंग्रेजी स्कूलों के लिए आभार
सवाल: 249 बालिका स्कूल क्यों छीने?

सरकारी शिक्षा का माध्यम बदलना तो जरूरी लेकिन बालिका शिक्षा से अन्याय क्यों?

एक्सक्लूसिव

विजय शर्मा
patrika.com

जयपुर. स्कूल शिक्षा विभाग ने 348 सरकारी स्कूलों का माध्यम बदलकर अंग्रेजी कर दिया और नए रूप में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू किए हैं। लेकिन, इन्हें शुरू करने की कड़ी में बालिका शिक्षा के साथ अन्याय किया जा रहा है। परिवर्तित होने वाले 348 में से 249 बालिका स्कूल हैं।

इन स्कूलों का माध्यम हिंदी से अंग्रेजी होने के साथ ही बालिका विशेष से सह-शिक्षा में बदला जाएगा। इसका सीधा प्रभाव उन छात्राओं पर पड़ेगा, जो केवल बालिका स्कूल या हिंदी माध्यम में पढ़ना चाहती हैं। सरकार ने अगर इन बालिकाओं की शिक्षा के लिए कोई उचित प्रबंध नहीं किया तो यह भी संभव है कि ये बालिकाएं शिक्षा से ही दूर हो जाएं। महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल में निजी स्कूलों से काफी बच्चे आ रहे हैं।

...और यह बुराई, 249 स्कूल बंद होने से छूट सकता है बालिकाओं का स्कूल

- **249** बालिका स्कूलों के बंद होने का सीधा असर छात्राओं पर पड़ेगा।
- **माध्यम** बदलने के साथ ही इन स्कूलों को बालिका विशेष से सह-शिक्षा में होगा।
- **पहली** से आठवीं तक छात्र व छात्राएं एक साथ पढ़ेंगे।
- **सह-शिक्षा** वाले स्कूलों में पढ़ाने से हिचकने वाली बालिकाओं को स्कूलों से बाहर होना पड़ेगा
- **बालिका** स्कूल नहीं मिलने या अधिक दूरी पर स्कूल होने पर भी बालिकाओं को शिक्षा से भी वंचित होना पड़ सकता है। इससे बालिकाओं का ड्राप आउट भी बढ़ सकता है।

ये सवाल, जो बता रहे बालिका शिक्षा खतरे में

1. **जो** बालिकाएं हिंदी माध्यम में ही पढ़ना चाहती हैं उन्हें दूसरा स्कूल क्या नजदीक मिल पाएगा?
2. **जो बालिकाएं बालिका विशेष स्कूल में ही पढ़ना चाहती हैं या अभिभावक उन्हें उसी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, अब** उनका क्या होगा?
3. **अंग्रेजी** माध्यम होने से निजी स्कूलों से काफी बच्चे सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं। नामांकन बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में इन स्कूलों की वर्तमान बालिकाओं के ड्राप आउट होने का क्या पता आंकड़ों में लग पाएगा?
4. **महात्मा** गांधी अंग्रेजी स्कूलों में फिलहाल पढ़ रही सौ फीसदी छात्राएं स्कूलों में पढ़ाई जारी रखें, सरकार इसे कैसे सुनिश्चित करेगी?

यह अच्छाई

एक लाख बच्चों को मिलेगा पढ़ने का अवसर

- अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में करीब एक लाख सीटें होंगी।
- अंग्रेजी स्कूलों की संख्या 500 से अधिक हो जाएगी।
- **कई अंग्रेजी स्कूलों में आइएएस, विधायक और सरकारी अधिकारियों के बच्चों ने प्रवेश लिया।**
- प्रवेश से वंचित रहे छात्रों के लिए एक बार फिर मौका मिलेगा।

अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का फायदा

- एक कक्षा में निर्धारित सीटों की संख्या 30 से अधिक भी होगी। स्कूल में अगर छात्र संख्या अधिक हुई तो दो पारियों में स्कूल चलेंगे।
- अंग्रेजी माध्यम स्कूलों से समाज की सोच बदली है।
- यह स्कूल आज के समय की जरूरत हैं। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी पीछे नहीं रहेंगे।
- निजी स्कूलों की फीस के बोझ तले दबे अभिभावकों को ये स्कूल राहत देंगे।

एनसीआरबी-2020 की रिपोर्ट में खुलासा

16-09-2021

बलात्कार में राजस्थान अव्वल

जयपुर दूसरे नंबर पर

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के 2020 के आंकड़ों के अनुसार देश में बलात्कार के 19 प्रतिशत मामले राजस्थान में दर्ज हुए। महानगरों में जयपुर देशभर में दूसरे नंबर पर रहा। ज्यादातर मामलों में पीड़िता की आयु 18 से 26 साल थी।

एनसीआरबी-2020 की बुधवार को जारी रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ। कोरोना के कारण 2020 में देश में लॉकडाउन रहा।

पढ़ें **बलात्कार** @ पेज 12

रेप में टॉप तीन राज्य

राजस्थान	5310	मप्र	2339
यूपी	2769	कुल	28046

बलात्कार के प्रयास

राजस्थान	965	असम	485
प.बंगाल	872	कुल	3741

महानगरों में रेप के मामले

दिल्ली शहर	976	जयपुर	409
		मुंबई	322

महिलाओं के खिलाफ अपराध

उत्तरप्रदेश	**49,385**
पश्चिम बंगाल	**36,439**
राजस्थान	**34,535**

महिला अपराधों में वृद्धि

एनसीआरबी आंकड़ों के अनुसार पिछले साल पूरे देश में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के कुल 3,71,503 मामले दर्ज हुए थे। जबकि 2019 में 4,05,326 थे और 2018 में 3,78,236 थे।

इनका कहना है

राजस्थान में फ्री रजिस्ट्रेशन कर रखा है। एफआइआर दर्ज हुई हैं, इससे क्राइम नहीं बढ़ा है। एफआइआर दर्ज होने से अपराध की वास्तविक स्थिति सामने आ जाती है। महिलाएं थानों में बेखौफ जाकर अपनी बात कह सकती हैं। राजस्थान पुलिस आमजन की सुनवाई को प्राथमिकता देती है। **रवि प्रकाश मेहरड़ा,** एडीजी क्राइम, राजस्थान

विधानसभा : भारी विरोध के बीच विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक पारित

अब बाल विवाह का भी होगा रजिस्ट्रेशन
विपक्ष बोला काला कानून, किया वॉकआउट

12-09-2021

नहीं मानी मत विभाजन की मांग, वेल में आया विपक्ष, नारेबाजी

30 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन अधिकारी को देनी होगी सूचना

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. प्रदेश में अब बाल विवाह का भी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। विधानसभा में शुक्रवार को जोरदार हंगामे के बीच सभी तरह के विवाहों के रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने के लिए राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक पारित हो गया।

भाजपा ने इस विधेयक को काला कानून कहते हुए विरोध कर सवाल उठाए। भाजपा विधायकों ने कहा कि बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन करना, बाल विवाह को वैध करने जैसा है। विधेयक पर सरकार का समर्थन कर रहे निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने भी खासा विरोध किया। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने जैसे ही पारित करवाने का प्रस्ताव रखा, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया व उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित भाजपा के सभी सदस्यों ने मत विभाजन की मांग उठा दी।

पढ़ें **अब** @ पेज 12

कानूनविदों की राय

- **इस** संशोधन से बाल विवाह की अनुमति का संदेश जाएगा। समाज के ताने बाने को प्रभावित करेगा।
- **यह** संशोधन बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम का विरोधाभाषी है। कोर्ट में अनावश्यक मुकदमेबाजी बढ़ेगी।
- **जब** बाल विवाह की अनुमति ही नहीं है तो कम आयु वालों के पंजीयन की अनुमति ही क्यों दी है!

धारीवाल : बातें कपोलकल्पित, बाल विवाह रहेगा अवैध

धारीवाल ने कहा रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि बाल विवाह वैध होगा। विधेयक में कहां लिखा है कि बाल विवाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और बाल विवाह वैध हो गया है। एक बार बाल विवाह का भी रजिस्ट्रेशन जरूर होगा, लेकिन वैध नहीं माना जाएगा। कलक्टर ऐसे विवाह के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने विपक्ष को कहा कि कपोलकल्पित बातें करने में आप लोग मास्टर हो। इस बिल के पास होने से कम उम्र वाले भी यदि शादी कर लेते हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन शादी के 30 दिन की अवधि में किया जा सकेगा।

कटारिया : 'पाप कर रहे हो, क्या मुंह दिखाएंगे'

धारीवाल के जवाब से पहले गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि ऐसा बिल लाकर आप पाप कर रहे हो। क्या ये बिल बाल विवाह की अनुमति नहीं देता। आप सहित सदन में बैठे हम सभी को जनता को जवाब देना होता है। ये बिल पास हो गया और हम इसका विरोध नहीं करेंगे, तो जनता को बाहर क्या मुंह दिखाएंगे। यदि ऐसा बिल लाने की मजबूरी हो, तो सदन में बैठे सभी सदस्यों का ही नहीं, जनता का भी मन जानना जरूरी है।

राठौड़ : चौदह साल की बच्ची की शादी हुई तो...

राठौड़ ने धारीवाल को जवाब देने के बीच टोका और कहा कि इस बिल के प्रावधान घोर आपत्तिजनक हैं। उन्होंने सवाल किया कि यदि किसी बच्ची की 14 साल की उम्र में शादी हुई और 18 साल की उम्र में वह कहेगी, मैं शादी कैंसिल करूंगी, यह कैसे पॉसिबल होगा। क्यों ऐसा काला कानून ला रहे हो। इस पर धारीवाल ने कहा कि यदि नाबालिग बच्ची 18 वर्ष की आयु के बाद विवाह का विरोध करेगी, तो उसके विवाह को अवैध माना जा सकेगा। धारीवाल ने कहा कि बाल विवाह आज भी राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं।

पत्रिका के सवाल पर संसदीय कार्य मंत्री
शांति धारीवाल के जवाब

Q बाल विवाह का पंजीयन करना क्या अवैध काम को वैध करने जैसा नहीं है?

धारीवाल: बाल विवाह अवैध ही रहेगा। हर तरह के विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य किया है, बस। बाल विवाह करने और करवाने वालों पर कार्रवाई होती रहेगी। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

Q ऐसे विवाहों का पंजीकरण करना क्या पॉक्सो एक्ट की धाराओं की अवहेलना नहीं है?

धारीवाल: संशोधन में पॉक्सो एक्ट या बाल विवाह की धाराओं के तहत किसी भी कार्रवाई को नहीं रोका जा रहा। कलक्टर, पुलिस या अन्य एजेंसी कार्रवाई कर सकती है।

Q ऐसे विवाह का पंजीकरण करवाने का मतलब खुद अपराध की सूचना देना है, ऐसा पंजीकरण लोग क्यों करवाएंगे?

धारीवाल: सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में निर्देश दिए हैं कि हर विवाह का पंजीकरण करना जरूरी है, इसलिए ये संशोधन लाए हैं। लोग पंजीकरण नहीं करवाएंगे, तो कई कानूनी पेचीदगियों के चलते नुकसान भी होगा।

सरकार ने रात को जारी की सफाई

सदन में भारी हंगामे के बाद रात को सरकार ने इस संशोधन विधेयक को लेकर सफाई जारी की। सरकार ने कहा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में वर की आयु 21 व वधु की 18 साल होने का प्रावधान है, विवाह पंजीयन अधिनियम मे दोनों की आयु 21 साल होने का प्रावधान है। इसे संशोधित कर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अनुरूप बनाया गया है। विवाह पंजीयन किसी भी तरह विवाह को वैधता प्रदान नहीं करता, बल्कि विवाह पंजीयन कराने वाले दंपति की संतान के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। सरकार का दावा है कि अब विवाह पंजीयन आसान हो सकेगा।

आप कुतर्क कर रहे हो...

निर्दलीय विधायक संयम लोढा ने धारीवाल को जवाब देते समय बीच में टोका और कहा कि मंत्रीजी आप कुतर्क कर रहे हो। लोढा ने तर्क दिया कि पॉक्सो एक्ट में वयस्क ने किसी नाबालिग की सहमति से शारीरिक संबंध बना लिए, तो भी इसे अवैध माना जाता है। क्या बाल विवाह में नाबालिग की सहमति की कोई वैधता है? आप यह ठीक नहीं कर रहे हो।

सम्पर्क पोर्टल पर सबसे ज्यादा शिकायत

एक साल में 18 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com
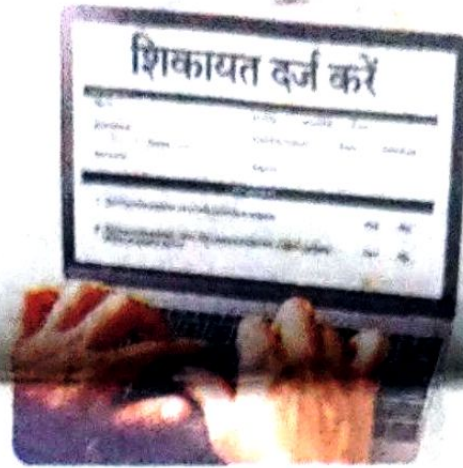
सीकर. सोशल मीडिया व कोरोना काल के दौर में फरियादियों के शिकायत करने का तरीका भी हाईटेक हो गया है। पिछले एक साल में सम्पर्क पोर्टल पर 248 विभाग, बोर्ड, आयोग सहित अन्य संस्थाओं की 18 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज हुई। जबकि पिछले साल इस तरह की ऑनलाइन शिकायतों का आंकड़ा 11 लाख तक ही सीमित था। प्रदेश की जनता ने ऑनलाइन पोर्टल को शिकायत का बड़ा हथियार बना लिया है।

पहले प्रदेश के सभी जिलों में ज्ञापन, चिट्ठी व ई-मेल के जरिए रोजाना 40 से 70 शिकायत दर्ज होती थी। अब ऑफलाइन शिकायतों का रोजाना का आंकड़ा दस से बारह तक ही रह गया है। विभाग का दावा है कि 18 लाख में से 10 लाख से अधिक शिकायतों का निपटारा निश्चित समय सीमा में किया गया है।

टॉप 5 शिकायतों वाले विभाग

- **273847** : कोविड 19 में विभिन्न तरह की परेशानी
- **172580** : जलदाय विभाग
- **123698** : पंचायतीराज
- **90913** : स्वायत्त शासन
- **82604** : कौशल एवं आजीविका विकास निगम

फैक्ट फाइल

- 1 अप्रेल 2020 से 31 मार्च 2021 तक दर्ज शिकायत: 18,60,847
- तय अवधि में समाधान: 10,12,886
- तय अवधि के बाद समाधान: 8 लाख
- लंबित शिकायतें: 6055

रेवड़ पर चढ़ा कंटेनर,

रीट-2021 : मोबाइल से ली गई थी फोटो, अब चल रही पड़ताल आखिर पेपर कब मिला...

पेपर लीक! 10 बजे होना था शुरू...सुबह 8:32 बजे कांस्टेबल के मोबाइल पर था रीट का पेपर

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

सवाईमाधोपुर/टोंक. रीट का पेपर शुरू होने के तय समय दस बजे से पहले ही परीक्षा केन्द्र के बाहर पहुंच चुका था। सवाईमाधोपुर जिले के कुछ परीक्षा केन्द्रों पर यह गड़बड़ी सामने आई है।

पुलिस ने दो पुलिसकर्मियों सहित आठ जनों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में शामिल पुलिस कांस्टेबल देवेन्द्र गुर्जर के मोबाइल में रीट पेपर मिला है, जिसकी रविवार सुबह 8.32 बजे फोटो खींची गई थी। कांस्टेबल के अलावा सवाईमाधोपुर शहर उप अधीक्षक के रीडर [illegible] सिंह तथा दो अन्य को परीक्षा से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद परीक्षा केन्द्र पर ही दोनों पुलिसकर्मियों की पत्नियों सहित चार परीक्षार्थी महिलाओं की पहचान कर उनकी कॉपी में नोट भी [illegible] गया। परीक्षा केन्द्र से निकलते ही चारों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। वहीं बोर्ड अधिकारियों का कहना है कि पेपर कोषागार तक सुरक्षित पहुंचा दिए गए। सुरक्षा का जिम्मा पुलिस के पास है। सवाईमाधोपुर वाले मामले में हमें अभी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

पढ़ें पेपर @ पेज 09

कई परीक्षार्थी चिह्नित

अब घर जाने की तैयारी...देर रात तक जयपुर जंक्शन पर अभ्यर्थियों का रैला

- देवेन्द्र अभी वन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर
- दोनों ने पत्नियों को कराई नकल, 8 लोग गिरफ्तार
- अलवर के एक केंद्र के पहली पारी का पेपर पुनः कराया जाएगा

85 फीसदी अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा

जयपुर. प्रदेश में 16 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के पंजीकरण के चलते राज्य सरकार के लिए चुनौती बनी रीट परीक्षा रविवार को सम्पन्न हो गई। 4 हजार से अधिक केन्द्रों पर सरकार के

सवाल

- तय समय से पहले पेपर कैसे बाहर आया?
- पुलिसकर्मियों के अलावा पेपर किस-किस तक पहुंचा?
- गिरोह के तार परीक्षा तंत्र से जुड़े कर्मचारी व अधिकारियों से तो नहीं जुड़े?
- कर्मचारियों की मिलीभगत तो क्या उन्हें बर्खास्त किया जाएगा?

अलवर : आधा घंटे तक पेपर नहीं दिया

अलवर. प्रशासन की लापरवाही के कारण परीक्षा के दौरान मांढण (अलवर) के टीकवाड़ स्थित एक परीक्षा सेंटर पर आधा घंटे तक प्रश्न पत्र नहीं दिया गया। अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। एक कक्ष में अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट भरकर देने का भी आरोप लगाया। पुलिस ने तीन अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया है। कलक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने पेपर में देरी का ठीकरा शाहजहांपुर के किसान आंदोलन पर फोड़ते हुए कहा कि आंदोलन के कारण यातायात व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। उन्होंने प्रश्न पत्र लीक या नकल कराने की बात से इंकार किया। सेंटर की पहली पारी की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। पहली पारी के पेपर पुन: कराने का निर्णय लिया गया है।

हाईटेक नकल...चप्पल में ब्लूटूथ और कान में माइक्रो इयरफोन

सात लाख में सौदा, एडवांस में लिए चेक व स्टाम्प, 25 अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराई डिवाइस लगी चप्पलें

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

बीकानेर. सख्ती के बावजूद रीट परीक्षा में परीक्षार्थी नकल की जुगत लगाने से बाज नहीं आए।

पुलिस ने परीक्षा शुरू होने से पहले ही एक महिला सहित पांच अभ्यर्थियों को दबोच लिया गया। बीकानेर पुलिस की सूचना पर अजमेर के किशनगढ़ एवं सीकर के नीमकाथाना में एक-एक एवं प्रतापगढ़ में दो अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रीतिचन्द्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर नोखा रोड स्थित नया बस स्टैंड से एक महिला समेत पांच लोगों को दबोचा। इनके पास से नकल कराने वाली सामग्री जब्त की गई। नकल माफिया तुलसाराम ने प्रदेश भर में 25 से अधिक लोगों को विशेष डिवाइस लगी चप्पलें उपलब्ध कराई थी। तुलसाराम फिलहाल फरार है।

ऐसे करवाता नकल

तुलसाराम ने अभ्यर्थियों को ब्लूटूथ डिवाइस लगी चप्पल उपलब्ध कराई थी। ये डिवाइस अभ्यर्थी के कान में लगे माइक्रो इयरफोन से कनेक्ट थी। ब्लूटूथ डिवाइस चिप से मोबाइल की सिम कनेक्ट थी। परीक्षा केन्द्र में जाने से पहले तुलसाराम ने मोबाइल फोन से ब्लूटूथ को कनेक्ट कर लिया। बाद में वह प्रश्न पत्र में से प्रश्नों का हल करके मोबाइल के माध्यम से अभ्यर्थियों को बताता।

ऐसे पकड़े नकलची

अलर्ट के बाद पुलिस ने अभ्यर्थियों के पहनावे पर नजर रखी। सेंट पॉल स्कूल में प्रथम पारी का पेपर देकर जब श्रीडूंगरगढ़ के नया कल्याणसर निवासी सुरजाराम (30) आया और उसने चप्पल पहनी तब उसे दबोच लिया गया। उससे पूछताछ की जा रही है।

गिरोह का सरगना तुलसाराम

नकल गिरोह का मास्टर माइंड सुजानगढ़ हाल पवनपुरी निवासी तुलसाराम जालोर है जो पहले भी नकल प्रकरण में पकड़ा जा चुका है। वह पूर्व में चाणक्य इंस्टीट्यूट चलाता था। तुलसाराम ने एक पारी पेपर के अभ्यर्थियों से सात लाख रुपए में सौदा तय किया था।

रीट-2021: सीएम ने दोषी पाए जाने पर बर्खास्तगी के दिए निर्देश

एक आरएएस, 2 आरपीएस, 1 डीईओ व 13 कार्मिक निलंबित

तीन पुलिसकर्मी भी सस्पेंड

29-09-2021

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. रीट- 2021 के दौरान संदिग्ध गतिविधियों में शामिल अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एक आरएएस, दो आरपीएस, शिक्षा विभाग के एक डीईओ सहित 14 शिक्षक-कार्मिक और तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इनमें से शिक्षा विभाग के 12 कार्मिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है।

मुख्यमंत्री ने प्रकरणों की जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और कार्मिकों को राज्य सेवा से बर्खास्तगी के निर्देश दिए हैं। सरकार ने सवाईमाधोपुर जिले के वजीरपुर एसडीएम नरेन्द्र कुमार मीणा (आरएएस), सवाईमाधोपुर सीओ सिटी नारायण तिवारी (आरपीएस) व सवाईमाधोपुर (एसआइयूसीएडब्लू) उपाधीक्षक राजूलाल मीणा को विभागीय जांच कार्यवाही का प्रकरण लम्बित रखते हुए निलम्बित किया है।

पढ़ें एक @ पेज 10

लापरवाही चारों अधिकारियों पर गिरी गाज

सवाईमाधोपुर. रीट पेपर लीक प्रकरण में पुलिस सूत्रों की मानें तो सीओ सिटी नारायण तिवाड़ी के कार्यालय का रीडर हैडकांस्टेबल यदुवीर सिंह अपनी पत्नी सीमा गुर्जर को लेकर परीक्षा केन्द्र पर कुछ देरी से पहुंचा था। उसको वहां प्रवेश नहीं दिया गया। सीओ सिटी नारायण तिवाड़ी ने फ्लाइंग दल में शामिल पुलिस उपाधीक्षक राजूलाल को फोन कर प्रवेश दिलाने का आग्रह किया। राजूलाल ने उसकी पत्नी को प्रवेश दिला दिया। यदुवीर सिंह एवं उसकी पत्नी पेपर लीक प्रकरण से जुड़े थे। फिर भी उनको प्रवेश दिलाने में फ्लाइंग स्क्वॉयड की भूमिका संदेह के घेरे में आ गई है।

नरेन्द्र मीणा
एसडीएम वजीरपुर

प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर फ्लाइंग टीम में लगाया गया था। ताकि कोई भी बात हो तो प्रशासनिक प्रतिनिधि के रूप में उसे हैंडल कर सकें।

नारायण तिवाड़ी
सीओ सिटी, स.माधोपुर

पेपर लीक प्रकरण में पुलिस उपाधीक्षक, शहर कार्यालय का रीडर हैडकांस्टेबल यदुवीर सिंह आरोपी है। ऐसे में इनकी भूमिका भी संदिग्ध मानी गई है।

राधेश्याम मीणा
डीईओ, स.माधोपुर

इनको शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि के तौर पर फ्लाइंग टीम में लगाया गया था। परीक्षा का आयोजन माशिबो की ओर से था। इसलिए परीक्षा की निगरानी में लगाया था।

राजूलाल मीणा डिप्टी (महिला अत्याचार निवारण प्रकोष्ठ)
इनको पुलिस प्रतिनिधि के तौर पर फ्लाइंग स्क्वॉयड में लगाया गया था। पेपर लीक प्रकरण में इनकी भी लापरवाही मानी गई है।
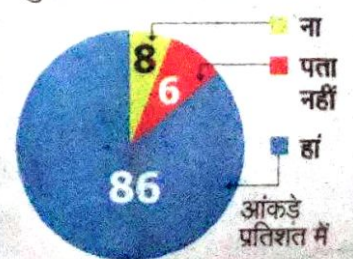
आज का सवाल: प्रवेश पत्र में त्रुटि एवं अन्य अव्यवस्था के कारण जिन सेंटरों पर अभ्यर्थी रीट देने से चूक गए, क्या उन्हें मौका मिलना चाहिए?

हां ■ ना ■ पता नहीं

https://forms.gle/egQVriRsUYE6uD3n7

जवाब देने के लिए क्यूआर कोड को **स्कैन करें**

रीट का पेपर क्या लीक हुआ। आप क्या मानते हैं?

विसल में घुसपैठ की आशंका

भारत को बदनाम करने विस्थापितों पर डोरे डाल रही आइएसआइ

11.10.2021

पत्रिका

सुरेश व्यास
patrika.com

जोधपुर. पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ भारत को बदनाम करने के लिए धार्मिक उत्पीड़न से परेशान होकर देश छोड़ रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं पर डोरे डाल रही है। इसके लिए जोधपुर में सक्रिय दलाल नेक्सस के जरिए विस्थापित हिंदुओं को वापस पाकिस्तान लौटने के लिए मजबूर करने और वहां पहुंचने पर भारत सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करवाने की रणनीति का खुलासा हुआ है। इसके तहत मजबूर पाक विस्थापित परिवारों को दलालों के जाल में फंसाकर वापस पाकिस्तान वापस भेजा जा रहा है। हाल ही दलालों के जाल में फंसे 91 विस्थापितों की बस को पुलिस ने जोधपुर-नागौर रोड पर स्थित करवड़ थाना इलाके में रोक लिया था। कुछ दिन बाद दलालों ने इन्हें निजी वाहनों से वाघा बोर्डर भेज दिया। चूंकि मामला चौड़े आ चुका था और इन लोगों की दस्तावेजी औपचारिकताएं भी पूरी नहीं हैं। ऐसे में ये पाकिस्तान नहीं जा पा रहे। जबकि सैकड़ों लोग दलालों की मदद से वाघा बोर्डर क्रॉस कर लौट चुके हैं। इनका पाकिस्तानी अधिकारियों ने न सिर्फ स्वागत किया, बल्कि इनसे भारत विरोधी बयान भी दिलाकर इसका भारत के खिलाफ दुष्प्रचार में इस्तेमाल किया गया। कहा गया कि मेहमान बनकर गए इन लोगों को जलालत भरी जिंदगी जीनी पड़ी, इसलिए ये मजबूर होकर वापस अपने वतन को लौटे हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसे दुष्प्रचार के कई वीडियो मौजूद हैं।

पिछले महीने जोधपुर-नागौर रोड पर करवड़ में रोकी गई बस में सवार पाक विस्थापित। दलाल इन लोगों को बिना अनुमति पाकिस्तान लौटने के लिए वाघा बोर्डर भेज रहे थे। फाइल फोटो- पत्रिका

खबर को विस्तार से पढ़ें
https://bit.ly/2YNBYk8

पाकिस्तान उठा रहा फायदा

वापस लौटने वालों का इस्तेमाल पाकिस्तानी एजेंसियां भारत के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए कर रही हैं। पिछले साल 9 अगस्त को जोधपुर के देचू इलाके में भील विस्थापित परिवार की सामूहिक आत्महत्या को पाकिस्तान ने वैश्विक स्तर पर उठाने की कोशिश की और कहा कि पाकिस्तान से जाने वाले हिंदूओं पर भारत में जुल्म ढाए जा रहे हैं।

दलालों के इशारों पर पूरी मदद

पाकिस्तान के बिगड़े रिश्तों के बीच आवागमन के साधन बंद है। एलटीवी पर रहने वालों को नो ऑब्जेक्शन ऑन रिटर्न इंडिया (नोरी) वीजा भी नहीं मिल रहा। ऐसे में अपरिहार्य स्थिति में पैदल ही बोर्डर क्रॉस करने का विकल्प बचता है। दलाल दोनों देशों के इमिग्रेशन अधिकारियों की मदद से प्रति पासपोर्ट 8 से 10 हजार लेकर मजबूर विस्थापितों को बोर्डर क्रॉस करवा देते हैं। पाकिस्तानी इमिग्रेशन अधिकारी भी दलालों के इशारों पर विस्थापितों के वापस लौटने के दौरान पूरी मदद करते हैं।

कई परेशान होकर, कई मजबूरी में लौट रहे

भारत आने के बाद कई लोग या तो रोजाना दरपेश आने वाली दिक्कतों, दलालों की करतूतों व काम धंधा न मिलने से परेशान होकर वापस जाने का मन बनाते हैं या फिर इनकी परिवार के लोगों को न ला पाने की मजबूरी कारण बनती है। मसलन, पति-पत्नी दोनों ने भारत आने का वीजा मांगा। पति को मिल गया। पत्नी-बच्चे वहीं रह गए तो कुछ दिन बाद पति वापस लौटने की कोशिश करता है। दलाल इसी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं।

एक ही दवा खरीद रही तीन सरकारी एजेंसियां, चांदी निजी कंपनियों की

सालाना हजार करोड़ की खरीद फिर भी मरीजों को नहीं मिल रही पूरी दवाइयां

600 करोड़ की खरीद करता है आरएमएससीएल

200 करोड़ की खरीद करता है कॉनफेड, 04 साल से आरडीपीएल बंद

200 करोड़ की अस्पताल करते हैं लोकल खरीद

विकास जैन
patrika.com

जयपुर. प्रदेश में मरीजों और पेंशनर्स को नि:शुल्क दवाओं के लिए खरीदी जा रही हजारों करोड़ रुपए की दवा खरीद प्रक्रिया को खुद सरकार ने ही निजी कंपनियों के फायदे का सौदा बना दिया है। एक ओर जहां सरकार सरकारी महकमों में सिंगल विंडो जैसे कदम उठा रही है, वहीं सरकारी दवा खरीद की प्रक्रिया को अलग-अलग कई एजेंसियों के हवाले कर रखा है। नि:शुल्क दवा योजना के लिए करीब 600 करोड़ सालाना की दवाएं राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लि. (आरएमएससीएल) खरीद रहा है, जो कि सिर्फ दवा खरीद के लिए सरकार का एकमात्र सरकारी निगम है। इसके बावजूद करीब 200 करोड़ सालाना दवा खरीद कॉनफेड के जरिए पेंशनर्स के लिए की जा रही है। इससे यह पूरी प्रक्रिया मकड़जाल बनकर रह गई है। इसका खमियाजा लाखों मरीजों को दवा के लिए परेशान होकर चुकाना पड़ रहा है।

इतनी खरीद के बावजूद अस्पतालों को अपने स्तर पर भी दवाओं की अनुपलब्धता होने पर सीधे आपूर्तिकर्ताओं से लोकल खरीद के जरिए दवा खरीद की छूट दी हुई है। प्रदेशभर के अस्पतालों में इस तरह से भी करीब 200 करोड़ की दवाएं हर साल खरीदे जाने का अनुमान है। इस पूरे मकड़जाल से सरकारी राजस्व को तो नुकसान हो ही रहा है, वहीं मरीजों को भी हर समय पूरी दवाइयां नहीं मिल पा रहीं। सरकारी क्षेत्र की एक मात्र दवा कंपनी राजस्थान ड्रग एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड (आरडीपीएल) करीब चार साल से बंद है।

आरडीपीएल के 'पुनरूत्थान' की मंशा

राज्य सरकार पहले से केन्द्र सरकार को दे चुकी है आरडीपीएल को शुरू करने की पुनरूत्थान योजना

केन्द्र से बंद पड़ी 300 करोड़ की प्रदेश की एकमात्र सरकारी दवा कंपनी की देनदारियों से मुक्त करने की रखी मांग

सरकार ने खुद माना...कोरोना काल में महसूस हुई आरडीपीएल की कमी

प्रदेश में कोरोनाकाल के दौरान राजस्थान सरकार को सरकारी क्षेत्र की बंद पड़ी एक मात्र कंपनी आरडीपीएल की कमी महसूस हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी हाल ही प्रदेश के चार मेडिकल कॉलेजों के शिलान्यास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मांग रखते हुए कह चुके हैं कि केन्द्र भारत सरकार व राज्य सरकार के इस संयुक्त उपक्रम को देनदारियों से मुक्त करें। आरडीपीएल आधुनिक मशीनों सहित कई तरह की दवाइयां बनाने के लिहाज से उपयोगी है।

आरडीपीएल में 51 प्रतिशत शेयर भारत सरकार और 49 प्रतिशत राज्य सरकार का

इस कंपनी में भारत सरकार का 51 और राज्य सरकार का 49 प्रतिशत शेयर है। केन्द्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग में इस कंपनी को 28 दिसंबर-2016 को बंद कर दिया गया था। उसके बाद 2017-18 व 2019 में केन्द्र सरकार के 51 प्रतिशत शेयर राज्य को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव राज्य को दिया गया था।

केन्द्र ने बंद की आरडीपीएल

आरडीपीएल को राज्य सरकार शुरू करना चाहती है। इसे चार साल पहले केन्द्र सरकार ने ही बंद किया था। अब मुख्यमंत्री ने पीएम और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को भी इसे शुरू करने की स्वीकृति देने के लिए कहा है। राज्य सरकार ने इस कंपनी के पुनरूत्थान की योजना भी केन्द्र को दे दी है। यह शुरू होगी तो दवाओं पर राज्य सरकार की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। पेंशनर्स के लिए कॉनफेड से दवा खरीद की व्यवस्था आज से नहीं, बल्कि पुरानी है, जो सरकार का नीतिगत निर्णय है। **रघु शर्मा**, चिकित्सा मंत्री

भारत की निगाहें फिर बादशाहत पर
@स्पोर्ट्स &गेमिंग

80% लोग बोले- पैकेट बंद फूड पर चेतावनी लिखना हो अनिवार्य
@इंडिया&वर्ल्ड

दशहरे के दिन बर्बर घटना: हरियाणा में पंजाब के युवक की हत्या

कुंडली में लिंचिंग, आंदोलन की 'कुंडली' पर पड़ेगी भारी

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. दशहरे के दिन एक बर्बर और लोमहर्षक घटना में हरियाणा के कुंडली बॉर्डर पर एक युवक का क्षत-विक्षत शव बरामद होने के बाद सनसनी फैल गई। शव वहीं बरामद हुआ जहां करीब एक साल से संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले नए कृषि कानूनों के विरोध में धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके बाद देश का सियासी पारा काफी गर्म हो गया।

मृतक की पहचान पंजाब के तरनतारन जिले निवासी लखबीर सिंह के रूप में हुई है। वह दलित समुदाय से था। यह घटना इतनी बर्बर है कि किसान आंदोलन के भविष्य की कुंडली बदल सकती है। घटना का वीडियो काफी वायरल हुआ है और आंदोनकारी किसान निशाने पर हैं। बताया गया कि निहंग सिख ने इसकी जिम्मेदारी ली है और एक को हिरासत में लिया गया है। निहंग सिख भी किसान आंदोलन में शामिल हैं।

एक रिपोर्ट में बताया गया कि पवित्र ग्रंथ की कथित बेअदबी को लेकर लखबीर सिंह को पीट-पीटकर मार डाला गया। उसका बायां हाथ और दाहिना पैर काट दिया गया। लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद से उठा सियासी तूफान अभी थमा भी नहीं था कि इस नए विवाद से आंदोलनकारी रक्षात्मक मुद्रा में आ गए।

पढ़ें **कुंडली**@ पेज 14

नृशंस हत्या के बाद आत्मसमर्पण...

समर्पण के बाद निहंग सरबजीत सिंह। वीभत्स होने के कारण हम शव की धुंधली तस्वीर दिखा रहे हैं। (नीचे)

अराजक तत्त्वों का पर्दाफाश किया जाए: भाजपा

भारतीय जनता पार्टी ने बर्बर तरीके से की गई युवक की हत्या के बाद आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा कि इन प्रदर्शनकारियों के बीच जो अराजक तत्त्व हैं उनका पर्दाफाश किया जाना जरूरी है।

किसानों के खिलाफ साजिश: संकिमो

संयुक्त किसान मोर्चा ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह एक साजिश का हिस्सा है जिसमें आंदोलन को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है।

हिंसा की कोई जगह नहीं: कांग्रेस

कांग्रेस ने इस घटना पर कहा कि कहीं भी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। यह पुलिस की जिम्मेदारी है कि जांच कर दोषियों को पकड़ने और सजा दिलाने की कार्रवाई करे।

लखीमपुर हिंसा

पुलिस के हाथ लगा बड़ा सुराग, पिस्टल बरामद

लखनऊ@पत्रिका. लखीमपुर हिंसा के आरोपी अंकित दास के फ्लैट से पुलिस ने एक पिस्टल और रिपीटर गन बरामद की है। पिस्टल का लाइसेंस अंकित दास के नाम पर है, वहीं रिपीटर गन का लाइसेंस उसके बॉडीगार्ड लतीफ उर्फ काले के नाम पर है।

अंकित ने बताया था कि वह आशीष से मिला था व प्रदर्शनकारी किसानों के बारे में बताने पर आशीष ने कहा था कि चलो उन्हें सबक सिखाते हैं। 'थार के पीछे मैं काली फार्चुनर में था। आगे चल रही जीप किसानों को कुचलते हुए आगे निकल गई।'

आगे चल रही थार हरिओम चला रहा था व पायदान पर दो लोग खड़े थे। वहीं जिस गाड़ी में अंकित था उसे शेखर भारती चला रहा था। किसानों के घिरने पर उसने उन पर फायरिंग की थी।

कोयला व बिजली संकट: ऊर्जा महकमे से लेकर सरकार तक हिली पर सवाल वही, जिम्मेदार कौन...कुप्रबंधन, ढिलाई या अफसरशाही

खरीदी 15 करोड़ यूनिट महंगी बिजली, करंट हमारी जेब पर!

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com
16.10.21

जयपुर. कोयले की कमी के कारण उपजे बिजली संकट ने ऊर्जा महकमे से लेकर राज्य व केन्द्र सरकार तक को हिलाकर रख दिया।

कोयले की कमी के कारण सस्ती बिजली उत्पादन के प्लांट बंद करने पड़े और बाजार से करोड़ों की महंगी बिजली खरीदी गई। दस दिन में बिजली एक्सचेंज (बाजार) से करीब 15.26 करोड़ यूनिट बिजली खरीदी, जिसके लिए 149 करोड़ रुपए चुकाए गए। अधिकतम 17 रुपए प्रति यूनिट तक बिजली के दाम चुकाने पड़े, जबकि औसत दर 11.46 रुपए प्रति यूनिट तक रही। पिछले पांच दिन में तो हर दिन दो करोड़ यूनिट से ज्यादा बिजली ली गई। अफसरों का तर्क है कि यह कुल बिजली खपत का कुछ ही प्रतिशत है। लेकिन इस महंगी बिजली का करंट भी राज्य के 1.50 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं को ही लगेगा। विद्युत विनियामक आयोग में टैरिफ पीटिशन दायर होगी, तब यह खर्चा भी जोड़ा जाएगा।

पढ़ें **खरीदी** @ पेज 14

एक्सचेंज से बिजली के 17 रुपए प्रति यूनिट तक चुकाए दाम

कोयले की कमी से सस्ती बिजली के बंद रहे प्लांट
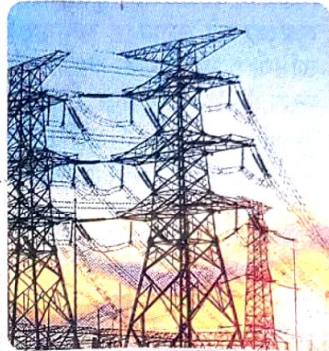
एक्सचेंज से कब—कितनी, किस दर पर खरीदी बिजली

दिन	खरीद (लाख यू.)	औसत दर (रु./यूनिट)	लागत (करोड़ रु.)
1 अक्टूबर	0	0	0
2 अक्टूबर	0.19	5	0.01
3 अक्टूबर	0	0	0
4 अक्टूबर	0	0	0
5 अक्टूबर	15.25	4.76	0.73
6 अक्टूबर	145.58	9.67	14.07
7 अक्टूबर	154.37	10.13	15.64
8 अक्टूबर	186.24	13.96	26.01
9 अक्टूबर	178.09	10.07	17.94
10 अक्टूबर	228.99	6.31	14.44
11 अक्टूबर	200.63	9.17	18.40
12 अक्टूबर	205.35	11.46	23.53
13 अक्टूबर	211.37	8.31	17.56

केंद्र में इन पर है जिम्मेदारी

प्रह्लाद जोशी, केंद्रीय कोयला मंत्री

अनिल जैन, केंद्रीय कोयला सचिव

आर.पी. गुप्ता, केंद्रीय पर्यावरण सचिव

आलोक कुमार, केंद्रीय ऊर्जा सचिव

(कोयला संकट के अलावा छग में उत्पादन निगम की अतिरिक्त खदान के लिए हस्तांतरण अटका)

आखिर जिम्मेदार कौन- चिह्नित तो करो सरकार

1. बी.डी. कल्ला, ऊर्जा मंत्री, राजस्थान: कोयला और बिजली संकट के शुरुआती दौर में प्रभावी मॉनिटरिंग नहीं। जब मामला हाथ से निकलने लगा तो केंद्रीय कोयला और ऊर्जा मंत्री से बात की, फिर भी सीएम को कमान हाथ में लेनी पड़ी।

2. सुबोध अग्रवाल, ऊर्जा सचिव: ऊर्जा विभाग की कुछ समय पहले ही कमान संभाली। हालांकि, कोयला संकट आते ही केंद्रीय कोल सचिव से लगातार बात की। तीन दिन तक दिल्ली में रहे। अब कोयला रैक बढ़कर आ रही है।

3. आर.के शर्मा, सीएमडी, राज्य विद्युत उत्पादन निगम: केंद्रीय ऊर्जा सचिव, कोल सचिव ने अगस्त में ही चेताते हुए कोयला स्टॉक के लिए कहा, पर नहीं चेते।

4.नवीन अरोड़ा: एमडी जयपुर डिस्कॉम, वी.एस.भाटी– अजमेर डिस्कॉम व अविनाश सिंघवी-जोधपुर डिस्कॉम– बिजली खरीदते रहे लेकिन भुगतान नहीं दिया। उत्पादन निगम के करोड़ों रुपए बकाया, जिससे वे कंपनियों को बकाया भुगतान नहीं कर सके।

चिंताजनक: 116 देशों में भारत 101वें स्थान पर, केवल 15 देश ही हमसे पीछे, केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट को वास्तविकता से परे बताया

भारत वैश्विक भूखमरी सूचकांक में पाक, नेपाल से भी नीचे

16-10-2021

नई दिल्ली @ पत्रिका. वैश्विक भूखमरी सूचकांक (ग्लोबल हंगर इंडेक्स, 2021) में भारत की स्थिति चिंताजनक है। शुक्रवार को जारी इस सूची में भारत कुल 116 देशों में 101वें स्थान पर है। यानी भुखमरी के मामले में भारत सिर्फ 15 देशों से आगे है। भारत इस लिस्ट में पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी नीचे है। सरकार ने रिपोर्ट को वास्तविकता से परे बताया और कहा कि यह ओपिनियम पोल पर आधारित है, तथ्यों और आंकड़ों पर नहीं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस रिपोर्ट को अवैज्ञानिक करार दिया।

कोविड से बुरी तरह प्रभावित हुआ देश

आयरलैंड की एजेंसी कन्सर्न वर्ल्डवाइड और जर्मन संगठन वेल्ट हंगर हिल्फ ने मिलकर तैयार किया वर्ल्ड हंगर इंडेक्स रिपोर्ट

भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति

देश	रैंक
चीन	05
नेपाल	76
बांग्लादेश	76
म्यांमार	71
पाकिस्तान	92

भारत की स्थिति

वर्ष	रैंक
2015	93
2016	97
2017	100
2018	103
2019	102
2020	94
2021	101

28.8 से 27.5 अंकों के बीच रहा भारत का स्कोर वर्ष 2012 और 2021 के बीच

रैंकिंग के पैमाने अल्पपोषण, 5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनका वजन लंबाई के हिसाब से कम, बच्चे जिनकी उम्र के मुताबिक लंबाई कम और बाल मृत्यु दर।

देश की जीएचआइ स्कोर लगातार गिरा

ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआइ) में 5 से कम स्कोर के साथ चीन, ब्राजील और कुवैत शीर्ष पर हैं। जीएचआइ स्कोर कम होने का मतलब है कि उस देश में भुखमरी का स्तर कम चिंताजनक है। वहीं, स्कोर ज्यादा होने का का मतलब है कि देश में भुखमरी का संकट गंभीर है। भारत का जीएचआइ स्कोर वर्ष 2000 में 38.8 अंक था जो वर्ष 2012 से 2021 के बीच गिरकर 27.5 पर पहुंच गया।

नर्सिंग एडमिशन में गड़बड़झाला : किसी बड़ी प्रवेश प्रोफेशनल परीक्षा में सीधे 50 प्रतिशत सीटों पर इस तरह प्रवेश का दुर्लभ मामला

निजी संस्थानों में आधी सीटों पर 'चहेतों' के हवाले दाखिला

विकास जैन
patrika.com

19.10.2021

जयपुर. प्रतिस्पर्धा के दौर में देशभर में प्रोफेशनल कोर्सेज की एक- एक सीट एक-एक छात्र के लिए कीमती हो चुकी है, लेकिन राजस्थान के विभिन्न नर्सेज कोर्सेज में इन सीटों को मेधावी विद्यार्थियों से भरने के बजाय चहेतों के जरिये नर्सिंग संस्थानों के फेडरेशन को ही सौंप दिया गया है। जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, बीएससी और एमएससी नर्सिंग कोर्सेज में इस तरह दिए जा रहे प्रवेश से सीधे तौर पर 6 हजार में से करीब 3 हजार यानी 50 प्रतिशत सीटें फेडरेशन को सौंप दी गई है। राजस्थान सरकार के एजी और इंडियन नर्सिंग काउंसिल भी इसे गलत बताते हुए चिकित्सा विभाग को इस तरह प्रवेश बंद करने के लिए कह चुके हैं, लेकिन उसे भी दरकिनार कर दिया गया है।

चिकित्सा मंत्री और उच्च स्तर के अधिकारियों को इस तरह प्रवेश की जानकारी होने के बावजूद मेधावी विद्यार्थियों को दरकिनार कर प्रवेश दिए जा रहे हैं।

देशभर में प्रोफेशनल परीक्षाओं में कोड ऑफ कंडक्ट... लेकिन राजस्थान की नर्सिंग में सबकुछ चहेतों के हवाले

मलाई ऐसी..फेडरेशन भी दो

फेडरेशनों के जरिये एडमिशन में मलाई का ऐसा बड़ा खेल है कि प्रदेश में दो अलग अलग फेडरेशन बनी हुई है, जिनके जरिये प्रवेश दिया जा रहा है। इसमें इतनी छूट है कि जो संस्थान जिस फेडरेशन के जरिये जुड़कर प्रवेश देना चाहे, वहां जा सकता है।

कोर्ट भी बता चुका गलत

पूर्व में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में पीसीपीएमटी के जरिये प्रवेश दिया जाता था, लेकिन उसे भी बंद हुए कई साल पूरे हो चुके हैं। अब उनमें सीधे तौर पर देशभर की नीट प्रवेश परीक्षा की तय प्रणाली के अनुसार ही 100 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिया जाता है। नर्सिंग में फेडरेशन के जरिये प्रवेश को पूर्व में कोर्ट भी गलत बताकर इसे रोकने के आदेश दे चुका है।

नर्सिंग प्रवेश की पूरी प्रक्रिया का परीक्षण करवाएंगे, जो खामी होगी, उसे ठीक किया जाएगा। **वैभव गालरिया,** चिकित्सा सचिव

ताक पर दिशा-निर्देश

50% सीटों पर परीक्षा से प्रवेश के लिए हजारों विद्यार्थी शामिल होते हैं। इसमें मेधावी विद्यार्थियों का चयन होकर अपनी वरीयता के अनुसार संस्थान उन्हें मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हीं कॉलेजों में निजी संस्थान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर मोटी फीस लेकर न्यून अंक वाले को भी प्रवेश दे देते हैं। यह प्रवेश प्रक्रिया राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विवि के जरिये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग आयोजित करवाता है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल भी फेडरेशन पर इंडियन नर्सिंग काउंसिल (आइएनसी) के दिशा-निर्देशों की पालना नहीं करने को लेकर नाराजगी जता चुका है।

पढ़ें **निजी** @ पेज 10

ट्रेनों में फिर मिलेगी

कार्रवाई : फौतगी म्यूटेशन ...

आहोर एसडीएम धनतेरस से पहले 40,000 घूस लेते गिरफ्तार

सरकारी आवास से एसीबी ने पकड़ा

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जालोर/जोधपुर . एसीबी टीम ने सोमवार को आहोर के एसडीएम मसिंगाराम जांगिड़ को 40 हजार रुपए की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी एसडीएम ने यह रिश्वत फौतगी म्यूटेशन अपील का आदेश पारित करवाने की एवज में ली थी।

एसीबी टीम ने एएसपी महावीर सिंह के नेतृत्व में एसडीएम के सरकारी आवास पर कार्रवाई को अंजाम दिया। परिवादी लक्ष्मण सांखला ने 22 सितंबर को रिपोर्ट दी थी कि एसडीएम आहोर मसिंगाराम फौतगी म्यूटेशन अपील का आदेश पारित के बदले 50 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। शिकायत की सत्यापन के एसीबी ने एसडीएम को सरकारी आवास से 40 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। एसडीएम बाड़मेर जिले के तारातरा गांव का निवासी है। परिवाद मिलने के बाद से ही एसडीएम पर नजर रखी जा रही थी।

गौरतलब है कि आहोर उपखंड क्षेत्र के भैंसवाड़ा में फौतगी म्यूटेशन के इस प्रकरण को एसडीएम ने अकारण ही निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद इस प्रकरण के निस्तारण की एवज में रिश्वत की मांग की गई।

जालोर . आहोर एसडीएम को सरकारी आवास से सोमवार को गिरफ्तार कर ले जाती एसीबी की टीम।

झालावाड़ : बाबू निकला करोड़पति

डेढ़ किलो सोना, दो किलो चांदी, 13 लाख रुपए नकद...वैध आय से 750% अधिक सम्पत्ति

झालावाड़ . भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) बूंदी की टीम ने सोमवार को झालावाड़ नगर परिषद के कनिष्ठ सहायक श्यामलाल गुर्जर के यहां आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में कार्रवाई की है। जांच में कनिष्ठ सहायक के पास लाखों रुपए की सम्पत्तियां मिली हैं। इसमें डेढ़ किलो सोने और दो किलो चांदी के जेवरात और 13 लाख रुपए की नकदी मिली है। आरोपी के पास तीन करोड़ से अधिक की सम्पत्ति मिली है। बूंदी एसीबी के उपाधीक्षक ज्ञानचंद मीणा ने बताया कि डीजी बी.एल. सोनी के निर्देश पर कार्रवाई की गई है।

'अपने कैमरा से इसको फोन पर स्कैन करें'

पढ़ें **झालावाड़** @ पेज 16

सोना-चांदी, जमीन-प्लॉट

- **एक किलो** 646 ग्राम **सोने** तथा दो किलो 479 ग्राम **चांदी** के जेवरात मिले हैं। इसकी कीमत 65 लाख रुपए आंकी है।
- **13 लाख** 15 हजार 600 रुपए की नकदी मिली।
- **स्वयं,** पत्नी राधा बाई के नाम एवं बेनामी 39 बीघा जमीन है, जिसकी कीमत दो लाख बीघा के हिसाब से 78 लाख रुपए आंकी गई।
- **झालावाड़** ऐश्वर्य नगर में दो भूखण्डों पर मकान है।
- **कनक** रेजीडेंसी में एक मकान
- **ईस्ट** कंचन सिटी कॉलोनी में तीन आवासीय मकान है, जिनकी कीमत 1.5 करोड़ आंकी गई।

कालीसिंध थर्मल में कार्यरत एसई: 85 हजार की घूस लेते गिरफ्तार

करोड़पति बाबू के बाद घूसखोर अधीक्षण अभियंता को दबोचा

29 लाख के बिल पास करने की एवज में मांगी थी घूस

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

झालावाड़. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) कोटा शहर की टीम ने धनतेरस पर मंगलवार को झालावाड़ में बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कालीसिंध थर्मल के अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार खटीक को 85 हजार रुपए की घूस लेते हुए रंगेहाथों गिरफ्तार किया है। झालावाड़ में एसीबी की लगातार दूसरे दिन बड़ी कार्रवाई है। एक दिन पहले ही एसीबी ने झालावाड़ नगर परिषद के कनिष्ठ सहायक श्यामलाल गुर्जर को पकड़ा था, जिसके पास सोने-चांदी व नकदी के रूप में अथाह संपत्ति मिली है।

कालीसिंध थर्मल के अधीक्षण अभियंता (सिविल) विनोद कुमार खटीक एक माह पहले छबड़ा थर्मल में पदस्थापित थे। छबड़ा थर्मल में गार्डन मेंटीनेंस से संबंधित 29 लाख के पास किए गए बिल व अन्य बिलों की एवज में कमीशन की मांग की थी। उसने कालीसिंध थर्मल में भी आठ लाख का भुगतान रोक रखा है। आरोपी एसई ने बिल पास करने की एवज में 85 हजार रुपए की घूस की मांग की। एसीबी ने शिकायत के सत्यापन के बाद मंगलवार को 85 हजार की घूस लेते हुए एसई खटीक को गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई एसीबी कोटा शहर के निरीक्षक अजीत बगडोलिया ने की। 03-11-21

एक माह पहले परिवाद

एसीबी कोटा रेंज के कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक ठाकुर चन्द्रशील ने बताया कि परिवादी ने 1 नवम्बर को परिवाद दिया था कि उसकी फर्म के पास छबड़ा व कालीसिंध पावर प्लांट में गार्डन मेंटीनेंस का ठेका है।

पहली पोस्टिंग में एसीबी के हत्थे चढ़ा एसडीओ

एसडीओ का रीडर गिरफ्तार, अपने लिए अलग से मांगी थी रिश्वत

एसडीओ के 40 हजार रुपए रिश्वत लेने पर रंगे हाथों गिरफ्तारी प्रकरण

जोधपुर. एसीबी ने जालोर के आहोर में 40 हजार रुपए रिश्वत लेने पर एसडीओ को रंगे हाथों पकड़ने के बाद मंगलवार को रीडर को भी गिरफ्तार किया। उसने अपने लिए अलग से रिश्वत मांगी थी। ब्यूरो ने फाइल भी जब्त की।

प्रकरण में आरएएस अधिकारी व जालोर जिले में आहोर के एसडीओ मासिंगाराम जांगिड़ को 40 हजार रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था। इस संबंध में जांच के बाद एसडीओ के रीडर व वरिष्ठ सहायक सिरोही निवासी गजेन्द्र कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। ब्यूरो की जालोर चौकी प्रभारीने एसडीओ मासिंगाराम व रीडर गजेन्द्र को पाली में एसीबी मामलात की विशेष अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए गए।

दो साल पहले बना था आरएएस

बाड़मेर में चौहटन तहसील के मासिंगाराम वर्ष 2019 बैच के आरएएस अधिकारी हैं। आहोर एसडीओ पद पर उसकी पहली पोस्टिंग है।

एएसआइ आठ हजार लेते गिरफ्तार

जोधपुर@ पत्रिका. एसीबी ने पाली में पुलिस स्टेशन कोतवाली के एएसआइ धनराज को आठ हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ब्यूरो का कहना है कि परिवादी के खिलाफ कोतवाली थाने में गत दिनों एफआइआर दर्ज हो रखी है। इस मामले में परिवादी व उसकी पत्नी को गिरफ्तार न करने की एवज में एएसआइ ने परिवादी से ग्यारह हजार रुपए मांगे थे। जिसे देने में उसने असमर्थता जताई। तब एएसआइ नौ हजार रुपए लेने पर राजी हुआ। शिकायत मिलने पर ब्यूरो ने गोपनीय सत्यापन कराया तो रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई।

रेकी के बाद पकड़ा, जैसलमेर जेल में बंद

रोशनी का स्विच ऑ...

दलाल के जरिए ₹11 लाख वसूलने वाला तत्कालीन सीओ दूदू गिरफ्तार

ट्रक मालिक महेंद्र के मोबाइल फोन से एफएसएल ने रिकवर की वसूली की चैट

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com 04.11.2021

जयपुर . अवैध बजरी परिवहन के लिए चौथ वसूली करने वाले तत्कालीन दूदू सीओ विजय सेहरा को एसओजी ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। विजय सेहरा ने दलाल के माध्यम से बजरी ट्रक ऑपरेटर्स से दो माह में ग्यारह लाख रुपए की वसूली की थी। दूदू में ट्रेलर मालिक के गिरफ्तार होने पर सीओ के वसूली नेटवर्क का खुलासा हुआ था। अब एसओजी सीओ के मुख्य दलाल को तलाश रही है। नेटवर्क में शामिल अन्य पुलिसकर्मियों की भूमिका भी खंगाली जा रही है।

गिरफ्तार विजय सेहरा को इसी मामले के चलते पुलिस महानिदेशक एम.एल.लाठर ने एपीओ किया था। एसओजी एडीजी अशोक राठौड़ ने बताया कि चौथवसूली के नेटवर्क का खुलासा 6 जून को हुआ था,जब पुलिस ने दूदू में डम्पर मालिक गीगल निवासी महेन्द्र मीणा को गिरफ्तार किया था। पहले मामला दूदू थाने में दर्ज हुआ। फिर फाइल सीआइडी भेजी गई। इसके बाद सरकार के निर्देश पर एसओजी को जांच दी गई।

दलाल पकड़ा गया तो डिलीट करवाई वसूली की चैट: विजय सेहरा के लिए वसूली नेटवर्क दूदू क्षेत्र में रेस्टोरेंट चलाने वाला राजेन्द्र चौधरी चलाता था।

पढ़ें **दलाल** @ पेज 13

सेहरा के करीबी भी आएंगे जद में

एसओजी विजय सेहरा के चौथवसूली नेटवर्क में शामिल अन्य पुलिसकर्मियों की भूमिका खंगाल रही है। दलाल राजेन्द्र से भी साठगांठ भांकरोटा थाने के ही एक कांस्टेबल ने कराई थी। इसके अलावा कई पुलिसकर्मियों ने ट्रक चालकों से ऑनलाइन घूस स्वीकार की थी।

पत्रिका में प्रकाशित

एक फेरे के 3 हजार, 2 माह में लिए 11 लाख रुपए

उप अधीक्षक के खिलाफ अब एसओजी करेगी तफ्तीश

पहले थाने से सीआइडी भेजी थी फाइलें

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. अवैध बजरी परिवहन के बदले वसूली के आरोपों से

राजस्थान पत्रिका

बीस दिन में सीओ व

अलवर : सभापति और उनके पुत्र कुलदीप से 80 हजार रुपए बरामद

कर्मचारियों को भ्रष्ट बताने वाली सभापति को रिश्वत लेते पकड़ा

कमीशन भुगतान में घूस 23·11·2021

अलवर. @ पत्रिका. अधिकारी और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाली अलवर नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता खुद अपने बेटे कुलदीप के साथ 80 हजार रुपए की रिश्वत लेती सोमवार को पकड़ी गईं। दोनों को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया।

एसीबी जयपुर के एएसपी बजरंग सिंह शेखावत और एसीबी अलवर के एएसपी विजयसिंह ने बताया कि परिवादी मोहनलाल सोमवंशी ने एसीबी मुख्यालय जयपुर में शिकायत दी कि वह नगर परिषद में नीलामी की बोली लगाने का काम करता है, जिसकी एवज में नगर परिषद की ओर से प्रति नीलामी के हिसाब से उसे 2 प्रतिशत कमीशन दिया जाता है। शहर के गायत्री मंदिर रोड स्थित नगर परिषद की 17 दुकानों के ऑक्शन के दौरान उसने नीलामी की बोली लगाई थी। जिसमें उसका 2 प्रतिशत के हिसाब से करीब 3.50 लाख रुपए कमीशन बना। इस कमीशन राशि का भुगतान करने की एवज में नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता उससे 50 फीसदी राशि रिश्वत के रूप में मांग रही है। एसीबी के सत्यापन के दौरान सभापति ने परिवादी से 50 हजार रुपए की रिश्वत ली तथा शेष एक लाख रुपए सोमवार को देना तय हुआ। परिवादी सोमवार दोपहर सवा तीन बजे सभापति के गायवाला मोहल्ला स्थित घर पहुंचा।

पढ़ें **कर्मचारियों** @ पेज 08

एसीबी कार्रवाई के दौरान बैठी सभापति बीना गुप्ता।

सभापति के घर से एसीबी को मिला आधा किलो सोना व दो किलो चांदी

अलवर नगर परिषद सभापति के घर से एसीबी को आधा किलो सोना और दो किलो 213 ग्राम चांदी बरामद की है। इनकी बैंक पास बुक में अभी तक 50 हजार की एंट्री मिली हैं। पिछले काफी समय से पास बुकों में जमा व निकासी की एंट्री नहीं मिली है जिसके कारण पूरी रकम का पता नहीं लग पाया है। एसीबी की टीम मंगलवार को बैंक जाकर इनके खातों व लॉकर्स की जानकारी लेगा। सभापति और उनके पुत्र को तत्काल अरावली विहार पुलिस थाने में रखा गया है।

नगर परिषद में आतिशबाजी

सभापति के ट्रैप होते ही भाजपा पार्षद नगर परिषद कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने आतिशबाजी करते हुए सभापति के ट्रैप होने पर खुशी जाहिर की।

@स्पोर्ट्स &गेमिंग

800 साल पुरानी म...

@इंडिया &वर्ल्ड

शीतकालीन सत्र : संसद के दोनों सदनों ने कानून वापसी पर लगाई मुहर

6 मिनट में 3 कृषि कानून रद्द

30.11.2021

जिन तीन कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले एक साल से किसान आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें रद्द करने में संसद के दोनों सदनों को मात्र छह मिनट का समय लगा। वादे के मुताबिक, सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को दोनों सदनों में तीनों कानूनों की वापसी वाला बिल पेश किया। बिल पेश करते ही विपक्ष ने बहस की मांग करते हुए हंगामा किया। हंगामे के बीच बगैर बहस बिल पास हो गया। इस पर विपक्ष ने नाराजगी जताई। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी हो गई। अब सिर्फ राष्ट्रपति की मंजूरी बाकी है।

सदन में चर्चा करवा सरकार को घेरने की विपक्ष की नीति धराशायी

पत्रिका ब्यूरो
patrika.com

नई दिल्ली. संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सांसदों व पूर्व सांसदों के निधन पर शोक जताया गया। इसके बाद कृषि मंत्री तोमर ने विपक्ष के हंगामे के बीच तीनों कृषि कानून रद्द करने के लिए विधेयक सदन के पटल पर रखा तो तृणमूल कांग्रेस और टीआरएस के सांसद वेल में आकर शोरशराबा करने लगे।

इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नाराजगी भी जताई। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस विधेयक पर सदन में चर्चा की मांग की, लेकिन शोरशराबे में यह संभव नहीं हो सका। ऐसे में महज करीब तीन मिनट से कम समय में कानून रद्द करने का विधेयक पारित हो गया। इसके कुछ देर बाद ही तोमर ने इस विधेयक को राज्यसभा में भी पेश कर दिया। राज्यसभा में भी हंगामे के बीच महज तीन मिनट से कम समय में इसे पारित किया गया। सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस ने विपक्षी दलों के साथ बैठक की।

पढ़ें **6 मिनट**@ पेज 09

शीतकालीन सत्र का पहला दिन

किसानों के मुद्दों पर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन करते कांग्रेस के वरिष्ठ नेता।

मोदी... संसद में सवाल भी हों और शांति भी

संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा, 'संसद को कैसा चलाया, कितना अच्छा योगदान दिया, कितना सकारात्मक काम हुआ, भविष्य में इसे परखा जाए। सरकार हर विषय पर खुली चर्चा के लिए तैयार है। हम चाहते हैं संसद में सवाल भी हों और शांति भी'

खड़गे... बहस होती तो सभी मुद्दे शामिल होते

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 'हम कानून रद्द करने का स्वागत करते हैं, हम सदन में बहस चाहते थे। इसमें किसानों के मुद्दों एमएसपी, आंदोलनमें मृत किसानों के परिजनों के मुआवजे,लखीमपुर जैसे घटनाओं पर चर्चा हो जाती।'

बिरला... चर्चा तब होगी, जब व्यवस्था होगी

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के हंगामे पर कहा, 'हम बिल पर चर्चा कराने को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष का यह रवैया ठीक नहीं है। चर्चा तभी होगी, जब सदन में व्यवस्था होगी।' विधेयक पारित करने के बाद बिरला ने कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी।

12 राज्यसभा सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड

शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन राज्यसभा ने एक दर्जन सांसदों पर बड़ी कार्रवाई की। अनुशासनहीनता के आरोप में शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी सहित 12 सांसदों को सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है। सांसदों पर यह कार्रवाई, बीते मानसून सत्र के अंतिम दिन 11 अगस्त को उग्र एवं हिंसक व्यवहार, सुरक्षाकर्मियों पर हमले और सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप में हुई है। कांग्रेस ने राज्यसभा के सांसदों के निलंबन को संसदीय नियमों के खिलाफ बताया है।

पढ़ें **12 राज्यसभा**@ पेज 09

किसानों ने मनाया जश्न

मोर्चा का सरकार को आज का अल्टीमेटम

नई दिल्ली. संसद में कृषि कानूनों के रद्द होने के प्रस्ताव को संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी जीत बताया। किसानों की अन्य मांगों पर सरकार को मंगलवार तक का समय दिया है। किसान नेताओं ने कहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी कानून समेत अन्य मांगों पर सरकार का रुख देखने के बाद बुधवार को बैठक में अगली रणनीति पर चर्चा की जाएगी।

पढ़ें **मोर्चा**@ पेज 09

कागजों में हेराफेरी कर पत्नी की जमीन को बंधा दुग्ध सहकारी समिति को बेचना दर्शाया

पूर्व अध्यक्ष गुंजल का कारनामा, निजी फार्म पर बना दिया सहकारी चारा डिपो

01-12-2021

■ प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समिति बंधा का कारनामा, इस समिति के अध्यक्ष थे गुंजल के बड़े भाई

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. कोटा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ (कोटा डेयरी) के पूर्व अध्यक्ष श्रीलाल गुंजल के सहकारी चारा डिपो खोलने के मामले में बड़ा घोटाला सामने आया है। कागजों में हेराफेरी कर डेयरी के पूर्व अध्यक्ष ने पत्नी के नाम जमीन प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समिति बंधा को बेचना दिखाकर निजी फार्म हाउस पर लाखों रुपए का चारा डिपो खोल लिया है। इस समिति के अध्यक्ष श्रीलाल गुंजल के बड़े भाई दयालराम गुंजल थे। मिलीभगत कर जमीन का विक्रय पत्र दिखाकर यह चारा डिपो स्वीकृत करवाया था। डेयरी प्रबंधन ने हाल में चारा डिपो का सत्यापन किया तो इस निजी उपयोग करना पाया गया। दस लाख रुपए की लागत से यह डिपो बनाया गया था।

ऐसे किया खेल

भारत सरकार के उपक्रम राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) 29 अक्टूबर 2014 को कोटा डेयरी को पत्र भेजकर डेयरी के अधीन आने वाली प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों में 50 मीट्रिक टन चारा संग्रहण की क्षमता के बायोमास बंकर (चारा डिपो)के प्रस्ताव भेजने को कहा। इस पर बंधा समिति के समेत पांच सहकारी समितियों से प्रस्ताव लिए गए। चारा डिपो बनाने की पहली शर्त थी कि सहकारी समिति के पास खुद के स्वामित्व की जमीन होनी चाहिए। इस समिति के पास कोई जमीन नहीं थी। आनन-फानन में डेयरी के तत्कालीन अध्यक्ष श्रीलाल गुंजल की पत्नी के नाम धर्मपुरा में जमीन थी। इस जमीन का कुछ हिस्सा 29 दिसम्बर 2015 को समिति के नाम विक्रय पत्र कर दर्शा दिया गया। जबकि प्रस्ताव 15 नवम्बर2015 को ही भेज दिया था। इसकी जमीन की समिति के नाम रजिस्ट्री भी नहीं करवाया। इसका खुलासा समिति की ऑडिट रिपोर्ट में हुआ है।

नियमों से परे जाकर बनाया चारा डिपो

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समिति बंधा के तत्कालीन अध्यक्ष दयाल गुंजल और कोटा डेयरी के पूर्व अध्यक्ष श्रीलाल गुंजल ने कागजों में हेराफेरी कर 10 लाख की लागत से बंकर (चारा डिपो) का निर्माण करा लिया। जिस जमीन पर यह चारा डिपो बनाया गया है। वह भूमि बंधा में है ही नहीं। यह जमीन धर्मपुरा में स्थित श्रीलाल गुंजल के फा र्म हाउस पर है। नियमों के तहत बंधा समिति के कार्य क्षेत्र में ही चारा डिपो खुलना था। श्रीलाल गुंजल का फार्म हाउस धर्मपुरा प्राथमिक दुग्ध सहाकरी समिति के क्षेत्र में आता है।

सारी प्रक्रिया ही संदेह के घेरे में

बंधा समिति की जमीन पर चारा डिपो का निर्णय ही संदेह के घेरे में है। योजना के अंतर्गत समिति परिसर में बंकर बनाने का निर्णय तो लिया गया, लेकिन पत्रावली में कमेटी की रिपोर्ट ही नहीं हैं। कमेटी की ओर से बंकर बनाने की सूची एनडीडीबी को भिजवाने का प्रावधान था। लेकिन पत्रावली में ऐसी प्रक्रिया अपनाए जाने का उल्लेख नहीं हुआ है।

यह थी योजना

एनडीपी योजना के अंतर्गत जिस क्षेत्र में जानवरों के लिए चारे की कमी होती है। वहां बायोमाश फोडर (चारा डिपो) बनाया जाना प्रस्तावित किया गया था। इसमें बंकर में किसानों से सस्ती दर पर खरीदकर चारे को सुरक्षित रखा जाता है। चारे की कमी होने पर समिति के द्वारा उचित मूल्य पर इस चारे को बेचा जाता है। जिससे पशुओं को चारा उपलब्ध हो सके। एक बंकर के निर्माण पर 10 लाख का खर्च आया है।

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति बंधा में चारा डिपो बनाने का मामला मेरे से पहले का था। उस समय क्या प्रक्रिया अपनाई गई मुझे जानकारी नहीं है।

-राकेश शर्मा, एमडी कोटा डेयरी

निकल कर बर्फबारी का लुत्फ भी उठाया और तस्वीरें खींची। ऊंचाई वाले इलाकों में जहां बर्फ गिरा, वहां ... रविवार को मध्यम से भारी बारिश हुई।

हाल-ए-भ्रष्टाचार : राजस्थान सबसे आगे, बिहार दूसरे तो यूपी तीसरे स्थान पर

रिश्वत का वायरस... काम में तभी दिखेगा दम, जब होगी अपनी जेब गरम

देश में हर दूसरा घूस देने को मजबूर

अरुण कुमार 06-12-2021
patrika.com

जयपुर. देश में जिस तरह से घूसखोर अधिकारी-कर्मचारी और नेता एंटी करप्शन ब्यूरो के शिकंजे में फंस रहे हैं, उससे लगता हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्ट देशों की सूची में भारत की स्थिति और खराब हुई है। हर दूसरे व्यक्ति ने रिश्वत देने की बात मानी है। ट्रैस रिश्वत जोखिम मेट्रिक्स 2021 की हालिया रिपोर्ट में भारत 82वें स्थान पर पहुंच गया है। 2020 में 77वें स्थान पर था। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 74 फीसदी का कहना है कि पिछले 3 साल में रिश्वतखोरी बढ़ी है, जबकि दुनिया में यह बात स्वीकार करने वालों की संख्या 60% है। इंडिया करप्शन सर्वे के अनुसार, घूसखोरी में राजस्थान सबसे आगे है। वाशिंगटन की संस्था ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी के अनुसार भारत में आजादी से लेकर अब तक रिश्वत ने 450 अरब डॉलर का नुकसान किया है। पिछले साल भारत में काम करवाने के लिए 54% लोगों ने रिश्वत दी, जबकि पूरी दुनिया की चौथाई आबादी घूस देने को मजबूर है।

ये है स्थिति : काम के बदले कितनी रिश्वत

राज्य	रिश्वत दी
राजस्थान	78%
बिहार	75%
उत्तर प्रदेश	74%
कर्नाटक	63%
तमिलनाडु	62%
छत्तीसगढ़	57%
मध्यप्रदेश	55%
महाराष्ट्र	55%
गुजरात	48%
प. बंगाल	46%
दिल्ली	46%

स्रोत: इंडिया करप्शन सर्वे 2019
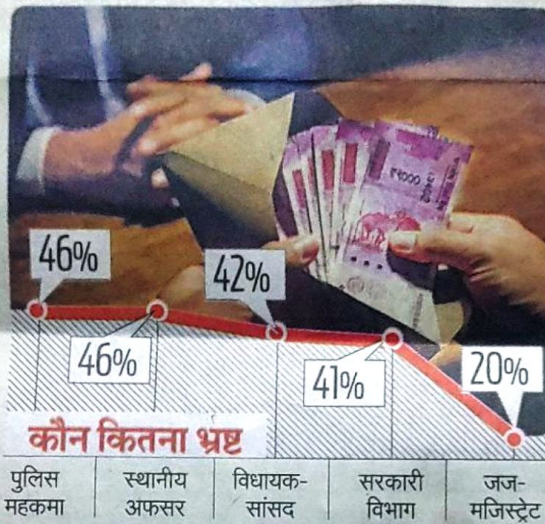
नोट लेकर दिया वोट

एशिया में बड़ी मात्रा में रिश्वत लेकर वोट देने की बात भी लोगों ने मानी है। 18 प्रतिशत की दर के साथ भारत इसमें चौथे नंबर पर है। सबसे ऊपर थाईलैंड और फिलीपींस 28% दर के साथ हैं। वहीं, 26 फीसदी की दर के साथ इंडोनेशिया तीसरे नंबर पर है। भारत में 51 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्हें सरकार पर या तो कम विश्वास है या बिल्कुल विश्वास नहीं है, जबकि जापान में ऐसा 56 फीसदी लोगों ने कहा।

खामियाजा भुगतने का डर: देश में 63% लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुंह खोला तो उन्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। बांग्लादेश में भी 63% लोग ऐसा ही महसूस करते हैं।

देश में सबसे ऊंची रिश्वत की दर

भारत में 39 फीसदी लोगों ने कहा कि उन्हें सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल करने के लिए रिश्वत देनी पड़ी। ये एशिया में सबसे ऊंची रिश्वत की दर है। नेपाल में यह दर 12%, बांग्लादेश में 24%, चीन में 28% और जापान में दो प्रतिशत पाई गई। लोगों ने माना कि पुलिस, अदालत, सरकारी अस्पताल, पहचान पत्र, बिजली और पानी जैसी सेवाएं बिना घूस के नहीं मिलती। काम के बदले 42% लोगों ने पुलिस को रिश्वत दी। पहचान पत्र और अन्य सरकारी कागजात लेने के लिए 41 प्रतिशत लोगों को रिश्वत देनी पड़ी।

सेवा के बदले सेक्स

पहली बार सर्वेक्षण में सरकारी अधिकारियों द्वारा सेवा के बदले सेक्स मांगने को भी शामिल किया है। भारत में इसकी दर 11 प्रतिशत है। 18 फीसदी की दर के साथ इंडोनेशिया सबसे ऊपर है। श्रीलंका में यह दर 17% पाई गई और थाईलैंड में 15 प्रतिशत।

17-12-2021

4 दिन गुजरे ▸ न मुकदमा दर्ज...न ही कोई तफ्तीश पुलिस का कहना है...कुछ पता नहीं

मंत्री बोले-सब पागल हो गए हैं, जो करना हो कर लेना

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

बांसवाड़ा . शहर में पिछले दिनों शादी समारोह में मंत्रीपुत्र के हर्ष फायरिंग मामले में पुलिस जांच अधर में है। सामान्य व्यक्ति के मामले में तत्काल मुकदमा दर्ज करने वाली पुलिस 4 दिन बाद भी प्रकरण तक दर्ज नहीं कर पाई है। इससे पुलिस की मंशा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मुद्दे पर बातचीत के दौरान केबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीया भी बौखला गए। उनके बिगड़े बोल यहां तक थे कि 'सब पागल हो गए हैं। जिसको जो जांच करानी हो, जो करना हो कर लेना।'

पुलिस प्रशासन का दावा है कि संज्ञान खुद लिया, इसलिए जांच होगी ही, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो पाया। बांसवाड़ा शहर में केबिनेट मंत्री मालवीया के बेटे चंद्रवीरसिंह व भाजपा सरकार में रहे पूर्व मंत्री धनसिंह रावत की पुत्री का विवाह समारोह सोमवार को था। बारात में शामिल मेहमानों के साथ मालवीया के बेटे आनंदपुरी के उपप्रधान प्रेमप्रताप सिंह ने भी हवाई फायर किए। इसके वीडियो वायरल हुए थे।

वीडियो हो रहे वायरल, पुलिस ढूंढ रही सबूत

जांच अधिकारी दे रहे व्यस्तता का हवाला

चौकी प्रभारी के जिम्मे अनुसंधान

कोतवाली सीआई रतनसिंह चौहान ने बताया कि प्रकरण का अनुसंधान हाउसिंग बोर्ड चौकी प्रभारी एसआइ कन्हैयालाल के जिम्मे है। बारात आनंदपुरी से आई थी, लिहाजा फोटो-वीडियो की तस्दीक कर कौन-कौन लोग बिनौले में थे, फायरिंग किस-किस ने की और हथियार वैध थे या अवैध, जांच करवाई जा रही है। अनुसंधान अधिकारी कन्हैयालाल ने बताया कि वीआईपी ड्यूटी और अन्य कार्यों के चलते दो दिन से व्यस्त रहा। मामले में अब जांच करेंगे।

> कोतवाली के अधिकारी से जांच करवा रहे हैं। फायरिंग किस-किस ने की और इस्तेमाल किए हथियार लाइसेंसी हैं या नहीं, इसकी तस्दीक होनी है। जब पुलिस ने खुद संज्ञान लिया है, तो जांच और कार्रवाई होगी ही। **राजेश कुमार मीना,** एसपी

केबिनेट मंत्री मालवीया से सीधी बातचीत

Q फायरिंग मामले को लेकर क्या कहना है?

मंत्री: ये प्रकरण चल रहा है या चलाया गया है।

Q क्यों इसमें ऐसा क्या हुआ?

मंत्री: सब पागल हो गए हैं। ये भी तो पता होना चाहिए, किसके घर शादी है।

Q आप कहना क्या चाहते हैं, ऐसे कैसे बात कर रहे हैं?

मंत्री: तो कैसे करूं। घर का त्योहार खराब करने में मजा आ रहा है क्या।

Q हमने कौनसा त्योहार खराब किया है?

मंत्री: और नहीं तो क्या किया है। पेपर में तो आया है। जांचें करवा रहे हो। जो करवाना हो कर लेना।

बहुचर्चित कोयला भुगतान प्रकरण : अडानी पावर फिर पहुंची सुप्रीम कोर्ट

506 करोड़ वापस मांगे तो अवमानना याचिका

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com 24-12-2021

जयपुर. बहुचर्चित कोयला भुगतान मामले में अडानी पावर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। कंपनी ने ऊर्जा विकास निगम के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। इस पर न्यायालय ने नोटिस जारी कर निगम से 6 जनवरी तक जवाब मांगा है। इससे परेशान ऊर्जा विकास निगम और ऊर्जा विभाग के अफसर कानूनविदों से राय ले रहे हैं। सरकार के उच्चाधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी गई है।

अडानी पावर ने कोयला भुगतान को लेकर करीब 4680 करोड़ रुपए का अतिरिक्त क्लेम किया था। इस पर ऊर्जा विकास निगम और डिस्कॉम अफसरों की कमेटी ने गणना कर कंपनी को ही 506 करोड़ रुपए लौटाने का नोटिस थमा दिया। अब अडानी पावर ने अवमानना याचिका दायर की। पढ़ें **506** @ पेज 09

5,637 करोड़ रुपए मार्च, 2021 तक कंपनी ने क्लेम किया

1,469 करोड़ रुपए कैरिंग चार्ज के कंपनी ने मांगे

2,627 करोड़ रुपए डिस्कॉम ने कंपनी को अक्टूबर, 2018 में चुकाए

4,680 करोड़ रुपए बाकी रकम का कंपनी का क्लेम रहा

506 करोड़ रुपए वापस मांगे, अक्टूबर 2018 में दी रकम में से

छूट

अब भूमि सुरक्षा राशि के 1710 करोड़ की बजाय 342 करोड़ रुपए ही लेगी सरकार

चार बड़ी कंपनियों को ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए बड़ी रियायत

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. देश की चार बड़ी कंपनियां राजस्थान में 34 हजार 200 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता के अक्षय ऊर्जा-के पार्क व प्लांट लगाने जा रही हैं। इसके लिए उन्होंने करीब 69 हजार हैक्टेयर जमीन की जरूरत जताई है। इनमें अडानी ग्रीन एनर्जी, रिन्यू पावर, जेएसडब्ल्यू व ग्रीनको एनर्जी कंपनी शामिल हैं। खास यह है कि सरकार ने 1.64 लाख करोड़ रुपए के बड़े निवेश प्रोजेक्ट देखते हुए बड़ी रियायत दी है। जमीन के लिए बतौर भूमि सुरक्षा राशि ₹1710 करोड़ की बजाय ₹342 करोड़ ही लेंगे। यह भी बैंक गारंटी के रूप में जमा होगी। यानी, पांच गुना कम राशि।

राजस्थान पर इसलिए फोकस

- **175** गीगावाट विंड एनर्जी की क्षमता
- **142** गीगावाट सोलर एनर्जी की क्षमता
- **1.25** लाख हैक्टेयर जमीन उपलब्ध
- **70** हजार मेगा. क्षमता के प्लांट लग सकते हैं

ये हैं विद्युत उत्पादन प्रोजेक्ट

30-12-2021

- **अडानी ग्रीन एनर्जी:** 9700 मेगावाट (सोलर व हाइब्रिड) के प्रोजेक्ट के लिए 20 हजार हैक्टेयर जमीन की जरूरत। भूमि सुरक्षा राशि 485 करोड़ की बजाय 97 करोड़ ही जमा होगी।
- **रिन्यू पावर:** 10 हजार मेगावाट (सोलर) क्षमता का प्रोजेक्ट 20 हजार हैक्टेयर जमीन पर लगेगा। यहां 500 करोड़ की बजाय 100 करोड़ रुपए ही बैंक गारंटी के रूप में लेंगे।
- **जेएसडब्ल्यू:** बीस हजार हैक्टेयर जमीन पर 10 हजार मेगावाट (सोलर व हाइब्रिड) क्षमता का प्रोजेक्ट आएगा। इसमें भी 500 करोड़ की बजाय 100 करोड़ रुपए ही लेंगे।
- **ग्रीनको एनर्जी:** 4500 मेगावाट (पंप स्टोरेज) प्रोजेक्ट के लिए 9 हजार हैक्टेयर जमीन चाहिए। 225 करोड़ की बजाय 45 करोड़ रुपए ही बैंक गारंटी के रूप में जमा होंगे।

(ग्रीनको एनर्जी के प्रोजेक्ट के लिए ज्यादातर भूमि वन क्षेत्र की है)

नहीं मिल पाएगी ब्याज की मोटी रकम

भूमि सुरक्षा राशि 5 लाख रुपए प्रति मेगावाट ली जाती रही है। कंपनियों के करोड़ों रुपए इसमें ब्लॉक होते हैं। नकद राशि के रूप में रोकड़ मिलने पर उसका ब्याज अक्षय ऊर्जा निगम को मिलता है। चारों कंपनियों ने कस्टमाइज पैकेज मांगा, जिसके बाद इनके लिए भूमि सुरक्षा राशि पांच लाख से घटाकर 1 लाख रुपए प्रति मेगावाट कर दी गई। इसमें भी नकद राशि जमा कराने की बजाय बैंक गारंटी देने की छूट का प्रावधान है।

9 राज्य, 38 संस्करण | अजमेर ▪ अलवर ▪ अहमदाबाद ▪ इंदौर ▪ उज्जैन ▪ उदयपुर ▪ कोटा ▪ कोलकाता ▪ खंडवा ▪ गंगापुरसिटी ▪ ग्वालियर ▪ चेन्नई ▪ छिंदवाड़ा ▪ जगदलपुर ▪ जबलपुर ▪ जयपुर ▪ जोधपुर ▪ दिल्ली ▪ नागौर ▪ पाली ▪ बाड़मेर ▪ बांसवाड़ा ▪ बिलास

ित्तौड़गढ़ में सवालों के घेरे में चिकित्सा प्रशासन: कबाड़ी के यहां मिले बड़ी मात्रा में इंजेक्शन, सिरप और गोलियां

अवधि पार नहीं फिर भी कबाड़ में बिक रही सरकारी दवाइयां

तेन्द्र सारण
trika.com

त्तौड़गढ़. सरकारी अस्पतालों को कार की ओर से उपलब्ध करवाई रही बेशकीमती दवाइयां त्तौड़गढ़ में कबाड़ी को बेची जा है। यहां तक कि सरकारी स्पतालों के वार्डों में मरीजों को ढ़ाई जाने वाली ड्रिप्स भी कबाड़ी दे रहे हैं, जो खून से सनी हैं।

राज्य सरकार प्रदेश में निःशुल्क ा योजना संचालित कर लाखों ए की दवाइयां सरकारी स्पतालों को सप्लाई करवा रही है। के विपरीत पत्रिका की ओर से की पड़ताल में गुरुवार को सरकारी स्पतालों को भिजवाई गई कीमती दवाइयां शहर के एक कबाड़ी के यहां पड़ी हुई मिली। वार्डों में मरीजों को चढ़ाई जाने वाली ड्रिप्स की खाली बोतलें भी कबाड़ी के यहां पड़ी हुई थीं। इससे संक्रमण की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। कबाड़ी का कहना था कि उसके यहां वाहन में भरकर दवाइयां और अस्पतालों का बॉयोवेस्ट बेचने के लिए लाया जाता है। जिसे वह रुपए देकर खरीदता है। कबाड़ी के यहां मिली दवाइयों में से कई दवाइयां अवधि पार भी नहीं थीं।

कबाड़ी के यहां पड़ी दवाइयां और सिरप के डिब्बे।

कबाड़ में मिली यह दवाइयां

पत्रिका को कबाड़ी के यहां मिली दवाइयों में फोलिक एसिड की गोलियां, ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन सेट, बीटामिथासोन क्रीम, मिकोनाजोल नाइट्रेट क्रीम, इट्राकोनाजोल केप्सूल्स, एमोक्सीसिलीन सीरप आदि दवाइयां शामिल हैं। सभी दवाइयां सरकारी अस्पतालों के लिए सप्लाई की गई थी। इन पर स्पष्ट रूप से राजस्थान सरकार सप्लाई नोट फॉर सेल तथा नि:शुल्क वितरण के लिए क्यूसी पास्ड अंकित किया हुआ है।

सरकार के यह हैं नियम

राज्य सरकार के साफ नियम हैं कि सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क दी गई दवाइयों का पूरा हिसाब रखा जाएगा। कितनी दवाइयां मरीजों को दी गई हैं। स्टॉक में रखी दवाइयां कितनी हैं, आदि का हिसाब पेश करना होगा। अवधि पार दवाइयां भी जमा करवानी होगी। इसके लिए सीधे तौर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी जिम्मेदार हैं।

आखिर कौनसा नेटवर्क कर रहा है काम

नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाने वाली सरकारी दवाइयों को कबाड़ी के यहां तक पहुंचाने में कौनसा नेटवर्क काम कर रहा है, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। कबाड़ी का कहना है कि यह सब वाहन में डालकर उसके यहां लाया जाता है।

अस्पतालों में नि:शुल्क मिलने वाली सरकारी दवाइयां तथा बॉयोवेस्ट कबाड़ी तक पहुंचना गंभीर मामला है। इस संबंध में कल ही कार्रवाई करेंगे।

डॉ. रामकेश गुर्जर, सीएमएचओ
चित्तौड़गढ़

नागल अध्यक्ष मनोनीत : अखण्ड ...
अर्चना नागल को महिला जिला अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है।

BVSc & AH ... काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का ...

राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा पूर्व में ... विज्ञप्ति क्रमांक राजुवास/ बीवीएससी एण्ड एएच प्रवेश/2021-22/3256 दिनांक 15.12.2021 के क्रम में ऑनलाईन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि 31.12.2021 को बढ़ाकर 15.01.2022 की जाती है। इस संबंध में अन्य सभी विवरण उक्त संदर्भित विज्ञप्ति अनुसार रहेगा। चेयरमैन, केन्द्रीय स्नातक प्रवेश मण्डल

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर दक्षिण

पोलीटेक्नीक कॉलेज परिसर के अन्दर, गौरव पथ, जोधपुर
फोन सं.- 0291-2651499, e-mail: ceo_nnj@rediffmail.com

क्रमांक: 153 दिनांक: 30.12.2021

-: उजरदारी सूचना :-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 69-ए, संशोधित (2021), स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प 8(ग) ( ) (PSKS) अभियान -2021 / नियम/ डी एल.बी/2021/68191 दिनांक 27.09.2021 में धारा 69-ए नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 में आवेदन पत्र मय स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों मय शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत कर भूखण्ड का लीजडीड/ पट्टा / एक्सचेंज डीड अपने पक्ष में जारी करने की मांग की है।

क्र. सं.	वार्ड सं.	नाम पता	पड़ोस	वर्गगज/ वर्गमीटर
01		श्री अजीत सिंह राठौड़ पुत्र श्री चिमनसिंह राठौड़, ईस्ट पटेल नगर, गणेशपुरा रातानाडा, जोधपुर	पूर्व- 40 फीट रोड व बहादुर सिंह के बंगले में जाने का रास्ता पश्चिम- 10 फीट की गली उत्तर- प्लॉट सं. जी 8 दक्षिण- प्लॉट सं. जी 6	90.90 वर्गगज
02		श्री शफी मोहम्मद पुत्र फैज मोहम्मद 77 डी पोस्ट ऑफिस के पीछे, सुभाष चौक चक्की वाली गली रातानाडा, जोधपुर	उत्तर- निसार मोहम्मद का मकान दक्षिण- रामा कक्का का मकान पूर्व- गली पश्चिम- आम रास्ता	74.32 वर्गमीटर
03		श्रीमती ललीता देवी पत्नी कालूदास रांकावत, 85 बी पूर्वी ईस्ट पटेल नगर, गणेशपुरा, रातानाडा, जोधपुर	उत्तर- रास्ता 20 फीट दक्षिण- भूखंड सं. 86 ए पूर्व- रास्ता 10 फीट पश्चिम- भूखंड सं. 85 ए	62.50 वर्गगज
04	51	श्री अनिल कुमार प्रजापत पुत्र श्री ओमप्रकाश प्रजापत, 387 जे.के. नर्सिंग होम की गली प्रथम बी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर	उत्तर- मन्नूमल जी का मकान दक्षिण- भूखंड सं. 387 का आधा हिस्सा जो होतचंद जी को बेचान किया गया पूर्व- सेनेट्री लाईन के लिए छोड़ी गई गली पश्चिम- रास्ता 25 फीट	91.20 वर्गगज
05		श्री पवन झुगट पुत्र श्री सत्यनारायण, श्री सत्यनारायण झुगट पुत्र स्व. श्री नत्थूराम झुगट, सी 116, प्रथम विस्तार, कमला नेहरू नगर, जोधपुर	उत्तर- इसी भूखण्ड का 107 का हिस्सा जो कि वीरूमल जी को बेचान है। दक्षिण- सेनेटरी गली 6 फीट चौड़ी पूर्व- इसी भूखंड का 107 का हिस्सा जो कि कन्हैयालाल जी को बेचान है। पश्चिम- 22 फीट चौड़ा रास्ता	108 वर्गगज
06		श्री उपदेश करण माथुर पुत्र स्व. श्री देवकरण माथुर, 528, 8 वीं बी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर	उत्तर- श्रीमती संतोष पत्नी ओमप्रकाश का मकान, दक्षिण- शरद राठी पुत्र श्याम राठी का मकान, पूर्व- महेश सोनी का मकान पश्चिम- मकान नं. 531	66.63 वर्गमीटर
07		श्री राकेश अरोड़ा पुत्र श्री रतनचन्द अरोड़ा 74 ए ईस्ट पटेल नगर, रातानाडा, जोधपुर	उत्तर- सड़क 30 फीट दक्षिण- प्लॉट सं. 75 पूर्व- प्लॉट सं. 74 बी पश्चिम- सड़क 20 फीट	138.88 वर्गगज
08		श्री महंत अचलानंदगिरी शिष्य पुत्र श्री गुरू महंत रामानंद, क्वार्टर सं. 14, पुराना फरासखाना बाबा रामदेव मंदिर, राईका बाग, जोधपुर	उत्तर- क्वार्टर सं. 15 की जायदाद दक्षिण- क्वार्टर सं. 13 की जायदाद पूर्व- रास्ता 50 फीट पश्चिम- रास्ता 30 फीट	417.66 वर्गगज
09		श्री मानसिंह तंवर पुत्र श्री लादूराम तंवर शिव मंदिर के सामने वाली गली, रातानाडा, जोधपुर	उत्तर- खीवराज जी का मकान दक्षिण- इसी भूखंड का हिम्मतसिंह जी का मकान, पूर्व- 14 फीट गली पश्चिम- गली	87.09 वर्गमीटर
10		श्री दिनेश सिंह राजपुरोहित/महेन्द्र सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री रामरतन सिंह, 18 बी ईस्ट पटेल नगर, रातानाडा, जोधपुर	उत्तर- भूखंड सं. 19 दक्षिण- भूखंड सं. ए पूर्व- सड़क 30 फीट पश्चिम- भूखंड सं. 4 ए	74.30 वर्गगज
11		श्री रामप्रकाश मालपानी पुत्र श्री रामप्रसाद श्रीमती दुर्गा देवी पत्नी रामप्रकाश, भूखंड सं. 3 सी 4 व 3 सी 4, उदय निवास पावटा बी रोड, जोधपुर	उत्तर- अन्य भूखण्ड दक्षिण- अन्य भूखण्ड पूर्व- प्लॉट नं. 03 उदय निवास पश्चिम- मुख्य सड़क	200.20 वर्गगज
12		श्री रामप्रकाश मालपानी पुत्र श्री रामप्रसाद श्रीमती दुर्गा देवी पत्नी रामप्रकाश, भूखंड सं. 3 ए व 3 बी, खेजड़ला हाउस पावटा बी रोड, जोधपुर	उत्तर- प्लॉट सं. 2 दक्षिण- प्लॉट सं. 4 पूर्व- 60 फीट रोड पश्चिम- 25 फीट सड़क	499.99 वर्गगज
13		श्रीमती संतोष परिहार पत्नी श्री परसराम, 3 जे गायत्री कॉलोनी, गणेशपुरा, रातानाडा, जोधपुर	उत्तर- प्लॉट सं. 4 दक्षिण- 25 फीट रोड पूर्व- खुली जमीन 25 फीट चौड़ा रास्ता पश्चिम- 25 फीट चौड़ी सड़क	130 वर्गमीटर
14		मैसर्स राजेन्द्र क्राउन प्लाजा प्रा.लि., जरिये प्रतिनिधि श्री भूपेन्द्र पारिक पुत्र श्री घेवरचन्द पारिक, पता- मकान नं. बी-63/64 तिलक स्कूल के पास, चौपासनी रोड, जोधपुर	उत्तर- 10 फुट गली दक्षिण- अन्य जायदाद पूर्व- 20 फुट गली पश्चिम- अन्य जायदाद	719.44 वर्गगज
15		श्री सुन्दरलाल पुत्र स्व. दौलाराम प्लॉट नं. 49 बी वाके गोरूऊ हाऊस, रातानाडा, जोधपुर	उत्तर- 15 फुट की गली दक्षिण- भूखंड सं. 49 इसी भूखंड में से आधा हिस्सा सुरजाराम जी का मकान पूर्व- रास्ता 20 फीट का पश्चिम- भूखंड सं. 62	166.16 वर्गगज
16		श्री ओमप्रकाश वैष्णव (रांकावत) पुत्र श्री भंवरलाल 85-ए पूर्वी पटेल नगर, गणेशपुरा, रातानाडा, जोधपुर	उत्तर- रास्ता 20 फीट दक्षिण- भूखंड सं. 86 ए पूर्व- भूखंड सं. 85 ए पश्चिम- भूखंड सं. 85	62.50 वर्गगज
17		श्रीमती दुर्गा प्रजापत पत्नी श्री श्यामलाल प्रजापत गली नं. 4, गणेशपुरा, रातानाडा, जोधपुर	उत्तर- रास्ता दक्षिण- विरेन्द्र जी प्रजापत का मकान पूर्व- रामचन्द्र जी का मकान पश्चिम- श्रीमती लीला पत्नी किशनलाल जी का मकान	24 वर्गगज
18		श्रीमती मेजर गोपिका भाटी पुत्री स्व. श्री किशोर सिंह, 27 बी हनवंत कॉलोनी, राईका बाग, जोधपुर	उत्तर- रकबीर सिंह जी का मकान दक्षिण- खाली भूखंड पूर्व- श्रीमती लक्ष्मीकुमारी का मकान पश्चिम- रोड 25 फीट	230.73 वर्गमीटर
19		श्रीमती लक्ष्मी कुमारी पत्नी स्व. श्री किशोर सिंह, 27 हनवंत कॉलोनी, राईका बाग, जोधपुर	उत्तर- रकबीर सिंह जी का मकान दक्षिण- खाली प्लॉट पूर्व- रोड 50 फीट पश्चिम- मेजर गोपिका भाटी का मकान	273.10 वर्गमीटर
20		श्रीमती अलका पत्नी श्री भरत, 106 ए, ईस्ट पटेल नगर, गणेशपुरा, रातानाडा, जोधपुर	उत्तर- 30 फीट रोड दक्षिण- प्लॉट नं. 106 सी पूर्व- गली पश्चिम- भूखंड सं. 106 बी	28.98 वर्गमीटर
21		श्रीमती उगमा देवी पत्नी श्री श्रवण कुमार, 106 सी, ईस्ट पटेल नगर, गणेशपुरा, रातानाडा, जोधपुर	उत्तर- गली व प्लॉट सं. 106 ए व 106 बी दक्षिण- प्लॉट सं. 119 पूर्व- प्लॉट सं. 104 पश्चिम- प्लॉट नं. 107	43.47 वर्गमीटर
22		श्री मुकेश कुमार पुत्र आनंदराम, 147 ईस्ट पटेल नगर, गणेशपुरा रातानाडा, जोधपुर	उत्तर- प्लॉट सं. 146 दक्षिण- प्लॉट सं. 148 पूर्व- पहाड़ी पश्चिम- रोड 30 फीट	90.30 वर्गमीटर
23		श्री मनीष शर्मा पुत्र श्री प्रेमराज शर्मा, 54 प्रभु निवास शिव रोड, रातानाडा, जोधपुर	उत्तर- प्लॉट सं. 55 दक्षिण- प्लॉट सं. 53 पूर्व- सड़क 20 फीट पश्चिम- प्लॉट सं. 3	328.6 वर्गगज
24		श्री रणवीर सिंह पुत्र तुलसी सिंह, 41 ए महाराजा हनवंत नगर, पार्वती नगर के सामने, सर्किट हाऊस रोड, जोधपुर	उत्तर- महाराज गजसिंह की जायदाद दक्षिण- भूखण्ड सं. 42 पूर्व- अन्य भूमि पश्चिम- रास्ता 20 फीट	88.33 वर्गगज
25		श्रीमती निर्मला गहलोत पत्नी राजेन्द्र सोनी/ पुत्री मंगलराम, 233 शिव मंदिर के पास, रातानाडा, जोधपुर	उत्तर- मूलाराम जी का मकान दक्षिण- अन्नाराम जी का मकान पूर्व- 22 फीट का रास्ता पश्चिम- 6 फीट की गली व मकान सं. 234	57.971 वर्गमीटर
26		श्री दिनेश गहलोत पुत्र स्व. श्री भीकाराम 233 शिव मंदिर के पास, रातानाडा, जोधपुर	उत्तर- 6 फीट की गली व आगे प्लॉट सं. 236, दक्षिण- इसी जायदाद में अन्नाराम जी का हिस्सा, पूर्व- 22 फीट का आम रास्ता पश्चिम- 6 फीट की गली व मकान सं. 234	69.33 वर्गगज
27		श्री स्वामी अचलानंद गिरी उर्फ अचलूराम पुत्र श्री गुरु रामानन्द जी प्लॉट सं. 3 बाबा रामदेव मन्दिर के पास राईका बाग जोधपुर	उत्तर- 21 फीट चौड़ी सड़क दक्षिण- शेरसिंह का मकान पूर्व- 6 फीट की गली पश्चिम- श्रीमती देवेन्द्र बाईसा एव नवीन माथुर का मकान	337.21 वर्गगज
28	71	श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी माणकचन्द पता- मकान नं. 161 ईस्ट पटेल नगर गणेशपुरा, रातानाडा, जोधपुर	उत्तर- सड़क दक्षिण- राजा श्री गजसिंह जी की सम्पत्ति पूर्व- भूखण्ड संख्या 160 पश्चिम- भूखण्ड संख्या 162	138.88 वर्गगज
29	63	श्री अरविन्द श्रीमाली पुत्र स्व. श्री नारायणदत्त श्रीमाली पता- भूखण्ड सं. 3/17 हाईकोर्ट कॉलोनी के पास, रातानाडा, जोधपुर	उत्तर- सड़क दक्षिण- भूखण्ड संख्या 3/18 पूर्व- भूखण्ड संख्या 3/1 व 3/2 पश्चिम- भूखण्ड संख्या 3/16	300.00 वर्गगज
30	55	श्री रघुवीर सिंह भदावत पुत्र स्व. श्री दीपसिंह भदावत पता- मकान नं. 27-ए हनवन्त बिहार, बाबा रामदेव मन्दिर के पास, राईका बाग, जोधपुर	उत्तर- भूखण्ड संख्या 26 दक्षिण- भूखण्ड संख्या 27 पूर्व- आम रास्ता पश्चिम- आम रास्ता	526.88 वर्गगज
31		श्री शिवरतन व्यास पुत्र स्व. श्री नवरतन व्यास पता मकान नं. 3/17 सिटी बस स्टैण्ड, जालोरी गेट, जोधपुर	उत्तर- सड़क दक्षिण- गली पूर्व- श्री कान्तिलाल जी का मकान पश्चिम- श्री कमोद टाटिया जी का मकान	61.75 वर्गगज
32	71	श्री जब्बर सिंह पुत्र श्री दलपत सिंह पता- मकान नं. 75 गणेशपुरा, जोधपुर	उत्तर- श्री जीवराज जी का निवास दक्षिण- श्री नत्थुजी माली का निवास पूर्व- भाखर आया हुआ है पश्चिम- आम रास्ता	453.33 वर्गगज
33	71	श्री मनीष शर्मा पुत्र श्री प्रेमराज शर्मा पता- 56 पूर्वी पटेल नगर, गणेशपुरा रातानाडा, जोधपुर	उत्तर- सड़क दक्षिण- भूखंड सं. 55 पूर्व- सड़क पश्चिम- भूखंड सं. 2	532.27 वर्गगज
34	71	श्री मनीष शर्मा पुत्र श्री प्रेमराज शर्मा पता- 55 पूर्वी पटेल नगर, गणेशपुरा रातानाडा, जोधपुर	उत्तर- भूखण्ड संख्या 56 दक्षिण- भूखण्ड संख्या 56 पूर्व- सड़क पश्चिम- भूखण्ड संख्या 03	267.58 वर्गगज
35	71	श्री मनीष शर्मा पुत्र श्री प्रेमराज शर्मा पता- मकान नं. 02 गणेशपुरा रातानाडा, जोधपुर	उत्तर- सड़क दक्षिण- भूखण्ड संख्या 03 पूर्व- भूखण्ड संख्या 56 पश्चिम- सड़क	595.55 वर्गगज
36	71	श्री रविन्द्र पुत्र श्री मंसाराम पता- मकान नं. 286, गणेशपुरा रातानाडा, जोधपुर	उत्तर- भूखण्ड संख्या 67 दक्षिण- भूखण्ड संख्या 64 पूर्व- ऑपन लैण्ड पश्चिम- गली	179.71 वर्गगज
37		श्री जगदीप कल्याण पुत्र श्री बुद्धिसागर कल्याण पता मकान नं. 1-बी पोकरण हाउस पीडब्ल्यूडी कॉलोनी, रातानाडा जोधपुर	उत्तर- भूखण्ड संख्या 1 ए दक्षिण- रास्ता पूर्व- भूखण्ड संख्या 02 पश्चिम- सड़क	75.33 वर्गगज
38	54	श्रीमती पूजा पारख पत्नी स्व. श्री अभिषेक पारख पता- मकान नं. 34-बी-1 हनवंत नगर, सर्किट हाउस रोड, जोधपुर	उत्तर- भूखण्ड संख्या 35 दक्षिण- रोड पूर्व- भूखण्ड संख्या 41 पश्चिम- रोड	150.00 वर्गगज
39		श्रीमती अरुणा शर्मा पत्नी स्व. श्री हरीशचन्द्र शर्मा पता- मकान नं. 37-एम हनवंत नगर सर्किट हाउस रोड, रातानाडा, जोधपुर	उत्तर- महाराज गजसिंह जी की जायदाद दक्षिण- भूखण्ड संख्या 36 पूर्व- भूखण्ड संख्या 38 व 39 पश्चिम- सड़क	152.77 वर्गगज
40	53	डॉ. श्री विनय अबिचन्दानी पुत्र श्री हीरालाल अबिचन्दानी पता मकान नं. 379/ए/2 चौथी सी रोड सरदारपुरा जोधपुर	उत्तर- भूखण्ड संख्या 379/ बी दक्षिण- सड़क पूर्व- सड़क पश्चिम- भूखण्ड संख्या 379/ए	128.25 वर्गमीटर
41	53	श्री हेमन्त कांकरिया पुत्र श्री लूणकरण श्रीमती संगीता कांकरिया पत्नी श्री हेमन्त कांकरिया पता मकान नं. 9 सेक्टर एम हनवंत नगर, रातानाडा, जोधपुर	उत्तर- रास्ता दक्षिण- आधुनिक समिति के भूखण्ड पूर्व- भूखण्ड संख्या 9-ए पश्चिम- भूखण्ड संख्या 08	200.00 वर्गगज
42	71	श्री मांगीलाल सोनी पुत्र श्री चम्पालाल सोनी, श्री मुरलीधर सोनी पुत्र श्री चम्पालाल सोनी पता- मकान नं. 37-ए उम्मेद क्लब, जोधपुर	उत्तर- सड़क दक्षिण- भूखण्ड संख्या 37-बी पूर्व- गली पश्चिम- भूखण्ड संख्या 36	111.11 वर्गगज
43		श्री घनश्याम लाल पुत्र स्व. श्री मदनगोपाल पता- मकान नं. 47-ए भाग सी. पीडब्ल्यूडी कॉलोनी, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर	उत्तर- इसी भूखण्ड का शेष भाग दक्षिण- सड़क पूर्व- इसी भूखण्ड का भाग- सी- 2 पश्चिम- भूखण्ड संख्या 47-ए	555.55 वर्गगज
44		श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री हरिसिंह पता- मकान नं. 382, लक्ष्मी नगर पावटा बी रोड, जोधपुर	उत्तर- गली दक्षिण- श्री विनोद कवाड़ जी का मकान पूर्व- भूखण्ड संख्या बी पश्चिम- गली	69.44 वर्गगज
45		श्री श्याम उर्फ श्याम सुन्दर मोदी पुत्र श्री सोहननाथ मोदी पता मकान नं. पार्ट-बी तृतीय बी व सी रोड सरदारपुरा, जोधपुर	उत्तर- श्री सुरेश नाथ जी का मकान दक्षिण- श्री सुबोधनाथ जी का मकान पूर्व- रास्ता पश्चिम- इसी भूखण्ड का शेष भाग	69.44 वर्गगज

अतः हर खास व आम को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था या विभाग को कोई उजर/एतराज हो तो अपनी आपत्ति सात दिवस के अन्दर-अन्दर निगम कार्यालय में निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करे, अन्यथा बाद म्याद गुजरने के पश्चात् भूखण्ड का लीजडीड/ पट्टा/ एक्सचेंज डीड के अन्तर्गत 69-ए नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत जारी करने की अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

उपायुक्त
नगर निगम, जोधपुर दक्षिण

एंट्रिक्स-डेवास विवाद

भारत सरकार को झटका

कनाडा में एयर इंडिया और एएआइ की संपत्तियां जब्त

05.01.22

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

मुंबई/नई दिल्ली. इसरो की एंट्रिक्स कॉरपोरेशन और देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड विवाद में कनाडा की एक अदालत ने एयरइंडिया और एयरपोर्ट ऑथिरिटी ऑफ इंडिया (एएआइ) की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश देकर भारत सरकार को जोरदार झटका दिया है। इसके तहत करीब 50 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है। इसे डेवास मल्टीमीडिया कंपनी के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है। यह विवाद दस साल से जारी है।

कनाडा के क्यूबेक की सुपीरियर कोर्ट ने इस सिलसिले में 24 नवंबर और 21 दिसंबर को दो फैसले दिए थे। इनमें एएआइ के पास रखी एएआइ और एयर इंडिया की संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया गया था, ताकि डेवास के पक्ष में वसूली की जा सके। इन आदेशों के बाद एएआइ की करीब 6.8 मिलियन डॉलर (करीब 50 करोड़ रुपए) की संपत्तियां क्यूबेक में जब्त की गईं हैं।

हालांकि, एयर इंडिया की जब्त संपत्तियों का सटीक आंकड़ा सामने नहीं आया है। बताया जा रहा है, एयर इंडिया की 30 मिलियन डॉलर से ज्यादा की संपत्तियां जब्त हुई हैं।

ये संपत्तियां कनाडा के क्यूबेक प्रांत में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पास रखी हुई थीं। एयर इंडिया को यह झटका ऐसे समय लगा है जब टाटा समूह ने एयरइंडिया को खरीद लिया है। हालांकि समझौते के अनुसार, एयरइंडिया के पिछले सभी कानूनी दावों की जिम्मेदारी से टाटा समूह को मुक्त रखा गया है।

डेवास के तीन शेयरधारक ने अदालत के फैसले को अमल में लाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उनके वकील मैथ्यू डी मैकगिल ने कहा कि, अदालत के आदेश से दुनियाभर में डेवास के शेयरधारकों का विश्वास बढ़ेगा। यह कार्रवाई उनके पक्ष में पहला बड़ा कदम है।

सैटेलाइट सौदे से जुड़ा है मामला

यह मामला इसरो की एंट्रिक्स कॉरपोरेशन और डेवास के बीच हुए एक सैटेलाइट सौदे से जुड़ा है, जिसे 2011 में निरस्त कर दिया गया था। इस मामले में इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स की कोर्ट ने डेवास के पक्ष में फैसला सुनाया था और भारत सरकार को 1.3 अरब डॉलर देने का आदेश दिया था। डेवास के विदेशी शेयरधारक इस फैसले को आधार बनाकर रिकवरी के लिए कनाडा और अमरीका समेत कई देशों में भारत सरकार के खिलाफ अदालत की शरण में गए थे, जिस पर ये फैसला उनके पक्ष में आया है।

फैसले पर सुनवाई के लिए जज नियुक्त

एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के अनुसार, कोर्ट ने भारत सरकार के वकील की इस अपील को स्वीकार करते हुए जब्ती को खारिज करने के फैसले पर सुनवाई के लिए एक जज को नियुक्त कर दिया है।